भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

दिसंबर 2024

खंड 78 अंक 12

अध्यक्ष
माइकल देवब्रत पात्र

संपादक समिति
मनीष कपूर
अजीत आर जोशी
रेखा मिश्र
प्रज्ञा दास
सुनिल कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया ‘हाल के प्रकाशन’ खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 (4-6 दिसंबर)

गवर्नर का वक्तव्य 01

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, 4 से 6 दिसंबर 2024 09

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करना मौद्रिक नीति का मुख्य सिद्धांत
श्री शक्तिकान्त दास 15

आर्थिक शोध में नए आयाम
माइकल देवब्रत पात्र 21

मौद्रिक नीति संचरण
माइकल देवब्रत पात्र 27

प्रभावी समाधान के लिए आईबीसी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
श्री एम. राजेश्वर राव 33

जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करना और संवहनीय वित्त के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना
श्री एम. राजेश्वर राव 39

आरबीआई: 90 वर्षों की विरासत, विनियमन और आकांक्षा पर एक दृष्टि
श्री एम. राजेश्वर राव 45

समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना
श्री स्वामीनाथन जे 49

उभरते जोखिमों के मध्य पर्यवेक्षण
श्री स्वामीनाथन जे 53

एमएसएमई - ऋण देने में विश्वास बढ़ाकर ऋण अंतर को पाटना
श्री स्वामीनाथन जे 55

परिवर्तन लाने में बोर्ड की भूमिका
श्री स्वामीनाथन जे 59

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 63

सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा 111

बैंकों का दैनिक मुद्रा रिज़र्व संधारण व्यवहार 131

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव 145

वर्तमान सांख्यिकी **157**

हाल के प्रकाशन **211**

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25
(4-6 दिसंबर)

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकान्त दास

चूंकि हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, मैं 2024 की घटनापूर्ण यात्रा पर विचार करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप, केंद्रीय बैंकों को एक बार फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर, विशाल और जटिल आघातों से बचाने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बैंक लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताओं, जो सभी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, द्वारा निर्मित नए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों के लिए अवस्फीति का अंतिम चरण लंबा और कठिन होता जा रहा है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा बफर्स का निर्माण करना, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

भारत में, संवृद्धि और मुद्रास्फीति के पथ में हाल के विचलन के बावजूद, अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर एक सतत और संतुलित पथ पर अपनी यात्रा जारी रख रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के बीच, भारत उभरते रुझानों से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को हुई। उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, इसने 4:2 बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से 'तटस्थ' रुख जारी रखने तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

* गवर्नर का वक्तव्य: 6 दिसंबर 2024.

अब मैं संक्षेप में इन निर्णयों के औचित्य को बताऊंगा। एमपीसी ने संवृद्धि की गति में हाल की मंदी पर ध्यान दिया, जो चालू वर्ष के लिए संवृद्धि के पूर्वानुमान में कमी के रूप में सामने आता है। इस वर्ष की दूसरी छमाही और अगले वर्ष की ओर बढ़ते हुए, एमपीसी ने संवृद्धि की संभावना को आघात-सह बताया, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता बताई। दूसरी ओर, खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि के कारण अक्तूबर माह में मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा से ऊपर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव के इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में बने रहने की संभावना है और 2024-25 की चौथी तिमाही से ही कम होना शुरू होगा, जिसे सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार, खरीफ फसल की आवक, संभावित अच्छे रबी उत्पादन और पर्याप्त अनाज बफर स्टॉक से समर्थन मिलेगा।

उच्च मुद्रास्फीति, उपभोक्ताओं के हाथों में प्रयोज्य आय को कम कर देती है और निजी उपभोग को प्रभावित करती है, जिसका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की बढ़ती घटनाएं, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और वित्तीय बाजार में अस्थिरता, मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। एमपीसी का मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ ही उच्च संवृद्धि के लिए मजबूत आधार सुरक्षित किया जा सकता है। एमपीसी अर्थव्यवस्था के समग्र हित में मुद्रास्फीति संवृद्धि संतुलन को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने तथा मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख को जारी रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावना की निगरानी और आकलन करने तथा उचित रूप से कार्य करने में लचीलापन मिलता है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वैश्विक संवृद्धि

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2024 में असाधारण समुत्थानशीलता प्रदर्शित की है।[1]

[1] वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में और सुधार हुआ और यह 52.4 पर पहुंच गया तथा नवंबर 2024 में लगातार तेरहवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा। नवंबर में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में सुधार हुआ और यह 50.0 के तटस्थ स्तर पर वापस आ गया। वैश्विक सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी रहा तथा पीएमआई नवंबर में लगातार बाईसवें महीने 53.1 पर विस्तार क्षेत्र में रहा। ओईसीडी ने अपने दिसंबर 2024 के आउटलुक में 2024 के लिए जीडीपी संवृद्धि पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आईएमएफ ने भी अपने नवीनतम अक्तूबर 2024 वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट में 2024 के लिए संवृद्धि अनुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

मुद्रास्फीति धीरे-धीरे अपने बहु-दशकीय उच्चतम स्तर से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण कई केंद्रीय बैंक नीतिगत बदलाव करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।[2] वैश्विक व्यापार आघात-सह बना हुआ है[3], जो बढ़ती मात्रा में भू-राजनीतिक गुटों के भीतर सीमित है।[4] पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, बढ़ते अमेरिकी डॉलर और मजबूत बॉण्ड प्रतिफल के कारण वित्तीय बाजार अनिश्चित बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उभरते बाजारों से बड़ी मात्रा में पूंजी का बहिर्वाह हुआ है और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता आई है। आगे चलकर, संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण संभावना धुंधली हो जाएगी, जिससे वैश्विक संवृद्धि कमजोर हो सकती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

घरेलू संवृद्धि

दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही जो अनुमान से काफी कम रही।[5] संवृद्धि में यह गिरावट मुख्य रूप से औद्योगिक संवृद्धि में भारी गिरावट के कारण हुई, जो पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत रह गई, जिसका कारण विनिर्माण कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन,[6] खनन गतिविधि में संकुचन और बिजली की मांग में कमी था।[7] हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी व्यापक नहीं थी, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों, लौह एवं इस्पात तथा सीमेंट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थी।[8]

आगे बढ़ते हुए, अब तक उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि घरेलू आर्थिक गतिविधि में मंदी 2024-25 की दूसरी तिमाही में समाप्त हो गई, और तब से मजबूत त्यौहारी मांग और ग्रामीण गतिविधियों में तेजी के कारण इसमें सुधार हुआ है। कृषि संवृद्धि को स्वस्थ खरीफ फसल उत्पादन[9], उच्च जलाशय स्तर[10] और बेहतर रबी बुवाई[11] से समर्थन मिल रहा है। औद्योगिक गतिविधि सामान्य होने और पिछली तिमाही के निचले स्तरों से उबरने की उम्मीद है।[12] वर्षा ऋतु के खत्म होने और सरकारी पूंजीगत व्यय में अपेक्षित वृद्धि से सीमेंट और लौह एवं इस्पात क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। मानसून संबंधी व्यवधानों के बाद खनन और बिजली क्षेत्र के भी सामान्य हो जाने की उम्मीद है। नवंबर माह के लिए विनिर्माण हेतु क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 56.5 पर अधिक बना रहा। अक्तूबर -नवंबर में आपूर्ति श्रृंखला का दबाव कम हो गया और ऐतिहासिक औसत से नीचे आ गया।[13] सेवा क्षेत्र में मजबूत गति से वृद्धि जारी है।[14] नवंबर में पीएमआई सेवाएं 58.4 पर स्थिर रहीं, जो निरंतर विस्तार का संकेत है।[15]

मांग पक्ष पर, ग्रामीण मांग[16] में वृद्धि का रुझान है, जबकि

2 पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में अमेरिका, यूके, यूरो क्षेत्र, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, चेक गणराज्य और दक्षिण कोरिया तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में चीन, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, पेरू और चिली ने अपनी नीतिगत दरों में कटौती की है। दूसरी ओर, रूस और ब्राजील ने अपनी बेंचमार्क दरें बढ़ा दी हैं। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान, इजरायल, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, पोलैंड, रोमानिया और तुर्की ने इस अवधि के दौरान दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

3 सीपीबी नीदरलैंड, वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर के अनुसार, सितंबर में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा संवृद्धि में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

4 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट आईएमएफ, अक्तूबर 2024।

5 आपूर्ति पक्ष पर, योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 5.6 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई, जिसे कृषि और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों से सहायता मिली।

6 कॉरपोरेट नतीजों में नरमी के कारण विनिर्माण जीवीए वृद्धि में कमी आई। 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान 1679 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में 0.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई।

7 जबकि खनन गतिविधि में 0.1 प्रतिशत की कमी आई, अत्यधिक वर्षा और प्रतिकूल आधार के कारण बिजली क्षेत्र में 3.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

8 जहां तेल कंपनियों को इन्वेंट्री घाटे और कम रिफाइनिंग मार्जिन के कारण नुकसान उठाना पड़ा, वहीं इस्पात (स्टील) कंपनियों को चीन से अधिक आपूर्ति और कम वैश्विक कीमतों के कारण घरेलू मूल्य दबाव का सामना करना पड़ा। सीमेंट कंपनियों को कम बिक्री कीमतों के अलावा भारी बारिश के कारण दूसरी तिमाही में कमजोर मांग का सामना करना पड़ा।

9 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 164.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 5.7 प्रतिशत अधिक है। खरीफ की एक प्रमुख फसल चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

10 28 नवंबर 2024 तक 155 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल भंडारण कुल क्षमता का 82 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 65 प्रतिशत था और दशकीय औसत 70 प्रतिशत था।

11 29 नवंबर 2024 तक रबी फसल की बुवाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक है। गेहूं और दालों की बुवाई क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत अधिक है।

12 आरबीआई के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के शुरुआती नतीजों के अनुसार, विनिर्माण फर्मों ने 2024-25 की तीसरी तिमाही में मांग की स्थिति में सुधार का आकलन किया है; तथा 2024-25 की चौथी तिमाही और 2025-26 की पहली छमाही में और सुधार की उम्मीद है। अक्तूबर में आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 3.1 प्रतिशत बढ़ा।

13 भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) अक्तूबर और नवंबर में कम हुआ और भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के बावजूद अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे रहा। स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

14 अक्तूबर 2024 में ई-वे बिल में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर के दौरान जीएसटी राजस्व में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और टोल संग्रह में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगातार दो महीनों तक संकुचन के बाद अक्तूबर में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि सकारात्मक रही। 15 नवंबर 2024 तक कुल बैंक ऋण और जमाराशि में क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

15 भारत जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 से क्रमशः विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्चतम पीएमआई रीडिंग दर्ज करना जारी रखा।

16 अक्तूबर-नवंबर 2024 में खुदरा दोपहिया वाहनों की बिक्री में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मांग अक्तूबर में 7.5 प्रतिशत घटी, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार में सुधार को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2023-24 की चौथी तिमाही के बाद से शहरी क्षेत्रों की तुलना में एफएमसीजी बिक्री में अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

शहरी मांग में उच्च आधार पर कुछ नरमी दिख रही है।[17] सरकारी उपभोग में सुधार हो रहा है।[18] निवेश गतिविधि में भी सुधार होने की उम्मीद है।[19] बाह्य मोर्चे पर, अक्टूबर 2024 में व्यापारिक निर्यात में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवा निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि (अक्टूबर में 22.3 प्रतिशत) जारी रही।[20] इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अब 6.6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें तीसरी तिमाही 6.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 7.2 प्रतिशत पर होगी। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 7.3 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फीति

सितंबर और अक्टूबर 2024 में मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई,[21] खाद्य पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ऐसा हुआ।[22] हालांकि मूल मुद्रास्फीति कम स्तर पर रही, लेकिन अक्टूबर में इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई।[23] अक्टूबर में ईंधन समूह लगातार 14वें महीने अपस्फीति में रहा।[24] निकट भविष्य में, कुछ नरमी के बावजूद, खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से तीसरी तिमाही में मूल मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है।

आगे चलकर, खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजन महत्वपूर्ण होगा। शुरुआती संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी सामग्री और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं, जो रबी की बुवाई के लिए अनुकूल है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की ऊंची कीमतों में राहत मिलेगी।[25] सब्जियों की कीमतों में भी मौसमी सर्दियों में सुधार की उम्मीद है। सकारात्मक पक्ष यह है कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी और उनकी वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों के बदलते रुख पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।[26] रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए विनिर्माण और सेवा फर्मों ने 2024-25 की चौथी तिमाही में इनपुट लागत और बिक्री मूल्यों में वृद्धि की ओर इशारा किया है।[27] इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें तीसरी तिमाही 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत पर होगी। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

---

[17] त्योहारी मांग के चलते अक्तूबर-नवंबर में खुदरा यात्री वाहनों की बिक्री में 11.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। अक्तूबर 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 9.6 प्रतिशत और नवंबर में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[18] केंद्र सरकार का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत बढ़ा और 2024 की पहली तिमाही में 1.5 प्रतिशत घटने के बाद अक्तूबर 2024 में 47.1 प्रतिशत बढ़ा।

[19] 1,689 सूचीबद्ध कंपनियों के संक्षिप्त अर्ध-वार्षिक तुलन-पत्र के अनुसार, निजी विनिर्माण कंपनियों की अचल आस्तियां मार्च 2024 के अंत तक ₹18.1 लाख करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 7.0 प्रतिशत) से बढ़कर सितंबर 2024 के अंत तक ₹18.6 लाख करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 7.8 प्रतिशत) हो गईं। आरबीआई के तिमाही आदेश बही, माल सूची और क्षमता उपयोग (ओबीआईसीयूएस) सर्वेक्षण के शुरुआती परिणामों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 74.7 प्रतिशत है, जो दीर्घकालिक औसत 73.8 प्रतिशत से अधिक है। अक्तूबर 2024 में स्टील की खपत में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सीमेंट उत्पादन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अक्तूबर 2024 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[20] अक्तूबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 3.6 प्रतिशत बढ़कर 66.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्तूबर 2024 में सेवाओं के निर्यात में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सेवाओं के आयात में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[21] सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान औसत 3.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.5 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2023 के बाद से एक वर्ष से अधिक समय में सबसे अधिक थी।

[22] सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान औसत 5.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 8.4 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 9.7 प्रतिशत हो गई। नतीजतन, खाद्य समूह (सीपीआई बास्केट में 45.9 प्रतिशत के भार के साथ) का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान जुलाई-अगस्त के दौरान लगभग 68 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर में लगभग 74 प्रतिशत हो गया। अनाज, मांस और मछली तथा फलों में बढ़ती मुद्रास्फीति के परिदृश्य में सब्जियों, तेल और वसा में मूल्य गति में तेज वृद्धि ने खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को बढ़ावा दिया। तेल और वसा में मूल्य गति तेजी से बढ़कर सितंबर में 3 प्रतिशत और अक्तूबर में 6 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही, सब्जियों में गति सितंबर में 3.5 प्रतिशत और अक्तूबर में 8.2 प्रतिशत हो गई।

[23] सीपीआई मूल मुद्रास्फीति ने मई-जून के दौरान चालू श्रृंखला में सबसे कम 3.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की, जो सितंबर में 3.5 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गई। आवास में मुद्रास्फीति जून 2024 से 2.7 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद अक्तूबर में बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गई, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति सितंबर में 9 प्रतिशत और अक्तूबर में 11 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान औसतन 8.2 प्रतिशत थी।

[24] बिजली की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति की धीमी गति के कारण सीपीआई ईंधन में अपस्फीति सितंबर में कम होकर (-)1.3 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में (-)5.3 प्रतिशत थी। अक्तूबर में, सीपीआई ईंधन में अपस्फीति की दर और बढ़कर (-)1.6 प्रतिशत हो गई, जो कि केरोसिन की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेज गिरावट को दर्शाती है।

[25] 5 नवंबर 2024 को जारी 2024-25 के लिए खरीफ उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 में चावल उत्पादन में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अरहर दाल का उत्पादन 2.5 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है।

[26] अक्तूबर 2024 में एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह आधार पर 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेल, चीनी, डेयरी और अनाज की कीमतों में वृद्धि है। वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक में सितंबर की तुलना में अक्तूबर में (माह-दर-माह आधार पर) 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मार्च 2024 के बाद कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि है।

[27] नवंबर में ही विनिर्माण कंपनियों के लिए पीएमआई ने पिछले ग्यारह वर्षों में उत्पादन कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की। साथ ही, सेवा कंपनियों ने भी करीब 12 वर्षों में उत्पादन कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है?

अक्टूबर की नीति के बाद से भारत में सन्निकट मुद्रास्फीति और संवृद्धि के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल हो गए हैं। मुद्रास्फीति पर मध्यम अवधि का पूर्वानुमान, लक्ष्य के साथ आगे संरेखण का सुझाव देता है, जबकि संवृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। लगातार उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और उपभोग और निवेश मांग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संवृद्धि के लिए इन कारकों का समग्र निहितार्थ नकारात्मक है। इसलिए, सतत संवृद्धि के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है। दूसरी ओर, संवृद्धि में मंदी - यदि यह एक सीमा से अधिक बनी रहती है - तो नीतिगत समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

रिज़र्व बैंक की मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति का रुख, उल्लेखनीय अवस्फीति लाने में महत्वपूर्ण कारक रहा है। आगे चलकर, जैसे-जैसे खाद्य कीमतों में गिरावट आएगी, हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है और यह हमारे अनुमानों के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी। वर्तमान में, मुद्रास्फीति में गिरावट की पुष्टि के लिए आने वाले आंकड़ों की प्रतीक्षा करने और उन पर नज़र रखने के लिए तटस्थ रुख द्वारा प्रदान किए गए लचीलेपन का लाभ उठाना आवश्यक है। हाल ही में हुई तेजी के बावजूद, अवस्फीति की व्यापक दिशा में अब तक प्राप्त लाभ को बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, संवृद्धि की गति और उभरती संभावना पर भी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, विवेक और व्यावहारिकता की मांग है कि हम गतिशील रूप से विकसित हो रही स्थिति और उसकी सभी जटिलताओं और परिणामों के प्रति सावधान और संवेदनशील रहें। इस प्रकार, एमपीसी की इस बैठक में मौद्रिक नीति में यथास्थिति बनाए रखना उचित और आवश्यक हो गया है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार स्थिति

प्रणालीगत चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (निवल एलएएफ) के तहत शुद्ध स्थिति द्वारा दर्शाया गया है, अधिक सरकारी व्यय[28] के कारण, त्यौहारी सीजन के दौरान प्रचलन में मुद्रा और पूंजी प्रवाह[29] में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, अक्टूबर-नवंबर[30] के दौरान अधिशेष में बनी रही। इन स्थितियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) परिचालन संचालित किया।[31] बड़े पैमाने पर जीएसटी बहिर्वाह[32] के कारण अस्थायी चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए, हालाँकि, अक्टूबर और नवंबर के दौरान सविराम परिष्कृत कार्य परिचालन परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालन का आयोजन किया गया।[33] रिज़र्व बैंक के दो-तरफ़ा चलनिधि परिचालन ने नीतिगत रेपो दर के साथ अंतर-बैंक एक-दिवसीय दर के बीच घनिष्ठ संरेखण सुनिश्चित किया।[34] ऋण बाजार में संचरण संतोषजनक रहा है।[35]

बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनी रहने के बावजूद, कर बहिर्वाह, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के कारण आने वाले महीनों में प्रणालीगत चलनिधि कम हो सकती है।

---

28 अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक के पास औसत सरकारी नकदी शेष राशि ₹2.9 लाख करोड़ से घटकर अक्तूबर-नवंबर के दौरान ₹1.65 लाख करोड़ रह गई। केंद्र सरकार ने 14-17 नवंबर 2024 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का लाभ उठाया।

29 अक्तूबर-नवंबर की अवधि के दौरान संचलन में नोटों की संख्या में ₹0.65 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

30 चलनिधि समायोजन सुविधा (निवल एलएएफ) के तहत निवल स्थिति द्वारा मापी गई प्रणालीगत चलनिधि औसतन, अक्तूबर-नवंबर के दौरान लगभग ₹1.5 लाख करोड़ के अधिशेष में थी, जबकि अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान यह ₹1.3 लाख करोड़ थी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में, प्रणालीगत चलनिधि कुछ दिनों (26-28 नवंबर) के लिए घाटे में थी। नतीजतन, अक्तूबर-नवंबर में सीमांत स्थायी सुविधा के लिए बैंकों का सहारा ₹4,794 करोड़ था, जो कि अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान ₹6,944 करोड़ की तुलना में कम था।

31 अक्तूबर-नवंबर के दौरान, पांच मुख्य और 23 फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों (1 से 4 दिन की परिपक्वता) से संचयी रूप से ₹11.7 लाख करोड़ की अधिशेष चलनिधि वापस ली गई।

32 अक्तूबर और नवंबर 2024 के लिए जीएसटी संग्रह क्रमशः ₹1.87 लाख करोड़ और ₹1.82 लाख करोड़ था, जो उच्च था।

33 25 अक्तूबर से नवंबर के अंत तक, 1-6 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले 5 फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) आयोजित किए गए, जिनसे कुल मिलाकर बैंकिंग प्रणाली में ₹1.25 लाख करोड़ आए।

34 भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) अक्तूबर-नवंबर के दौरान औसतन 6.51 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त-सितंबर के दौरान यह 6.53 प्रतिशत थी। हालांकि, संपार्श्विक खंड - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो - में दरें क्रमशः 6.38 प्रतिशत और 6.40 प्रतिशत पर बहुत सौम्य थीं। मीयादी मुद्रा बाजार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल कम हुआ। अक्तूबर-नवंबर में टी-बिल, सीडी और सीपी पर औसत प्रतिफल क्रमश: 6.46 प्रतिशत, 7.18 प्रतिशत और 7.54 प्रतिशत रहा, जबकि अगस्त-सितंबर में यह क्रमश: 6.60 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत और 7.68 प्रतिशत था। उच्च घरेलू मुद्रास्फीति प्रिंट और सख्त अमेरिकी प्रतिफल के बावजूद, 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल अक्तूबर और नवंबर में स्थिर रहा।

35 मई 2022 से 250 बीपीएस की संचयी नीति रेपो दर वृद्धि के जवाब में, एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में मई 2022 से अक्तूबर 2024 के दौरान क्रमशः 203 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान एससीबी की नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 241 बीपीएस और 193 बीपीएस की वृद्धि हुई है।

संभावित चलनिधि तनाव को कम करने के लिए, अब सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस प्रत्येक की दो बराबर किस्तों में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है। इससे सीआरआर एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत पर आ जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति सख्त करने के चक्र के शुरू होने से पहले प्रचलित था। सीआरआर में यह कटौती तटस्थ नीतिगत रुख के अनुरूप है और इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध होगी।

आगे चलकर, रिज़र्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में मुस्तैद और सक्रिय बना रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रा बाजार की ब्याज दरें व्यवस्थित तरीके से विकसित हों और अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताएं पूरी हों।

2024-25 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, भारतीय रुपये (आईएनआर) में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अक्तूबर तथा नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बिकवाली का दबाव है। फिर भी, रुपये का अवमूल्यन और इसकी अस्थिरता, दोनों ही ईएमई समकक्षों की तुलना में कम थी, जो भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और बाह्य क्षेत्र की संभावना में सुधार को दर्शाता है।[36]

रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति पिछले कई वर्षों से एक समान रही है और यह बाजार द्वारा निर्धारित है। इसका मुख्य सिद्धांत बाजार की कार्यकुशलता से समझौता किए बिना, सुव्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है। अनुचित अस्थिरता को कम करने, बाजार में विश्वास बनाए रखने, अपेक्षाओं को नियंत्रित करने और समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। ये हस्तक्षेप किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर या बैंड को लक्षित करने के बजाय अत्यधिक और विघटनकारी अस्थिरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही, विदेशी मुद्रा बाजार को गहन और आधुनिक बनाने के हमारे प्रयासों ने (i) पहुंच और सहभागिता को व्यापक बनाने; तथा (ii) कुशल मूल्य खोज सुनिश्चित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं।

हमारा समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रतिस्पर्धी और व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखते हुए आघात अवशोषक के रूप में कार्य करे, तथा अर्थव्यवस्था को बाह्य प्रभाव-विस्तार से सुरक्षित रखे। लचीली या बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था, केवल बाह्य आघातों को प्रबंधित करने का एक उपकरण नहीं है; यह समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के प्रति हमारे दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बाजार अनुशासन को विवेकपूर्ण हस्तक्षेप के साथ जोड़कर, हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो स्थिरता, समुत्थानशीलता और संवृद्धि का समर्थन करती है।

वित्तीय स्थिरता

बैंकों और एनबीएफसी के वित्तीय मापदंड मजबूत बने हुए हैं।[37] प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण और जमा की वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया है और जमाराशि की वृद्धि ऋण वृद्धि के साथ तालमेल बनाए हुए है।[38]

वित्तीय क्षेत्र और इसकी संस्थाओं पर रिज़र्व बैंक की निगरानी लगातार सतर्क और सक्रिय बनी हुई है। यदि कोई तनाव के संकेत दिखाई देते हैं, तो चाहे वह प्रणालीगत स्तर पर हो या संस्था स्तर पर, उन पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और सक्रिय कार्रवाई शुरू की जाती है। हमेशा कोशिश यही रहती है कि मुद्दों को बिना किसी व्यवधान के सुलझाया जाए। विनियमित संस्थाओं के साथ कई महीनों तक लगातार बातचीत की जाती है। केवल चरम मामलों में, जहाँ पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं

36 वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर) के आधार पर, भारतीय रुपया (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम मूल्यह्रास (-1.3 प्रतिशत) दर्ज किया गया, जबकि इसके कुछ उभरते बाजार समकक्षों जैसे वियतनामी डोंग (-2.1 प्रतिशत), फिलीपीनी पेसो (-4.2 प्रतिशत), तुर्की लीरा (-6.7 प्रतिशत), रूसी रूबल (-14.1 प्रतिशत), ब्राजीलियन रियल (-16.6 प्रतिशत), अर्जेंटीना पेसो (-15.0 प्रतिशत) और मैक्सिकन पेसो (-19.0 प्रतिशत) में उच्च मूल्यह्रास दर्ज किया गया। 2024-25 के दौरान अब तक (अप्रैल-नवंबर), भारतीय रुपया 0.4 प्रतिशत के भिन्नता गुणांक के साथ, चीनी युआन, वियतनामी डोंग, फिलीपीन पेसो, इंडोनेशियाई रुपिया, चिली पेसो और तुर्की लीरा सहित समकक्ष ईएमई मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिर था।

37 एससीबी की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में और सुधार हुआ और सितंबर 2024 के अंत तक यह 2.54 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के बाद सबसे कम है। वार्षिक गिरावट (स्लिपेज) अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए की अभिवृद्धि को मापता है, सितंबर 2024 के अंत तक 1.35 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 1.70 प्रतिशत था। बैंकिंग बही में नए तनाव के निर्माण का एक प्रमुख संकेतक, एसएमए-2 अनुपात सितंबर 2024 में 0.88 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 0.87 प्रतिशत के आंकड़े के समान था। दूसरी ओर, प्रावधान कवरेज अनुपात, पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सितंबर 2024 में क्रमशः 76.79 प्रतिशत, 16.77 प्रतिशत और 128.59 प्रतिशत थे, जो विनियामक सीमा से काफी ऊपर थे। सितंबर 2024 में कुल इक्विटी के मुकाबले निवल एनपीए का अनुपात 3.57 प्रतिशत था, जो अब तक का सबसे कम है। सितंबर 2024 में आस्तियों पर वार्षिक रिटर्न (आरओए), इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमशः 1.40 प्रतिशत, 14.58 प्रतिशत और 3.52 प्रतिशत रहा।

38 15 नवंबर 2024 तक बकाया ऋण और जमा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत थी।

दिखती, रिज़र्व बैंक उपभोक्ताओं और वित्तीय स्थिरता के हित में अंतिम उपाय के रूप में कारोबारी प्रतिबंध लगाता है।

अदावी जमाराशि, निष्क्रिय खातों और केवाईसी अद्यतन के लंबित रहने के कारण फ्रीज किए गए खातों की समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों को सूचित[39] किया गया है कि वे ऐसे खातों की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और प्रक्रिया को सरल बनाएं। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को अलग करें और ग्राहकों के ऐसे कमजोर वर्गों को असुविधा पहुँचाए बिना डीबीटी राशियों के निर्बाध ऋण और उपयोग की सुविधा प्रदान करें। इस संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी।

बाह्य क्षेत्र

अक्तूबर में भारत के व्यापारिक निर्यात में 28 महीने की सबसे अधिक वृद्धि हुई। लगातार सातवें महीने वस्तु आयात में भी वृद्धि हुई।[40] सेवाओं के निर्यात में उछाल जारी रहा और 2024-25 की दूसरी तिमाही के साथ-साथ अक्तूबर 2024 में भी दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।[41] मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत प्रेषण प्राप्तियों के कारण 2024-25 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) को टिकाऊ स्तरों के भीतर रखने की उम्मीद है। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत धन विप्रेषण प्राप्तियों[42] के कारण 2024-25 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) धारणीय स्तर पर रहने की उम्मीद है।

बाह्य वित्तपोषण के मामले में, भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वर्ष की पहली छमाही के दौरान मजबूत गति से बढ़ा। हालांकि, इस अवधि के दौरान अधिक प्रत्यावर्तन और बढ़ते हुए बाह्य एफडीआई के कारण निवल एफडीआई में कमी आई।[43] अक्टूबर 2024 में ईएमई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह में आम तौर पर गिरावट आई है।[44] भारत में निवल एफपीआई अंतर्वाह 2024-25 में अब तक (अप्रैल-दिसंबर 4) 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसे मुख्य रूप से ऋण खंड में अंतर्वाह का समर्थन मिला। दूसरी ओर, बाहरी वाणिज्यिक उधार और गैर-निवासी जमा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निवल अंतर्वाह देखा गया।[45] भारत का बाहरी क्षेत्र समुत्थानशील बना हुआ है, जैसा कि विभिन्न प्रमुख संकेतकों में परिलक्षित होता है जहां भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।[46]

अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आज से, बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के नए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को वर्तमान में 250 बीपीएस के मुकाबले एकदिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) प्लस 400 बीपीएस की अधिकतम सीमा तक दरों को बढ़ाने की अनुमति है। इसी तरह, 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए, सीमा को वर्तमान में 350 बीपीएस के मुकाबले एकदिवसीय एआरआर प्लस 500 बीपीएस तक की अधिकतम सीमा तक बढ़ा दी गई है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

[39] कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 दिसंबर 2024 को जारी बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों पर परिपत्र देखें। https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Notifications.aspx?ID=7994

[40] अक्तूबर 2024 में, भारत का व्यापारिक निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.2 प्रतिशत बढ़कर 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि व्यापारिक आयात 3.6 प्रतिशत बढ़कर 66.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2024 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 27.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[41] अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा निर्यात 2024-25 की दूसरी तिमाही और अक्तूबर 2024 के दौरान क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत बढ़ा (वर्ष-दर-वर्ष), जबकि इसी अवधि के दौरान सेवा आयात में 12.5 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा निवल सेवा निर्यात में क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[42] भारत में आने वाले धन प्रेषण में 2024-25 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में आने वाले धन प्रेषण के 2024 में 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 में बढ़कर 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है (विश्व बैंक, जून 2024)।

[43] अप्रैल-सितंबर 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 25.6 प्रतिशत बढ़कर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-सितंबर 2024-25 में निवल एफडीआई प्रवाह 8.6 प्रतिशत घटकर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक वर्ष पहले 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[44] अक्तूबर 2024 के दौरान ईएमई में निवल पोर्टफोलियो प्रवाह 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अगस्त और सितंबर 2024 में यह क्रमशः 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 56.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (स्रोत: इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस)। जबकि कर्ज खंड में अक्तूबर 2024 में 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, वहीं बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई नीति अनिश्चितता और पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन के बीच इस महीने के दौरान इक्विटी क्षेत्र से 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ।

[45] अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत निवल अंतर्वाह बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-सितंबर 2024-25 में अनिवासी जमाराशियों में 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[46] भारत का सीएडी/जीडीपी अनुपात 2023-24 में 0.7 प्रतिशत (2022-23 के दौरान 2.0 प्रतिशत) और 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान 1.1 प्रतिशत (2023-24 की पहली तिमाही में 1.0 प्रतिशत) रहा। भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात मामूली रूप से घटकर जून 2024 के अंत में 18.8 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2024 के अंत में 18.9 प्रतिशत था। 22 नवंबर 2024 तक आरक्षित निधि का आयात कवर लगभग 11 महीने का था, जबकि निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) जून 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 10.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

भारत कनेक्ट के साथ जोड़कर एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार

2019 में शुरू किए गए एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को अब एनपीसीआई के भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इससे उपयोगकर्ता, बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के मोबाइल ऐप के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर लेन-देन कर सकेंगे। इससे एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार होगा, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) की शुरूआत - सुरक्षित मुद्रा बाजारों पर आधारित एक बेंचमार्क

भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने तथा ब्याज दर बेंचमार्क की विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नया बेंचमार्क - सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) - शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जो सभी सुरक्षित मुद्रा बाजार लेनदेन – एकदिवसीय बाजार रेपो के साथ-साथ टीआरईपीएस (TREPS) पर आधारित होगा।

'Connect 2 Regulate' – निष्पक्ष विनियमन के लिए एक पहल

विनियमन तैयार करने में रिज़र्व बैंक के परामर्शी दृष्टिकोण के भाग के रूप में, आरबीआई@90 स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत 'Connect 2 Regulate' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हितधारकों को विशिष्ट विषयों पर अपने विचार और इनपुट साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर इसके लिए अलग से एक खंड उपलब्ध कराया जाएगा।

संचार के अन्य माध्यम के रूप में पॉडकास्ट सुविधा की शुरूआत

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शिता बढ़ाने और जन सामान्य से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए अपने संचार संबंधी साधनों और तकनीकों को बढ़ाया है। इस प्रयास को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक सूचना के व्यापक प्रसार के लिए अपने संचार संबंधी साधनों में 'पॉडकास्ट' जोड़ने का प्रस्ताव करता है।

संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण – सीमा में वृद्धि

संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को पिछली बार 2019 में संशोधित किया गया था। कृषि इनपुट लागत और समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता में और वृद्धि होगी।

यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था– लघु वित्त बैंकों तक दायरा बढ़ाना

यूपीआई पर ऋण व्यवस्था सितंबर 2023 में शुरू की गई थी और इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। अब छोटे वित्त बैंकों को भी यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे वित्तीय समावेशन और गहन होगा तथा औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से ऋण लेने वाले नए' ग्राहकों के लिए।

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा - एक समिति का गठन

वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जो एआई, टोकेनाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम हुआ है। एल्गोरिदम संबंधी पक्षपातपूर्णता, व्याख्यात्मकता, डेटा गोपनीयता आदि जैसे संबंधित जोखिमों को दूर करते हुए इन प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने के लिए, वित्तीय क्षेत्र में एआई (फ्री-एआई) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा की अनुशंसा करने हेतु विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

अवैध धन वाहक (म्यूल) बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई समाधान – MuleHunter.AI™

डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच), बेंगलुरु द्वारा MuleHunter.AI™ नामक एक अभिनव एआई/एमएल आधारित मॉडल, विकसित किया गया है। इससे बैंकों को अवैध धन वाहक बैंक खातों से संबंधित से तेज़ी से निपटने और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आज की दुनिया में गंभीर जटिलताएँ और गहन अनिश्चितताएँ व्याप्त हैं। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, हमारा काम स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था निरंतर उच्च संवृद्धि बनाए रखे।

पिछली नीति के बाद से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जबकि संवृद्धि में नरमी आई है। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना पर बेहतर दृश्यता की प्रतीक्षा करने के लिए विवेकपूर्ण और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, विवेक, व्यावहारिकता और निर्णयन का समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिज़र्व बैंक में हमारा प्रयास हमेशा अधिकतम प्रभाव के लिए समय पर और सावधानीपूर्वक सुविचारित उपायों को लागू करना रहा है। यह भावी सभी कार्रवाइयों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूँ: "ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धैर्य और शांत-चित मनोदशा से प्राप्त न किया जा सके"।[47]

पिछले कुछ वर्षों में, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में और शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी सबसे कठिन दौर से गुजरे हैं। यह निरंतर उथल-पुथल और आघातों का दौर रहा। एक देश के रूप में, हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने न केवल कठिनाइयों के इस दौर को सफलतापूर्वक पार किया है, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरी है। जैसा कि हम भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं, मुझे 8 फरवरी 2023 के अपने वक्तव्य की याद आती है जिसमें मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उद्धृत किया था: “भारत के भविष्य पर अपना विश्वास कभी मत खोना”।[48]

धन्यवाद, नमस्कार।

[47] महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियाँ, खंड 86.

[48] "भारत स्वतंत्र होगा" - 17 अगस्त, 1945 का पूर्वी एशिया में भारतीयों के लिए संदेश - सुभाष चंद्र बोस के चुनिंदा भाषण, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 (4-6 दिसंबर)

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, 4 से 6 दिसंबर 2024

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2024-25 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, 4 से 6 दिसंबर 2024**

मौद्रिक नीति निर्णय

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 दिसंबर 2024) की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

- एमपीसी ने मौद्रिक नीति के लिए तटस्थ रुख को जारी रखने और संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है, मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद संवृद्धि की गति बनी हुई है, हालांकि यह गति धीमी है। भू-राजनीतिक जोखिम और नीति अनिश्चितता, विशेष रूप से व्यापार नीतियों के संबंध में, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न कर रही है।

घरेलू स्तर पर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की अपेक्षा से कम संवृद्धि दर्ज की, क्योंकि निजी खपत और निवेश में गिरावट आई, जबकि सरकारी व्यय में पिछली तिमाही में संकुचन के बाद अभी सुधार हुआ। आपूर्ति पक्ष पर, दूसरी तिमाही के दौरान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में संवृद्धि को आघात-सह सेवाओं और कृषि क्षेत्र में सुधार का समर्थन मिला, लेकिन औद्योगिक गतिविधि - विनिर्माण, बिजली और खनन - में कमजोरी ने समग्र संवृद्धि को धीमा कर दिया। आगे चलकर, मजबूत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और रबी की बेहतर संभावनाओं के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षित तेजी और सेवाओं में निरंतर उछाल, निजी खपत के लिए शुभ संकेत हैं। निवेश गतिविधि में तेजी आने की उम्मीद है। विश्व व्यापार की आघात-सह संभावनाओं से बाहरी मांग और निर्यात को समर्थन मिलना चाहिए। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-आर्थिक विखंडन से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां संभावनाओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती रहेंगी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि तीसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत अनुमानित है। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत अनुमानित है (चार्ट 1)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

अक्तूबर में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सहन-सीमा के ऊपरी स्तर से ऊपर 6.2 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 5.5 प्रतिशत थी तथा जुलाई-अगस्त में यह 4.0 प्रतिशत से नीचे थी, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि तथा मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति में वृद्धि है। आगे चलकर, सब्जियों की कीमतों में मौसमी कमी और खरीफ की फसल आने के कारण चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना है; तथा मिट्टी की नमी की अच्छी स्थिति के साथ-साथ जलाशयों का भरपूर स्तर रबी उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, प्रतिकूल मौसम की घटनाएं और अंतरराष्ट्रीय कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्य मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करती है। भले ही हाल के दिनों में ऊर्जा की कीमतों में नरमी आई है, लेकिन इसके बने रहने पर नज़र रखने की ज़रूरत है। व्यवसायों को उम्मीद है कि इनपुट लागतों से दबाव उच्च बना रहेगा और चौथी तिमाही से बिक्री कीमतों की वृद्धि में तेज़ी आएगी।[1] इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि तीसरी तिमाही 5.7

* 6 दिसंबर 2024 को जारी किया जाएगा।

चार्ट 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि का तिमाही पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

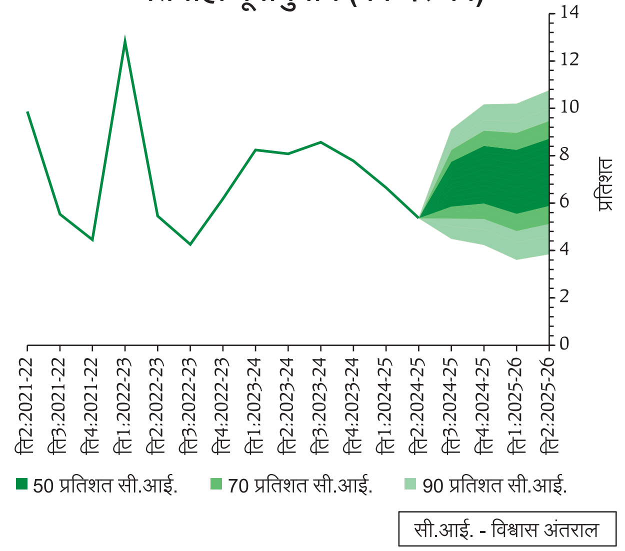

चार्ट 2: सीपीआई मुद्रास्फीति का तिमाही अनुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

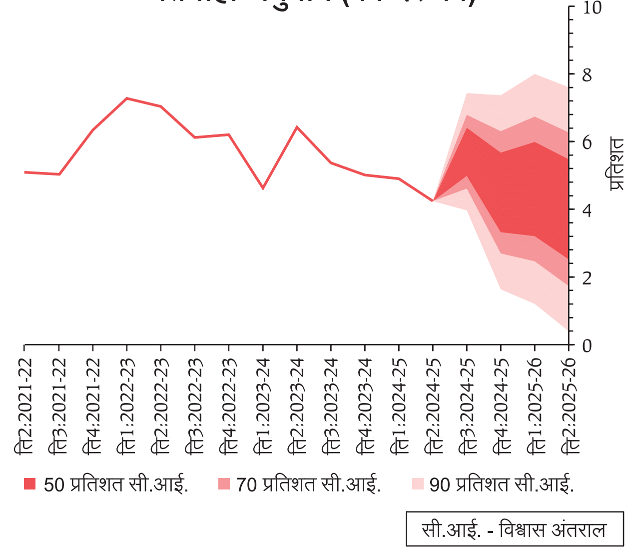

प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत अनुमानित है। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 2)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य

एमपीसी ने कहा कि अक्तूबर की नीति के बाद से भारत में सन्निकट मुद्रास्फीति और संवृद्धि के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल हो गए हैं। हालांकि, आगे चलकर, रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों में यथापरिलक्षित, कारोबार और उपभोक्ता मनोभावों में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि में सुधार होने की संभावना है। मुद्रास्फीति में हाल ही में हुई वृद्धि, मुद्रास्फीति संभावना और अपेक्षाओं के लिए कई और अतिव्यापी आघातों के निरंतर जोखिमों को उजागर करती है। बढ़ी हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता, मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करते हैं। उच्च मुद्रास्फीति, ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और निजी उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। एमपीसी इस बात पर जोर देती है कि उच्च संवृद्धि के लिए मजबूत आधार केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ ही सुरक्षित किया जा सकता है। एमपीसी अर्थव्यवस्था के समग्र हित में मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया क्योंकि इससे अवस्फीति और संवृद्धि की प्रगति और संभावना की निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने में लचीलापन मिलता है। एमपीसी संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

श्री सौगत भट्टाचार्य, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। डॉ. नागेश कुमार और प्रोफेसर राम सिंह ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक कम करने के लिए वोट किया।

डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति के लिए तटस्थ रुख को जारी रखने और संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए वोट किया।

एमपीसी की इस बैठक का कार्यवृत्त 20 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा।

एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 के दौरान निर्धारित है।

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 (4-6 दिसंबर)

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) चलनिधि और वित्तीय बाजार; (ii) विनियमन; (iii) संचार; (iv) वित्तीय समावेशन; (v) भुगतान प्रणाली; और (vi) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. चलनिधि और वित्तीय बाजार

1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात को कम करना

सभी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 25 बीपीएस की दो बराबर श्रृंखलाओं में 50 बीपीएस घटाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। इससे सीआरआर, एनडीटीएल का 4 प्रतिशत हो जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति के सख्ती चक्र की शुरुआत से पहले लागू था। सीआरआर में इस कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.16₹ लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि आएगी।

2. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें

वर्तमान में, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के लिए संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए एक-दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में 250 आधार अंक के योग की अधिकतम सीमा तथा 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के लिए एक-दिवसीय एआरआर में 350 आधार अंक के योग की अधिकतम सीमा के अधीन हैं। और अधिक पूंजी अंतर्वाह को आकर्षित करने के लिए, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आज (6 दिसंबर 2024) से बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक की परिपक्वता अवधि की नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को एआरआर प्लस 400 बीपीएस तक की दरों पर तथा 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों को एआरआर प्लस 500 बीपीएस तक की दरों पर जुटाने की अनुमति है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

3. भारत कनेक्ट के साथ संबद्धता के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार

उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विदेशी मुद्रा के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ने 2019 में एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। वर्तमान में, एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए, एनपीसीआई भारत कनेक्ट द्वारा संचालित भारत कनेक्ट (जिसे पहले भारत बिल भुगतान प्रणाली के रूप में जाना जाता था) के साथ एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को संबद्ध करने की सुविधा का प्रस्ताव है। यह संबद्धता उपयोगकर्ताओं को बैंकों (मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग आदि) और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, जो भारत कनेक्ट के साथ एकीकृत हैं, के ऐप के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और लेनदेन करने में सक्षम बनाएगा। पहले चरण में, व्यक्तियों और एकल स्वामियों द्वारा रुपये के सापेक्ष अमेरिकी डॉलर की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रयोग (पायलट) को लागू करने का प्रस्ताव है। आगे चलकर, रुपये के सापेक्ष अमेरिकी डॉलर की बिक्री और उपयोगकर्ताओं की अन्य श्रेणियों सहित अन्य एफएक्स लेनदेन को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार किया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के पास पहले की तरह एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म तक सीधे पहुंचने और मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत लेनदेन करने का विकल्प बना रहेगा। पायलट के परिचालन पहलुओं पर अनुदेश बैंकों को अलग से जारी किए जाएंगे।

4. सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) की शुरूआत - सुरक्षित मुद्रा बाजारों पर आधारित एक बेंचमार्क

रिज़र्व बैंक ने देश में रुपया ब्याज दर बेंचमार्क, विशेष रूप से मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) के उपयोग की समीक्षा करने और नए बेंचमार्क में बदलाव की आवश्यकता की जांच करने के लिए माइबोर बेंचमार्क पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री रामनाथन सुब्रमण्यन) का गठन किया था। समिति ने ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने तथा ब्याज दर बेंचमार्क की

विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जिसमें जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। रिज़र्व बैंक ने समिति की सिफारिशों के साथ-साथ प्राप्त टिप्पणियों की भी जांच की है। सिफारिशों के अनुरूप तथा वर्तमान बाजार गतिकी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित मुद्रा बाजार (बास्केट रेपो और टीआरईपी दोनों) पर आधारित एक बेंचमार्क - सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) विकसित करने का प्रस्ताव है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

II. विनियमन

5. 'Connect 2 Regulate' – निष्पक्ष विनियमन के लिए एक पहल

रिज़र्व बैंक अपने विनियमनों को तैयार करने में हितधारकों के साथ लगातार बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया का पालन करता रहा है। इसी दिशा में एक और सक्रिय कदम के रूप में, रिज़र्व बैंक ने जारी आरबीआई@90 स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत कनेक्ट-टू-रेग्युलेट (Connect 2 Regulate)' नामक एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित खंड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे हितधारकों को समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विषयों पर केस स्टडी/कॉन्सेप्ट नोट्स आदि के रूप में अपने विचार और इनपुट साझा करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम पर एक प्रेस प्रकाशनी अलग से जारी की जाएगी।

III. संचार

6. संचार के अतिरिक्त माध्यम के रूप में पॉडकास्ट सुविधा की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने निर्णयों की पारदर्शिता और उनका अत्यधिक प्रभाव सुनिश्चित करने, अपने निर्णयों के पीछे के तर्क को समझाने और व्यापक दर्शकों तक विभिन्न जागरूकता संदेशों का प्रसार करने के लिए अपने उपकरणों के एक प्रमुख हिस्से के रूप में पारंपरिक और साथ ही नए युग की संचार तकनीकों का उपयोग कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक सोशल मीडिया सहित अपनी जन जागरूकता गतिविधियों के दायरे का विस्तार कर रहा है। इस प्रयास को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक आम जनता के हित से संबंधित जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए पॉडकास्ट शुरू करने का प्रस्ताव करता है।

IV. वित्तीय समावेशन

7. संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण – सीमा में वृद्धि

वर्तमान में बैंकों द्वारा प्रति उधारकर्ता 1.6₹ लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2010 में निर्धारित 1₹ लाख की सीमा को वर्ष 2019 में बढ़ाकर 1.6₹ लाख कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1.6₹ लाख से बढ़ाकर 2₹ लाख करने का निर्णय लिया गया है। इससे औपचारिक ऋण प्रणाली में अधिक छोटे और सीमांत किसान शामिल होंगे। इस संबंध में परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

V. भुगतान प्रणाली

8. यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था – एसएफबी तक दायरा बढ़ाना

सितंबर 2023 में, पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं को एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से जोड़कर और भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निधीयन खाते के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के दायरे का विस्तार किया गया था।

यूपीआई पर ऋण व्यवस्था में 'नए-क्रेडिट-वाले' ग्राहकों को कम-टिकट, कम-अवधि के उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता है। एसएफबी अंतिम मील के ग्राहक तक पहुँचने के लिए एक उच्च तकनीक, कम लागत वाले मॉडल का उपयोग करते हैं और यूपीआई पर ऋण की पहुँच का विस्तार करने में एक सक्षम भूमिका निभा सकते हैं। अतएव, एसएफबी को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

VI. फिनटेक

9. वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा - एक समिति का गठन

अग्रणी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल), टोकनाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखती हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन कर सकती हैं, जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकती हैं, निर्णयन क्षमता को बढ़ा सकती हैं और अभूतपूर्व दक्षता ला सकती हैं। भले ही इसके कई लाभ हैं, लेकिन एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, निर्णयों की व्याख्या, डेटा गोपनीयता आदि जैसे जोखिम भी अधिक हैं। इनका लाभ उठाने लिए, स्वीकृति चक्र में प्रारंभिक रूप से जोखिमों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

इस दिशा में एक उपाय के रूप में, वित्तीय क्षेत्र में एआई (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और यह वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय एआई रूपरेखा की सिफारिश करेगी। समिति का विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

10. अवैध धन वाहक (म्यूल) बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई समाधान – MuleHunter.AI™

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में विभिन्न उपाय करता रहा है। इनमें साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और लेन-देन की निगरानी को मजबूत करने के लिए विनियमित संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश शामिल हैं। धोखाधड़ी से प्राप्त आय को चैनल करने के लिए जालसाजों द्वारा अवैध धन वाहक खातों का उपयोग एक आम पद्धति है। रिज़र्व बैंक वर्तमान में "शून्य वित्तीय धोखाधड़ी" विषय पर एक हैकथॉन चला रहा है जिसमें अवैध धन वाहक खातों पर एक विशिष्ट समस्या विवरण शामिल है, ताकि अवैध धन वाहक खातों के उपयोग को रोकने के लिए नवोन्मेषी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिशा में एक और पहल है - एआई/एमएल आधारित मॉडल, जिसे MuleHunter.AI™ कहा जाता है, जिसे रिज़र्व बैंक की सहायक संस्था रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मॉडल कुशल तरीके से अवैध धन वाहक बैंक खातों का पता लगता है। दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ किए गए प्रयोग ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। बैंकों को MuleHunter.AI™ पहल को और विकसित करने के लिए आरबीआईएच के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए अवैध धन वाहक बैंक खातों के इस्तेमाल की समस्या से निपटा जा सके।

भाषण

मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करना मौद्रिक नीति का मुख्य सिद्धांत
श्री शक्तिकान्त दास

आर्थिक शोध में नए आयाम
माइकल देवब्रत पात्र

मौद्रिक नीति संचरण
माइकल देवब्रत पात्र

प्रभावी समाधान के लिए आईबीसी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
श्री एम. राजेश्वर राव

जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करना और संवहनीय वित्त के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना
श्री एम. राजेश्वर राव

आरबीआई: 90 वर्षों की विरासत, विनियमन और आकांक्षा पर एक दृष्टि
श्री एम. राजेश्वर राव

समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना
श्री स्वामीनाथन जे

उभरते जोखिमों के मध्य पर्यवेक्षण
श्री स्वामीनाथन जे

एमएसएमई - ऋण देने में विश्वास बढ़ाकर ऋण अंतर को पाटना
श्री स्वामीनाथन जे

परिवर्तन लाने में बोर्ड की भूमिका
श्री स्वामीनाथन जे

*मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करना मौद्रिक नीति का मुख्य सिद्धांत**

- श्री शक्तिकान्त दास

'ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन' में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और यह सम्मेलन उसकी स्थापना के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। तब से रिज़र्व बैंक ने खुद को भारत में एक विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थान के रूप में स्थापित किया है। यह ऐतिहासिक आयोजन ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से वर्तमान नीति चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह आयोजन इस वर्ष हमारे द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों का भी एक हिस्सा है। इनमें तीन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शामिल हैं, और यह तीसरा है। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2024 में बेंगलुरु में आयोजित 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ' पर था। दूसरा सम्मेलन अक्टूबर 2024 के महीने में नई दिल्ली में 'केंद्रीय बैंकिंग चौराहे पर' विषय पर आयोजित किया गया था। आज के सम्मेलन का विषय विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के महत्वपूर्ण मुद्दों को समर्पित है। हमें बेहद खुशी है कि ग्लोबल साउथ और दुनिया के अन्य हिस्सों से आप सभी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं। आपकी प्रतिक्रिया और रुचि के आधार पर हम इसे एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने पर विचार कर सकते हैं, जिसके तहत हम ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकरों को एक साथ लाएंगे, जिसमें एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करने और हमारे सामने आने वाली अनिश्चितताओं को देखते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी; आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और पुनर्गठन; भू-राजनीतिक संघर्ष और युद्ध; मुद्रास्फीति में वैश्विक उछाल; व्यापार, प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह में भू-आर्थिक विखंडन; ऋण वहन करने संबंधी चुनौतियां; और जलवायु परिवर्तन के दिखाई देने वाले प्रभाव जैसे कई संकटों से गुज़री है। इसी के साथ इन संकटों ने सभी केंद्रीय बैंकों के लिए भारी चुनौतियां खड़ी की हैं जिनमें ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले हम सभी शामिल हैं।

यह सम्मेलन हमें एक-दूसरे के अनुभव से सीखने और पिछले कुछ वर्षों की अपनी-अपनी यात्राओं पर गौर करने का अवसर देता है। आज अपने संबोधन में, मैं नीति निर्माण और कार्यान्वयन के तीन चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों पर अपने विचार रखना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ के लिए उपयोगी सबक होंगे। ये क्षेत्र हैं - (i) मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करना; (ii) मौद्रिक नीति संचार; और (iii) संकट प्रबंधन। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, मैं पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करूँगा और फिर ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालूँगा।

मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करना

एफआईटी ढांचा

महामारी की शुरुआत के बाद की अवधि इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे द्वारा दी गई व्यवस्था के भीतर मूल्य स्थिरता और संवृद्धि के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। इस ढांचे का लचीलापन कानून में ही अंतर्निहित है, जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य अर्थात्, 'संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना' को परिभाषित करता है। अतः, हालांकि मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है, फिर भी कानून रिज़र्व बैंक को संवृद्धि के विषय पर भी उचित ध्यान देने का निर्देश देता है। लक्ष्य के निकट एक सहनशीलता सीमा की भी व्यवस्था दी गई है जो आपूर्ति आघातों, पूर्वानुमान त्रुटियों और माप मुद्दों को समायोजित करने के लिए है। इसके अलावा मुद्रास्फीति लक्ष्य को महीने-दर-महीने के आधार पर नहीं बल्कि औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। विफलता को लगातार तीन तिमाहियों के लिए लक्ष्य का उल्लंघन करने के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि मौद्रिक नीति दूरदर्शी स्वरूप की होती है, इसलिए इसका उद्देश्य भविष्य की मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखना होता है।

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का "हाई-लेवल पॉलिसी कॉन्फरेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम दी ग्लोबल साउथ बिल्डिंग सिनर्जीज़" मुंबई में संबोधन, 21 नवंबर, 2024।

मौद्रिक नीति में अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श कर निर्णय लेना होता है। किसी विशेष उद्देश्य - मुद्रास्फीति अथवा संवृद्धि - को कितना महत्व दिया जाना है यह अर्थव्यवस्था के संतुलित मार्ग में आने वाले जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। जब कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, तो अर्थव्यवस्था को न केवल अल्पावधि में बल्कि दीर्घावधि में भी अधिक नुकसान से बचाने के लिए समर्थन देना महत्वपूर्ण था। इसलिए हमने संवृद्धि को पुन: जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस ढांचे में निहित लचीलेपन का उपयोग किया, क्योंकि हमने पाया कि मुद्रास्फीति में उछाल अल्पावधि स्वरूप का है जो आपूर्ति आघातों के कारण है। पीछे मुड़कर देखें तो हमारा अनुमान सही था क्योंकि जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखला सामान्य हुई और महामारी कम हुई, मुद्रास्फीति में कमी आई। संयोग से, उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने महामारी से एक साल पहले ही दरों में कटौती का चक्र शुरू किया था क्योंकि आर्थिक विकास धीमा हो रहा था जबकि मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनी हुई थी।

हम महामारी के प्रभाव से उबरे भी नहीं थे कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और नीति निर्माण पर इसका भारी असर पड़ा। युद्ध के कारण प्रमुख वस्तुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में दबाव, साथ ही प्रतिकूल मौसम जैसे घरेलू कारकों ने मुद्रास्फीति को हमारे लक्ष्य की ऊपरी सीमा से परे धकेल दिया। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ी चिंता बन गई, भले ही संवृद्धि की गति मजबूत हो रही थी। हमने समय की मांग को देखते हुए समायोजन वापस लेने के रुख को बदला और उसके बाद प्रारंभ में ही दरों में बढ़ोतरी की। इसलिए, चाहे वह महामारी से प्रेरित संवृद्धि में मंदी हो या मुद्रास्फीति में युद्ध से प्रेरित उछाल, मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति और संवृद्धि, दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित उपाय किए। सबसे बड़ी प्राथमिकता मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन हासिल करना था। प्रत्येक नीतिगत उपाय का समय, विशेष रूप से जब कोई बदलाव होता है, भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इन उपायों को करते समय, हम वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों के प्रति बहुत सचेत थे। हमारी नीतियों का समग्र वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी हमारे प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा गया था - यानी संतुलन, चुनौतियों की जटिलता, जो मुझे लगता है कि दुनिया के हर केंद्रीय बैंक को, और विशेष रूप से, ग्लोबल साउथ में, ऐसे निर्णय लेते समय सामना करना पड़ता है।

पूरक नीतियों की भूमिका

2020-23 की अवधि खाद्य और तेल की कीमतों पर एक के बाद एक होने वाले कई आघातों की घटनाओं के मद्देनजर उल्लेखनीय थी, जिसने मौद्रिक नीति के संचालन को चुनौती दी। राजकोषीय नीति के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से इन आघातों के प्रभाव को बेअसर करना आवश्यक था। जबकि मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने और *डिमांड-पुल* दबावों को नियंत्रित करने पर काम किया, सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन किए जाने से आपूर्ति श्रृंखला दबावों को कम किया जा सका जिससे *कॉस्ट-पुल* मुद्रास्फीति कम हुई। इस प्रकार, प्रभावी राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय प्रतिकूल आघातों की एक श्रृंखला का सामना करने में भारत की सफलता का मूल था। इस दृष्टिकोण से, व्यापक आर्थिक स्थिरता मौद्रिक और राजकोषीय दोनों ही प्राधिकारियों की साझा जिम्मेदारी बन जाती है।

हाल के वर्षों में भारत में किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों, जैसे कि विशेष रूप से एफआईटी ढांचे की शुरुआत, राष्ट्रव्यापी माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन और दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) अधिनियमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और भारत की मध्यम और दीर्घकालिक विकास क्षमता को बढ़ाने में मदद की। समुत्थानाशील संवृद्धि ने हमें मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया है, जिससे उसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक स्थायी रूप से कम किया जा सकेगा। स्थिर मुद्रास्फीति या मूल्य स्थिरता लोगों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में है। यह टिकाऊ संवृद्धि के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है और निवेश के लिए स्थिर वातावरण प्रदान करती है।

ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक मुद्दे

(i) संवृद्धि और मूल्य स्थिरता का महत्व

ग्लोबल साउथ को संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, इन

देशों को अपनी प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए, संवृद्धि इन देशों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन यह मूल्य स्थिरता की कीमत पर नहीं हो सकती और न ही होना चाहिए। उच्च संवृद्धि हासिल करने के लिए, ग्लोबल साउथ देशों को भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का लाभ उठाने और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी के लिए ऐसी अनुकूल सार्वजनिक नीतियों की आवश्यकता है, जिनमें मौद्रिक नीति भी शामिल है, जो संवृद्धि को बढ़ावा दे और मुद्रास्फीति के साथ संतुलन बनाए रखे।

वास्तव में, आर्थिक माध्यमों को आगे की योजना बनाने, अनिश्चितता और मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम को कम करने, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य स्थिरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि संवृद्धि। ये सभी कारक अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि दर को बढ़ाने में अनुकूलता लाते हैं। इस प्रकार, दीर्घावधि के लिए मूल्य स्थिरता निरंतर उच्च संवृद्धि का समर्थन करती है। मूल्य स्थिरता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति गरीबों पर असंगत रूप से बोझ डालती है।

(ii) मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करने में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वयन - ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण क्यों?

संवृद्धि और आपूर्ति संचालित मुद्रास्फीति के बीच संतुलन के प्रबंधन का एक अन्य पहलू राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की भूमिका से संबंधित है। यह ग्लोबल साउथ देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास कम आय वाली आबादी अधिक है और जिनके लिए बड़े विकासात्मक कार्य जरूरी हैं। वे आपूर्ति आघातों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं और उन्हें राजकोषीय समर्थन की आवश्यकता है जिससे इन देशों के सीमित बजटीय संसाधनों पर और अधिक बोझ पड़ता है। इस संदर्भ में, प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक समन्वय के माध्यम से आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति के प्रबंधन में भारतीय अनुभव ग्लोबल साउथ के मेरे सभी साथी केंद्रीय बैंकरों के लिए एक सीख हो सकती है।

केंद्रीय बैंक संचार

पिछले कुछ दशकों में केंद्रीय बैंक संचार में बदलाव आया है - 1990 के दशक से पहले यह गूढ़ और अस्पष्ट था, लेकिन अब यह हाल के समय में अधिक स्पष्ट और दूरदर्शी हो गया है। यह बात अब और भी अधिक समझ में आ रही है कि मौद्रिक नीति संक्षेप में अपेक्षाओं को प्रबंधित करने की कला है और इसकी प्रभावशीलता सक्रिय और अधिक स्पष्ट संचार के माध्यम से बढ़ जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में हमने अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से संचार का उपयोग किया है। परिस्थितिनुसार जब आवश्यकता हुई, तो हमने अपनी नीतियों की अधिक प्रभावशीलता के लिए उचित अग्रगामी मार्गदर्शन के साथ दर और चलनिधि संचालन को जोड़ा। उदाहरण के लिए महामारी के दौरान हमने संवृद्धि को समर्थन देने के लिए मौद्रिक नीति के उदार रुख को जारी रखने के लिए स्थिति और समय-आधारित अग्रगामी मार्गदर्शन दोनों प्रदान किए। अप्रैल-मई 2022 में शुरू हुए सख्त चरण में, नीति दर वृद्धि के सफल प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए संचार के स्वरूप को उचित रूप से परिष्कृत किया गया। जब हमने अप्रैल 2023 में नीति दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि करने के बाद उस पर विराम लिया, तो केंद्रीय बैंक से आगे निकलने या बाजार की अपेक्षाओं के आगे बढ़ने को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण था। इसलिए, इस बात का एहसास दिलाया गया कि वह एक विराम था, न कि निर्णय। यह विराम यह सुनिश्चित करने के लिए था कि पिछली दर कार्रवाइयों को व्यापक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से प्रसारित किया जाए। मुद्रास्फीति को लक्ष्य के पास पुन: लाने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देकर मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हमने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि सहनशील सीमा के भीतर रहना पर्याप्त नहीं है और जब तक हम टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है।

संचार - यह ग्लोबल साउथ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्लोबल साउथ देशों के लिए संचार अधिक महत्वपूर्ण है और उनके लिए उसमें नए आयाम हैं। ग्लोबल नॉर्थ देशों के संबंध में यह पारंपरिक नीति सीमा की समाप्ति से अधिक जुड़ी है जब वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद वे नीति की निचली सीमा तक पहुँच गए। इसने जनता की अपेक्षाओं को निर्देशित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में अग्रगामी मार्गदर्शन को अपनाने का नेतृत्व किया। ग्लोबल साउथ देशों के लिए केंद्रीय

बैंक संचार पर ध्यान केंद्रित करना एक हालिया घटना है और यह उनके व्यापक आर्थिक, सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत और विकासात्मक चरणों के अनुरूप विभिन्न कारकों से जुड़ा हुआ है। इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा।

सबसे पहले, ग्लोबल साउथ अर्थव्यवस्थाओं के अधिक स्वतंत्र केंद्रीय बैंकों की स्थापना की ओर बढ़ने और जनता के प्रति लोकतांत्रिक जवाबदेही के हित में पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ संचार की भूमिका बढ़ गई है। सदी की शुरुआत से ही हममें से कुछ लोगों द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने से नीति व्यवस्था में बदलाव, संस्थागत पर्यावरण चुनौतियों और साथ ही अपेक्षाओं को निर्देशित करने के लिए प्रभावी और पारदर्शी संचार की आवश्यकता बढ़ गई।

दूसरा, जैसे-जैसे इन उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने परिचालन के क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हें नीतिगत निर्णयों को पर्याप्त रूप से समझाने के लिए संचार की आवश्यकता का एहसास हुआ, विशेष रूप से संवृद्धि और स्थिरता के बहु उद्देश्यों के संदर्भ में। इसके अलावा, जीएफसी और महामारी के बाद की अवधि में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति में ढील ने पूंजी प्रवाह, विनिमय दरों और कमोडिटी की कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव के साथ ग्लोबल साउथ के जोखिम को बढ़ा दिया। इससे निरंतर चल रही अस्थिरता के बीच नीति संतुलन को समझाने के लिए केंद्रीय बैंकों के कार्यों को और जटिल बना दिया।

तीसरा, यह मान्यता बढ़ रही है कि प्रभावी संचार बड़े या लगातार नीतिगत बदलावों, या यहां तक कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, अगर मुद्रास्फीति की उम्मीदों को उचित संचार के माध्यम से अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। बेशक, संचार समय-समय पर आवश्यक वास्तविक कार्रवाई द्वारा समर्थित होना चाहिए।

कुल मिलाकर, नीति के संचलन, रुख और लक्ष्यों के साथ तालमेल में प्रभावी संचार वृहद आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान देगा। मौद्रिक नीति के इस महत्वपूर्ण पहलू में एक-दूसरे के अनुभव से सीखना और तालमेल बनाना 'ग्लोबल साउथ के लिए संचार में सर्वोत्तम प्रथाओं' के लिए खाका तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है।

संकट प्रबंधन दृष्टिकोण

मैंने संकटग्रस्त वर्षों में हमारी संघर्षमय यात्रा पर संक्षेप में चर्चा की है। अब मैं संक्षेप में बताता हूँ कि केंद्रीय बैंकों के बीच रिज़र्व बैंक का अनुभव किस तरह अनूठा रहा है। जब कोविड-19 महामारी आई, हमने नीतिगत रेपो दर में कमी की लेकिन वह 4 प्रतिशत के अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम नहीं थी अन्यथा वास्तविक नीतिगत दरें नकारात्मक हो जातीं। संक्षेप में यह कि हमने दरों को अत्यधिक कम भी नहीं किया। हमने कोविड-19 से संबंधित स्थान बाधाओं और लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न चलनिधि बाधाओं को दूर करने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए। इन उपायों का उद्देश्य केवल प्रणाली में समग्र चलनिधि को बढ़ाना नहीं था, बल्कि जरूरतमंद क्षेत्रों में इसका वितरण सुनिश्चित करना भी था। इसके अलावा ये उपाय सीमित स्वरूप के थे। वास्तव में, उनमें से अधिकांश उपाय समयबद्ध थे और पूर्व-निर्धारित अंतिम तिथियों के साथ घोषित किए गए थे। परिणामस्वरूप, उनके समाप्त होने से बाजार में व्यवधान नहीं हुआ। इसके अलावा, हमारे चलनिधि कार्य में शामिल प्रतिपक्ष केवल बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) थे, जो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित थे और संपार्श्विक मानकों में कोई कमी नहीं की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का तुलनपत्र कमजोर नहीं हुआ और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि महामारी की शुरुआत के लगभग तीन साल के भीतर, रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का आकार फिर से उसी स्तर पर आ गया, जहां वह महामारी की शुरुआत में था। दूसरे शब्दों में, महामारी के दौरान उपलब्ध कराई गई चलनिधि को इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि चलनिधि उपाय असीमित स्वरूप के नहीं थे। उनकी घोषणा के समय उनकी समाप्ति तिथियों की घोषणा की गई थी। वास्तव में, अगर आपको याद हो, तो कोविड-19 महामारी ने मार्च 2020 में दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया था। वास्तव में हमने फरवरी 2020 के महीने में महामारी से पहले ही कुछ चलनिधि डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जनवरी 2021 में, हमने फरवरी 2020 के संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के संदर्भ में प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को कम करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों को धीरे-धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया।

अगर आपको याद हो, आज अपने संबोधन में मैंने निर्णयों के समय के महत्व के बारे में बताया था। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि न केवल निर्णय सही होने चाहिए बल्कि निर्णय सही समय पर होने चाहिए क्योंकि, जैसा कि मैंने हाल ही में कहीं और बताया है, अक्सर केंद्रीय बैंकों पर 'बहुत कम और बहुत देरी से' या 'बहुत जल्दी बहुत अधिक' करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए, समय हर निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सही समय पर लिया गया निर्णय इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। केंद्रीय बैंकरों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें सही आकलन करना चाहिए या कम से कम वर्तमान स्थिति और अपेक्षित स्थिति या दृष्टिकोण का सही आकलन करने का प्रयास करना चाहिए और अपने निर्णयों को उचित समय पर लेना चाहिए।

हमने अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम को सरकारी प्रतिभूतियों और केवल द्वितीयक बाजार के माध्यम तक सीमित रखा, जबकि मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले कुछ ईएमई केंद्रीय बैंकों ने सरकार को सीधे वित्तपोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार में परिचालन के लिए आपातकालीन प्रावधान किए। यह राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से बचने के लिए रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा एक सुविचारित और विवेकपूर्ण निर्णय था। पूर्व की प्रथा को रिज़र्व बैंक ने 1990 के दशक के अंत में बंद कर दिया था। इसी प्रकार बैंकों और गैर-बैंक ऋणदाताओं की कोविड-19 से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान उपाय असीमित स्वरूप के नहीं थे, बल्कि ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूर्ति किए जाने वाले कुछ वित्तीय और परिचालन मापदंडों के अधीन थे।

इस बात पर गौर किया जा सकता है कि महामारी के समय के हमारे अधिकांश उपाय भविष्य में उत्पन्न होने वाली कीमत और वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुविचारित थे। जिस तरह हमने घोषित किए गए चलनिधि उपायों को असीमित स्वरूप में नहीं रखा था, उसी तरह, दबावग्रस्त ऋणों के लिए समाधान रूपरेखाओं के संबंध में हमने कुछ परिचालनगत और वित्तीय मापदंड निर्धारित किए थे ताकि समाधान विवेकपूर्ण और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

यूक्रेन युद्ध के बाद के सख्त चक्र के दौरान हमारी भूमिका कई अन्य केंद्रीय बैंकों से भिन्न थी। सबसे पहले यह कि हमारी दर वृद्धि की मात्रा कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की तुलना में अधिक नहीं थी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 75 बीपीएस नया सामान्य हो गया था, क्योंकि उनके पास काफी समय से नकारात्मक या लगभग नकारात्मक ब्याज दरें थीं। दूसरा, मौद्रिक नीति के रुख को बदलते समय हमारी स्थिति एई की तरह तनाव में नहीं थी। हमारा संचार सुविचारित था और मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए केंद्रीय बैंकों की स्पष्ट प्रतिबद्धता पर बाजार का विश्वास बनाने पर केंद्रित था। तीसरा, हमने तत्समय चल रहे चक्र में टर्मिनल दर पर कोई भी अग्रिम मार्गदर्शन देने से परहेज किया, क्योंकि कि इस तरह का मार्गदर्शन अनिश्चित वातावरण में स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा था। चौथा, नीति दर पर विराम लगाते हुए भी, हमने मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन हासिल करने तक प्रतिबंधात्मक रुख जारी रखा।

संक्षेप में, महामारी और मुद्रास्फीति में उछाल दोनों स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया को निर्धारित करने में हम पारंपरिक सिद्धांत या किसी भी तरह की हठधर्मिता से बंधे नहीं थे। हम अपने कार्यों और नीतियों में चुस्त और लचीले थे। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा है "अच्छी नीति .... अर्थशास्त्री के विज्ञान को व्यवसायी की कला के साथ जोड़ने की आवश्यकता है"।[1] इस अर्थ में, हमारे कार्यों के माध्यम से हम शायद उस कहावत पर खरे उतरे हैं जिसका आशय है - "मौद्रिक नीति विज्ञान है लेकिन मौद्रिक नीति बनाना एक कला है।" हालाँकि, इसका फैसला दूसरों को करना है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहें तो पिछले कुछ वर्षों के अत्यधिक अस्थिर वातावरण में वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल रही है, लेकिन अनिश्चितताओं के बादल अभी भी क्षितिज पर मंडरा रहे हैं। अत्यधिक अनिश्चितता के इस माहौल में नीति निर्माण करना धुंधले रास्ते पर वाहन चलाने जैसा है, जिसमें गतिरोधक बाधाएँ भी हैं। ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो चालक के धैर्य और कौशल की परीक्षा लेंगी। ऐतिहासिक नियमितताएँ असंभव लग रही हैं, और नीति निर्माताओं की परीक्षा हो रही है। जब हमारे

[1] सी. ई. वाल्श (2001): दी सायंस (एंड आर्ट) ऑफ मोनिटरी पॉलिसी, फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ सैन फ्रांसिस्को (एफआरबीएसएफ) इकॉनॉमिक लेटर, 4 मई 2001।

समय का इतिहास लिखा जाएगा, तो पिछले कुछ वर्षों के अनुभव और सीख, सभी संभावनाओं के साथ, केंद्रीय बैंकिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे।

ग्लोबल साउथ देशों के लिए समग्र स्थिरता बनाए रखना, जिसमें टिकाऊ संवृद्धि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता शामिल है, एक कठिन चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय बैंकों को अधिक मजबूत, यथार्थवादी और सक्रिय नीति ढाँचे की दिशा में काम करने की आवश्यकता है जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए मौद्रिक, विवेकपूर्ण, राजकोषीय और संरचनात्मक नीतियों में तालमेल स्थापित करे। मुझे विश्वास है कि आज और कल का यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ के लिए भविष्य की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण विचार और निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद। नमस्कार!

आर्थिक शोध में नए आयाम*

- माइकल देवब्रत पात्र

गवर्नर श्री अहमद मुनव्वर, मालदीव मॉनिटरी ऍथोरिटी (एमएमए), डॉ. महमूद शौगी, मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, श्री अहमद इमाद, एमएमए के उप-गवर्नर, एमएमए के अन्य वरिष्ठ सहयोगी, प्रतिष्ठित प्रस्तुतकर्ता और पैनलिस्ट तथा प्रतिभागी, देवियो और सज्जनो, आप सभी को नमस्कार।

एमएमए के इस दो दिवसीय वार्षिक शोध सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस सम्मेलन का विषय 'आर्थिक शोध को आगे बढ़ाना: एक टिकाऊ भविष्य के लिए नीति और नवाचार' है जो बहुत ही उपयुक्त है। सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले शोध-पत्रों की प्रभावशाली श्रृंखला इस सामयिक विषय पर प्रकाश डालेगी। आज अपने संबोधन में मैं आर्थिक शोध में कुछ नए आयामों और वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण के लिए उनकी प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसमें ग्लोबल साउथ का भी उल्लेख होगा।

आर्थिक जिज्ञासा को निरंतर खोज में अन्वेषण की भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उस अदृश्य हाथों को समझने की कोशिश करता है जो आजीविका को बदलता है, समाज को आकार देता है और मानवता की आकांक्षाओं को परिभाषित करता है। इस अर्थ में, जैसा कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को प्रसिद्ध रूप से परिभाषित किया है, अर्थशास्त्री हमेशा अपने पेशे में स्थिर संतुलन स्थापित करने और इंपोसिबल त्रिनिटी के मानचित्रकार रहे हैं, जो जीवन के साधारण गतिविधियों में मानव जाति का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्रियों का जीवन इस तथ्य को लेकर जटिल है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हमेशा बदलती रहती है, और आर्थिक संरचनाओं, सूचना भंडार और प्रवाह, और उपलब्ध साधनों को नया रूप देती रहती है। आज, हम समय के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जिसे प्रौद्योगिकी और नवाचार की असीम संभावनाओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और विभूमंडलीकरण के जोखिमों द्वारा भी पुन: परिभाषित किया जा रहा है। इसलिए, जैसा कि ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा था, अर्थशास्त्र पेशे के संबंध में "परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है।"

हमारे शोध को न केवल आज के टेक्टोनिक बदलावों के अनुकूल होना चाहिए, बल्कि पार की जाने वाली कल की नई सीमाओं के अनुकूल भी होना है। इस पृष्ठभूमि में तथा समय के हित में, मैं अनुसंधान के चार उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो, मेरा मानना है, मानव व्यवहार और आर्थिक अनुसंधान को पुनः परिभाषित करेंगे।

I. आर्थिक ढांचे में प्रौद्योगिकी के आघातों को पुन: परिभाषित करना

डिजिटलीकरण का तेजी से प्रसार परिवर्तनकारी रहा है, जिसने हमारे जीने और काम करने के तरीके, आर्थिक माध्यमों, उत्पादन प्रक्रियाओं और बाजार संरचनाओं के बीच के अंतर-संबंधों को नया रूप दिया है। डिजिटलीकरण को आर्थिक विकास, उत्पादकता, श्रम बाजार, पुरानी प्रौद्योगिकी और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाला एक दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी आघात माना जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का पहले से ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत से अधिक योगदान है।[1] अकेले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेन-एआई) से अगले तीन वर्षों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7-10 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है।[2] इन बदलते विकासक्रमों को पढ़कर अंतर्निहित संबंधों और निहितार्थों को जानने और उनका आकलन करने में सक्षम होने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धतियों को विकसित करना आवश्यक है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों में दक्षता बढ़ा कर उत्पादकता को बढ़ाने की क्षमता है, इसके बावजूद, संवृद्धि लगातार उम्मीदों से कम रही है। इससे धीमे नवाचार प्रसार के विरोधाभासी परिदृश्य उत्पन्न हुए हैं।[3] हाल के अध्ययनों ने इस बहस को और गहरा कर

* 14 दिसंबर 2024 को मालदीव के माले में मालदीव मॉनिटरी ऍथोरिटी (एमएमए) अनुसंधान सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्रा द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। पल्लवी चव्हाण, बिनोद बी भोई, हरेंद्र बेहरा, सौमश्री तिवारी, रंजीता मिश्रा, साक्षी अवस्थी, कौस्तव सरकार, पूर्णा बनर्जी, निशा मिश्रा, संदीप कौर से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियाँ और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

1 संयुक्त राष्ट्र। (2023)। ओपनिंग सेशन ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट इनीशिएटिव डिजिटल कॉ-ऑपरेशन फोरम का उद्घाटन सत्र।

2 जेपी मॉर्गन। (2024)। *इस जनरेटिव एआई ए गेम चेंजर?*

3 ब्रिनजॉल्फसन, ई., और मैकफी, ए. (2014)। दी सेकंड मशीन एज: वर्क, प्रोग्रेस, एंड प्रोसपेरिटी इन ए टाइम ऑफ ब्रिलियंट टेक्नॉलोजीज़। डब्ल्यूडब्ल्यू नॉर्टन एंड कंपनी; हाल्डेन, ए. (2017)। प्रोडक्टिविटी पज़ल्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भाषण; समर्स, एल. एच. (2013)। स्टेनली फिशर के सम्मान में आईएमएफ के 14वें वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन में भाषण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 8।

दिया है, जिसमें उत्पादकता और आर्थिक विकास पर एआई के प्रभाव के बारे में अनिश्चितता को उजागर किया गया है।[4] हो सकता है उत्पादकता संबंधी यह पहेली संवृद्धि विघटन ढांचे में शोध की कमी के साथ-साथ क्षेत्रवार उत्पादकता में बदलाव और क्षेत्रों और आय समूहों में प्रौद्योगिकी आघातों के वितरण संबंधी प्रभावों को समझाने में प्राप्त ज्ञान की कमी की ओर इशारा करती हो।

डिजिटलीकरण का रोजगार पर दीर्घकालिक प्रभाव अब तक सौम्य प्रतीत होता है, लेकिन श्रम बाजारों पर इसके विघटनकारी प्रभावों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है।[5] जनसंख्या की उम्र बढ़ने से डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अधिक तेजी आ सकती है। एआई के कारण वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत नौकरियाँ प्रभावित होंगी, इसलिए शिक्षा, पुनः प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा तंत्र महत्वपूर्ण होंगे।[6] केंद्रीय बैंकों के भीतर भी फिनटेक विशेषज्ञों की भर्ती और उन्हें बनाए रखना बड़ी चुनौती बन रही है, जिनमें से 64 प्रतिशत भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 68 प्रतिशत उन्हें बनाए रखने संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।[7] डिजिटलीकरण द्वारा संचालित श्रम पुनर्वितरण, अनुरूप रोजगार दक्षता, डेटा विज्ञान जैसे रोजगार सृजन के नए आयाम और दूरस्थ-अनुकूल नौकरियों के माध्यम से महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाने में डिजिटलीकरण की भूमिका की जाँच करने के लिए अनुसंधान के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।

मौद्रिक नीति से संबंधित आर्थिक चरों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव, विशेष रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतों के बीच अंतर के कारण मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी की आवश्यकता है। इससे फिलिप्स वक्र भी प्रभावित हो सकता है और इसलिए पारंपरिक मुद्रास्फीति ढांचों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।[8] अनुसंधान के संदर्भ में यह पता लगाया जा रहा है कि डिजिटल भुगतान, फिनटेक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (सीबीडीसी) और एआई जैसे वित्तीय नवाचार मौद्रिक नीति संचरण को कैसे नया रूप दे सकते हैं और वित्तीय स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वेब-स्क्रैपिंग, टेक्स्ट माइनिंग, लार्ज लैंग्वेज तकनीक और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क (जैसे, ट्री-बेस्ड मॉडल और न्यूरल नेटवर्क)[9] जैसे गतिशील तरीके और बिग डेटा एनालिटिक्स समष्टि-वित्तीय विश्लेषण और मौद्रिक नीति तकनीक के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

II. जलवायु परिवर्तन और समष्टि आर्थिक स्थिरता

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर अत्यंत बड़े पैमाने में और तेज गति से आकार ले रहा है। इससे खाद्य और ऊर्जा की कमी जैसे आपूर्ति आघात हो रहे हैं और उत्पादन क्षमता में गिरावट आ रही है जिससे संवृद्धि और मूल्य स्थिरता प्रभावित हो रही है। बार-बार होने वाले जलवायु संबंधी आघातों से मुद्रास्फीति में अस्थिरता आ रही है, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदें प्रभावित हो रही हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्योगों और परिवारों की संपत्ति को होने वाले नुकसान के कारण भी मांग प्रभावित होती है, जिसके साथ वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम भी जुड़े होते हैं। भौतिक और संक्रमण जोखिम वित्तीय संस्थानों और बैंकों के तुलनपत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह सीमित हो सकता है। वास्तव में, संक्रमण जोखिम कई प्रकार के माध्यमों से संचालित हो सकते हैं, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण, बाजार, चलनिधि, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों सहित सभी श्रेणियों में पारंपरिक जोखिम बढ़ सकते हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण जैसी शमन और हरित संक्रमण नीतियाँ भी मूल्य स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से सापेक्ष कीमतों में बड़े और दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति प्रवृत्ति में बदलाव हो सकते हैं। जलवायु आपदाओं से अक्सर प्रभावित होने वाले देशों की मुद्राओं पर मूल्यह्रास दबाव भी वित्तीय अस्थिरता, उच्च आयात लागत और व्यापार की नकारात्मक शर्तों का कारण बन सकता है।

जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए उप लब्ध नीति विकल्पों की श्रेणी के लिए उच्च स्तर के शोध की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन जटिल, असमान तरीकों के संदर्भ में जिनमें जलवायु, वास्तविक अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और बाजार

4 गोल्डमैन सैक्स। (2024)। जन. एआई: टू मच स्पेंड, टू लिटल बेनिफिट रिपोर्ट।

5 ईसीबी। (2021)। डिजिटलीकरण: यूरो क्षेत्र में मौद्रिक नीति के लिए चैनल, प्रभाव और निहितार्थ।

6 *आईएमएफ। (2024)। जन-एआई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट।*

7 सर्वेक्षण में 33 बैंकों ने भाग लिया। स्रोत: सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट। (2024)। फिनटेक बेंचमार्क 2024 – दी प्रोमिस एंड थ्रेट ऑफ एआई।

8 एरी, एम. ए., गार्सिया-मैकिया, एम. डी., और मिश्रा, एस. (2023)। हैज दी फिलिप्स कर्व बिकम स्टीपर? आईएमएफ, डब्ल्यूपी/23/100.

9 ट्री-बेस्ड विधियाँ लचीली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैं जो कई तरह के कार्यों को संभाल सकती हैं। डिसीजन ट्रीज़, रुचि की विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार डेटा को क्रमिक रूप से महीन श्रेणियों में विभाजित करके व्यक्तिगत डेटा बिंदुओं को समूहीकृत करते हैं। न्यूरल नेटवर्क के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक कृत्रिम न्यूरॉन्स हैं, जो कई इनपुट स्वीकार करते हैं और उन्हें एक गैर-रैखिक तरीके से एकल संख्या आउटपुट करने के लिए रूपांतरित करते हैं - जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। स्रोत: बीआईएस. (2024)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेंट्रल बैंकिंग।

एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। कारणों और प्रतिक्रियाओं की दिशाओं को समझने के लिए बेहतर अंतःविषय मैक्रोइकॉनोमिक मॉडलिंग महत्वपूर्ण होती जा रही है।

III. वैश्वीकरण और ब्याज की प्राकृतिक दर

मौद्रिक नीति का निर्माण अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप विकसित हुआ है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी), जो सबसे लंबे समय तक चला आ रहा आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा है, भी कोई अपवाद नहीं है। इसका श्रेय ढांचे में निर्मित 'नियम-आधारित' सिद्धांत और साथ ही प्रचलन के साथ विकसित हुए "लचीलेपन" के तत्वों को दिया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि "वैज्ञानिक सिद्धांतों" के मूल समुच्चय के अनुप्रयोग ने प्रचलन में आकर काफी विस्तारित रूप धारण कर लिया है, लेकिन मौद्रिक नीति के संचालन में कला का तत्व बना हुआ है और संभवतः हमेशा बना रहेगा।[10]

नीति दरों को निर्धारित करने में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले एक सिद्धांत में ब्याज की प्राकृतिक दर शामिल है - जिसे अधिकतर आर-स्टार के रूप में जाना जाता है। यह मौद्रिक नीति के लिए एक सैद्धांतिक बेंचमार्क है, जो वास्तविक ब्याज दर को दर्शाता है और जो मुद्रास्फीति को कम और स्थिर रखते हुए अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार पर समर्थन देता है। आर-स्टार या प्राकृतिक दर की यह अवधारणा 1898[11] से चली आ रही है और वर्तमान में आधुनिक मैक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क का एक अभिन्न तत्व है। मौलिक कार्य में यह तर्क दिया जाता है कि "एक केंद्रीय बैंक को वास्तविक आर्थिक स्थितियों और अर्थव्यवस्था की उत्पादन और रोजगार क्षमता (क्रमशः वाई-स्टार और यू-स्टार) के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही वास्तविक ब्याज दर और प्राकृतिक दर (आर-स्टार) के बीच के अंतर को भी पाटना चाहिए, ताकि एक इष्टतम परिणाम प्राप्त किया जा सके।"[12] समस्या यह है कि आर-स्टार या उस सूत्रीकरण में कोई भी अन्य स्टार मूल रूप से अप्राप्य है। आर-स्टार[13] के मूल्य का अनुमान लगाने के औपचारिक प्रयासों को अनुमान दृष्टिकोणों के साथ-साथ संरचनात्मक परिवर्तनों और देश-विशिष्ट विशेषताओं के लिए लेखांकन के संदर्भ में वर्षों से परिष्कृत किया गया है।

यह सामान्य रूप से माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से आर-स्टार में गिरावट आई है, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जिसका कारण है आबादी की बढ़ती आयु, उत्पादकता वृद्धि में कमी और अत्यधिक वैश्विक बचत जैसे कारक। हालाँकि, हाल ही में, यह दृष्टिकोण जोर पकड़ रहा है कि महामारी के बाद की घटनाओं ने - विशेष रूप से निरंतर होने वाले आघातों ने इनमें से कुछ रुझानों को उलट दिया है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क फेड द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए आर-स्टार के वास्तविक समय माप में यह देखा गया है[14]। महामारी के बाद बनी यह विपरीत स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति से इस हालिया बदलाव के पीछे के कारणों की बेहतर समझ अनिश्चित भविष्य में मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए उपयोगी होगी।

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ आर-स्टार के सटीक आकलन को जटिल बनाती हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ श्रम बाजार की गतिशीलता, जड़ सेवा मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीति की अनिश्चितताओं के बीच सुस्त संवृद्धि का सामना करती हैं, और ये सभी कारक आर-स्टार के बढ़ने में योगदान देते हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ मजबूत आर्थिक गतिविधि और निवेश के साथ-साथ उत्पादकता में अंतर के कारण अपने आर-स्टार पर ऊपर की ओर दबाव का अनुभव कर सकती हैं। हालाँकि, उन्हें भू-आर्थिक विखंडन और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और वित्तीय बाजार की अस्थिरता से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इस बात का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये वैश्विक कारक आर-स्टार में बदलाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में मौद्रिक नीति प्रभावी बनी रहे।

IV. उपभोग का स्वरूप और उनका आर्थिक प्रभाव

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में तेजी से हो रही प्रगति पूंजी के संचलन के 'स्पेस टाइम फ्लो' को छोटा करने

[10] मिशकिन, फ्रेडरिक एस. (2007)। विल मॉनिटरी पॉलिसी बिकम मोर ऑफ ए साइंस? एनबीईआर वर्किंग पेपर 13566, अक्टूबर।

[11] विक्सेल, के. (1936)। ब्याज और कीमतें। लुडविग वॉन मिज़ इंस्टीट्यूट।

[12] वुडफ़ोर्ड, एम. (2003)। ब्याज और कीमतें: मौद्रिक नीति के सिद्धांत की नींव, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[13] लॉबैक, टी. और विलियम्स, जॉन सी. (2003)। ब्याज की प्राकृतिक दर को मापना। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की समीक्षा, नवंबर, खंड 85, संख्या 4, पृष्ठ 1063-1070।

[14] https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar

में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है जिससे इसकी गति और आकार में वृद्धि हो रही है।[15] डिजिटल वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म और साधनों का बढ़ता उपयोग भी कई तरह से परिवारों के व्यवहार को नए-नए प्रकारों से आकार दे रहा है।

सबसे पहले, डिजिटल उत्पादों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रसार के साथ व्यक्तिगत खरीदारी से ऑनलाइन खरीदारी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कई देशों में खुदरा बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑनलाइन बिक्री का है। महामारी ने ऑनलाइन खरीदारी को एक विशिष्ट स्थिति में बढ़ावा दिया, किंतु महामारी के बाद की अवधि में भी उसके बढ़ने की गति बनी रही। 2023 में दुनिया भर में ई-कॉमर्स खुदरा बिक्री का 19 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 2027 तक ऑनलाइन सेगमेंट कुल वैश्विक खुदरा बिक्री का लगभग एक चौथाई हिस्सा बन जाएगा।[16] वैश्विक वार्षिक खुदरा ई-कॉमर्स बिक्री वृद्धि जो 2022 में 6 प्रतिशत थी, 2024 में 9 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है।[17] ई-कॉमर्स के इस उदय ने डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में भी बदलाव किया है।[18] उदाहरण के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं की वैश्विक संख्या जो 2017 में 0.6 बिलियन थी, से बढ़कर 2024 में 1.4 बिलियन हो गई है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डिजिटल समाचार सेवाओं के संबंध में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई है।[19]

दूसरा, डिजिटल उपभोग के प्रसार के साथ-साथ ऑनलाइन ब्रोकरेज खाते, रोबो-एडवाइजर, निवेश ऐप और इसी तरह के बचत और निवेश निर्णयों में भी बदलाव आया है, क्योंकि वे आसान, तेज़ और अधिक सूचित हैं। डिजिटलीकरण ने परिवारों के उधार लेने के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। डिजिटल ऋण के लिए फिनटेक कंपनियों तक अधिक और आसान पहुंच बनी है, और टैक्स रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह और बिल भुगतान सहित कई स्रोतों के माध्यम से सूचना विषमताएं कम हुई हैं।[20]

साथ ही, ये नई प्रौद्योगिकियां मौद्रिक और विनियामक नीति निर्माण के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। पहली चुनौती यह कि बचत के पारंपरिक तरीकों से होने वाला बदलाव वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति आवेगों के संचरण को प्रभावित कर सकता है।[21] दूसरी, केंद्रीय बैंकों को परिवार स्तर पर ऋण वृद्धि और जोखिम निर्माण की संभावनाओं के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है।[22]

तीसरी चुनौती यह कि इस बात के सबूत हैं कि 'अभी खरीदें-बाद में भुगतान करें' और क्रेडिट कार्ड-आधारित खर्च तत्काल उपभोग को सुगम बनाते हैं, खासकर युवा पीढ़ियों के लिए, जो उनकी बचत को कम कर सकते हैं।[23] चौथी यह कि अपर्याप्त डिजिटल वित्तीय साक्षरता के कारण परिवारों के मामले में वित्तीय सेवाओं की गलत बिक्री संबंधी चिंता उभर सकती है।[24]

उपभोक्ता व्यवहार में इन बदलावों को देखते हुए केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को पारंपरिक मैक्रोइकॉनोमिक मॉडल को छोड़कर एजेंट-आधारित मॉडलिंग, व्यवहार अर्थशास्त्र के एकीकरण, नाउकास्टिंग, नीति सिमुलेशन और उन्नत चलनिधि तनाव परीक्षणों की बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त रियल टाइम, उच्च-आवृत्ति डेटा की जांच करने के लिए मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे अत्याधुनिक कम्प्यूटेशनल टूल से खुद को लैस करने की भी आवश्यकता है।

V. निष्कर्ष

जब हम आर्थिक शोध के नए क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे जॉन मेनार्ड कीन्स के शब्द याद आ रहे हैं: *"कठिनाई*

[15] डिजिटल वित्तीय प्रणाली कम अवधि में अधिक और बड़े लेनदेन को पूरा करने की अनुमति देती है। पराना, एडेमिलसना। 2018. डिजिटल वित्त: वित्तीय पूंजीवाद और सूचनात्मक क्रांति। लीडेन और बोस्टन: ब्रिला.

[16] ई-मार्केटर; स्टेटिस्टा।

[17] ई-मार्केटर; स्टेटिस्टा।

[18] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। 2020। वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक: ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एस्केंट। अक्टूबर 2020।

[19] स्टेटिस्टा मार्केट इनसाइट्स।

[20] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। 2020. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अक्टूबर।

[21] बेक, टी., सेचेट्टी, एस. जी., ग्रोथ, एम., केम्प, एम., पेलिज़ोन, एल., और सेरानो, ए. एस. 2022. विल विडियो किल दी रेडियो स्टार? डिजिटलाइजेशन एंड दी फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। यूरोपीयन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड।

[22] पेंगपेंग, वाई., कोर्कमाज़, ए., झिचाओ, ए. और हैगांग जेड. 2022. दी राइज़ ऑफ डिजिटल फाइनांस: फाइनांशियल इन्क्लूजन ऑर डेट ट्रैप? फाइनांस रीसर्च लेटर्स। 47 (भाग ए)।

[23] कॉर्नेली, जी., गैम्बकोर्टा, एल. और पैनकोटा, एल. 2023. बाय नाऊ, पे लेटर: ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, 4 दिसंबर, 2023।

[24] मॉर्गन, पी., हुआंग, बी. और ट्रिन्ह, लॉन्ग। 2019। दी नीड टू प्रमोट डिजिटल फाइनांशियल लिटरसी फॉर दी डिजिटल एज। टी20 जापान टास्क फोर्स 7 के तहत नीति संक्षिप्त सूचना। 31 मार्च 2019।

नए विचारों को विकसित करने में नहीं, बल्कि पुराने विचारों से बचने में है"।

आर्थिक शोध एक घने जंगल में विचरण करने जैसा है: प्रत्येक नई खोज एक रास्ता बनाती है, लेकिन साथ ही गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। जैसे-जैसे हम प्रसिद्ध विज्ञान आधारित टेलीविजन श्रृंखला स्टार ट्रेक की स्टारशिप एंटरप्राइज की तरह, साहसपूर्वक ऐसी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पहले कोई नहीं गया है, मुझे टी.एस. इलियट के शब्द याद आते हैं: 'केवल वे ही, जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठाएंगे, यह पता लगा सकते हैं कि कोई कितनी दूर जा सकता है'। हाल के वर्षों में, आर्थिक शोध तेजी से बहु-विषयक ढांचे, अग्रगामी और कम्प्यूटेशनल रूप से गहन विश्लेषणात्मक साधनों और उच्च आयामी डेटा से लैस हो रहा है। तो आइए, हम जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करने, जटिल को समझने योग्य बनाने और मानव अनुभव को आकार देने वाली शक्तियों के संबंध में अपनी समझ को बदलने की प्रतिबद्धता के साथ अज्ञात को समझने के लिए कदम उठाएं।

धन्यवाद।

*मौद्रिक नीति संचरण**

माइकल देवब्रत पात्र

मौद्रिक नीति की घोषणाएँ सार्वजनिक चर्चाओं में लगाई जा रहीं अटकलों से जुड़ी होती हैं। तदनुसार अनुमानों को संशोधित किया जाता है, और जोखिमों का संतुलन पुन: निर्धारित किया जाता है। छाया मौद्रिक नीति समितियाँ मुद्रणों और दृक-श्राव्य माध्यमों से अपनी स्थिति बनाती हैं। केंद्रीय बैंक अपनी समझ के अनुसार कार्य शुरू करता है। क्या वह समय से पीछे रहता है? – ऐसा समझते हुए उस पर व्यंग किए जाते हैं। बाजार पुनः मूल्य निर्धारण के लिए तैयार हो जाते हैं, और वित्तीय संस्थान ब्याज मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। जमाकर्ता और व्यवसायकर्ता जनता की राय पर परस्पर विरोधी मत बनाते हैं। दरों में बदलाव की संभावना, कितना बदलाव होगा, रुख क्या होगा ऐसे सवालों के बारे में बातें होने लगती हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाले कई आघातों के बीच मौद्रिक नीति का संचालन दुनिया भर में एक मौन परिवर्तन से गुजर रहा है। महामारी के दौर से गुजरने के बाद कई केंद्रीय बैंकों ने इस शांत क्रांति की मौन पुष्टि करते हुए अपने नीति ढांचे की रणनीतिक समीक्षा की है।[1] इन समीक्षाओं ने मौद्रिक नीति के संचार के विवादास्पद मुद्दे पर भी प्रकाश डाला है, जो मेरे संबोधन का विषय है।

II. मौद्रिक नीति संचार का विकास-क्रम

मौद्रिक नीति संरचना और उसके कार्यान्वयन में हुए परिवर्तनों का इतिहास पिछले कुछ वर्षों में मौद्रिक नीति संचार के विकास की कहानी में बेहतर ढंग से दर्ज हुई है। 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों तक मौद्रिक नीति के संचालन में गोपनीयता एक विशिष्ट तत्व था। केंद्रीय बैंक रहस्यों में लिपटे रहते थे और उनका मानना था कि ऐसा होना भी चाहिए। पारंपरिक रूप से यह मानना था कि मौद्रिक नीति निर्माताओं को जितना संभव हो उतना कम बोलना चाहिए और बात को सांकेतिक रूप से कहना चाहिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड (1920-44) के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे गवर्नर मोंटेगू नॉर्मन का व्यक्तिगत आदर्श वाक्य था : "कभी स्पष्टीकरण न दें, कभी बहाना न बनाएं"।[2] मौद्रिक नीति को एक गूढ़ कला माना जाता था, जिसकी पहुँच और जिसका उचित निष्पादन केवल आरंभिक अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। इसकी विशेषता यह थी कि इसके कथनों को स्पष्ट और बोधगम्य शब्दों और वाक्यों में व्यक्त करना असंभव था।[3] वास्तव में, पिछली शताब्दी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के दो बार पुन:स्थापना के बाद - 1992 में मुद्रास्फीति लक्ष्यकर्ता के रूप में, और 1997 में एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक के रूप में - इसकी मौद्रिक नीति समिति के एक सदस्य (2003-06) ने उस रहस्यमय युग को स्मरण करते हुए कहा - "बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रेस अधिकारी का घोषित उद्देश्य बैंक को प्रेस से और प्रेस को बैंक से दूर रखना था।"[4]

यह मौद्रिक रहस्य तब दूर हुआ जब फरवरी 1994 में अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एमओएमसी) ने पहली बार फेडरल फंड दर के लक्ष्य पर अपने फैसले की घोषणा शुरू की। इसके बाद भी, अगस्त 1997 तक फेड ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था कि मौद्रिक नीति फेडरल फंड्स दर के लक्ष्य के संदर्भ में तैयार की जाती है और इसे एक संख्या दी जाती है। इसके बावजूद, मौद्रिक नीति संचार को 'रचनात्मक अस्पष्टता'[5] या जिसे 'बहुत असंगति के साथ व्यक्त होना'[6] के रूप में जाना जाता है। एलन ग्रीनस्पैन, जो उस समय फेडस्पीक के अध्यक्ष और ख्याति प्राप्त विद्वान थे, ने अस्पष्टता के प्रति

---

* 21 नवंबर 2024 को मुंबई, भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित "ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन" में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्रा द्वारा उद्घाटन भाषण। इंद्रनील भट्टाचार्य, बिनोद बी भोई, जी.वी. नदनाएल और सुभद्रा संकरन से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों के लिए आभार।

[1] अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए में अर्थशास्त्र और सार्वजनिक मामलों के गॉर्डन एस. रेंटस्लर मेमोरियल प्रोफेसर एलन ब्लाइंडर का कथन।

[2] बी.एस. बर्नानके (2015), फेडरल रिज़र्व कम्युनिकेशंस, कैटो इंस्टीट्यूट के 25वें वार्षिक मौद्रिक सम्मेलन में दिया गया भाषण, वाशिंगटन, डी., 14 नवंबर।

[3] के. ब्रूनर, (1981), The art of central banking, University of Rochester Center for Research in Government Policy and Business Working paper GPB 81-6.

[4] एफ. कैपी (2010), बैंक ऑफ इंग्लैंड 1950 से 1979 तक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

[5] जी. ई. कोरिगन (1990), Testimony to Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee, 02 मई।

[6] ए. ग्रीनस्पैन (1987), Speaking to a Subcommittee of the US Congress, नवंबर-दिसंबर 1987।

प्रतिबद्धता को एक कला रूप में बदल दिया। उन्होंने संचार को कम रखते हुए नियमित रूप से संवाद की एक शैली बनाई। कई मौकों पर उनके बोलने से पहले लोगों को कम जानकारी हुआ करती थी। इस अस्पष्टता के पीछे एक अंतर्निहित तर्क था। ग्रीनस्पैन का मानना था कि उद्देश्यपूर्ण अस्पष्टता की भाषा जवाब न देने; या "कोई टिप्पणी नहीं" कहने; या "मैं जवाब नहीं दूंगा" कहने से कहीं बेहतर है। सैद्धांतिक आधार यह था कि बातें बनाने वाले आर्थिक एजेंट, जो मौद्रिक नीति के रुख और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करते हैं, केवल चकित करने वाले नीतिगत घोषणाओं के माध्यम से ही प्रभावित हो सकते हैं।

विरोधाभास यह है कि वे एलन ग्रीनस्पैन ही थे जिन्होंने मौद्रिक नीति के संचार में अधिक पारदर्शिता और खुलेपन की ओर कदम बढ़ाया। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हुए वक्तव्य दिया कि "फेड लंबी अवधि के लिए फेडरल निधि दर को कम रखेगा"। यह प्रवृत्ति व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को भी दर्शा रही थी। लोकतांत्रिक जवाबदेही से संबंधित विचारों ने रचनात्मक अस्पष्टता पर विजय हासिल कर ली थी। केंद्रीय बैंक एक सार्वजनिक संस्थान है जिसे प्राधिकार दिया गया है, इसलिए इस रूप में उसे लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होना चाहिए। वास्तव में, पारदर्शिता को केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का एक निहित तत्व माना जाने लगा। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उस समय ब्याज दर शून्य की ओर बढ़ रहे थे और असामान्य रूप से अत्यधिक समायोजन किए जाने से तुलन-पत्रों के आकार बढ़ गए थे। इन परिस्थितियों में संचार को महत्वपूर्ण माना गया और उसे मौद्रिक नीति साधन का दर्जा प्राप्त हुआ। अल्पकालिक मुद्रा बाजार दर से परे जाकर लंबी अवधि की दरों को सीधे प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा फॉरवर्ड गाइडेंस (अग्रगामी मार्गदर्शन) का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया। 'लंबे समय तक कम' (लो फॉर लॉन्गर) और 'जो करना है वो करना है' (टू डू वॉट इट टेक्स) जैसे वाक्यांश केंद्रीय बैंकों की भाषा में आने लगे। जब महामारी आई तो स्पष्टीकरण, जुड़ाव और शिक्षा संचार के तीन तत्व बन गए थे। जीएफसी के सबक महामारी के दौरान तब काम आए जब केंद्रीय बैंक उच्च अनिश्चितता के माहौल में रक्षा की पहली पंक्ति बन गए। लोगों ने सहायता के साथ-साथ इस आश्वासन के लिए केंद्रीय बैंकों की ओर देखा कि वे आजीविका के नुकसान को रोकने के साथ-साथ वित्तीय बाजारों और संस्थानों में स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मौद्रिक नीति संचार ने भय और अनिश्चितता के महासागर में दीपस्तंभ की भूमिका निभाई।

जब 2021 की दूसरी छमाही से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और यह 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हुई वृद्धि के स्तरों तक पहुँच गई, तब केंद्रीय बैंकों ने, देरी से ही सही, ब्याज दरों में बड़ी और लगातार वृद्धि करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। अचानक जीएफसी के सबक अप्रासंगिक हो गए क्योंकि मुद्रास्फीति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते इस सख्त चरण में टर्मिनल दरों को संप्रेषित नहीं किया जा सका। सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष गवाही देते हुए, जब अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पर 'लोगों के जीवन के साथ जुआ खेलने' का आरोप लगाया गया; उन्होंने जवाब दिया: "क्या कामकाजी लोगों का भला होगा यदि हम अपनी नौकरी छोड़ दें और मुद्रास्फीति फिर से बढ़ जाए?"[8] इसके अलावा, केंद्रीय बैंक प्राधिकारियों ने लक्ष्य प्राप्त होने तक मुद्रास्फीति-रोधी बने रहने की आवश्यकता का बार-बार समर्थन करते हुए बोलना शुरू किया। अग्रगामी मार्गदर्शन ने वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मचा दी और उभरते बाजारों में भी इसका प्रभावप्रसार देखने को मिला। मार्च 2023 में वित्तीय दबाव ने कुछ क्षेत्राधिकारों में बैंकों को विफल कर दिया, अगस्त 2024 में कैरी ट्रेड को समाप्त कर दिया गया और सितंबर 2024 में मंदी की आशंकाओं के कारण दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली हुई। मौद्रिक नीति संचार ने अपने विकास के एक नए चरण में प्रवेश किया क्योंकि इसे लोवर सिग्नल-टू-शोर अनुपात और 'कैकोफनी समस्या' का सामना करना पड़ा, अर्थात - बहुत सारी अलग-अलग आवाज़ें जनता को समझाने के बजाय भ्रमित करती हैं।

[7] ए. हाल्डेन, ए. मैकाले और एम. मैकमोहन, (2020): The 3 E's of central bank communication with the public, Staff Working Paper No. 847, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जनवरी।.

[8] 7 मार्च 2023 को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल में "The Semi-annual Monetary Policy Report to the Congress" पर अमेरिकी सीनेट बैंकिंग, आवास और शहरी मामलों की समिति की सुनवाई के समक्ष गवाही।

आज, मौद्रिक नीति संचार का चक्र पूरा होता है। अपनी रणनीतिक समीक्षा के बाद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल ने " सुनने को अपने संचार की एक नियमित विशेषता बनाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति संचार को आधुनिक बनाने के लिए सहमति व्यक्त की... "।[9] मौद्रिक नीति रणनीतियों, साधनों और संचार की यूएस फेड की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ यह है कि 'Fed listens'।[10] यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई एक दशक से अधिक समय से 'सुनने' को महत्व दिया है, लेकिन इस पर बाद में और बात करेंगे। अब यह माना जाता है कि संचार एक दो-तरफ़ा सड़क है। यह केवल बताने के बारे में नहीं है बल्कि सुनने के बारे में भी है ताकि अर्थव्यवस्था को चलाना सीखा जाए। इन दिनों में केंद्रीय बैंक जितना अधिक संवाद बनाए रखेगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उसे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देगी।[11]

मौद्रिक नीति संचार के ऐतिहासिक विकासक्रम के माध्यम से यह निर्देशित यात्रा मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है: (क) संचार के अंतर्निहित सिद्धांत पत्थर पर उकेरे नहीं जा सकते - संचार को अर्थव्यवस्था की स्थिति, व्यापार चक्र की स्थिति और सामाजिक प्रभावों के प्रति सजग होना चाहिए; (ख) पारदर्शिता की सीमाएँ होती हैं, और अपेक्षाओं तथा व्यवहार्यता के बीच संतुलन आवश्यक होता है; (ग) प्रतिसूचना तंत्र और कार्यनिष्पादन समीक्षा को संचार में शामिल किया जाना चाहिए ताकि केंद्रीय बैंक केवल वक्तव्य देने के साथ-साथ जनता की बात भी सुनें। अपने संबोधन के बाकी हिस्सों में मैं मौद्रिक नीति संचार के इस सबक पर आरबीआई की स्थिति पर बात करूंगा।

III. आरबीआई मौद्रिक नीति का संचार कैसे करता है

शुरुआत में यह कहना उचित होगा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति संचार रणनीति लगातार विकसित हो रही है क्योंकि यह देश-विशिष्ट हितधारकों की विविध और पुरजोर मांगों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संतुलित करती है। इसके अलावा, इसकी संचार रणनीति में कई परतें हैं जो कब, क्या, किसे, कैसे और कितना संचार करना है, इसके द्वारा निर्धारित होती हैं और तदनुसार बारीकियों को आकार देती हैं।

उद्देश्य, नीति ढांचा, निर्णय प्रक्रिया, साधन और आम जनता के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं की जानकारी को अद्यतन किया जाता है और आरबीआई की वेबसाइट पर डाला जाता है, जिसमें प्रमुख नीति दरों, वक्तव्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिप्यंकन और मौद्रिक नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त के लिंक होते हैं। टेक्स्ट-माइनिंग माध्यम पर आधारित आकलन से संकेत मिलता है कि पारदर्शिता के स्तर में, खासकर लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाने के बाद, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।[12] पूर्वगामी मूल्य आकलन, अर्थव्यवस्था के बारे में समग्र भावनाओं और समग्र धारणाओं पर प्रमुख वस्तुओं की कीमतों के प्रभाव जैसे पूर्वाग्रहों के लिए समायोजित संयोग सर्वेक्षण-आधारित जानकारी से पता चलता है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें भी स्थिर हो गई हैं, और वे वास्तविक मुद्रास्फीति की पहचान भी करती हैं।[13] इससे पता चलता है कि आम जनता में मौद्रिक नीति के बारे में जागरुकता बढ़ रही है।

2016 में एफआईटी को अपनाने के बाद से आरबीआई की मौद्रिक नीति संचार प्रथाओं ने आर्थिक स्थितियों के विश्लेषण को प्रकाशित करने के मामले में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित किया है। इसमें संवृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और संबंधित जोखिम शामिल हैं, तथा नीतिगत निर्णयों के लिए तर्कों को नीति वक्तव्यों और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, और नीति घोषणा के एक पखवाड़े बाद एमपीसी कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं। हालाँकि, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्था वाले केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई ने आम तौर पर नीति दर पर स्पष्ट अग्रगामी मार्गदर्शन प्रदान करने से परहेज किया है, तथापि बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान टाइम एंड स्टेट कॉन्टींजेंट अग्रगामी मार्गदर्शन दोनों प्रदान किए। अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता और एक के बाद एक होने वाले आघातों के बीच नीति के सख्त चक्र के दौरान, आरबीआई का

[9] ईसीबी स्ट्रेटेजी रिव्यू (2021), Clear, consistent, and engaging: ECB monetary policy communication in a changing world, European Central Bank Occasional Paper Series No 274, दिसंबर (संशोधित)।

[10] बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिज़र्व सिस्टम (2020) । Fed Listens: Perspectives from the Public। वाशिंगटन: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जून।

[11] एच.एस. शिन (2017), Can central banks talk too much?" Communications challenges for policy effectiveness" पर ईसीबी सम्मेलन में भाषण, फ्रैंकफर्ट, 14 नवंबर।

[12] सामंता, जी.पी., और श्वेता कुमारी (2021) Monetary Policy and Anchoring of Inflation Expectations, आरबीआई वर्किंग पेपर 03/2021।

[13] मुदुली, एस., जी.वी. नदनाएल और एस. पटनायक (2022), परिवार पूर्वाग्रहों के संबंध में मुद्रास्फीति अपेक्षाओं का आकलन, आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर।

मानना था कि अग्रगामी मार्गदर्शन स्वयं नीति अनिश्चितता का स्रोत हो सकता है जो नीति विश्वसनीयता को कम कर सकता है। तदनुसार, बैंक ने नीतिगत सख्त चक्र के दौरान अग्रगामी मार्गदर्शन से परहेज किया। फिर भी, आरबीआई ने मौद्रिक नीति के उच्च और निम्न आवृत्ति संचार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए संचार में स्पष्टता पर जोर दिया है।

हाल के वर्षों में, केंद्रीय बैंक ने संचार को आगे बढ़ाने में जुड़ाव और शिक्षा की पूरक भूमिका पर भी महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। विभिन्न हितधारकों, जैसे कि विश्लेषकों; अर्थशास्त्रियों; शिक्षाविदों; बैंकों; उद्योग निकायों; और डोमेन विशेषज्ञों के साथ नीति-पूर्व परामर्श आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद आम जनता तक पहुँचते हुए प्रसार माध्यमों के साथ नीति-पश्चात बातचीत की जाती है। हर महीने जारी होने वाली आरबीआई बुलेटिन में "अर्थव्यवस्था की स्थिति" पर लेख होता है जिसका उद्देश्य जनता को अर्थव्यवस्था का अद्यतन संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रदान करना है। गवर्नर और उप गवर्नर द्वारा विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषण और साक्षात्कार नीतिगत निर्णयों, उनके औचित्य और नीति चुनौतियों के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने, जुड़ने और शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंकिंग अनुसंधान ने समकालीन व्यापक आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए, मुद्रा और वित्त (आरसीएफ) 2020-21 पर थीम-आधारित रिपोर्ट, जो "मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा" विषय पर आधारित थी और दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के नवीनीकरण से पहले जारी की गई थी; 2021-22 की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए "पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण" विषय लिया गया; 2022-23 की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की गई और उभरते विषय पर सार्वजनिक नीति चर्चा को समृद्ध करने के लिए "एक हरित स्वच्छ भारत की ओर" विषय लिया गया; और 2023-24 की रिपोर्ट में भारत की डिजिटल क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया गया। शैक्षिक मोर्चे पर देखें तो आरबीआई शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, छात्रों के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रायोजित कर रहा है और लोगों को आरबीआई की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके।

हाल के वर्षों में आरबीआई की संचार रणनीति की सराहना की गई है। उदाहरण के लिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने अपनी 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया ""...the Reserve Bank of India issues short and simplified press releases for an audience with limited financial literacy. Establishing links with the media, such as through background briefings, is another common tool." इसके अलावा, अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि कोविड-19 महामारी की शुरुआती लहरों के दौरान अनिश्चितता को कम करने और आस्ति कीमतों का समर्थन करने में अग्रगामी मार्गदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में मौद्रिक नीति रुख के बारे में बाजार की अपेक्षाओं को निर्देशित करने में मौद्रिक नीति संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया, और जिसमें नीतिगत ब्याज दरों का संभावित मार्ग भी शामिल है।[14] उदाहरण के लिए, 9 अक्टूबर 2020 को आरबीआई का निर्णय और अग्रगामी मार्गदर्शन पर गवर्नर का वक्तव्य आरबीआई के समायोजनात्मक रुख की अवधि के बारे में विशिष्ट था, जिसने उसी दिन 10-वर्षीय दरों के कम होने में योगदान दिया।

IV. निष्कर्ष

हालांकि बहुत कम नीति दरों पर अग्रगामी मार्गदर्शन की उपयोगिता स्पष्ट रूप से सिद्ध है, उच्च दरों के संबंध में इसकी प्रभावकारिता संदिग्ध है। यह मौद्रिक नीति चक्र की परिवर्तनशील प्रकृति के अनुरूप है - नीचे की ओर जाने की एक निचली सीमा होती है, लेकिन ऊपर की ओर जाने की कोई ऊपरी सीमा तकनीकी रूप से अप्रतिबंधित होती है। बढ़ती अनिश्चितता के तहत, अग्रगामी मार्गदर्शन में विवेकशीलता ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों के बीच अधिक महत्व प्राप्त किया है। भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि नीतिगत सख्त चक्र में अग्रगामी मार्गदर्शन का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि नीति दर एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है।[15]

[14] एफ. अहमद, एम. बिनिसी और जे. टुरुनेन (2022): Monetary Policy Communication and Financial Markets in India, आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/22/209, अक्टूबर।

[15] एम. डी. पात्र, आई. भट्टाचार्य और जे. जॉन (2023), जब सतर्कता संचार का बेहतर हिस्सा होता है, आरबीआई बुलेटिन, 17 जुलाई।

संक्षेप में, संचार का इष्टतम स्तर सभी केंद्रीय बैंकरों के लिए स्वर्ण मानक बना हुआ है - बहुत अधिक संचार "संकेत संशय समस्या" (सिग्नल एक्सट्रैक्शन प्रोब्लेम) पैदा कर सकता है जबकि बहुत कम संचार बाजारों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर सकता है। एक पूर्व फेड चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा था, “Monetary policy may be 98% talk and only 2% action but cost of sending the wrong message can be high.[16] इस संबंध में, मौद्रिक नीति ढांचे और इसके संचार दोनों को नीति निर्माण में अंतर्निहित अनिश्चितता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक सख्त चक्र में अग्रगामी मार्गदर्शन तनावपूर्ण होता है, लेकिन संचार के माध्यम से ऐसा कहना नीति के इरादे को खत्म कर सकता है। इसी तरह, जबकि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता है, उन्हें अत्यधिक प्रबंधित करना प्रतिकूल साबित हो सकता है।[17] लोगों को लक्षित करने के संदर्भ में, केंद्रीय बैंक अभी भी यह सीख रहे हैं कि अधिक से अधिक जनता के साथ सर्वोत्तम संवाद कैसे किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि भ्रम और स्पष्टता के बीच ‘संचार’ पुल का काम करता है। केंद्रीय बैंकों को इसे प्रभावी बनाने के लिए इस "सॉफ्ट स्किल" को लगातार परिष्कृत और उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। फिल्म स्कोर के प्रसिद्ध कंपोजर जॉन पॉवेल ने कहा है, "Communication works best for those who work at it"। धन्यवाद!

[16] बी.एस. बर्नानके (2015), नए ब्लॉग का उद्घाटन, द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, इकॉनोमिक स्टडीज़।

[17] एम. मैकमोहन (2024), Lessons for Monetary Policy Communication: Communication, Getting Through and Expectation Formation, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुति।

*प्रभावी समाधान के लिए आईबीसी ढांचे का सुदृढ़ीकरण**

श्री एम. राजेश्वर राव

नमस्कार

सबसे पहले मैं भारतीय दिवाला और धनशोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 'धनशोधन अक्षमता समाधान: विकासक्रम और वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया, जो आईएनएसओएल-इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नीति निर्माताओं, इस क्षेत्र के व्यावसायिकों और शिक्षाविदों की विचार प्रक्रियाओं का यह संगम शायद देश में समाधान और धनशोधन अक्षमता व्यवस्था के एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को आकार देने में मदद करेगा। आशा है इससे हम भविष्य के लिए समाधान प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने हेतु मार्ग तैयार करने में सक्षम बन पाएंगे।

आज, मैं बैंकों के तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की भूमिका और हमारे दृष्टिकोण से प्रमुख हितधारकों, अर्थात वित्तीय ऋणदाताओं के लिए इसकी क्षमता का और अधिक लाभ उठाने के संभावित तरीकों पर विचार करके शुरुआत करना चाहता हूं। भारत में वर्तमान दिवाला और धनशोधन अक्षमता व्यवस्था डॉ. टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली धनशोधन अक्षमता कानून सुधार समिति द्वारा दिए गए सुझावों का परिणाम थी। नई दिवाला और धनशोधन अक्षमता समाधान प्रणाली के लिए समिति की सिफारिशें कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थीं, जो इस प्रकार थीं - (i) प्रारंभिक चरण में उद्यम की व्यवहार्यता के आकलन का प्रावधान करना; (ii) ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना की समरूपता को सक्षम करना; (iii) आर्थिक मूल्य को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करना; (iv) प्राथमिकता को स्पष्ट करते हुए सभी ऋणदाताओं के अधिकारों का सम्मान करना; और (v) परिणामों की अंतिमता सुनिश्चित करना।

इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप 2016 की दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) अस्तित्व में आई। तब से यह संहिता (कोड) और इससे संबंधित पारितंत्र विकसित होते रहे हैं, जो ऊपर वर्णित सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से आगे ले जाते हैं। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन उस व्यापक पारितंत्र का एक कार्य है जिसमें यह संचालित होता है, इस कोड को अपने अपेक्षाकृत अल्प समय में विभिन्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से समयसीमा का पालन करने में देरी और असंतोषजनक वसूली के संदर्भ में, जिसका आंशिक रूप से कारण था हितधारकों के बीच असमान हित। हालांकि आईबीसी के लागू होने के बाद इनमें से कुछ मुद्दों को दूर करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

बैंक तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में आईबीसी की भूमिका

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है - विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए, जो मार्च 2018 में 11.2% के शिखर पर था, से घटकर मार्च 2024[1] में 2.8% हो गया। यह कमी आने में आईबीसी के तहत सक्षम समाधान प्रक्रियाओं का उल्लेखनीय योगदान है। यदि आईबीसी का समग्र मूल्यांकन किया जाए, तो यह समाधान तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण स्तर की गति को दर्शाता है। सितंबर 2024 तक 8,002 मामले[2] कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में स्वीकार किए गए और इनमें से लगभग 75% मामले समाधान, वापसी, समीक्षा, निपटान या परिसमापन के माध्यम से बंद कर दिए गए। बंद किए गए मामलों में से 56% का समाधान, निपटान या वापसी हुई। सकारात्मक रूप में समाधान और परिसमापन का अनुपात जो 2017-18 में 21% था, से बढ़कर 2023-24 में 61% हो गया। समाधान परिणामों को सुविधाजनक बनाने के अलावा, आईबीसी का उपयोग वित्तीय और परिचालन दोनों प्रकार के ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं (उधारकर्ताओं) को अपने ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रभावी

* 7 दिसंबर 2024 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और आईएनएसओएल इंडिया द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। वैभव चतुर्वेदी, खबीर अहमद और अरुण कुमार पचमल द्वारा दी गई जानकारी के लिए आभार।

[1] आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

[2] आईबीसी के तहत संदर्भित मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में इस भाषण में संदर्भित डेटा आईबीबीआई त्रैमासिक समाचार पत्रों से संकलित किया गया है।

ढंग से किया गया है। मार्च 2024 तक ₹10.22 लाख करोड़ की बकाया डिफ़ॉल्ट राशि से जुड़े 28,818 मामले दाखिल होने से पहले ही वापस ले लिए गए।

बैंककारी विनियमन अधिनियम में सम्मिलित नई धारा 35एए के तहत निहित शक्तियों के संदर्भ में, आरबीआई ने 2017 में 41 संस्थाओं के संबंध में बैंकों को सीआईआरपी आवेदन दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे, जिनकी उस समय बैंकिंग प्रणाली के एनपीए में 35% से अधिक हिस्सा था। अब तक 17 उधारकर्ताओं के मामले में समाधान योजना को मंजूरी दी गई है, 12 उधारकर्ताओं के मामले में परिसमापन के आदेश जारी किए गए हैं, 2 उधारकर्ताओं के साथ ऋणदाताओं द्वारा समझौता किया गया है; और 4 मामलों में ऋणदाताओं ने एआरसी को अपने ऋण मामले सौंपे हैं। निपटाए गए 17 मामलों से वित्तीय ऋणदाताओं के लिए कुल प्राप्ति स्वीकृत दावों का लगभग 50% और परिसमापन मूल्य का 190% रही है।

वित्तीय ऋणदाता अब तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए इस संहिता का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहे हैं। सितंबर 2024 तक लगभग 633 कारपोरेट उधारकर्ताओं के मामले, जहां वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया अपनाई गई थी, आईबीसी के तहत सफलतापूर्वक हल किए गए, जिससे स्वीकृत दावों का औसतन 30.09% प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 702 कारपोरेट उधारकर्ता खातों में वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दायर सीआईआरपी आवेदनों को या तो अपील/समीक्षा/निपटान के माध्यम से हल किया गया है या धारा 12ए के तहत वापस ले लिया गया है। इसी तरह, 1224 कारपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में परिसमापन आदेश पारित किए गए हैं।

इसके अलावा, 2019 में इस संहिता की धारा 227 लागू होने पर रिज़र्व बैंक को वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के समाधान के लिए आईबीसी तंत्र का लाभ उठाने का अधिकार प्राप्त हुआ। रिज़र्व बैंक ने अब तक चार एफएसपी के खिलाफ धनशोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया है और आज की तारीख तक उन सभी का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। जाहिर है, आईबीसी ने बैंक तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

[3] 3 संबंधित बैंकों से आरबीआई द्वारा संकलित डेटा।

हालांकि आईबीसी ऋणदाताओं के लिए एक मूल्यवान माध्यम साबित हुआ है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ ऐसे कारकों के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से इसकी प्रभावशीलता बाधित हुई है, ताकि यह स्पष्ट रूप से समझा जा सके कि आईबीसी की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग क्यों नहीं किया गया है।

(i) आरंभ करने में देरी

समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए समय और समय निर्धारण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जबकि आईबीसी प्रक्रिया में देरी पर व्यापक रूप से चर्चा होती है, उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा आईबीसी प्रक्रिया को आरंभ करने में देरी करने का भी है। आईबीसी सभी ऋणदाताओं को डिफ़ॉल्ट होने पर सीआईआरपी आरंभ करने का अधिकार देता है। लेकिन वास्तव में, डिफ़ॉल्ट की तिथि से लेकर सीआईआरपी दाखिल करने तक वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा लिया जाने वाला औसत समय अक्सर कई महीनों का होता है। इस अवधि के दौरान मूल्यराशि के एक बड़े हिस्से का नुकसान होता है, जो अंततः वसूली के परिणाम को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में वित्तीय ऋणदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें आगे के नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

जबकि आईबीसी का उपयोग हाल में ही बढ़ा है, हमें यह मालूम होना चाहिए है कि यह ऋणदाताओं के लिए वित्तीय दबाव को हल करने के लिए उपलब्ध तंत्रों में से एक है। सुरक्षा को लागू करने के लिए और भी वैधानिक तंत्र उपलब्ध हैं और साथ ही समाधान के लिए अदालत से बाहर के विकल्प भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका और सीमाएँ हैं। विनियामक दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक वित्तीय संकट के त्वरित समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू किए जाने के मुद्दे को छोड़कर ऋणदाताओं द्वारा चुने गए तंत्रों के बारे में तटस्थ रहता है।

(ii) न्यायालय के बाहर समझौते की प्रभावकारिता

औपचारिक दिवाला ढांचे की वास्तविक सफलता इसके वास्तविक उपयोग के आधार पर नहीं बल्कि निवारक के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। न्यायालय के बाहर समझौता प्रक्रियाओं को ही समाधान के प्राथमिक साधन के रूप में कारगर बनाने की आवश्यकता है जो औपचारिक दिवाला ढांचे के अंतर्गत

हो। भारतीय संदर्भ में, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई का विवेकपूर्ण ढांचा न्यायालय के बाहर समझौता तंत्र प्रदान करता है। यह विवेकपूर्ण ढांचा उधारकर्ताओं द्वारा दबाव की शीघ्र पहचान और समयबद्ध समाधान के लिए एक व्यापक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था प्रदान करता है। हालाँकि, इस तंत्र की प्रभावकारिता कई कारकों के कारण बाधित हुई है, जिसमें ऋणदाताओं के बीच समन्वय के मुद्दे भी शामिल हैं। इसलिए, न्यायालय के बाहर समझौते के तहत सिद्धांत-आधारित समाधान दृष्टिकोण को आईबीसी की वैधानिक छत्रछाया के साथ जोड़ने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय के बाहर शुरू किए गए समाधान को आईबीसी के तहत परिवर्तित किया जा सके और लागू किया जा सके।

इस आवश्यकता को पहचानते हुए, 2021 में प्री-पैक धनशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी/प्री-पैक) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नियमित सीआईआरपी के विकल्प के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों (एमएसएमई) का समाधान करना था। प्री-पैक को एमएसएमई के लिए बहुत ही कारगर माना गया था क्योंकि इसमें सफल समाधान उपाय बनाने के लिए सभी तत्व मौजूद थे, जैसे कि - उधारकर्ता के पास कब्जा, लागत प्रभावी, त्वरित समाधान समयसीमा और स्वयं एमएसएमई द्वारा तैयार की गई आधार समाधान योजना। प्री-पैक व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप से प्री-पैक धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले एमएसएमई और ऋणदाताओं को समाधान के लिए एक पूर्व समझौते पर पहुंचना होता है। इन सभी लाभों के बावजूद पीपीआईआरपी के तहत अब तक केवल दस आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से एक को वापस ले लिया गया और पाँच मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई।

आईबीबीआई ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी जिसने मई 2023 में दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत ऋणदाताओं के नेतृत्व वाले समाधान दृष्टिकोण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आईबीसी के तहत मौजूदा फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को पीपीआईआरपी के समान 'ऋणदाता के नेतृत्व वाली' और 'अदालत से बाहर' दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने का सुझाव दिया गया है, लेकिन पीपीआईआरपी को अपनाने में देखी गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस संबंध में एक ऐसा उपयुक्त ढांचा अपनाया जा सकता है जो आईबीसी के सार तत्व को कम किए बिना इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति में मददगार होगा।

(iii) ऋणदाता समिति (सीओसी) की भूमिका

आईबीसी सीआईआरपी में ऋणदाता समिति (सीओसी) को एक केंद्रीय भूमिका सौंपता है। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीओसी के निष्पादन में कई पहलुओं में कमी पाई गई है जैसे कि समूह के सामूहिक हित के बजाय व्यक्तिगत ऋणदाताओं के हितों को असंगत रूप से प्राथमिकता देना; कम मूल्यांकन या व्यवहार्यता की कथित कमी के बारे में चिंताओं के कारण समाधान योजना को मंजूरी देने पर सीओसी सदस्यों के बीच असहमति; समाधान योजना पर सहमति होने पर भी आय के वितरण पर असहमति; सीओसी बैठकों में सहभागी न होना और सदस्यों के बीच प्रभावी जुड़ाव न होना, और समन्वय या सूचना के आदान-प्रदान की कमी होना। कारपोरेट वित्त, कानून और संबंधित उद्योगक्षेत्र के ज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपर्याप्त कौशल के बारे में उदाहरण देखे गए हैं; और यह भी कि सीओसी में वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा नामित व्यक्तियों को ऐसी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं जो उनके वास्तविक अधिकार से कहीं अधिक होती हैं।

यह ऋणदाताओं के व्यापक हित में है कि सीओसी के संचालन से संबंधित मुद्दों को विनियामक निर्देशों या आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना सदस्यों द्वारा स्वयं संबोधित किया जाए। हालांकि, यह वास्तविकता है कि जब हितों का समुचित रूप से ध्यान न रखा गया हो तो सर्वोत्तम प्रथाओं से विचलन होना एक आम बात बन जाती है। इसलिए, हमें सीओसी के लिए लागू करने योग्य एक आचार संहिता की आवश्यकता है। जाहिर है, वित्तीय ऋणदाताओं के विविध समूह को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों के विनियामकों के लिए इसे लागू करना संभव नहीं होगा। सही मायने में आईबीबीआई, जो आईबीसी के तहत नामित विनियामक है, के पास आईबीसी प्रक्रिया के तहत सभी हितधारकों के कार्य को ध्यान में लेते हुए मानदंडों को लागू करने की शक्तियाँ होनी चाहिए।

(iv) समाधान पेशेवर की भूमिका

आईबीसी पारितंत्र के तहत एक अन्य प्रमुख हितधारक समाधान पेशेवर (आरपी) है, जिसकी विशेषज्ञता और दक्षता समाधान प्रक्रिया के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती

है। समाधान पेशेवर को संबंधित उद्योग, व्यावसायिक वातावरण और लागू कानूनों का गहन ज्ञान होना चाहिए तथा उसे संकटग्रस्त फर्मों के वित्तीय विश्लेषण और प्रबंधन में भी कुशल होना चाहिए। प्रबंधन पहलू यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरपी संकटग्रस्त कारपोरेट उधारकर्ता का नियंत्रण लेता है और सीओसी के परामर्श के आधार पर एमडी/सीईओ के कर्तव्य का निर्वहन करता है। आरपी के चयन और कार्रवाई में कोई भी कमी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बाधा होगी। कोड में दावों के संग्रह से लेकर संभावित समाधान आवेदकों को खोजने और समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए सीओसी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने तक आरपी पर बहुत सारी परिचालन जिम्मेदारियाँ होती हैं। हालाँकि, कई मामलों में, आरपी को अन्य हितधारकों का सहयोग नहीं मिलता है जो आरपी की अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने की क्षमता को बाधित करता है। एक संतोषजनक बात यह है कि आईबीबीआई ने निरंतर व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, वेबिनार और सेमिनारों के माध्यम से आरपी के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कदम उठाए हैं। संचालन संबंधी विनियमों के बेहतर प्रवर्तन के साथ ये कदम इन मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

(v) समाधान पेशेवरों के लिए प्रोत्साहन

विनियम किसी गतिविधि के लिए सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हर विवरण को विचार में नहीं ले सकते। हालांकि विनियमनों ने समाधान पेशेवरों (आरपी) के लिए एक पारितंत्र बनाने में मदद की है, लेकिन उनका मुआवज़ा वाणिज्यिक तौर पर बाज़ार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं द्वारा समस्या को हल करने के सभी प्रयास जब विफल हो जाते हैं उसके बाद आरपी की भूमिका होती है, और वे उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। धनशोधन अक्षमता कार्यवाही के तहत एक कारपोरेट उधारकर्ता का प्रबंधन करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। बाज़ार को आरपी के लिए मुआवज़े का स्वरूप विकसित करना चाहिए जो समाधान प्रक्रिया के परिणामों से जुड़ा हो। इससे प्रिंसिपल-एजेंट मुद्दा भी सुलझेगा और वह आरपी के लक्ष्यों को सीओसी के साथ संरेखित करेगा, जिससे दोनों पक्षों के लिए मूल्य अधिकतम होगा। यह अनुभवी पेशेवरों को भी आकर्षित करेगा, जिससे पूरी प्रणाली को लाभ होगा।

आगे की राह

इस कोड को लागू हुए लगभग आठ साल हो चुके हैं और कोड के तहत कई बड़े मामलों को सफलतापूर्वक हल किया गया है। धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग भविष्य में क्रेडिट अंडरराइटिंग के साथ-साथ मूल्यांकन के लिए इनपुट के रूप में किया जा सकता है।

यदि यह आईबीसी पारितंत्र समाधान या परिसमापन संबंधी अनुभव की समीक्षा के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, तो यह आईबीसी पारितंत्र अपूर्ण होगा। यदि हम ऐसे मामलों से डेटा संकलित करते हैं, तो धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत रखे गए उद्यमों का विस्तृत अध्ययन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। वर्तमान में इस तरह के डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित नहीं किया जाता है और जो अभी बिखरा हुआ है तथा ज्यादातर व्यक्तियों के अपने अनुभव और जानकारी तक सीमित है। यदि इस डेटा को एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र और संस्थागत रूप दिया जाता है तो यह हमें जटिल मामलों में कार्रवाई करने के तरीके पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मिसाल दे सकता है। इसलिए इस तरह के डेटा को एक संरचित तरीके से एकत्र करने की आवश्यकता है ताकि इसे सभी शामिल हितधारकों के लाभ के लिए प्रसारित किया जा सके।

डेटा का लाभ उठाना…

समग्र समाधान पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर अधिक गंभीरता से काम करना होगा। सबसे पहले, चूक होने के कारणों की बेहतर समझ – क्या वह सामान्य आर्थिक वातावरण, विशिष्ट उद्योग चुनौतियों या पेशेवर कुप्रबंधन के कारण थी। यह दृष्टिकोण उचित समाधान तैयार करने में मदद कर सकता है। दूसरा, धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया में कुछ कारपोरेट उधारकर्ताओं द्वारा सहयोग की कमी के कारण होने वाली देरी जैसे कि सूचना प्रस्तुत करने में देरी, मूल्यवान विवरण रोक रखना, कार्य प्रगति को रोकने के लिए मुकदमेबाजी का उपयोग करना, या संभावित समाधान आवेदकों को हतोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष बाधाएं पैदा करना, को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। अंत में, मूल्यांकन की जांच करना, जिसमें यह जानकारी शामिल है कि संपार्श्विक प्रकार किस तरह मूल्यप्राप्ति (रियलाइजेशन) बनाम मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, वसूली पर समय का

प्रभाव, और समाधान समयसीमा और मूल्यांकन परिणामों के बीच संबंध, हमें ऐसी जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो हमें प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। शायद मूल्यांकन के समय बेहतर मूल्यांकन (एप्राइजल) महत्वपूर्ण है। अक्सर मूल्यांकन और समाधान चरणों के बीच मूल्यांकन में असमानता मूल्यांकन को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने और उचित परिश्रम की संभावित कमी का संकेत है।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रौद्योगिकी के उदय के साथ भुगतान पारितंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। फिनटेक सेवा प्रदाता निर्मित हुए विशाल भुगतान डेटा के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ऋण हामीदारी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में, विशेष रूप से नकदी प्रवाह-आधारित मॉडल के माध्यम से छोटे उधारकर्ताओं और एमएसएमई के मामले में कुछ प्रगति हुई है। अगला कदम बैंकों और अन्य हितधारकों के लिए तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के साथ मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होना चाहिए। प्रौद्योगिकी को कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे कि उधारकर्ता के डेटा के आधार पर चूक होने से पहले उनका अनुमान लगाना, प्रारंभिक सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम करना; संबंधित पक्ष या तरजीही लेनदेन की पहचान करने के लिए संरचित और असंरचित दोनों प्रकार के डेटा का विश्लेषण करना, ऋणदाताओं और समाधान पेशेवरों के लिए संसाधनों की बचत करना; संवितरण पश्चात ऋण निगरानी में नियमित कार्यों को स्वचालित करना, ऋणदाताओं के लिए अधिक जटिल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की बचत करना; और कारपोरेट उधारकर्ता का मूल्यांकन करते समय सीओसी और समाधान आवेदकों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी दस्तावेजों और अनुबंधों को पढ़ना। जैसे-जैसे इन मोर्चों पर प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग विकसित होगा, समाधान से जुड़ी लागतों के साथ-साथ इसमें शामिल श्रम में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

निष्कर्ष

मैं कुछ अंतिम विचारों के साथ अपनी टिप्पणी समाप्त करना चाहूँगा! यह संभव है कि धनशोधन अक्षमता या परिसमापन कार्यवाही कंपनी के पुनरुद्धार और नए सिरे से शुरू करने का एकमात्र तरीका हो। लेकिन, हमें ऐसी इकाइयों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार को पहले विकल्प के रूप में देखना चाहिए और उस पर त्वरित और समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। किसी उद्यम के भीतर मूल्यवान संपत्ति निहित होती है जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में चलाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, भले ही ऋणदाताओं के रूप में परिसमापन प्रक्रिया सुरक्षित और जोखिम मुक्त विकल्प के रूप में दिखाई दे। इसके लिए एक ऐसा पारितंत्र बनाना आवश्यक है जो उद्यमों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करे। हालांकि आईबीसी 2016 ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है, जिसने देश में कारपोरेट प्रथाओं के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम पर है कि सामूहिक रूप से, हम एक संपन्न पारितंत्र बनाने के लिए इस कोड की क्षमता का दोहन करें जो मूल्य संरक्षण को सक्षम बनाता हो।

समाधान ढांचे को बेहतर बनाने की हमारी यात्रा में, हमें न केवल कथित बाधाओं या अड़चनों को देखना चाहिए, बल्कि अब तक हमने जो रास्ता तय किया है और रास्ते में क्या सीखा है उस पर भी ग़ौर करना चाहिए। हमें ऐसे उपायों के बारे में सोचना चाहिए जो अड़ियल या बेईमान उधारकर्ताओं के मामले में कोड के प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे किंतु इस कोड को संबंधित उद्यम के आर्थिक मूल्य की पहचान करने के लिए एक प्रभावी विकल्प बना सकेंगे। पिछला दशक हम सभी के लिए सीखने, सुधार करने और विकास की एक यात्रा रहा है जो विनियामकों, वित्तीय संस्थानों या उधारकर्ताओं के रूप में इस प्रक्रिया में हितधारक हैं। इस सम्मेलन से इस बारे में नई अंतर्दृष्टि सामने आनी चाहिए कि कोड की क्षमता को कैसे उपयोग में लाया जाए जिससे कि यह वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने का काम करे, और यह हमारे राष्ट्र के मजबूत विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके।

धन्यवाद और नमस्कार।

जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करना और संवहनीय वित्त के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना*

श्री एम. राजेश्वर राव

सबसे पहले मैं जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार साझा करने के लिए मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जो न केवल व्यक्तियों के रूप में, बल्कि सामूहिक वैश्विक समुदाय के रूप में हमारे सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है।

कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की 1 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 ईआरएएस पुनर्विश्लेषण डेटासेट में सबसे गर्म वर्ष होगा, जो 1940 तक वापस जा रहा है। यह भी अनुमान लगाया गया था कि अक्टूबर 2023 के बाद यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे गर्म अक्टूबर होगा, जिसमें औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.65ºC ऊपर था, जबकि इसे 16 महीने की अवधि में 15वें महीने में भी चिह्नित किया गया था जहां औसत तापमान पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5ºC सीमा से ऊपर था। इस प्रकार, दीवार पर लेखन हमें बताता है कि जब तक हम सामूहिक रूप से कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारा भविष्य चिंतनीय है। हाल की दुखद घटनाएं, चाहे वह वालेंसिया, स्पेन, वायनाड, केरल में हों या संयुक्त राज्य अमेरिका में बैक-टू-बैक तूफान हों, जलवायु परिवर्तन के खतरों की याद दिलाती हैं जो बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने है। यह हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, चाहे वह भारी वर्षा, अचानक बाढ़, चक्रवात, सूखा, ग्लेशियरों का पिघलना, जैव विविधता का नुकसान आदि के माध्यम से हो, और वह भी बढ़ी हुई आवृत्ति और गंभीरता के साथ। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन वित्तीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बड़े पैमाने पर एक बड़ा जोखिम होने जा रहा है, जिसमें गंभीर विनाशकारी घटनाओं के जोखिम हमारे अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हैं।

वित्तीय प्रणाली को न केवल जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले वर्तमान और भविष्य के प्रभावों के लिए तैयार होने और खुद को तैयार करने की आवश्यकता है, बल्कि परिणामी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका भी निभानी चाहिए। हमारे और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सतत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की कमी है और जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने और एक मजबूत स्थायी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे की कमी है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील दिखता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2100 तक, जलवायु परिवर्तन से 3% से 10%[2] की वार्षिक जीडीपी हानि हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम और वित्तीय प्रणाली पर इसका प्रभाव

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अनिवार्य रूप से दो प्रकार के जोखिम हैं जिन्हें हमें संबोधित करने की आवश्यकता है: भौतिक और संक्रमण जोखिम। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विचार अनुकूलन और संबंधित जोखिम और उपाय भी है। मुझे थोड़ा विस्तार से बताने दें।

भौतिक जोखिम क्रमिक और अचानक जलवायु प्रभावों दोनों से उपजी हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, वास्तविक संपत्ति और वित्तीय साधनों को प्रभावित करती हैं। ये जोखिम परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ऋण हानि और संपार्श्विक क्षति होती है, साथ ही अप्रत्यक्ष लागत, जिसमें व्यापार में व्यवधान, पूंजी प्रतिस्थापन और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे शामिल हैं। ये जोखिम व्यापार, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। भौतिक जोखिमों से ऋण नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि इस तरह के नुकसान पर ऐतिहासिक डेटा की कमी है, क्योंकि वित्तीय संस्थानों ने उन्हें ट्रैक नहीं किया है। यहां तक कि उपलब्ध डेटा भी भौतिक घटनाओं की बदलती आवृत्ति, तीव्रता और स्थान के कारण सीमित उपयोग का है, जिससे पिछले डेटा के आधार पर अनुमान थोड़ा जोखिम भरा हो जाता

* 29 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (आईएसएएस) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। सुनील नायर और साकेत कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

1 वर्ष 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म के रूप में समाप्त होने वाला है | कोपरनिकस (https://climate.copernicus.eu/year-2024-set-end-warmest-record)।

2 मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, आरबीआई (2023)।

है। वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण घाटे पर इस तरह के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे क्रेडिट जोखिम को प्रभावित करते हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट की संभावना और डिफ़ॉल्ट रूप से नुकसान शामिल है।

जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों से संक्रमण जोखिम उत्पन्न होते हैं। यह फर्मों और अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संक्रमण की आवश्यकता से उत्पन्न होता है क्योंकि वे अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो विघटनकारी हो सकता है। यह कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के साथ-साथ उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश के बारे में निवेशक वरीयताओं का परिणाम हो सकता है। यह जलवायु संबंधी नियमों जैसे कार्बन मूल्य निर्धारण और करों, पारदर्शिता आवश्यकताओं, उत्पादों और सेवा नियमों से भी बाहर हो सकता है। इस प्रकार, संक्रमण जोखिम विभिन्न आर्थिक कारकों की अपेक्षाओं से उत्पन्न डिस्कनेक्ट के कारण उभरता है और इससे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में तेजी से आर्थिक समायोजन लागत हो सकती है। यह फर्मों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है, जो वित्तीय स्थिरता पर इसके परिणामी प्रभाव के साथ वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है।

जबकि संक्रमण महत्वपूर्ण है, हम जलवायु घटनाओं के तत्काल प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें अनुकूलन उपायों को भी देखने की जरूरत है जो वर्तमान में जलवायु रणनीतियों के संबंध में एक लापता लिंक प्रतीत होता है। अनुकूलन में जलवायु घटना प्रभावों का जवाब देना शामिल है, जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थितियों को लगातार खराब करते हैं, जैसे कि पानी, ऊर्जा, वायु गुणवत्ता और सहनीय कार्य तापमान तक पहुंच। इन स्थितियों को तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसे अल्पकालिक झटके से बाधित किया जा सकता है, जिनके अचानक और विनाशकारी प्रभाव होते हैं। हमें उन रणनीतियों को देखने की जरूरत है जो नुकसान और क्षति को कम करती हैं और अनुकूलन वित्तपोषण आर्थिक लचीलापन बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होने की संभावना है।

जलवायु संबंधी जोखिमों से घरों, कंपनियों और संप्रभु पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जो खपत, उत्पादन और निवेश पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। फर्मों के लिए उनके एक्सपोजर को देखते हुए, चाहे क्रेडिट या निवेश के रूप में, साथ ही साथ अपने स्वयं के संचालन के रूप में, ये जोखिम क्रेडिट, बाजार, तरलता और परिचालन जोखिमों की पारंपरिक जोखिम श्रेणियों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करते हैं। इन हानियों को वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच, वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों के बीच और गैर-वित्तीय क्षेत्र के भीतर परस्पर संबंध के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम के बीच अंतर-संबंध वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले गैर-रैखिक जोखिम के लिए एक विशेष स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इन जोखिमों को सीमा पार व्यापार और उत्पादन अन्योन्याश्रितताओं के माध्यम से भी बढ़ाया जा सकता है।

नियामक प्रतिक्रिया और चुनौतियां

हालांकि इस बात पर कुछ बहस है कि जलवायु परिवर्तन केंद्रीय बैंक के लिए अधिदेश का हिस्सा है या नहीं, तथ्य यह है कि इसका मूल्य और वित्तीय स्थिरता दोनों पर असर पड़ता है, इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर नियामक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इन जोखिमों के प्रति उनके एक्सपोजर की सीमा और मौजूद न्यूनीकरण उपायों पर निर्भर करता है। नियामकों के सामने दुविधा और चुनौती न केवल विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, बल्कि वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित और सतत विकास के लिए एक सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में भी कार्य करना है। महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय निर्भरताओं को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन जोखिमों के शमन के लिए न केवल नियामकों से व्यक्तिगत क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, बल्कि अंतर-नियामक समन्वय की भी आवश्यकता होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के अपने संकल्प में सक्रिय रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने इस दिशा में अनेक वृद्धिशील उपाय किए हैं। यह जलवायु परिवर्तन जोखिमों का आकलन करने और स्थायी वित्त के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बैंक के भीतर एक समर्पित

[3] उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)।

समूह की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 34 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कवर करते हुए जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर सर्वेक्षण जारी किया गया। रिज़र्व बैंक पारंपरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु परिवर्तन जोखिमों के एकीकरण के लिए वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न रहा है; उनकी बैलेंस शीट में कमजोरियों की पहचान करने के लिए जलवायु परिदृश्य विश्लेषण; शमन उद्देश्यों के लिए ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए क्षमताओं में अंतराल को संबोधित करना।

अपेक्षाओं को निर्धारित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जलवायु परिवर्तन जोखिम शमन कार्यों को कम करने के उपायों में से एक जलवायु प्रकटीकरण मानकों को निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएसएसबी) जैसे वैश्विक मानक निर्धारक निकाय इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं और भारत सहित अधिकांश क्षेत्राधिकार अपनी साझा किंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधित प्रकटनों को अपने नुस्खों के साथ अंशांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु प्रकटन ढांचे का मसौदा जारी किया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। प्रकटन ढांचे का आशय जलवायु परिवर्तन जोखिमों को कम करने के लिए दक्षताओं की पहचान करने और निर्माण करने के लिए विनियमित संस्थाओं को तैयार करना है और किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग को ऋण देने को प्रतिबंधित नहीं करना है।

यद्यपि हमारे बीच व्यापक समझ हो सकती है, हमें अभी उस चरण तक पहुंचना है जहां हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का व्यापक रूप से आकलन कर सकें। जलवायु परिवर्तन जोखिमों के सही आकलन के लिए प्रमुख चुनौती आवश्यक डेटा की उपलब्धता है। जलवायु डेटा को समान पद्धति की कमी, पहुंच में विखंडन, डेटा के प्रकाशन में एकरूपता की कमी और मीट्रिक्स, इकाइयों और प्रारूपों में अंतर की विशेषता है। जलवायु जोखिमों से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक ऋण हानि डेटा की कमी है, जलवायु घटनाओं के ऐतिहासिक और भविष्य के पूर्वानुमानों को शामिल करने वाले खतरनाक डेटा, और शुद्ध शून्य में संक्रमण के लिए क्षेत्रीय बेंचमार्क शामिल हैं। वर्तमान में वित्तीय संस्थानों के बीच ऋण परिसंपत्तियों को लेबल करने का कोई निर्धारित अभ्यास नहीं है जो किसी भी जलवायु जोखिम घटना के आधार पर खराब हो गए हैं। यह चूक की संभावना का अनुमान लगाने के लिए पारंपरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल में जलवायु संबंधी जोखिमों के एकीकरण के लिए यथार्थवादी ऋण हानि डेटा की उपलब्धता को सीमित करता है। यह वित्तीय संस्थाओं को भविष्य में वास्तविक हानि आकलनों पर पहुंचने के लिए विभिन्न अनुरूपण और परिदृश्य विश्लेषण अभ्यास करने से भी रोकती है। परिणामस्वरूप, इस बिंदु पर ऋण हानि डेटा पर पहुंचने और भविष्य में होने वाली संभावित हानियों को मापने के लिए विभिन्न सन्निकटन विधियों/डेटा सेटों का उपयोग किया जा रहा है।

जब हम भौतिक जोखिम और विशेष रूप से जोखिम के आंकड़ों पर विचार करते हैं, तो भारत विशिष्ट डेटा की आवश्यकता होती है जो वैश्विक रूप से स्वीकृत परिदृश्यों पर आधारित हो सकता है। यह कहते हुए कि, एनजीएफएस और जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा प्रदान किए गए परिदृश्य भारत विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। संक्रमण जोखिमों के मामले में, क्षेत्रीय संक्रमण बेंचमार्क की उपलब्धता के संदर्भ में एक अंतर है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा फर्मों के सापेक्ष संक्रमण जोखिमों को मापने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित वर्गीकरण की अनुपस्थिति भी यह निर्धारित करने के लिए एक बाधा है कि किन क्षेत्रों को उसी के लिए एक सांकेतिक रोड मैप के साथ संक्रमण की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन के माप भी प्रगति पर हैं।

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक - रिपोर्ट (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1215).

[5] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/CLIMATERISK46CEE62999A4424BB731066765009961.PDF

[6] भारतीय रिज़र्व बैंक - अधिसूचनाएं (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0).

[7] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=57408

[8] डेटा अंतरालों को पाटने पर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) की अंतिम रिपोर्ट में जलवायु संबंधी डेटा में मुद्दों के रूप में उपलब्धता (जैसे, कवरेज, ग्रैन्युलैरिटी, एक्सेसिबिलिटी), विश्वसनीयता (जैसे, गुणवत्ता, ऑडिटेबिलिटी, पारदर्शिता) और तुलनात्मकता पर प्रकाश डाला गया है।

स्कोप 3 उत्सर्जन अनिवार्य रूप से एक फर्म के लिए मूल्य-श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उत्सर्जन से संबंधित है। मूल्य-श्रृंखला में प्रत्येक खिलाड़ी का यह प्रयास होना चाहिए कि वे अपने संबंधित स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन का ध्यान रखें, ताकि स्कोप 3 से संबंधित मुद्दे पर स्वचालित रूप से ध्यान दिया जा सके। यह इस दृष्टिकोण से है कि जलवायु जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए वित्तीय प्रणाली को संबंधित स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को पकड़ने की आवश्यकता है। यह न केवल फर्मों को अपने स्वयं के जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के आकलन के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि आगे बढ़ने वाले किसी भी प्रणालीगत मुद्दों के वार्ड के लिए बड़े पैमाने पर प्रणाली तैयार करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक का इरादा रिज़र्व बैंक-जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) नामक डेटा रिपॉजिटरी के निर्माण के साथ जलवायु डेटा उपलब्धता में अंतराल को दूर करने का है, जिसकी घोषणा गवर्नर द्वारा 09 अक्टूबर, 2024 को की गई थी। इसमें दो भागों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। पहली, एक वेब-आधारित निर्देशिका, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोतों (मौसम विज्ञान, भू-स्थानिक, आदि) को सूचीबद्ध किया गया है, जो आरबीआई की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होगा। दूसरा, एक डेटा पोर्टल जिसमें डेटासेट (मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल हैं। इस डेटा पोर्टल तक पहुंच चरणबद्ध तरीके से विनियमित संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।

सतत वित्त के साथ मुद्दे और चुनौतियां

यहां मैं स्थायी वित्त के दायरे को बढ़ाने में एक चुनौती को चिह्नित करता हूं। दुनिया और विशेष रूप से भारत को संबंधित शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी मात्रा में धन की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन बाकू, अजरबैजान में हाल ही में संपन्न पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) 29 में पर्याप्त जलवायु संबंधी वित्त की उपलब्धता के बारे में गर्म बहस का विषय था, जिसमें दो मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था, पहला जलवायु संबंधी वित्त अभी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बातचीत करता है और दूसरा ईएमडीई प्राथमिकताएं अभी भी विकसित देशों के साथ संरेखित नहीं हैं। हालाँकि समझौते में ईएमडीईएस के लिये जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना करने का प्रस्ताव है, लेकिन यह ईएमडीईएस की उम्मीदों से कम हो गया। भारत सीओपी 26, इसके पंचामृत लक्ष्यों (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसीएस)) के लिये प्रतिबद्ध था। अनुमान है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 160 बिलियन अमरीकी डालर है।

स्थायी वित्त के प्रभावी प्रवाह के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई गुना चुनौतियां हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हरित या टिकाऊ परियोजनाओं/प्रस्तावों की अंतर्निहित जोखिम है। जलवायु जोखिम शमन में सबसे आगे हरित और टिकाऊ विकल्प की उपलब्धता होने जा रही है जिसके लिए काफी तकनीकी विकास की आवश्यकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि, हरित या टिकाऊ परियोजनाएं अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित होती हैं जो अभी तक स्थिर नहीं हुई हैं और मुख्यधारा में हैं, इन परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इससे पारंपरिक परियोजनाओं की तुलना में एक अंतर्निहित बढ़ा हुआ क्रेडिट जोखिम होता है।

इसके अलावा, जब टिकाऊ वित्त की बात आती है, तो हमारे जैसे देश में, शमन के अलावा, अनुकूलन के लिए संसाधनों का प्रवाह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बैंक योग्य परियोजनाओं को हमेशा क्रेडिट मिलता है, हालांकि आंशिक रूप से बैंक योग्य और गैर-बैंक योग्य परियोजनाओं के साथ समस्याएं हैं, जो आम तौर पर अनुकूलन से जुड़ी होती हैं। डेटा, ज्ञान और क्षमता अंतराल, तकनीकी और संस्थागत बाधाओं के रूप में कई मुद्दे अनुकूलन परियोजनाओं की उचित पहचान और विकास को सीमित करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय और निजी वित्त दोनों तक पहुंच को सीमित करता है। इस प्रकार, अनुकूलन वित्त को मुख्यधारा में लाने और विशिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े वित्त पोषण और सार्वजनिक निवेश से ऊपर उठने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

[9] भारतीय रिज़र्व बैंक - प्रेस प्रकाशनी (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58852).

[10] https://www.iea.org/commentaries/india-s-clean-energy-transition-is-rapidly-underway-benefiting-the-entire-world

सरकार टिकाऊ और जलवायु वित्त को बढ़ावा देने में भी सबसे आगे रही है, चाहे वह ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, पीएम-कुसुम, पीएम-सूर्यघर योजना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, लोंग-टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी (एलटी-एलईडीएस) आदि हो। सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित करके इन प्रयासों को और बढ़ाने तथा विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) की भूमिका सहित मिश्रित वित्त विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, अखंडता और प्रकटीकरण के साथ-साथ परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और संबंधित बाजार विफलताओं को संबोधित करने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। सामूहिक रूप से यह सोचने की आवश्यकता है कि नई और विकासशील प्रौद्योगिकियों को शामिल करने वाली स्थायी परियोजनाओं को वित्तीय प्रणाली को किसी भी स्पिल-ओवर जोखिम के अधीन किए बिना कैसे जोखिम से मुक्त किया जा सकता है। टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर अधिक गहन ध्यान देने की भी आवश्यकता है।

एक संबंधित क्षेत्र जो विभिन्न मंचों पर चर्चा के लिए आता है, वह हरित और टिकाऊ वित्त के क्षेत्र में विश्वसनीय परियोजनाओं की अनुपलब्धता है। इस संदर्भ में, सबसे पहले कॉर्पोरेट परियोजनाओं और एसएमई/एमएसएमई से संबंधित परियोजनाओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। एक स्थायी परियोजना एक नवीकरण बिजली परियोजना की स्थापना से लेकर घरों/फर्मों की छतों पर सौर प्रकाश की स्थापना जैसी कुछ हो सकती है। भारत तेजी से विकसित तकनीकी परिवर्तन का गवाह बन रहा है और अधिक से अधिक युवा समस्या समाधान के लिए उद्यमशीलता का मार्ग अपनाकर स्टार्ट-अप स्थापित कर रहे हैं। इस संदर्भ में, ऐसे तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और सतत विकास में योगदान दिया है। हमें एक हरित और टिकाऊ परिसंपत्ति भंडार के निर्माण पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है जो वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामलों को प्रदर्शित करेगा।

अन्य क्षेत्रीय घरेलू निवेश आवश्यकताओं के अलावा, स्थायी वित्त के लिए आवश्यक वित्त पोषण की मात्रा को देखते हुए, जलवायु न्यूनीकरण और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त निधियों का लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता है। दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इस प्रक्रिया में महान समर्थकों के रूप में कार्य कर सकते हैं - एक पारदर्शिता और दूसरा क्षमता निर्माण। प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता, और पर्याप्त क्षमता निर्माण दाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों को शामिल जोखिमों का आकलन करने और तदनुसार धन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करेगा। पारदर्शिता और प्रकटीकरण के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने और स्थायी वित्त के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। इन संस्थागत क्षमताओं का लाभ वित्तीय संस्थानों और सरकारी मशीनरी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है और स्थायी वित्त से संबंधित वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संगठनों, डीएफआई और एमडीबी के साथ एक पुल के रूप में कार्य किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन जोखिमों ने वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और आने वाले भविष्य में प्रणालीगत जोखिम पैदा करने की परिकल्पना की गई है। वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों के साथ जलवायु-विशिष्ट कमजोरियों की परस्पर क्रिया वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा कर सकती है। इस संदर्भ में, इन जोखिमों का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने और उपयुक्त अनुकूलन और शमन उपायों को लागू करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है। पारदर्शिता और क्षमता निर्माण प्रमुख अंतर होने जा रहे हैं और हमें सामूहिक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास और पर्यावरण के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान करने में सक्षम होंगे।

धन्यवाद।

आरबीआई: 90 वर्षों की विरासत, विनियमन और आकांक्षा पर एक दृष्टि*

श्री एम. राजेश्वर राव

केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित प्रतिभागी, देवियों और सज्जनों,

अपनी स्थापना के 90 वर्ष मनाए जाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित 'सहक्रियाओं का निर्माण' विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मेलन एक सार्थक संवाद विकसित करने और ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाले मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास का एक हिस्सा है। आज मुझे आपके बीच अब तक तय किए गए रास्तों और नियामकों के रूप में आगे बढ़ते समय पेश आने वाली कुछ संभावित चुनौतियों के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

इस वर्ष बैंकिंग प्रणाली के औपचारिक नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में हमारी यात्रा के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधिनियमन से आगे बढ़ा था। पीछे मुड़कर देखें, तो नियामक शक्तियों का औपचारिकीकरण 1930 के दशक के मध्य और 1940 के दशक की शुरुआत में वाणिज्यिक बैंकों की बड़े पैमाने पर विफलताओं और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए उस बिंदु पर आवश्यक कार्यों की अगली कड़ी थी। इस प्रकार विनियामक दृष्टिकोण को ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा आंशिक रूप से अनुकूलित किया गया और आकार दिया गया है, जो भारतीय विकास की कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

अतीत का अवलोकन[1]

जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई भारत के ऐसे बहुत कम संस्थानों में से एक है जो स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में आया था और स्वतंत्रता से पहले और बाद के युग में फैला हुआ है। अपने प्रारंभिक वर्षों में आरबीआई के प्रमुख कार्य मुद्रा के मुद्दे को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए भंडार बनाए रखना और देश के लाभ के लिए क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना था।

यहां तक कि जब आरबीआई मुद्रा और आरक्षित निधि प्रबंधन के अपने निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने में शामिल था, 1930 और 40 के दशक की अवधि में किसी भी ठोस नियामक क्षेत्राधिकार या प्राधिकरण के अभाव में बड़ी संख्या में बैंक विफलताएं देखी गईं। मोटे अनुमानों के अनुसार, 1940 के दशक के दौरान भारत में 570 से अधिक बैंक विफल हुए। इस परिवेश में, भारतीय संसद ने बैंकों पर आरबीआई को नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां प्रदान करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम ('बीआर अधिनियम'), 1949 अधिनियमित किया। बीआर अधिनियम के साथ मिलकर आरबीआई अधिनियम की कानूनी संरचना ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को एक ठोस वैधानिक आधार प्रदान किया। इसने आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में संस्थानों के अवांछित रूप से बढ़ने को नियंत्रित करने का भी अधिकार दिया। इसलिए, बीआर अधिनियम के अधिनियमन को भारतीय वित्तीय प्रणाली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक माना जा सकता है।

1950 के दशक के दौरान बैंकों के समेकन पर विनियामकीय ध्यान जारी रहा, जबकि 1960 के दशक ने संस्था निर्माण के प्रयासों को बल दिया, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई को सशक्त बनाने के लिए 1960 में विधायी संशोधन लागू किए गए थे, जिसके कारण अगले कुछ दशकों में 200 से अधिक बैंकों का पुनर्निर्माण और समेकन हुआ, और लगातार बैंक विफलताओं की घटनाएँ इतिहास की घटनाएं बन गईं। विनियामक क्षेत्राधिकार के दायरे को व्यापक बनाते हुए, आरबीआई को इस चरण के दौरान गैर-बैंक संस्थाओं की जमा स्वीकार करने वाली गतिविधियों और सहकारी बैंकिंग प्रणाली के संचालन को विनियमित करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया गया। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, 1969 में (और बाद में 1980 में) प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अगले कुछ दशकों में भारत में वित्त और वित्तीय संस्थानों तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें लीड बैंक योजना शुरू की गई,

* श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर द्वारा 22 नवंबर, 2024 को मुंबई, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने 90वें वर्ष के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित "ग्लोबल साउथ में केंद्रीय बैंकों के उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन" में दी गई प्रारंभिक टिप्पणी। खबीर अहमद और सौरभ प्रताप सिंह द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

[1] आरबीआई इतिहास-कालक्रम घटनाओं से प्राप्त जानकारी।

[2] अध्याय 12: संकट, समेकन और विकास, आरबीआई इतिहास, खंड- II (1951-67)।

[3] आरबीआई इतिहास-घटनाक्रम का कालक्रम: 1960 से 1971।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए मानदंडों का विकास, शाखा नेटवर्क का विस्तार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया।

उसी प्रगतिशील भावना के साथ, 1990 के दशक में विभिन्न सुधार हुए जिन्होंने आधुनिक लचीले वित्तीय क्षेत्र की नींव रखी जैसा कि हम आज देखते हैं। 1991 में उदारीकरण सुधारों के बाद, उद्योग में दो प्रमुख विकास हुए। पहला, निजी क्षेत्र के लिए बैंकिंग क्षेत्र खोलने के लिए 1993 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि वित्तीय सेवाओं के वितरण और मूल्य निर्धारण में दक्षता में सुधार किया जा सके और दूसरा, 1997 में एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय पेश किया गया था, जिसमें आरबीआई को एनबीएफसी को विनियमित करने और उनके लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानकों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। इन दो उपायों ने वित्तीय क्षेत्र को 21वीं सदी की आगामी चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान किया।

पिछले दशक में भारत में विभेदित बैंकिंग का विकास देखा गया है, जिसमें लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक जैसे संस्थानों की कई अनूठी श्रेणियां क्षितिज पर उभर रही हैं। बहुत जीवंत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान और सहकारी बैंकिंग के साथ बैंकिंग प्रणाली के विकास ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ावा दिया है। उनके पैमाने के बारे में कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी की संपत्ति 31 मार्च, 2024 तक क्रमशः लगभग ₹280 ट्रिलियन और ₹50 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया बकाया ऋण लगभग ₹205 ट्रिलियन है।

वित्तीय संस्थानों के इस व्यापक नेटवर्क ने हमारे देश में वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद की है, जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता को मापने वाले वित्तीय समावेशन सूचकांक में निरंतर वृद्धि से परिलक्षित होता है। एक और क्रांति जो हुई है वह डिजिटल क्षेत्र में है। आज, डिजिटल भुगतान आधारभूत ढांचा ₹2400 ट्रिलियन (वित्त वर्ष 2023-24) से अधिक मूल्य के लिए एक वर्ष में 160 बिलियन से अधिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। खुदरा डिजिटल लेनदेन का मूल्य ₹720 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से लगभग 265 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को अकेले स्वदेशी यूपीआई और आईएमपीएस के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। ये डेटा बिंदु हमें उस यात्रा की एक झलक देते हैं जो हमने अपेक्षाकृत मामूली शुरुआत से लेकर एक विश्व में अग्रणी होने तक की यात्रा की है, विशेष रूप से डिजिटलीकरण में।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सक्रिय रूप से विनियामक नीतिगत उपायों का अनुसरण किया है जिनमें प्रमुख नीतिगत मानकों को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंशांकन की मांग की गई है। जिसमें बाद वाले को शहरी सहकारी बैंकों के लिए तैयार किए गए सिद्धांत-आधारित/ गतिविधि-आधारित विनियमों के मिश्रण द्वारा चित्रित किया गया है जहां नियामक मानदंड सहकारी बैंकों के स्तर-वार वर्गीकरण पर आधारित हैं; एनबीएफसी के लिए एक पैमाना आधारित विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है ताकि उन्हें उनके संचालन के पैमाने और परस्पर जुड़ाव की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके; और एमएफआई क्षेत्र के लिए मानदंड। हमारे नीतिगत ढांचे के एक भाग के रूप में, हम विनियमन के प्रति 'ट्विन-पीक दृष्टिकोण' का पालन कर रहे हैं, विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी दोनों मुद्दों को महत्व देते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, बैंकों को व्यापक क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रथाओं द्वारा समर्थित मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। संस्थानों को अपने विकास में विवेक सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट गुणवत्ता और तरलता जैसे मानकों का अनुपालन करना होगा।

आचरण संबंधी पहलुओं से जुड़ी चुनौतियां समान रूप से संवेदनशील हैं। जब प्रणाली अधिक जटिल हो जाती है, तो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं भी उपयुक्त रूप से विकसित होती हैं। इसलिए, विनियमित संस्थाओं को अपेक्षाओं के एक मुश्किल चतुर्थांश का प्रबंधन करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है तेजी से डिजिटलीकरण को सक्षम करना; मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को बढ़ाना; मजबूत केवाईसी मानदंड सुनिश्चित करना; और महत्वपूर्ण रूप से ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता बनाए रखना।

इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शासन में सुधार लाने और हमारी विनियमित संस्थाओं के आचरण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ विनियामक उपाय किए हैं। उचित उधार प्रथाओं से संबंधित दिशानिर्देश, बैंकों से संबंधित शासन मुद्दों पर दिशानिर्देश जैसे बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली, उत्तराधिकार योजना और पारिश्रमिक के अभिशासन ढांचे को

[4] पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई सीआईएमएस; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का खाद्य और गैर-खाद्य ऋण।

सुदृढ़ करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उधारकर्ताओं को सुविज्ञ निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक शुल्कों और प्रभारों के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाकर उधार और उधार प्रभारों में पारदर्शिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैसा कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि अतीत में शुरू किए गए नियामक विकास और नीतिगत उपायों ने भारत में एक लचीली और मजबूत वित्तीय प्रणाली का विकास किया है जिसने कई संकटों का सामना किया है। लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए हमारे जो लक्ष्य हैं, उनके लिए हमें वित्तीय संस्थानों के पैमाने और आकार में एक लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता है। यह संभवतः संस्थाओं और उसके उपयोगकर्ताओं को जोखिम की बढ़ी हुई मात्रा में भी उजागर करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मजबूत शासन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन, दोहरे आधार होने जा रहे हैं जो हमारे वित्तीय संस्थानों को बचाए रखेंगे और उन्हें स्थायी रूप से बढ़ने में मदद करेंगे। वृहद परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा को अभी भी एक जटिल और तेजी से विकसित वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय संस्थानों की मजबूत नींव की आवश्यकता है। बैंकों के अलावा, मौजूदा संस्थाओं को अपनी बढ़ती परिसंपत्ति को निधि देने के लिए मजबूत पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच की आवश्यकता होगी, साथ ही गहरे वित्तीय बाजारों तक पहुंच होगी जो उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर संबंधित जोखिमों को हेज करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, बढ़ती क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए नए खिलाड़ियों, उत्पादों और सेवाओं (जैसे निजी ऋण) का प्रवेश होगा। इसलिए, इन चुनौतियों का सामना करने और नवाचार की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए एक सक्षम नियामक प्रणाली स्थापित करनी होगी।

भविष्य की कल्पना

हाल ही में भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित विकास और लचीलापन इस गति को जारी रखने के लिए हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है ताकि हमारी विकास आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। यह अपेक्षा तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास उभरती चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक नियामक के रूप में लचीलापन बनाए रखते हुए भी उनका अनुमान लगाने की आवश्यक क्षमता हो। इस संदर्भ में मैं ऐसे तीन उभरते जोखिमों को रेखांकित करना चाहूंगा जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए प्रासंगिक हैं।

(i) चरम जलवायु घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से जोखिम: बहुत समय पहले, जलवायु संबंधी जोखिम के बारे में चर्चा अधिकतर एक बौद्धिक प्रवचन होती थी। लेकिन चीजें बदल गई हैं! चरम मौसम की स्थिति, गर्मी के लंबे दौर और असमान मानसून ने नीति निर्माताओं को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आज, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच जलवायु जोखिमों पर भौतिक और संक्रमणकालीन दोनों तरह के विस्तार से चर्चा करता है और संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श करता है। अनुकूलन जोखिमों को भी चिह्नित किया जा रहा है। एक नीति निर्माता के रूप में, जलवायु संबंधी जोखिमों और वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव को मापना अभी भी एक चुनौती है। भौतिक, संक्रमण और अनुकूलन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए वास्तविक क्षेत्र की संस्थाओं को निधि देने के लिए संसाधनों की मांग का मतलब नए संस्थान, संसाधनों की नई श्रेणियां और मौजूदा संस्थानों के बीच नए व्यापार मॉडल हो सकते हैं। नियामकों के लिए ये नई चुनौती होगी।

(ii) उभरती प्रौद्योगिकियों से जोखिम: दुनिया में हुआ सबसे बड़ा विघटनकारी परिवर्तन प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इसने निश्चित रूप से अभूतपूर्व तरीकों से हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसने एक संपूर्ण ईकोसिस्टम का विकास भी किया है जो इस बड़े पैमाने पर आउटरीच पर पनपता है। ब्लॉक-चेन, और एआई/एमएल द्वारा समर्थित नई प्रक्रियाओं के आगमन, टोकनयुक्त संपत्ति जैसे नए उत्पाद, और बिगटेक/फिनटेक जैसी नई संस्थाओं ने नीति निर्माताओं को सदैव तैयार रहने के लिए मजबूर किया है। हम ऐसी प्रगतिशील प्रथाओं को दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार नवोन्मेष और विवेक के बीच संतुलन खोजने की खोज एक चुनौती होने जा रही है।

(iii) गैर-बैंकिंग क्षेत्र में लचीलापन: भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व, आकार और पैमाने को

देखते हुए, हम किसी भी संभावित मध्यस्थता से बचने के लिए उनके लिए नियामक दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, भारत में गैर-बैंकिंग क्षेत्र में केवल एनबीएफसी की तुलना में बहुत सारी विविध संस्थाएं शामिल हैं और, वित्तीय प्रणाली में जटिलता को देखते हुए, ऐसी सभी संस्थाओं के बीच परस्पर संबंध अधिक गहरा हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है।.

निष्कर्ष

दुनिया में ऐसे बहुत कम केंद्रीय बैंक हैं जिनका अधिदेश आरबीआई जितना व्यापक है। हम मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण, भुगतान प्रणाली, वित्तीय समावेशन, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन आदि जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में फैले अधिदेश के साथ एक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस विशाल जिम्मेदारी के बावजूद, आरबीआई के अस्तित्व के नौ शानदार दशकों और नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में हमारे 75 वर्षों के अनुभव ने एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र की नींव बनाई है जो देश की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है।

मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए और इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को और आयोजन टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना**

श्री स्वामीनाथन जे.

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री सुमन रे; नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री सचिन शेंडे; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मुख्य महाप्रबंधक, सुश्री रश्मि दराद; बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और एसएलबीसी महाराष्ट्र के संयोजक, श्री आर.डी. देशमुख; बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) और यहां उपस्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे साथी-गण।

सुप्रभात, आज मुझे महाराष्ट्र के अग्रणी जिला प्रबंधकों के इस सम्मेलन को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

नागपुर के पास आकर और वह भी एलडीएम के सम्मेलन के लिए यहाँ होने के कारण, अगर मुझे श्री बाबा आमटे की याद न आए, जिनका आश्रम कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह अनुचित होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था-संचालित संवृद्धि के समर्थकों में से एक थे। उनके लिए एक उद्धरण का यह अंश है, जो कहता है, *"एक संतुलित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें सभी के लिए पर्याप्तता और कुछ के लिए आधिक्य होता है..."*

जब आप इस उद्धरण का विश्लेषण करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि एलडीएम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पर्याप्तता को सुगम बना रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्तता को सुगम बनाकर अर्थव्यवस्था को संतुलित करना आज भी उतना ही सच है जितना तब रहा होगा जब यह कथन कहा गया था। जब आप आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 के परिणामों को देखते हैं, तो यह पाया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है।[1]

इसलिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के साथ, लीड बैंकों की भूमिका पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। दरअसल, आरबीआई ने आरबीआई@100[2] के लिए बहु-वर्षीय समय-सीमा में जो आकांक्षात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे *'समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और गुणवत्ता'* पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह वह अंतर्निहित सिद्धांत है जिसने वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना (लीड बैंक स्कीम - एलबीएस) की संकल्पना की थी। अग्रणी बैंक से यह अपेक्षा है कि वह ऋण संस्थाओं और सरकार के प्रयासों के समन्वय के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाए। और इस नेतृत्व की भूमिका के अंतर्गत, एलडीएम की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता।

एलबीएस ढांचे के प्रमुख स्तंभों के रूप में, आपके पास अल्प-सेवित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने और ऋण तक पहुँच प्रदान करने, आर्थिक उन्नति को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी है, जिसके परिणाम व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद हो सकते हैं। तेलंगाना में एसएलबीसी के संयोजक के रूप में कार्य करने के बाद, मैं एलबीएस मंच के माध्यम से जनित वास्तविक प्रभाव से प्राप्त गहन संतुष्टि की पुष्टि कर सकता हूं।

पिछले कुछ वर्षों में एलडीएम की भूमिका और जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। लेकिन इन असंख्य उद्देश्यों की बुनियाद वही है। आज मैं एलडीएम के कामकाज से हमारी कुछ अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आसानी से याद रखने के लिए, मैंने संक्षिप्त नाम - एलडीएम - को एक अलग रूप देने का प्रयास किया है और तीन विशेषताओं की पहचान की है, यथा **(एल/L) संपर्क, (डी/D) डिजाइनिंग और विकास, और (एम/M) निगरानी और प्रेरणा।** अब मैं इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

संपर्क

संपर्क/मेल-जोल का कार्य अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत से ही निहित है। स्वतंत्रता के बाद समावेशी विकास की ओर भारत की यात्रा को गरीबी कम करने और जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों द्वारा आकार दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य

* 30 नवंबर 2024 को ताडोबा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में आयोजित महाराष्ट्र के अग्रणी जिला प्रबंधकों के सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का बीज वक्तव्य।

[1] आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

[2] गवर्नर का वक्तव्य: 7 जून 2024।

सेवा और स्वच्छता जैसी अत्यावश्यक सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना, साथ ही उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करना, इन प्रयासों का केंद्र रहा है। यह बात सुनिश्चित करने पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर खड़े समूहों तक पहुँचे। अपने मूल में, एलबीएस ढांचा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवा तक पहुँच में सुधार होता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है।

एलबीएस तंत्र की पहुँच उधारकर्ता स्तर से शुरू होकर सीधे राज्य तक है। और नोडल निकाय के रूप में कार्य करने में एलडीएम का कर्तव्य माइल-टू-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, उन्हें नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों और आरबीआई के अग्रणी जिला अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करके, बैंकिंग-रहित केंद्रों की जानकारी एकत्र करने, ऋण प्रवाह के संबंध में बाधाओं या अंतरालों की पहचान करने के लिए आरंभिक स्तर पर समन्वय करना पड़ सकता है। इसके लिए एक स्व-चालित प्रणाली का होना आवश्यक है, जिसमें जिला परामर्शदात्री समितियों से लेकर एसएलबीसी तक की विभिन्न बैठकें प्रभावी ढंग से और समय पर आयोजित हों। इस प्रकार, एलडीएम की भूमिका का एक महत्वपूर्ण गुण जमीनी स्तर पर प्रभावी संपर्क है।

डिजाइन और विकास

डिजाइन और विकास का पहलू, ऋण योजनाओं से शुरू होता है। ऋण नियोजन को केंद्र की आवश्यकताओं को बताने के लिए अधरोर्ध्व (bottom-up) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त योजना तैयार करनी चाहिए। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जबकि लक्ष्य विचारों में आकांक्षापूर्ण होने चाहिए, वे कार्यान्वयन के स्वरूप में पर्याप्त यथार्थवादी होने चाहिए और स्थानीय ऋण आवश्यकताएं प्रतिबिंबित करने चाहिए।

इसके अलावा, डेटा और विश्लेषणात्मक मॉडलों की प्रचुरता के इस युग में, ऋण योजना के डिजाइन के लिए डेटा-आधारित अनुभवजन्य दृष्टिकोण आवश्यक है। ऐसी तकनीकें हस्तक्षेप के लिए लक्षित रणनीतियों को विकसित करने में आसानी प्रदान करती हैं। ऐसा कहने के बाद, डेटा संग्रह का प्राथमिक चरण क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से होना चाहिए और इसे केवल अकादमिक समझ से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। क्षेत्र सर्वेक्षण उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी सक्षम बनाता है जिन्हें ऋण प्रवाह की अधिक आवश्यकता है और जिनके पास ऋण सेवा की बेहतर क्षमता है। यह वह आधार होना चाहिए जिस पर आप बैंक योग्य योजनाएँ तैयार करते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अभी भी औपचारिक ऋण से जोड़ा जाना बाकी है, और लघु और सीमांत किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक वित्तपोषण तक पहुंच से वंचित है। संभावित उधारकर्ताओं का एक और वर्ग जो अल्प-सेवित रह गया है, वह है एमएसएमई और उसके भी भीतर, महिलाओं द्वारा संचालित। इसलिए, जब हम क्रेडिट प्लान के डिजाइन के लिए आपके व्यावहारिक अनुभव के साथ एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को उपयुक्त संभाव्यता-युक्त ऋण आयोजना के साथ-साथ ब्लॉक और जिला-स्तरीय क्रेडिट रणनीतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। विचार यह है कि आप अपनी योजनाओं को जिले के समग्र मूल्यांकन पर आधारित करें। अंतिम उद्देश्य क्रेडिट योजनाओं के व्यवस्थित डिजाइन के माध्यम से मापने योग्य परिणाम लाना है।

निगरानी और प्रेरणा

'एलडीएम' विशेषताओं का 'एम' निगरानी और प्रेरणा को दर्शाता है। वास्तव में, निगरानी वाला हिस्सा एलडीएम के निर्धारित कर्तव्यों में समाहित है। सरकारी विभागों और ब्लॉकों के बीच संपर्क होने के नाते, वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) और विभिन्न कार्यक्रमों के आरंभिक स्तर पर कार्यान्वयन की सफलता को संप्रेषित करने की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी एक प्रभावी निगरानी तंत्र पर टिकी हुई है। इससे ऋण के प्रवाह में आने वाली समस्याओं या बाधाओं की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जिसे लक्षित मध्यक्षेपों के लिए ऋण योजनाओं को तैयार करते समय उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।

आपके पास जिला स्तर से लेकर राज्य सरकार, एसएलबीसी या एसएलसीसी तक निगरानी तंत्र की पूरी मशीनरी है। प्रत्येक स्तर पर निगरानी की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की समीक्षा करते हैं और फिर सही चैनल के माध्यम से संचार करते हैं। अपनी कार्य-पद्धति में, मैं हमेशा 'समाधान करने' पर जोर देता हूं। संभवतः आप भी एक ऐसी ही उपयुक्त प्रणाली विकसित कर सकते हैं, जिसमें आपकी निगरानी

आवश्यक संचार के माध्यम से आगे बढ़े और उचित स्तर पर समस्या का अंततः समाधान हो।

अब मैं विशेषताओं के प्रेरक भाग पर आता हूँ। मेरा इससे तात्पर्य है, एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ में 'प्रेरक'। एलडीएम को वित्तीय साक्षरता को और बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, आप भी जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं और डिजिटल वित्तीय समावेशन को और अधिक अपनाने के लिए निर्देशित या प्रेरित कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता समग्र समावेशन की आधारशिला है, जो व्यक्तियों को सुविचारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है।

आम लोगों को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, चाहे वह बीमा और पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा उत्पाद हों, जो जोखिमों को कवर करेंगे, या श्रेणी-विशिष्ट ऋण उत्पाद जो उन्हें उत्पादक आर्थिक गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाएंगे। डिजिटल लेन-देन करने में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अकेले महाराष्ट्र में ही वित्तीय साक्षरता के लिए 118 केंद्र (सीएफएल) और 61 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जो आधारभूत स्तर पर वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। एलडीएम को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि एफएलसी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करें, सीएफएल का समर्थन करें, सीएफएल शिविरों में भाग लें और इन शिविरों के उचित संचालन की देखरेख करते हुए वित्तीय सेवाओं के जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल हमारी पहुंच का विस्तार करता है बल्कि बैंकिंग को अधिक सुलभ, दक्ष और किफायती बनाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और पायलट पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) सहित डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई का हालिया जोर, जिसे अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) नाम दिया गया है, डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ऋण तक पहुंच को सरल और व्यापक बनाना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

आपको यह भी विदित होगा कि 'एक्सपैंडिंग एंड डीपेनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम प्रोग्राम (ईडीडीपीई)' के तहत, एसएलबीसी ने देश के हर जिले को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ है। मुझे यह जानकर ख़ुशी हुई कि आज की तारीख में, देश भर में 410 जिले डिजिटल रूप से सक्षम हैं तथा इस पहल के तहत 13 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत जिलों को कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही महाराष्ट्र राज्य भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। इसके लिए, मैं एलडीएम सहित सभी हितधारकों से कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय का अनुरोध करता हूं।

एक और पहलू जिस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वह है संधारणीय वित्तपोषण का मुद्दा। हम सभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में सुन रहे हैं और वित्तीय संस्थाएँ इससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए किस तरह से कमर कस रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का एक मुख्य बिंदु - संधारणीय वित्तपोषण है। वर्तमान परिवेश में, हमें ऐसे वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो संधारणीय और जलवायु-सुदृढ़ प्रथाओं का समर्थन करता हो, ताकि जलवायु जोखिमों को कम किया जा सके और महत्वपूर्ण आजीविका की रक्षा की जा सके। इन परिवर्तनों को साकार करने के लिए कृषि और ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना में अधिक अवसर हैं। बुनियादी स्तर पर काम करने के स्वरूप, आपके पास देश को हरित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को प्रेरित करने का मंच है।

निष्कर्ष

सम्मेलन का विषय है *'समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना'।* एलडीएम अपनी भूमिका के अनुसार, विभिन्न स्तरों - ब्लॉक, जिला और राज्य - पर आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एक निर्बाध कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

पिछले कुछ दशकों में, एलबीएस भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप विकसित हुई है। अपने मूल में, एलबीएस ढांचा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग अभिगम में सुधार होता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है। इस संबंध में, हम पहले ही एलडीएम की भूमिका को विस्तार से परिभाषित कर चुके हैं। आज मैंने जिन 'एलडीएम' विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, वे इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें लागू करने का एक प्रयास हैं।

हम आज यहां ताडोबा अभ्यारण्य में हैं। यदि मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, तो एलबीएस के पीछे का उद्देश्य एक तरह का आर्थिक अभ्यारण्य बनाना भी है, जिसमें संसाधनों को अल्प-सेवित और हाशिए पर खड़े लोगों की ओर प्रवाहित किया जाता है और असुरक्षित लोगों की रक्षा की जाती है। और अगर मैं इस उदाहरण को आगे बढ़ाऊँ, तो एलडीएम वन्यजीव रेंजरों के समतुल्य हैं।

मुझे यकीन है कि आपको यह सम्मेलन उपयोगी लगा होगा, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस मंच का लाभ उठाकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करें और अपने जिलों और महाराष्ट्र राज्य तथा इस प्रकार देश की निरंतर प्रगति के लिए अधिक-से-अधिक विचार एकत्र करें। मैं आपके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और इस अवसर के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद।

उभरते जोखिमों के मध्य पर्यवेक्षण*

श्री स्वामीनाथन जे.

दुनिया भर से आए सम्मानित प्रतिनिधिगण, आदरणीय गवर्नर महोदय, उप गवर्नर-गण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सभी सहकर्मीगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार।

वास्तव में, मेरे लिए इस प्रतिष्ठित पैनल के समक्ष उद्घाटन भाषण देना सम्मान की बात है, जिसमें जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. जॉन मुशायावन्हू, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री एस.एस.मूंदड़ा, आईएमएफ के मौद्रिक और पूंजी बाजार विभाग के वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन प्रभाग के प्रभाग प्रमुख श्री जय सुरती, ई एंड वाई में साइबर सुरक्षा के भागीदार श्री कृष्ण शास्त्री पेंड्याला और पैनल के संचालक, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू शामिल हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी, जैसा कि हम आज समझते हैं, एक अपेक्षाकृत हालिया विकास घटनाक्रम है - लगभग पचास वर्ष पहले की बात है[1]। हालाँकि, बैंकों की निगरानी की अवधारणा केंद्रीय बैंकिंग की नींव में ही अंतर्निहित है। शुरुआती दिनों से, केंद्रीय बैंकों ने अंतिम ऋणदाता के रूप में अपनी भूमिका निभायी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय संस्थाएं शोधक्षम बनी रहें और प्रणालीगत संकटों से सुरक्षित रहें। वास्तव में, पर्यवेक्षण वह आधारशिला[2] रहा है जिसने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करके और इस तरह बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को बढ़ावा देकर वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता का समर्थन किया है।

जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही है, वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाले जोखिमों की प्रकृति भी बदल रही है। प्रौद्योगिकीय उन्नति से अविश्वसनीय दक्षता तो हासिल हुई है, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के खतरे और तीसरे पक्ष की निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम जैसी महत्वपूर्ण असुरक्षाएँ भी देखने को मिलती हैं।

जलवायु परिवर्तन, जिसे कभी दूरगामी चिंता माना जाता था, अब संस्थाओं और अर्थव्यवस्थाओं के लिए तत्काल और भौतिक जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अस्थिर बाजारों और बदलते समष्टि-आर्थिक रुझानों की जटिलताएं भी हैं। इस प्रकार, पर्यवेक्षण का कार्य पहले से कहीं अधिक गतिशील और महत्वपूर्ण हो गया है।

इसलिए, पर्यवेक्षण को समय के साथ विकसित करने की आवश्यकता है और अब इसका मतलब महज अनुपालन लागू करना नहीं रह गया है। इसके बजाय, इसे जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित, दोनों तरह के जोखिमों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने और वित्तीय प्रणाली में समुत्थानशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कुछ समय दें कि समुत्थानशीलता (रेज़िलिएन्स) का क्या अर्थ है। जहां स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रणाली अपनी कार्य करने की क्षमता गवाएँ बिना आघातों का सामना कर सकती है, समुत्थानशीलता एक कदम आगे जाती है। समुत्थानशीलता यह दर्शाती है कि वित्तीय प्रणाली झंझावात का सामना करने के अलावा, नई परिस्थितियों के अनुकूल बदलने और उसमें पनपने में सक्षम है[3], ताकि यह विश्वास और स्थिरता की द्योतक बनी रहे।

वित्तीय सुदृढ़ता विकसित करने के लिए पर्यवेक्षण सक्रिय, निरंतर, दूरदर्शी और जोखिम-केंद्रित होना चाहिए। एक प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली के लिए पर्यवेक्षक को प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का निरंतर, दूरदर्शी मूल्यांकन बनाए रखने की आवश्यकता होती है[4] - जो उनके प्रणालीगत महत्व के साथ संरेखित होता है। पर्यवेक्षकों को एकल संस्थाओं और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्पष्ट आकस्मिक योजनाओं के लिए एक भली-भांति परिभाषित रूपरेखा का होना भी शामिल है ताकि गैर-व्यवहार्य बैंकों का सुव्यवस्थित और

* 22 नवंबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का उद्घाटन भाषण।

1 मास्कियांडारो , डी एंड एम क्विंटिन (2013) “दि इवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन: द कंटीन्यूइंग सर्च फॉर द होली ग्रेल”, एसयूईआरएफ 50वीं वर्षगांठ खंड अध्याय: 263-318 ।

2 कीस्टोन, मेहराब के शिखर पर स्थित खूँटे (वेज) के आकार का टुकड़ा होता है जो अन्य टुकड़ों को अपनी जगह पर लॉक करता है।

3 मैरी डॉवेल-जोन्स और रॉस बकले, रीकंसीविंग रेजिलिएंस: ए न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन?, 37 न्यू. जे. इंटरनेशनल एल. एंड बिजनेस 1 (2017)। http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss1/।

4 *सिद्धांत 8: बासेल मूल सिद्धांतों के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण की एक प्रभावी प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक भविष्योन्मुख मूल्यांकन विकसित करे और उसे बनाए रखे, जो उसके प्रणालीगत महत्व के अनुपात में हो; बैंकों और समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान करे, उनका आकलन करे और उनका समाधान करे; समयपूर्व हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा तैयार करे; और अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों के साथ साझेदारी में, बैंकों के अव्यवहार्य हो जाने पर उनका सुव्यवस्थित तरीके से समाधान करने के लिए कार्रवाई करने की योजनाएं बनाए।*

कुशल तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए, पर्यवेक्षकों के पास आवश्यकतानुसार तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।

हाल के वर्षों में, हमने इस उद्देश्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। हमारी पर्यवेक्षी पहलों का उद्देश्य जोखिमों और असुरक्षाओं की समयपूर्व पहचान करना है, और इन जोखिमों को कम करने के लिए समयपूर्व हस्तक्षेप के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना है। हमने अपना ध्यान केवल असुरक्षाओं के लक्षणों को संबोधित करने से हटाकर उनके मूल कारणों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर केंद्रित कर दिया है, साथ ही वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षी कठोरता को सुसंगत बनाया है।

हमने एक सुविचारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण तैयार किया है और उसे लागू किया है, जो उच्च जोखिम वाली संस्थाओं और प्रथाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक लचीलापन और मापनीयता प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी तंत्र है जो हमें उभरते जोखिमों का पता लगाने और पर्यवेक्षित संस्थाओं में कमजोरियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिससे इन जोखिमों को बढ़ने से पहले कम करने या प्रबंधित करने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

अपनी पर्यवेक्षी क्षमता को और मजबूत करने के लिए, हम 'कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स' जैसी पहलों में भी निवेश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारे पर्यवेक्षी कर्मचारियों के कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाना है। क्षमता निर्माण के अतिरिक्त, हम पर्यवेक्षित संस्थाओं के भीतर जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बेहतर बनाने पर अपने प्रयासों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये संस्थाएं न केवल विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि सभी स्तरों पर जोखिम और अनुपालन के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, मजबूत दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती हैं।

जबकि पर्यवेक्षकों के रूप में हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, यहाँ चार्ल्स गुडहार्ट का कथन याद करना सार्थक हो सकता है -*"पर्यवेक्षण के संचालन में सराहना का स्थान नहीं है (थैंकलेस जॉब), जिसमें पर्यवेक्षक की प्रतिष्ठा धूमिल होने की बहुत अधिक संभावना है। एक पर्यवेक्षक के लिए सबसे अच्छी उम्मीद यह है कि कुछ भी अप्रिय न घटे। पर्यवेक्षकों पर केवल तभी ध्यान दिया जाता है जब उनके कार्यों से विनियमित संस्थाएं नाराज होती हैं, चाहे प्रतिबंधात्मक या दखलंदाजी उपायों के माध्यम से, या जब किसी विफलता के बाद उनकी आलोचना की जाती है, जैसे कि किसी वित्तीय संस्थान का पतन या ग्राहक को नुकसान पहुँचने पर। संस्थाओं को विफल होने के कगार पर कुछ छूट देने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के बावजूद, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पर्यवेक्षकों को अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रेस का सामना करना पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों।"*

जैसा भी हो, निष्कर्ष यह है कि पर्यवेक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक भी है। पर्यवेक्षकों के रूप में, यह हमारी सतर्कता, सक्रिय उपायों और पर्यवेक्षी ढांचे के निरंतर बदलते स्वरूप के माध्यम से है कि हम एक ऐसा वित्तीय वातावरण बना सकते हैं जहाँ संस्थाएँ महज जीवित न रहें बल्कि उभरते जोखिमों के बाद भी पनपती रहें।

अगले दशक के लिए हमारे विज़न, आरबीआई@100 के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य 'ग्लोबल साउथ' के केंद्रीय बैंकों के साथ और अधिक संबंध स्थापित करना है। हम जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण का एक वैश्विक मॉडल स्थापित करने के लिए समर्पित हैं, जो मजबूत जोखिम निर्धारण और अनुपालन संस्कृति पर जोर देता है, और एक "दीर्घकालिक" जोखिम मूल्यांकन ढांचा बनाता है। इसके अतिरिक्त, हम अपने पर्यवेक्षी कार्यों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत डेटा विश्लेषण पारितंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा दृष्टिकोण तेजी से बदलती दुनिया में दूरदर्शी और दक्ष बना रहे।

इन विचारों के साथ, मैं एक चित्ताकर्षक और अंतर्दृष्टिपूर्ण पैनल चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसमें उभरते जोखिमों के संदर्भ में पर्यवेक्षण की बदलती भूमिका का पता लगाया जाएगा।

धन्यवाद!

[5] गुडहार्ट, सी.ए.ई. (2000)। बैंकिंग पर्यवेक्षण का संगठनात्मक ढांचा। एफएसआई सामयिक पत्र, वित्तीय स्थिरता संस्थान, संख्या 1, नवंबर। पृष्ठ 20-21। https://www.bis.org/fsi/fsipapers01.pdf. पर उपलब्ध।

*एमएसएमई - ऋण देने में विश्वास बढ़ाकर ऋण अंतर को पाटना**

श्री स्वामीनाथन जे.

श्री सुरेश कुमार सिंघल, अध्यक्ष एफटीसीसीआई, श्री आर. रवि कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एफटीसीसीआई, श्री के. के. माहेश्वरी, उपाध्यक्ष, एफटीसीसीआई, श्री मीला जयदेव, संयोजक, एफटीसीसीआई सीईओ फोरम, आज यहाँ एकत्रित मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को शुभ संध्या। मुझे आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करते हुए खुशी हो रही है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है - एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की महत्वपूर्ण भूमिका और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऋण देने में विश्वास अर्जित करने का महत्व। पिछले कुछ वर्षों में, मुझे एमएसएमई इकाइयों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला है, और मैंने उनकी क्षमता और उनके संघर्ष दोनों को देखा है। मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक युवा अधिकारी के रूप में चहल-पहल वाले पीन्या औद्योगिक क्षेत्र में तैनात था, वहाँ मैंने एमएसएमई को परिभाषित करने वाली ऊर्जा और समुत्थानशीलता के साथ-साथ उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को भी देखा। बाद में, करियर के मध्य में, एसबीआई के मिड कॉरपोरेट्स ग्रुप में काम करते हुए मेरे अनुभव में वृद्धि हुई, जहाँ मैंने आगे यह बात समझी कि कैसे समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच- इन व्यवसायों को बदल सकती है। इन अनुभवों ने मुझे एमएसएमई के लिए ऋण अंतर को पाटने के महत्व के बारे में गहराई से अवगत कराया है - एक ऐसा कार्य जिसके लिए न केवल नवोन्मेषी समाधानों की आवश्यकता है, बल्कि ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक समान विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएसएमई क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करता है। ये उद्यम, बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक सहायक इकाइयों के रूप में काम करते हैं तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों के साथ,[1] एमएसएमई भारत के अंकित सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान देते हैं और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।[2] इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 22 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करते हैं[3] और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की अपार क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है बल्कि गरीबों का उत्थान भी करता है, आजीविका प्रदान करता है और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, इस क्षेत्र से हम जो आम शिकायत सुनते हैं, वह यह है कि उन्हें समय पर और पर्याप्त औपचारिक ऋण प्राप्त करना मुश्किल लगता है। यह चुनौती उनकी वित्तीय और कारोबारी व्यवहार्यता पर सूचना विषमता जैसे कारकों के कारण हो सकती है, और एमएसएमई क्षेत्र के भीतर आज भी सीमित औपचारिकता के कारण भी हो सकती है। कई एमएसएमई के पास व्यापक वित्तीय रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर का अभाव है, और कुछ मामलों में, उनके पास आवश्यक वित्तपोषण के पैमाने का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक नहीं हो सकता है। इन मुद्दों के परिणामस्वरूप इन इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं और उपलब्ध आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर होता है - जिसे क्रेडिट गैप के रूप में जाना जाता है। पांच वर्ष पहले, आरबीआई द्वारा गठित एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: यू.के. सिन्हा) की रिपोर्ट ने इस ऋण अंतर के ₹20 से ₹25 लाख करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया था।

आरबीआई की पहलें

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी ओर से कई लक्षित उपायों के माध्यम से एमएसएमई को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने को लगातार प्राथमिकता दी है। प्रमुख

* (16 नवंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजित फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ फोरम में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण)

1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। https://msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf (पृष्ठ 23) से लिया गया।

2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (22 जुलाई 2024)। सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान [प्रेस विज्ञप्ति]। प्रेस सूचना ब्यूरो। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2035073 से लिया गया।

3 3 उद्यम पंजीकरण पोर्टल (12 नवंबर 2024 तक का डेटा) https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm

पहलों में से एक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) दिशानिर्देश हैं, जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए बैंकों के समायोजित निवल बैंक ऋण के 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को अनिवार्य बनाता है, जबकि एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी ऋण पीएसएल के अंतर्गत आते हैं। आरबीआई ने बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक पर जोर न देने और वित्तीय संस्थाओं को सीजीटीएमएसई योजना के तहत ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करके संपार्श्विक-मुक्त ऋण को भी बढ़ावा दिया है, जो ऋण के गारंटीकृत हिस्से के लिए शून्य जोखिम भार वहन करती है।

एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने कई नवाचार शुरू किए हैं। व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम - TReDS), इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। एकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क और एए पारितंत्र में जीएसटीएन को शामिल करने से एमएसएमई ऋण के लिए वित्तीय डेटा तक पहुंच आसान हो गई है। हाल ही में, अगस्त 2023 में पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), एमएसएमई को डिजिटल डेटा का उपयोग करके प्रयोजन-विशिष्ट, निर्बाध ऋण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने ₹25 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए पुनरुत्थान और पुनर्वास ढांचा लागू किया है, जो दबाव-मुक्ति के लिए एक सदा-सुलभ संरचित तंत्र प्रदान करता है। क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आरबीआई एनएएमसीएबीएस (NAMCABS)[4] कार्यक्रम भी चलाता है, जो बैंकरों को एमएसएमई क्षेत्र की विशिष्ट ऋण आवश्यकताओं से परिचित कराता है, जिससे एमएसएमई वित्तपोषण के लिए उनकी समझ और समर्थन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मुद्रा और सीजीटीएमएसई जैसी सरकारी योजनाओं के साथ-साथ, इन प्रयासों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण में उल्लेखनीय सुधार किया है। 31 मार्च 2024 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिया जाने वाला बकाया ऋण ₹27.25 लाख करोड़ था, जो औपचारिक वित्तीय पारितंत्र में एमएसएमई के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में एमएसएमई के लिए बकाया बैंक ऋण में क्रमशः 12.39 और 20.58 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

एमएसएमई क्या कर सकते हैं?

जबकि विनियामक नीतियों और सरकारी योजनाओं ने एमएसएमई के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एमएसएमई के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे विश्वास स्थापित करने और ऋणदाताओं के साथ उनकी प्रत्यक्षता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। इस संदर्भ में, मेरे पास चार प्रमुख सुझाव हैं जिन पर एमएसएमई को वित्त तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विचार करना चाहिए।

औपचारिकता अपनाएं

सर्वप्रथम, एमएसएमई को औपचारिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई एमएसएमई अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जिससे ऋणदाताओं के लिए सूचना विषमता के कारण उनकी ऋण पात्रता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेषकर उनके वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करके और जीएसटी रिटर्न भर करके, एमएसएमई अपनी कारोबारी गतिविधि और वित्तीय स्थिति के स्तर पर पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और वित्तीय संस्थाओं की नज़र में उनकी विश्वसनीयता को मजबूत करके उन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार और सरकारी योजनाओं के लिए योग्य बनाया जा सकता है।

औपचारिकता को अपनाने के साथ-साथ, एमएसएमई को समग्र और सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए जो उधारदाताओं के साथ विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एमएसएमई को उचित लेखांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड, जैसे आय विवरण, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और नकदी प्रवाह विवरण सटीक और विश्वसनीय हैं। प्रमाणित पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण और योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए जाने से उनकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी।

औपचारिकता के साथ-साथ, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने से वित्तीय लेनदेन का डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, जिससे ऋणदाताओं के लिए फर्म की वित्तीय स्थिति का आकलन करना आसान हो जाता है।

[4] बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन

डिजिटल भुगतान नकदी प्रवाह प्रबंधन में भी सुधार करते हैं, जिससे एमएसएमई को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण मिलता है और उन्हें स्पष्ट वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलती है।

क्रेडिट अनुशासन

दूसरे, एमएसएमई को और भी अधिक क्रेडिट अनुशासन के लिए प्रयास करना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं और नकदी प्रवाह के अनुकूल उचित ऋण उत्पाद के सावधानीपूर्वक चयन से शुरू होता है। एमएसएमई को अपनी उधारी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण उत्पादों से मिलान करने के लिए मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, ओवरड्राफ्ट और इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे विभिन्न ऋण उत्पादों से स्वयं को परिचित कराना चाहिए। व्यापार चक्रों के अनुसार उधार लेना और अधिक-लीवरेजिंग से बचना महत्वपूर्ण है। ऋणदाताओं के बीच शर्तों की तुलना करना और बेहतर ब्याज दरों और पुनर्भुगतान विकल्पों के लिए बातचीत करना अधिक अनुकूल ऋण शर्तों के परिणामस्वरूप हो सकता है। इसके अलावा, औपचारिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का होना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एमएसएमई को ऋण और बिलों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, जो उनके क्रेडिट इतिहास पर धनात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि बैंक की निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिनके लिए इसे उधार लिया गया था। हालांकि, कभी-कभी यह देखा जाता है कि कार्यशील पूंजी निधि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया जाता है। कुछ लोग अपनी इक्विटी का पूरा निवेश नहीं करते पाए गए हैं या बैंकों से उधार ली गई निधि को अपने कारोबार से बाहर के उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करते पाए गए हैं। कई बार, अनियोजित और अनुचित तरीके से वित्तपोषित क्षमता या बाजार विस्तार, दबाव का एक प्रमुख स्रोत बन चुके हैं, जिससे क्रेडिट इतिहास और इस तरह उनके बैंकों के साथ विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ये सभी पूरी तरह से टाले जा सकते हैं, नैतिक और विवेकपूर्ण तरीके से कारोबार करने से ऐसी अदूरदर्शी कार्रवाइयों पर काबू पाने में मदद मिलती है।

क्षमता निर्माण

तीसरा, एमएसएमई को अपने परिचालन और वित्तीय प्रबंधन कौशल को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, उद्यमियों को ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं, बैंकिंग मानदंडों और सरकारी सहायता उपायों को समझने में मदद करते हैं, जिससे उधारकर्ता के रूप में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुपालन, बहीखाता पद्धति और बाजार के रुझान जैसे विषयों पर कौशल विकास कार्यशालाएँ, उन्हें अपने कारोबार और वित्त का बेहतर प्रबंधन करने के लिए तैयार करती हैं।

एमएसएमई क्षमता निर्माण और वित्तपोषण के लिए पारितंत्र का लाभ उठा सकते हैं। उद्योग निकायों और व्यापार संघों के साथ जुड़ने से एमएसएमई को संरक्षण, वित्तपोषण के अवसर और बाजार संपर्क मिलते हैं। इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के साथ सहयोग से प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और वित्तपोषण तक पहुँच मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, बिक्री पैटर्न या आपूर्तिकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग का उपयोग करने वाले फिनटेक समाधान, एमएसएमई को अधिक प्रभावी ढंग से वित्तपोषण प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

चतुर्थ, एमएसएमई को टीआरईडीएस के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बड़े खरीदारों को प्रस्तुत किए गए बिलों को भुना कर कार्यशील पूंजी तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करता है। खरीदारों को भी टीआरईडीएस पर लाने से लेनदेन प्रक्रिया में आसानी होती है और समय पर भुगतान होता है। एमएसएमई अपने परिचालन में टीआरईडीएस को एकीकृत करके, चलनिधि को अनलॉक कर सकते हैं, नकदी प्रवाह में सुधार कर सकते हैं और उधारदाताओं के साथ मजबूत विश्वास बना सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि आज हमारे बीच कुछ बैंकर भी मौजूद हैं। यद्यपि आरबीआई पृथक रूप से बैंकिंग समुदाय के साथ संवाद करता है, विशेष रूप से एमएसएमई पर स्थायी सलाहकार समिति के तहत, मैं इस अवसर पर एमएसएमई के लिए वित्तपोषण में सुधार के महत्व पर जोर देना चाहूँगा। ऋण अंतर को पाटना केवल एकल एमएसएमई के विकास का समर्थन करने के बारे में नहीं है; यह एक ऐसे क्षेत्र को सशक्त बनाने के बारे में है जो एक समुत्थानशील और गतिशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वित्त तक बेहतर पहुँच के साथ, एमएसएमई नवोन्मेष को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और देश भर में समुदायों के उत्थान के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। यह भारत के लिए अधिक समावेशी और धारणीय भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए, मैं बैंकरों से एमएसएमई के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करूँगा ताकि विश्वास स्थापित हो, ऋण अनुशासन बढ़े और यह सुनिश्चित हो कि वे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों से लैस हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सभी हितधारकों - सरकार, विनियामक निकायों, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार संघों और यहां तक कि बड़े कॉरपोरेट्स के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें भुगतान में देरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं, औपचारिक वित्त तक सीमित पहुंच, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर को अपनाना और कुशल श्रम शक्ति की कमी शामिल हैं। आरबीआई ने इन मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, ऋण तक पहुंच को आसान बनाया है और डिजिटलीकरण की वकालत की है। जबकि आरबीआई और सरकार ने एक मजबूत नीति ढांचा स्थापित किया है, जिसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, टीआरईडीएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण की पहलें शामिल हैं, एमएसएमई के लिए इन अवसरों का अधिक-से-अधिक लाभ उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे चलकर, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के निरंतर विकास और समुत्थानशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

इसके साथ ही, मैं फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए हैदराबाद आमंत्रित किया। मैं फेडरेशन को इस तरह के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

*परिवर्तन लाने में बोर्ड की भूमिका **

श्री स्वामीनाथन जे.

आदरणीय गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी), सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक और बोर्ड के प्रतिष्ठित सदस्य, आरबीआई से आए सहकर्मी-गण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को सुप्रभात।

आज आपके समक्ष अभिव्यक्ति वास्तव में सम्मान की बात है। इस तरह के सम्मेलन पर्यवेक्षकों और बैंकों को एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान करते हैं।

हम एक नई वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जो उद्योग की गतिशीलता को फिर से परिभाषित कर रही है। बैंकिंग उद्योग ने अतीत में कई प्रौद्योगिकी परिवर्तन देखे हैं, हालाँकि, वर्तमान बदलाव अपनी गति और पैमाने में अभूतपूर्व है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों द्वारा संचालित है। पिछले बदलावों के विपरीत, जो मौजूदा प्रक्रियाओं और परिचालन दक्षता को डिजिटल बनाने पर केंद्रित थे, आज के परिवर्तन में ग्राहक अनुभव को केंद्र में रखा गया है – जो तत्काल, व्यक्ति-विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करता है, न केवल शाखाओं में, बल्कि मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी।

यह परिवर्तन, हालांकि आशाजनक और स्वागत-योग्य है, लेकिन इसमें बैंकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी शामिल हैं। डिजिटल लेन-देन में वृद्धि, बैंकों को अधिक चलनिधि जोखिम और साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति एक्सपोज करती है, जबकि नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से परिचालन जोखिम बढ़ जाते हैं। तीसरे पक्ष के प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता, निर्भरता जोखिम को बढ़ाती है, और ग्राहक डेटा संग्रह का विस्तार सख्त डेटा गोपनीयता नियंत्रण की मांग करता है। इसके अलावा, तेजी से बदलती ऐसी प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए निरंतर अपडेट की आवश्यकता होती है, साथ ही विशेष प्रतिभा की जरूरत होती है। साथ ही, ग्राहकों की अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं; वे न्यूनतम डाउनटाइम के साथ निर्बाध सेवा की मांग करते हैं। इसके अलावा, आज के ग्राहक काफी वित्तीय समझदारी दिखा रहे हैं, अक्सर पारंपरिक बैंक जमाओं तक सीमित रहने के बजाय थोड़ा जोखिम उठाने और निवेश के वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं।

यहीं पर निदेशक मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए आपका नेतृत्व और अभिशासन प्रमुख हैं। आज अपने भाषण में, मैं चर्चा करना चाहूँगा कि एक सुदृढ़, परिवर्तनकारी बोर्ड का हिस्सा होने का क्या मतलब है - जो परिवर्तन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, जोखिमों को रणनीतिक रूप से संबोधित कर सकता है, और पूरे संगठन में समुत्थानशीलता को सुदृढ़ कर सकता है। आज मैं उन सात पहलुओं पर बात करना चाहूँगा, जिनके बारे में मुझे लगता है कि बोर्ड को ध्यान देना चाहिए।

नवोन्मेष को बढ़ावा देना

आज की दुनिया में, बैंकों के लिए नवोन्मेषी होना आवश्यक है, और यह केवल नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से कहीं अधिक है। बोर्ड के सदस्यों के रूप में, आपकी भूमिका एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना है जो नवाचार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करे और बैंक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। बोर्ड के सदस्यों के रूप में आप बैंक को जिम्मेदारी से नवोन्मेष करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति स्थिर, धारणीय और प्रासंगिक नियमों के अनुरूप हो। इसके लिए, बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन नवाचारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल और जोखिम प्रबंधन ढाँचे मौजूद हों। यद्यपि कभी-कभी प्रबंधन एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, यह बोर्ड का कर्तव्य है कि वह दिए गए कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे और उस पर प्रश्न उठाए ताकि उसे संगठन की वास्तविक स्थिति और जोखिमों की स्पष्ट, सटीक समझ हो।

कारोबार मॉडल जोखिम मूल्यांकन

एक प्रभावी कारोबार मॉडल बैंक की समुत्थानशीलता और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सफल मॉडल कैसा होना चाहिए, इसके लिए कोई अकेला “स्वर्णिम नियम” नहीं है; प्रत्येक बैंक को अपने विशिष्ट जोखिम-वहन क्षमता, बाजार की स्थिति और रणनीतिक लक्ष्यों के आधार पर अपना दृष्टिकोण तैयार करना

* 18 नवंबर 2024 को मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का विशेष संबोधन।

चाहिए। कारोबार मॉडल का आकलन करते समय, संभावित संकेंद्रण जोखिमों पर ध्यान देना आवश्यक है। बैंक अक्सर विशेष क्षेत्रों, खंडों या उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं जो अल्पावधि में लाभदायक या "सुरक्षित" लगते हैं। हालाँकि, किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से असंतुलित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे बैंक उस क्षेत्र या उत्पाद श्रेणी के भीतर स्थितियों में अचानक बदलाव होने पर असुरक्षित हो सकता है।

एक सुदृढ़ कारोबार मॉडल सुनिश्चित करने और अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए, बोर्ड कुछ सवालों पर विचार कर सकते हैं जैसे - *क्या हमारा वर्तमान मॉडल बैंक की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है, और क्या यह हमारी जोखिम वहन क्षमता पर पर्याप्त रूप से विचार करता है? क्या हम विशिष्ट क्षेत्रों, खंडों या उत्पादों में अत्यधिक संकेंद्रित हो रहे हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या न्यूनीकरण उपाय/सुरक्षा उपाय मौजूद हैं? क्या हम उद्योग के उन रुझानों का अनुसरण कर रहे हैं जो हमारी विशिष्ट शक्तियों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप नहीं हो सकते हैं? हम अपने मुख्य विशेषज्ञता क्षेत्र को कम किए बिना संतुलित और विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं?*

बोर्ड की निगरानी को एक ऐसे कारोबार मॉडल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वृद्धि को समुत्थानशीलता के साथ संतुलित करता हो, और आर्थिक चक्र के उतार और चढ़ाव, दोनों के लिए तैयार हो। एक निरंतर परिवर्तनशील बाजार में, अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है और इस विचार को सबसे प्रमुख स्थान दे कर बोर्ड अपने बैंकों का धारणीय, दीर्घकालिक सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं।

अभिशासन का केंद्र-बिंदु: जोखिम प्रबंधन और डेटा विश्वसनीयता

अब मैं ऐसे क्षेत्र पर बात करना चाहूँगा, जहाँ प्रभावी अभिशासन अत्यंत आवश्यक है, वह है जोखिम प्रबंधन। आज की जटिल दुनिया में, जोखिम अब केवल क्रेडिट या बाजार जोखिमों तक सीमित नहीं रह गए हैं। बोर्ड के सदस्यों के रूप में, सुविचारित निर्णय लेने की आपकी क्षमता समय पर, सटीक और व्यापक डेटा तक पहुँच पर बहुत हद तक निर्भर करती है। हम जो आम समस्याएँ देखते हैं, उनमें से एक यह है कि बोर्ड पुराने या अधूरे डेटा के साथ काम करते हैं। तस्वीर के केवल एक हिस्से के साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति का आकलन करने की कोशिश करने की कल्पना करें - यह जोखिम पूर्ण है और इससे खराब निर्णय लेने की संभावना हो सकती है। तो, समाधान क्या है?

बोर्ड को डेटा विश्वसनीयता पहलों को बढ़ावा देना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुदृढ़ डेटा प्रणालियाँ मौजूद हों जो बैंक में जोखिमों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करें। वास्तविक समय आधारित डेटा से आप संभावित समस्याओं का पहले ही पता लगा सकते हैं, अनर्जक आस्तियों में रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं या बाजार या चलनिधि की स्थिति में शुरुआती चेतावनी के संकेतों की पहचान कर सकते हैं। जब जोखिम की बात आती है, तो समय पर डेटा उपलब्ध होना न सिर्फ़ एक अच्छी बात है - यह आपके बैंक को समुत्थानशील बनाए रखने का एक अनिवार्य हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को दबाव परीक्षण को एक ऐसे साधन के रूप में सोचना चाहिए जो विनियामक आवश्यकताओं से परे है। इन परीक्षणों को परिचालन, साइबर और चलनिधि जोखिमों सहित जोखिमों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। नियमित, भली-भांति डिज़ाइन किए गए दबाव परीक्षण आपके बैंक को न केवल प्रतिक्रिया करने बल्कि संभावित संकटों का पूर्वानुमान लगाने की भी अनुमति देते हैं।

ग्राहक केंद्रीयता

इससे मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूँ - ग्राहक केंद्रीयता। हमने पहले भी इस पर विस्तार से चर्चा की है। दोहराने पर भी, मैं आप सभी से अपने बैंक के ग्राहक सेवा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करूँगा, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले महीनों और वर्षों में पर्याप्त पर्यवेक्षी ध्यान आकर्षित करेगा।

ग्राहक सेवा के उच्च मानक सिर्फ़ अपेक्षाएँ नहीं हैं; वे उन लोगों के प्रति दायित्व हैं जो आपको अपना पैसा सौंपते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों के सेवा वितरण में संवेदना और निष्पक्षता हो, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील समूहों के प्रति, जिन्हें अक्सर बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

यह चिंताजनक है कि कई मामलों में आंतरिक ओमबड्समैन संरचना सहित ग्राहक शिकायत तंत्र को एक मजबूत, प्रभावी संसाधन के बजाय औपचारिकता के रूप में अधिक माना जाता है। आंतरिक ओमबड्समैन तंत्र कागज पर लिखे शब्दों से कहीं

अधिक होना चाहिए; इसे निष्पक्ष और शीघ्रता से मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक भावना और सावधानी के साथ काम करना चाहिए।

बोर्ड को ग्राहक-केंद्रित बैंक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, आय या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अहम और सम्मानित महसूस करे। ग्राहक-केंद्रित अभिशासन प्रत्येक नीति, प्रक्रिया और सेवा टचपॉइंट में स्पष्ट होना चाहिए। विशेषकर तब जब बात अपने ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करने की हो। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम प्रणाली में ग्राहकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यदि पर्यवेक्षी हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है तो हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।

प्रतिभा प्रतिधारण और उन्नयन

जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, निजी क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग में नौकरी छोड़ने की दर[1] काफी अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 2024 में, निजी क्षेत्र के बैंक समूह में औसत पलायन दर लगभग 25 प्रतिशत थी, जबकि कतिपय बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में और भी उच्च स्तर का अनुभव किया है। पिछले वर्ष इस मामले पर चुनिंदा संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत के बाद, हम सुधार देखते हैं लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। नौकरी छोड़ने की संख्या केवल आँकड़े नहीं हैं; वे कार्मिक जुड़ाव और प्रतिधारण के लिए बैंक के दृष्टिकोण में गहनतर चुनौतियों के संकेतक हैं। यदि बैंक प्रतिभाशाली कर्मचारियों को खो देते हैं, विशेष रूप से जूनियर और फ्रंटलाइन स्तर पर, तो आप न केवल लोगों को खो रहे हैं - आप अनुभव, ग्राहक संबंध और परिचालन निरंतरता खो रहे हैं। इसका ग्राहक स्वामित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप फ्रंटलाइन काउंटरों पर अनुभव उतना संतोषजनक नहीं हो सकता है।

इसलिए, कर्मचारियों के पलायन को कम करना केवल मानव संसाधन का काम नहीं है; यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। निदेशकों के रूप में, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप ऐसी पहलों का पता लगाएँ और उनका समर्थन करें जो करियर विकास, मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रतिस्पर्धी लाभ और एक सहायक कार्यस्थल संस्कृति पर जोर देती हैं जो कर्मचारियों को अहम महसूस कराती हैं। कर्मचारी स्थिरता को प्राथमिकता देकर, बोर्ड दीर्घकालिक विकास की नींव रख रहे हैं और एक ऐसा बैंक बना रहे हैं जो प्रतिभा को आकर्षित और बनाए रखता है, और भावी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए उसका पोषण करता है।

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और समुत्थानशीलता

अब, मैं आपका ध्यान डिजिटल युग की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक की ओर आकर्षित करना चाहूँगा- साइबर सुरक्षा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक डिजिटल चैनल, साझेदारी या कस्टमर फेसिंग वाले ऐप संभावित असुरक्षाओं को प्रस्तुत करता है। इसलिए, एक मजबूत आईटी और साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक की समुत्थानशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। साइबर जोखिम प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए तैयारी और वास्तविक समय आधारित प्रतिक्रिया क्षमताएँ आवश्यक हैं। नियमित लेखा परीक्षाएँ और सिम्युलेटेड अभ्यास - असुरक्षाओं का आकलन करने और समुत्थानशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

परिचालन समुत्थानशीलता सिर्फ साइबर जोखिमों से कहीं अधिक है। अपने तीसरे पक्ष की निर्भरता और क्लाउड-आधारित सेवाओं के बारे में भी सोचें। एक भी विक्रेता की विफलता महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित कर सकती है। प्रत्येक तीसरे पक्ष की भागीदारी आपके बैंक के परिचालन का विस्तार है, और प्रत्येक संबंध में अपने जोखिम अंतर्निहित होते हैं। बोर्ड के सदस्यों के रूप में, आपको पारदर्शिता और समुचित सावधानी की मांग करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक विक्रेता, विशेष रूप से वे जो महत्वपूर्ण ग्राहक डेटा को प्रबंधित करते हैं, सुरक्षा और विश्वसनीयता के कठोर मानकों को पूरा करें।

केवाईसी, परिचालनगत चिंता का एक विषय

समापन से पहले, मैं एक ऐसे क्षेत्र पर भी बात करना चाहूंगा जो अब शिकायतों के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। यद्यपि रिज़र्व बैंक ने एफएटीएफ और पीएमएलए आवश्यकताओं के साथ पूर्ण संरेखण में केवाईसी पर मास्टर निदेशों को व्यापक रूप से अद्यतन किया है, पर जिस तरह से दिशानिर्देशों को लागू किया जा रहा है, उसके परिणामस्वरूप कई खाते फ्रीज हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों को अपने धन तक पहुँच से वंचित होना पड़ रहा है। हमारे मूल कारण विश्लेषण से कई मुद्दों का संकेत मिलता है, जिसमें ग्राहकों के केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतनीकरण में बैंक स्तर पर उच्च लंबितता शामिल है; आवश्यक ग्राहक दस्तावेज़ों

[1] निजी क्षेत्र के बैंकों में नौकरी छोड़ने की दरों पर आरबीआई का आंतरिक अध्ययन।

के लिए सहायता करने और उनकी प्राप्ति में सक्रिय दृष्टिकोण की कमी; ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपर्याप्त स्टाफ की तैनाती जिसके परिणामस्वरूप शाखाओं में भीड़भाड़ या सेवा से इनकार होता है; ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार शाखा में जाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनकी 'होम ब्रांच' से संपर्क करने का निर्देश देना; और ग्राहकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने के बाद भी प्रणाली में विवरण अपडेट करने में विफलता। हमारी जानकारी में यह भी आया है कि कुछ मामलों में सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करने वाले खातों को भी निष्क्रिय या अवरोधित कर दिया गया है, जो इस मामले में विनियामक दिशानिर्देशों के विपरीत है।

ऐसे मामलों में बोर्ड के लिए नीति निर्माण करना और प्रबंध के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाना आवश्यक है, जो न केवल विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हों बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक भी हों। मैं बोर्ड के सदस्यों, विशेष रूप से ग्राहक सेवा समिति के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि केवाईसी दिशानिर्देशों का सटीकता और संवेदना, दोनों के साथ पालन किया जाए। रिज़र्व बैंक उन संस्थाओं के विरुद्ध विनियामक या पर्यवेक्षी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा जो समयबद्ध और विचारशील तरीके से इन चिंताओं को दूर करने में विफल रहती हैं।

समापन विचार: एक समुत्थानशील भविष्य का निर्माण

जबकि वित्तीय निगरानी और जोखिम प्रबंधन जैसे पारंपरिक अभिशासन संबंधी उत्तरदायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहेंगे, आगे बढ़ते हुए, बोर्डों को प्रौद्योगिकी को अपनाने, डिजिटल परिवर्तनों को आगे बढ़ाने, ग्राहक केंद्रीयता अपनाने और नैतिक नेतृत्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, बोर्डों के पास प्रौद्योगिकीय साक्षरता से लेकर जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता और अभिशासन और हितधारक संबंधों की गहरी समझ तक व्यापक कौशल सेट होने की अपेक्षा की जाती है। ज्ञान और अभिशासन विशेषज्ञता के सही मिश्रण के साथ, आज इस तेजी से बदल रहे वित्तीय परिदृश्य में बोर्ड, बैंकों का दीर्घकालिक सफलता की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे।

हमारे बैंकिंग क्षेत्र का भावी सामर्थ्य आज हमारे द्वारा अपनाई गई अभिशासन पद्धतियों पर निर्भर करता है। एक समुत्थानशील बैंक वह होता है जो बदलाव का अनुमान लगा सकता है, जोखिमों का प्रबंधन कर सकता है, संकटों का सामना कर सकता है और निरंतर अनुकूलन कर सकता है। बोर्ड में आपकी भूमिका आपको एक परिवर्तनकारी शक्ति बनाती है, जो न केवल आपके बैंक की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है बल्कि इसके ग्राहकों के साथ विश्वास का निर्माण करती है।

धन्यवाद!

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति
सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा
बैंकों का दैनिक मुद्रा रिज़र्व संधारण व्यवहार
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि और नरम मुद्रास्फीति के साथ आघात-सहनीयता प्रदर्शित करना जारी रखती है। 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) यह संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्यौहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है। रबी की बुवाई के तेज विस्तार के साथ कृषि और इसलिए ग्रामीण खपत की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं। खाद्य कीमतों में कमी के कारण नवंबर 2024 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत तक कम हो गई।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि और नरम मुद्रास्फीति के साथ आघात-सहनीयता प्रदर्शित करना जारी रखती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के आकलन[1] में, वैश्विक व्यापार में सकारात्मक वृद्धि की गति कंटेनर और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में बढ़ोतरी के साथ-साथ वैश्विक तकनीकी चक्र में वृद्धि द्वारा कायम है। लाल सागर से दूर मार्ग बदलने के कारण प्रमुख एशियाई केंद्रों में शिपिंग जमावड़ा के बावजूद आपूर्ति श्रृंखलाएँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ई-कॉमर्स और शिपिंग में हो रही देरी से लाभ उठाते हुए हवाई माल ढुलाई की मात्रा बढ़ रही है।

2024 के दौरान पण्य की कीमतों में गिरावट आई है, जो कई कारकों के संगम को दर्शाता है। ऊर्जा बाजारों में, अक्तूबर 2024 से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ रही है क्योंकि वैश्विक जीडीपी की घटती ऊर्जा तीव्रता के साथ वैश्विक तेल की खपत में गिरावट आई है। आपूर्ति में भी विविधता आ रही है, गैर-ओपेक प्लस की बाजार हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। ओपेक प्लस खुद अतिरिक्त क्षमता को कम करने के लिए तैयार है। धातु बाजारों में, चीनी प्रोत्साहन के जवाब में सितंबर के अंत में हुई रैली तब से कमज़ोर होती जा रही है। भू-राजनीतिक तनावों के कारण सोने की कीमतों में उछाल आया, लेकिन अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती ने इसे पीछे छोड़ दिया। कृषि पण्य बाजारों में, कई प्रमुख फसलों की कीमतें अच्छी फसल के कारण कम हुई हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर जो मौसम और बीमारी से संबंधित आघातों और व्यापार प्रतिबंधों से प्रभावित हुई हैं। 2025 में, कृषि पण्य की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

फिर भी, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा नवंबर 2024 से मई 2025 की अवधि के लिए जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, 22 देशों और क्षेत्रों को कवर करने वाले 16 भूख हॉटस्पॉट में खाद्य असुरक्षा बिगड़ रही है। संघर्ष और सशस्त्र हिंसा इन हॉटस्पॉट में भूख के प्राथमिक चालक बने हुए हैं, इसके बाद मौसम की चरम सीमा, आर्थिक असमानताएं और उच्च ऋण स्तर हैं। दुनिया 2030 तक शून्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है। विश्व बैंक के समग्र वस्तु मूल्य सूचकांक में 2025 में मुख्य रूप से आपूर्ति की स्थिति में सुधार और वैश्विक विकास में कमी के कारण 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है[2]।

वित्तीय स्थितियों में सुधार जारी रहने के बावजूद, वैश्विक वित्तीय बाजार मिश्रित संकेत दे रहे हैं। शेयर बाजार ट्रम्प के व्यापार में जीत की राह पर लौट आए - S&P 500 और डॉव जोन्स ने नवंबर के अंत तक रिकॉर्ड बनाए - लेकिन फेडरल मार्केट्स ओपन कमिटी (एफओएमसी) के आर्थिक अनुमानों के सारांश के जारी होने के बाद इसमें गिरावट देखी गई, जिसमें 2025 में पहले से कम अनुमानित दर कटौती की ओर इशारा किया गया था। बड़े राजकोषीय असंतुलन और मौद्रिक सहजता की गति में अनुमानित मंदी की संभावना के कारण बॉण्ड प्रतिफल में भी वृद्धि हुई है। नवंबर के अंत से, तुलनात्मक परिपक्वता के ट्रेजरी पर यूएस उच्च-प्रतिफल वाले बॉण्ड पर प्रसार पहली बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर स्थिर-दर वाले आवासीय बंधक पर प्रसार से नीचे गिर गया, जो यूएस चुनावों के बाद जंक बॉण्ड बाजारों के उत्साहपूर्ण मूड को दर्शाता है। प्रतिफल की तलाश स्पष्ट रूप

* यह लेख माइकल देवब्रत पात्र, जीवी नथनेयल, श्रेया कंसल, दुर्गा जी, हर्षिता केशन, यामिनी झांब, हरेंद्र बेहरा, केएम नीलिमा, शेषाद्रि बनर्जी, अमित कुमार, जेसिका मारिया एंथनी, लव कुमार शांडिल्य, रागिनी, सिद्धार्थ आर्य, अमृता बसु, आयुषी खंडेलवाल, श्रीतमा रे, शिवम, शुभम अग्निहोत्री, मयंक शंकर दयाल राय, लाल बहादुर सिंह, साई धीरज वायुगुंडला चेंचू, सत्यम कुमार, अवनीश कुमार, ख़ुशी सिन्हा, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, अक्षरा अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] ओईसीडी, आर्थिक दृष्टिकोण, दिसंबर 2024।

[2] विश्व बैंक द्वारा वस्तु मूल्य अनुमान।

से भीड़ में बदल रही है। उभरते बाजार के उच्च-प्रतिफल वाले सॉवरेन डॉलर ऋण में उछाल आया है, भले ही उभरते बाजार के शेयर यूएस इक्विटी के सापेक्ष कम कारोबार कर रहे हों क्योंकि यूएस के लिए पोर्टफोलियो प्रवाह भगदड़ मचा रहा है। दूसरी ओर, चीन के दीर्घकालिक बॉण्ड प्रतिफल जापानीकरण से जूझ रहे हैं क्योंकि वे जापानी प्रतिफल से नीचे गिर गए हैं, जिसका वित्तीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हो रहा है, एफओएमसी के बयान के बाद 19 दिसंबर को डीएक्सवाई के लिए 108 से ऊपर टूट गया। इसी तरह, अन्य सभी मुद्राओं पर लगातार नीचे की ओर दबाव उन्हें नए निचले स्तर पर ले जा रहा है क्योंकि वे आने वाले अमेरिकी प्रशासन से निकलने वाले व्यापारिक बयानबाजी के कारण होने वाले गिरावट को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपने नेता और सरकार चुनने में जुट गई है, ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो अभी भी मज़बूत है, वह संरक्षणवाद के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो आर्थिक गतिविधि, व्यापार, अप्रवास से लेकर भूराजनीति तक हर चीज़ को फिर से संगठित करेगी और महामारी के बाद प्रति व्यक्ति आय में सुधार के रास्ते में देशों के बीच मतभेदों को और बढ़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अगर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक व्यापार युद्ध होता है, तो विश्व अर्थव्यवस्था संयुक्त फ्रांसीसी और जर्मन अर्थव्यवस्थाओं के आकार तक सिकुड़ सकती है, जिससे विश्व जीडीपी को लगभग 7 प्रतिशत का नुकसान होगा।[3] इलेक्ट्रिक वाहन पहले ही तनाव का विषय बन चुके हैं। मुद्राओं के इंजीनियर्ड अवमूल्यन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण सामग्रियों को फिर से स्थापित करने में राष्ट्रीय स्वार्थ, टैरिफ़ से प्रभावित देशों द्वारा अपनी कंपनियों को विदेश ले जाना और वित्त की दुनिया में दरार के रूप में व्यापक स्पिलओवर हो सकते हैं। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 'उच्च, बढ़ता हुआ और जोखिम भरा' होने के कारण,[4] राजकोषीय दबाव 2025 में वैश्विक विकास संभावनाओं को कमजोर कर सकता है, जिसकी शुरुआत विकसित देशों से होगी। आईएमएफ के वैश्विक ऋण डेटाबेस के अनुसार, इसके प्रति उत्तर में, परिवार और व्यवसाय निजी ऋण का भुगतान करने का विकल्प चुन रहे हैं। मुद्रास्फीति 2024 में एक तरह से आ गई और 2025 में भी जारी रहेगी, लेकिन गहरी मंदी के भयावह पूर्वानुमान नहीं हैं। ओईसीडी के अनुसार, उपभोक्ता विश्वास अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य और ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील है, क्योंकि महामारी की शुरुआत के बाद से खाद्य और ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति ने नाममात्र घरेलू डिस्पोजेबल आय में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। श्रम बाजार की स्थिति आसान हो रही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से में कटौती चक्र शुरू होने के बावजूद ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। शायद 2025 में वे पूरी तरह से सामान्य हो जाएँ, लेकिन वे किस स्तर पर स्थिर होंगी, यह सवाल है। ब्याज की प्राकृतिक दरें या आर स्टार कई भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, जो समग्र नीति अनिश्चितता को दर्शाती हैं।

2035 तक विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीओपी29 एक नए जलवायु वित्त लक्ष्य - न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (एनसीक्यूजी) के साथ समाप्त हुआ। यह बहुत कम था, विकासशील देशों की 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग के एक चौथाई से भी कम। भारत ने इसे 'ऑप्टिकल इल्यूजन' कहा। दुनिया भर में विनाशकारी मौसम से उत्पन्न गर्मी के कारण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव करने के लिए गरीब देशों द्वारा किए गए खर्च का केवल एक अंश ही कवर किया जाएगा। उन्हें निजी पूंजी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए गारंटी और सस्ती मुद्रा हेजिंग सुविधाओं जैसे उपायों के माध्यम से निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए इस अल्पकालिक वित्त सौदे के प्रभाव को अधिकतम करना होगा। नए उपायों में कार्बन बाजारों का संचालन, प्रकृति के लिए ऋण स्वैप और बहुपक्षीय वित्तीय सहायता भी शामिल हो सकती है। वास्तव में, देशों ने सीओपी29 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, जो देश-दर-देश व्यापार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जाने वाले कार्बन बाजार और गैर-बाजार तंत्रों का प्रावधान करता है, जिसे अनुच्छेद 6 के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह औद्योगिक देशों को विकासशील देशों से कार्बन-कटिंग ऑफसेट खरीदने की अनुमति देगा, जिससे वित्त को अनलॉक किया जा सकेगा। हालांकि, उत्सर्जन में कमी के

[3] आईएमएफ की पहली डीएमडी गीता गोपीनाथ बीबीसी से, 24 अक्तूबर , 2024।

[4] आईएमएफ ब्लॉग, निजी उधार में लगातार गिरावट से वैश्विक ऋण में कमी आएगी, 2 दिसंबर, 2024।

ग्रीनवाशिंग की संभावना और प्रकटीकरण में कमियों को सुधारने के लिए समय सीमा की अनुपस्थिति के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

नुकसान और क्षति के लिए प्रतिक्रिया कोष हेतु एक दीर्घकालिक संधारणीय संसाधन रणनीति की भी आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। कोष के लिए संचयी प्रतिबद्धताएं आवश्यकता का लगभग 0.25 प्रतिशत हैं। विकासशील देशों को भी जोखिम कम करने वाली क्षेत्रीय नीतियों, उचित वर्गीकरण और जलवायु-संबंधी प्रकटीकरणों के माध्यम से निवेशकों के लिए सक्षम वातावरण बनाकर हाउसकीपिंग में संलग्न होना चाहिए। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नए और बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी समाधान हैं, जिनके बिना अकेले वित्त केवल उप-इष्टतम समाधानों की ओर ले जा सकता है। इसलिए, बातचीत को जलवायु प्रौद्योगिकी में नवाचारों तक व्यापक किया जाना चाहिए - जब कोई नई स्केलेबल तकनीक उभरती है, तो यह पूरे उद्योगों की मूल्य श्रृंखला को बदल देती है और अपनाने की लागत को उत्तरोत्तर कम करती है। सबसे स्पष्ट उदाहरण फोटोवोल्टिक सेल्स और ईवी को वैश्विक रूप से अपनाना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। 2015 में पेरिस समझौते को अपनाने के बाद से अक्षय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय निवेश लगभग तीन गुना हो गया है। हालाँकि, विकासशील देशों को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का केवल पाँचवाँ हिस्सा ही मिला है। फिर भी, वैश्विक बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिसमें भारत सबसे आगे है। जबकि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हैं, वे दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं हैं। यह अक्षय ऊर्जा में सीमा पार व्यापार के महत्व को उजागर करता है। सीमाओं के पार अक्षय ऊर्जा का संचरण आपूर्ति-मांग के अंतर को दूर करने में मदद कर सकता है। भंडारण समाधान राष्ट्रों की अकार्बनीकरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करके बेहतर ग्रिड उपयोग और नए व्यापार अवसरों के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। अक्षय ऊर्जा में व्यापार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की कुल लागत को भी कम करेगा। विश्व व्यापार संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत के लिए, नवंबर में जारी 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) / सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) और मुख्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अनुमानों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के नवंबर अंक में की गई आशंकाओं की पुष्टि की है, जो धीमी विकास-उच्च मुद्रास्फीति पहेली की दुविधा को दोहराती है। जैसा कि दूरदर्शिता से बताया गया है, व्यय पक्ष से, अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट में योगदान देने वाला प्रमुख कारक निश्चित पूंजी निर्माण है। उत्पादन पक्ष से, मुख्य चिंता विनिर्माण है।[5] दोनों को कमजोर करने वाली मुद्रास्फीति है। बार-बार मुद्रास्फीति के आघातों और लगातार मूल्यगत दबावों के कारण क्रय शक्ति का क्षरण सूचीबद्ध गैर-वित्तीय गैर-सरकारी निगमों की बिक्री वृद्धि को कमजोर करने में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मांग की स्थिति पर उनका दृष्टिकोण भी मंद बना हुआ है क्योंकि मूल्यगत आघातों की घटनाओं में कोई कमी नहीं दिख रही है; वे तेजी से इनपुट लागत को बिक्री मूल्यों पर डालने के लिए इच्छुक होंगे। परिणामतः, अचल संपत्तियों में निवेश करके कोई मजबूत क्षमता निर्माण नहीं होता है। इसके बजाय, निगम मुद्रास्फीति से प्रभावित उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इसका परिणाम सुस्त निजी निवेश है। उपभोक्ता मांग में मंदी धीमी कॉरपोरेट वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक और बाधा जो उभर रही है वह है नाममात्र जीडीपी की धीमी दर, जो बजटीय घाटे और ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय सहित राजकोषीय व्यय में बाधा डाल सकती है। जैसा कि हमने नवंबर में बताया था, अगर मुद्रास्फीति को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है, तो यह वास्तविक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उद्योग और निर्यात की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

अब मुद्रास्फीति को कम करने और निवेश को मजबूती से पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करने का समय आ गया है, खासकर तब जब सर्दियों में खाद्य कीमतों में सामान्य कमी आ रही है और निजी खपत और निर्यात में तेजी की संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं। कृषि और इसलिए ग्रामीण खपत की संभावनाएं निश्चित रूप से बेहतर दिख रही हैं, खरीफ की फसल का एक बड़ा हिस्सा तीसरी

[5] रंगराजन सी. और डी.के. श्रीवास्तव, दूसरी तिमाही की वृद्धि में गिरावट के निहितार्थ।

तिमाही के जीडीपी के अनुमानों में दिखाई देने की संभावना है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमानित सामान्य से अधिक गर्म सर्दियों से पहले रबी की बुवाई में तेजी से विस्तार होगा। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि वस्तुओं के व्यापार को खोलने और सुविधाजनक बनाने वाले राज्यों की संख्या बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म पर अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार में तेजी से किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। सेवा गतिविधि सुदृढ़ बनी हुई है; विशेष रूप से होटलों में महीने-दर-महीने (माह दर माह) सुधार देखने को मिल रहा है और जैसे-जैसे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें इस वित्तीय वर्ष में पूरी तरह सुधार की उम्मीद है।

खपत के मोर्चे पर, एफएमसीजी कंपनियों ने खाद्य मुद्रास्फीति की चिंताओं पर शहरी सुस्ती को मांग में कमी का कारण बताया और उनका मानना है कि मंदी का दौर खत्म हो चुका है और यह स्थिर हो रहा है क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ने का इंतजार कर रहा है। इसलिए, वे अपने सबसे बड़े वितरण चैनल, यानी सामान्य व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, साथ ही कम इन्वेंट्री और बेहतर सर्विसिंग के रूप में समर्थन भी दे रहे हैं। इस बीच, वे भारी छूट और प्रिडेटरी मूल्य निर्धारण के लिए क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा निधि जुटाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर, भारतीय उपभोक्ता दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उच्च मूल्य की खरीदारी के लिए इन-स्टोर खरीदारी करना जारी रखते हैं। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक अमेरिका से आयातित ब्लैक फ्राइडे ने इस साल लोकप्रियता हासिल की।

खपत के लिए सकारात्मकता उन रिपोर्टों में भी दिखाई देती है, जिनमें नई नियुक्तियों में तेजी को दर्शाया गया है, जो संभवतः लॉजिस्टिक्स, ईवी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और कृषि रसायन, और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है।[6] नौकरी बाजार में भौगोलिक बदलाव चल रहा है। कोयंबटूर और गुड़गांव जैसे शहर नौकरी के केंद्र बन रहे हैं, जो महानगरों से परे रोजगार के अवसरों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविदात्मक स्टाफिंग या अस्थायी भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें आईटी पेशेवर भी शामिल हैं।[7] गिग इकोनॉमी से 2024 में 90 मिलियन नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है।[8] वैश्विक क्षमता केंद्र तेजी से प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास में उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 2025 तक 80,000 नौकरियां जोड़ने का लक्ष्य रखता है।

घरेलू वित्तीय बाजारों ने नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में अमेरिकी चुनावों के प्रतिकूल प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि अमेरिकी डॉलर में उछाल और लगातार मुद्रास्फीति के कारण अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में मजबूती आई। घरेलू इक्विटी ने 22 नवंबर को पांच महीने से अधिक समय में सर्वश्रेष्ठ एकल-दिवसीय उछाल दर्ज किया। हालांकि, बाजारों ने बाद में लाभ का कुछ हिस्सा कम कर दिया क्योंकि वैश्विक मौद्रिक नीति अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर के निरंतर सख्त होने से ईएमई में भावनाओं पर असर पड़ा। भारत की अस्थिरता सूचकांक (VIX) सीमित दायरे में रहा, लेकिन बाजारों को लंबी अवधि के समर्थन के लिए आय वृद्धि की आवश्यकता होगी। बाजार की धारणा में गिरावट के बीच नवंबर में अधिकांश आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) ने मामूली लिस्टिंग प्रतिलाभ दर्ज किया। हालांकि, दिसंबर में प्राथमिक बाजार गतिविधि ने गति पकड़ी। योग्य संस्थागत प्लेसमेंट रूट के माध्यम से निधि उगाहना कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक ₹1 ट्रिलियन को पार कर गया, जो इसके इतिहास में सबसे अधिक है। 2024 के पहले दस महीनों में वेंचर कैपिटल फंडिंग 44 फीसदी बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।[9] ऋण बाजार में, सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र ने सितंबर तिमाही में बढ़ती गिरावट के साथ आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट देखी। दूसरी ओर, इसी तिमाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रावधान में कमी आई। निजी बैंकों ने प्रावधान में वृद्धि दर्ज की, लेकिन आय के मोर्चे पर पीएसबी की

6 टीमलीज रोजगार आउटलुक रिपोर्ट H2 FY25.

7 "जब भारतीय कंपनियों में अस्थायी भर्ती एक स्थायी व्यवस्था बन जाती है", मिंट।

8 प्रगतिशील गिग वर्कर्स के लिए फोरम, काम के भविष्य को आकार देना: भारत की गिग अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, बिजनेस स्टैंडर्ड।

9 ग्लोबलडाटा डील्स डेटाबेस।

तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर, उच्च गैर-ब्याज आय और बेहतर वसूली ने निवल लाभ को बढ़ावा दिया। बड़े बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर दरों में ढील देने से छोटे साथियों द्वारा जुटाई गई निधियों की लागत भी कम हो रही है। भारतीय रुपया मजबूत अमेरिकी डॉलर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवल विक्रेता बने रहने से दबाव में रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष स्वरूप टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. वैश्विक स्थिति

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने दिसंबर 2024 के अपने आर्थिक परिदृश्य में 2024 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा और 2025 के अनुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जो अमेरिका, यूके जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और चीन तथा भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में सुधार को दर्शाता है (सारणी II.1)। जी20 अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.5 प्रतिशत और 2026 में 2.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के लिए संभावना उत्पन्न कर सकता है, हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम, व्यापार नीति अनिश्चितता, वित्तीय कमजोरियों के बीच राजकोषीय और मुद्रा दबाव नकारात्मक जोखिम पैदा करना जारी रखते हैं।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हमारा मॉडल-आधारित पूर्वानुमान 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक विकास की गति में नरमी की ओर इशारा करता है (चार्ट II.1)।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) नवंबर 2024 में लगातार दूसरे महीने स्थिर रहा, जो इसके ऐतिहासिक औसत से नीचे है (चार्ट II.2ए)। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण भू-राजनीतिक जोखिम बढ़े हुए हैं, हालांकि नवंबर 2024 में इसमें कुछ कमी आएगी (चार्ट II.2बी)। सितंबर और अक्तूबर के दौरान कुछ राहत दिखाने के बाद, नवंबर से शिपिंग लागत में वृद्धि शुरू हो गई है (चार्ट II.2सी)।

सारणी II.1: जीडीपी विकास अनुमान – चुनिंदा एई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)

(Per cent)

देश	2024		2025	
	दिसंबर 2024	सितंबर 2024	दिसंबर 2024	सितंबर 2024
विश्व	3.2	3.2	3.3	3.2
विकसित अर्थव्यवस्था				
यूएस	2.8	2.6	2.4	1.6
यूके	0.9	1.1	1.7	1.2
यूरो क्षेत्र	0.8	0.7	1.3	1.3
जापान	-0.3	-0.1	1.5	1.4
उभरती हुई अर्थव्यवस्था				
ब्राजील	3.2	2.9	2.3	2.6
भारत*	6.8	6.7	6.9	6.8
चीन	4.9	4.9	4.7	4.5
दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.0	1.5	1.4

टिप्पणि: #: भारत के आंकड़े राजकोषीय वर्ष के आधार पर हैं।
स्रोत: ओईसीडी

यू.एस. और यू.के. में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ, लेकिन यूरो क्षेत्र[10] में दिसंबर 2024 में स्थिति खराब हो गई (चार्ट II.3ए)। एई और ईएमई पर उच्च आवृत्ति डेटा ने नवंबर में वित्तीय स्थितियों में सहजता का संकेत दिया (चार्ट II.3बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसने लगातार तेरहवें महीने वृद्धि दर्ज की। यह तेजी मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा

[10] आर्थिक और वित्तीय मामलों के महानिदेशालय (डीजी ईसीएफआईएन), यूरोपीय आयोग सेवाओं द्वारा दिसंबर 2024 यूरो क्षेत्र सीसीआई के लिए फ़्लैश अनुमान।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान (तिमाही दर तिमाही)

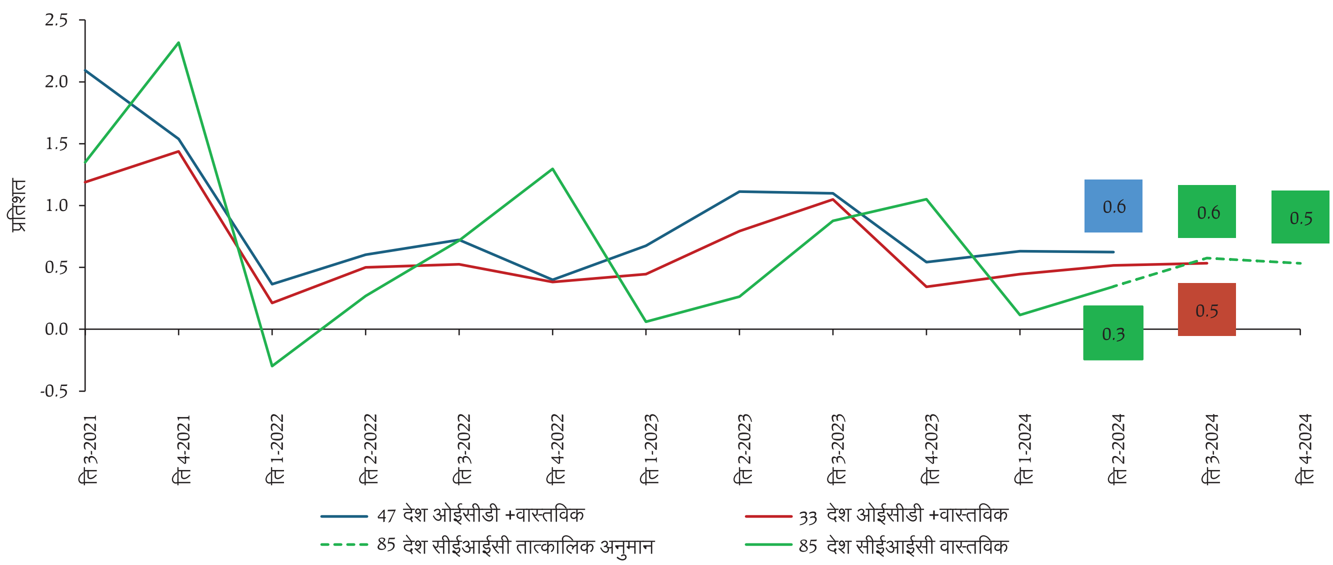

स्रोत: सीईआईसी, ओईसीडी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संचालित थी, जो नवंबर में लगातार बाईसवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा। विशेष रूप से, उपभोक्ता सेवा गतिविधि में और विस्तार हुआ, जिसने विनिर्माण के तुलनात्मक रूप से फीके प्रदर्शन की भरपाई की। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई, चार महीने के संकुचन

चार्ट II.2: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान

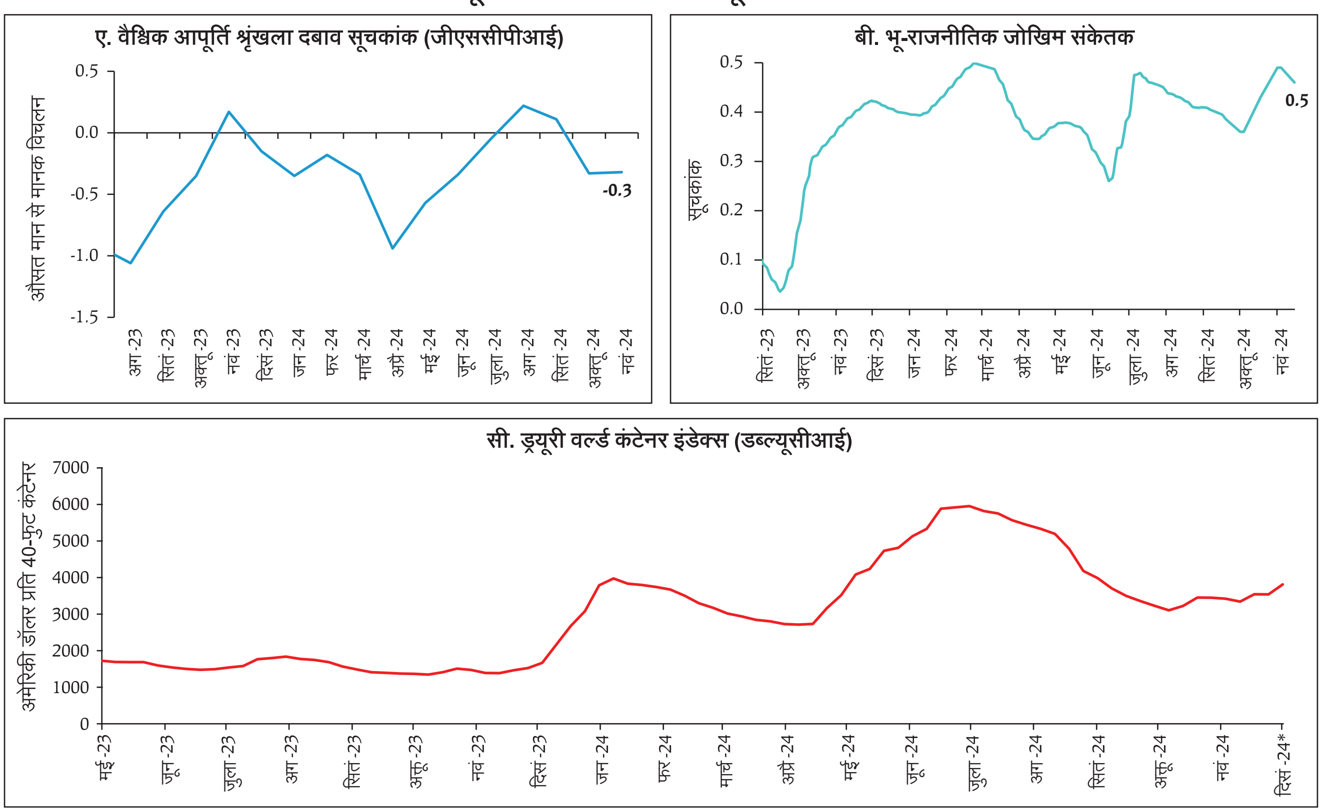

टिप्पणियाँ : 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. ड्यूरी द्वारा साप्ताहिक रूप से मूल्यांकन किया गया डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। यह समग्र मात्रा के आधार पर 8 शिपिंग मार्गों की भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रति 40-फुट कंटेनर की रिपोर्ट अमेरिकी डॉलर में की जाती है।
3. *: 19 दिसंबर तक के आंकड़े हैं।

स्रोत : फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, नवंबर 2024; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.3: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थिति

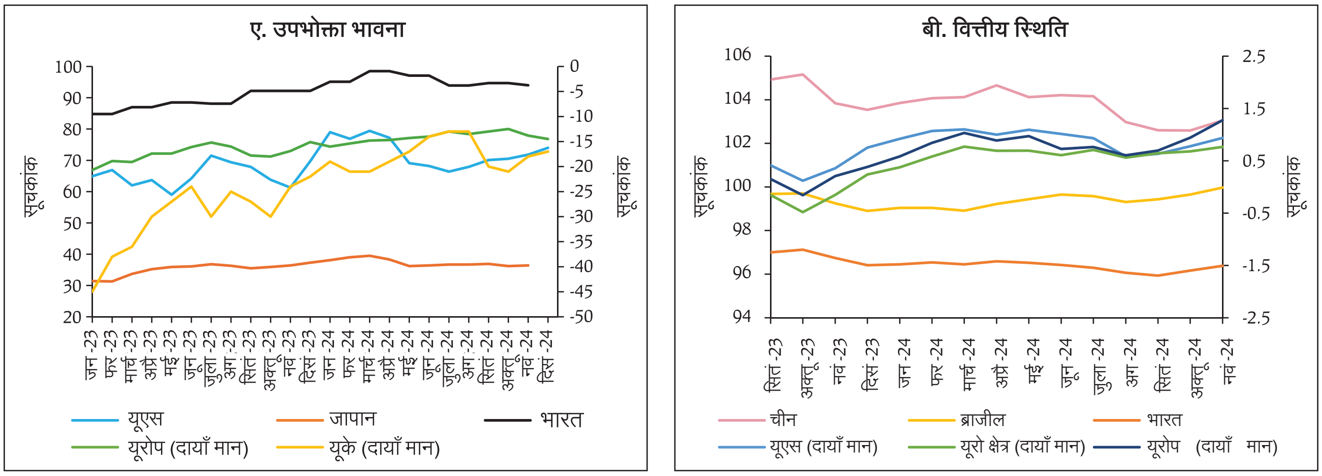

टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरो जोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, O तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास भी उतना ही अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का रीडिंग समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। एई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा तैयार सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक सकारात्मक मूल्य समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

के बाद नवंबर में क्रमिक रूप से बढ़कर 50 के तटस्थ निशान पर पहुंच गया (चार्ट II.4)।

सभी क्षेत्रों में, भारत के नेतृत्व में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने मजबूत विस्तार जारी रखा, जबकि जर्मनी और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट II.5)।

निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई जून 2024 से संकुचन क्षेत्र में रहा क्योंकि कमजोर विनिर्माण निर्यात ने सेवा ऑर्डर में वृद्धि को ऑफसेट करना जारी रखा। हालांकि, नवंबर में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात ऑर्डर में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.6)।

नवंबर में वैश्विक पण्य की कीमतों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव दर्ज किए गए क्योंकि ऊर्जा और कृषि पण्य की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई धातु की कीमतों में गिरावट से हुई। ब्लूमबर्ग

चार्ट II.4: वैश्विक पीएमआई

नोट: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं करता है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाती है।

स्रोत: एस&पी ग्लोबल।

चार्ट II.5: एसएंडपी वैश्विक संयुक्त पीएमआई का क्षेत्रवार तुलना

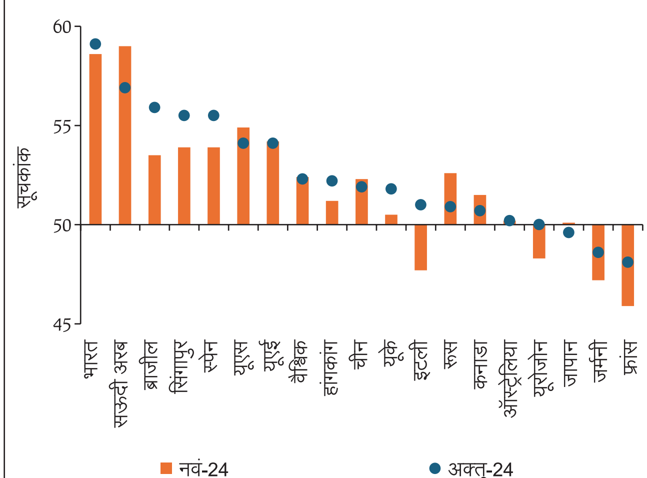

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: निर्यात आदेश

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं करता है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाती है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

पण्य सूचकांक नवंबर में अस्थिर रहा, पहले पखवाड़े में गिरावट के बाद दूसरे पखवाड़े में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7ए)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में नवंबर में 0.5 प्रतिशत (माह दर माह) की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से वनस्पति तेल (7.5 प्रतिशत) और डेयरी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई, जो आंशिक रूप से अनाज, चीनी और मांस की कीमतों में कमी से ऑफसेट हुई (चार्ट II.7बी)। भू - राजनीतिक घटनाक्रमों ने नवंबर में तेल की कीमतों को अस्थिर रखा है, मध्य पूर्व में युद्ध विराम ने नीचे की ओर दबाव डाला जबकि ईरान पर प्रतिबंधों के जोखिम ने समर्थन दिया। कुल मिलाकर, ओपेक प्लस द्वारा 2025 की पहली तिमाही में आपूर्ति में कटौती जारी रखने की अटकलों के बीच नवंबर में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 1.3 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि हुई (चार्ट II.7सी) । नवंबर में धातु की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि दुनिया में आधार धातुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन के लिए परिदृश्य अनिश्चित बना रहा। नवंबर के पहले पखवाड़े में सोने की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर ने निवेशकों के लिए अवसर लागत बढ़ा दी और

चार्ट II.7: पण्य वस्तु और खाद्यान कीमतें

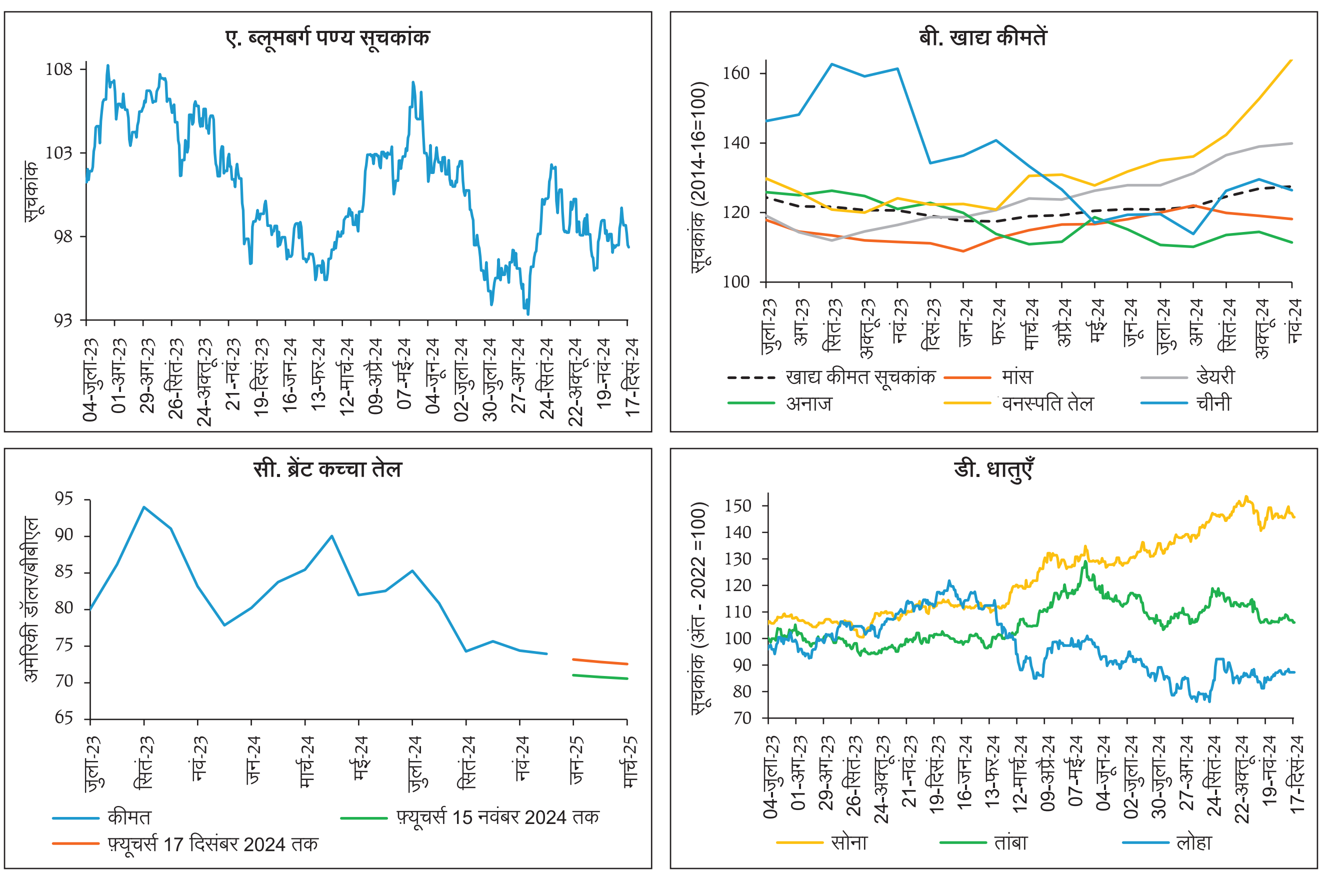

स्रोत: ब्लूमबर्ग: विश्व बैंक पिंक शीट: और एफ़एओ।

मध्य पूर्व में तनाव में आंशिक कमी ने सुरक्षित पनाहगाह की मांग को कम कर दिया। हालांकि, नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर की शुरुआत में कीमतों में सुधार हुआ, क्योंकि अमेरिकी फेड द्वारा नीति में ढील की उम्मीद थी (चार्ट II.7डी)।

हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब घूमती रहती है, लेकिन सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति के बीच कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनसे ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अक्तूबर में 2.6 प्रतिशत से नवंबर में बढ़कर 2.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) डिफ्लेटर के संदर्भ में मुद्रास्फीति भी अक्तूबर में 2.3 प्रतिशत से नवंबर में बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर में 2.0 प्रतिशत से नवंबर में 2.2 प्रतिशत हो गई और यूके में अक्तूबर में 2.3 प्रतिशत से नवंबर में 2.6 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजे भोजन को छोड़कर शेष सीपीआई) नवंबर में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8ए)। ईएमई में, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन नवंबर में चीन में नरमी आई (चार्ट II.8बी)। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर और सेवा मुद्रास्फीति हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट II.8सी और 8डी)।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में इक्विटी बाजारों ने मजबूत उछाल दर्ज किए जाने के कारण नवंबर में 3.6 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि दर्ज की, जो कर कटौती की उम्मीदों के साथ-साथ आने वाले आंकड़ों से पता चला, जो लचीली आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा करते थे (चार्ट II.9ए)। हालांकि, नवंबर में एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि टैरिफ वृद्धि पर अटकलों ने जोर पकड़ लिया। दिसंबर में अब तक, एमएससीआई क्षेत्र ने गिरावट दर्ज की, जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अवस्फीति की गति धीमी होने के साथ आगे चलकर अपनी दर

चार्ट II.8: मुद्रास्फीति – एई और ईएमई

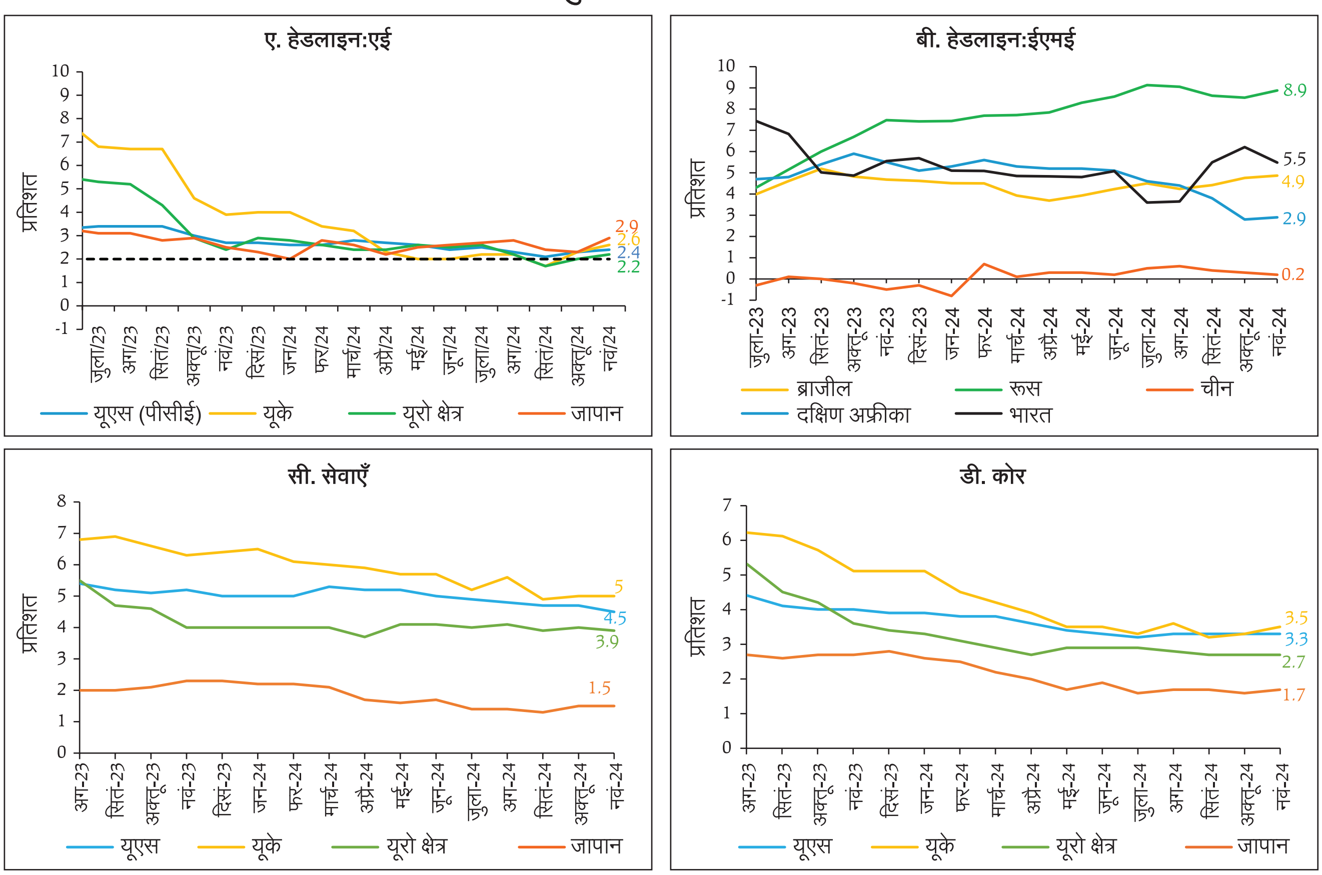

स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार

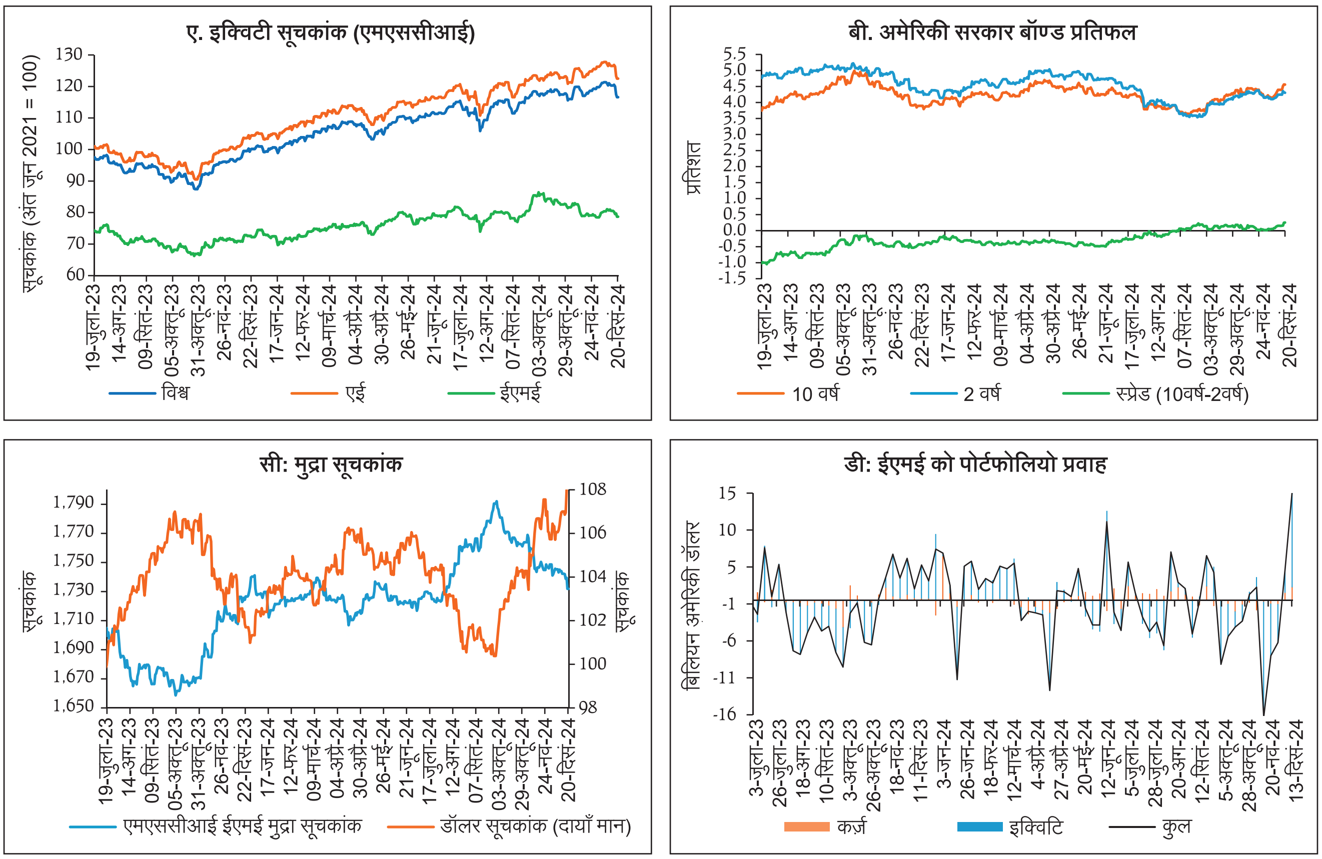

स्रोत: ब्लूमबर्ग और आईआईपी।

कटौती में अधिक सावधानी बरतने का संकेत दिया। नवंबर में 10-वर्ष और 2-वर्ष के बॉण्ड दोनों के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का प्रतिफल क्रमशः 12 बीपीएस और 2 बीपीएस कम हुआ (चार्ट II.9बी)। हालांकि, दिसंबर में प्रतिफल में मजबूती आई और यूएस 10-वर्षीय खजाना प्रतिफल मई 2024 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, साथ ही प्रतिफल वक्र में भी तेजी आई, क्योंकि एफओएमसी के आर्थिक अनुमानों के सारांश ने 2025 में ब्याज दरों में कटौती की अनुमानित गति से धीमी गति का संकेत दिया। अमेरिकी जीडीपी डेटा और अमेरिकी चुनाव परिणामों के चलते नवंबर में अमेरिकी डॉलर में 1.7 प्रतिशत (माह दर माह) की मजबूती आई। दिसंबर में यह उछाल जारी रहा क्योंकि फेड के डॉट प्लॉट ने उनके मध्य प्रक्षेपण के माध्यम से रेखांकित किया, 2025 के अंत तक पहले से अनुमानित मुद्रास्फीति और नीति दरों की तुलना में अधिक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था रही। सहवर्ती रूप से, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक नवंबर और दिसंबर में लगभग 1 प्रतिशत कम हुआ (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

एई केंद्रीय बैंकों में, यूएस फेडरल रिज़र्व ने 18 दिसंबर, 2024 को संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा को 25 बीपीएस से घटाकर 4.25-4.50 प्रतिशत करने का फैसला किया और संकेत दिया कि संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा में आगे समायोजन की सीमा और समय आने वाले डेटा, विकसित दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन के सावधानीपूर्वक आकलन पर आधारित होगा। ईसीबी ने दिसंबर में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कटौती की और कनाडा और स्विट्ज़रलैंड ने अपनी बेंचमार्क दरों में 50-50 बीपीएस की कमी की, जबकि यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति दरों को अपरिवर्तित रखा (चार्ट II.10 ए)। दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य ने नवंबर में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कमी की थी। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर में अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस

चार्ट II.10: मौद्रिक दरों में परिवर्तन

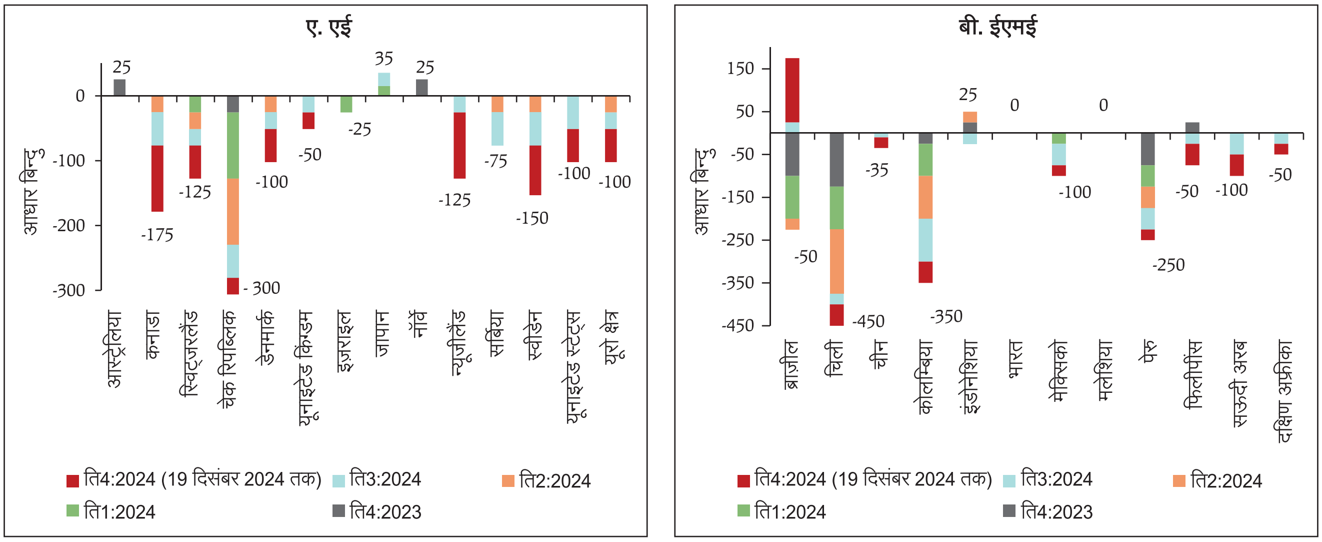

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

की कटौती की और चिली ने दिसंबर में अपनी बेंचमार्क दर में 25 बीपीएस की कटौती की। दूसरी ओर, ब्राजील ने अपनी नवीनतम बैठक में अपनी दर में 100 बीपीएस की वृद्धि की (चार्ट II.10बी)।

III. घरेलू घटनाक्रम

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई गति में नरमी से उबर रही है, जो मजबूत त्यौहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर उछाल से प्रेरित है। आने वाले वर्ष के लिए उच्च आशावाद से उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा मिला, जो स्थितियों के वर्तमान आकलन में क्रमिक नरमी से बाहर निकला (चार्ट III.1ए)। आपूर्ति श्रृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे रहा, नवंबर में और कम हुआ (चार्ट III.1बी)। आर्थिक गतिविधि सूचकांक[11] के आधार पर, जो मौसमी रूप से समायोजित आधार पर नवंबर में गति में तेजी का संकेत देता है, 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत रखा गया है (चार्ट III.1सी और 1डी)।

आंतरिक डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) पर आधारित अनुमानों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 2025-26 के लिए वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2025-26 में औसतन 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सारणी III.1 और चार्ट III.2)।

समग्र मांग

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत पर आ गई, जो सात तिमाहियों में सबसे कम है, जबकि 2023-24 की दूसरी तिमाही में यह 8.1 प्रतिशत और 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत थी। क्रमिक नरमी घरेलू कारकों, निजी खपत और स्थिर निवेश में कमी के कारण थी। हालांकि, सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में सुधार हुआ और निवल निर्यात ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.3)।

कुल मांग का प्रमुख घटक, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) बढ़ा, जो एक साल पहले दर्ज 2.6 प्रतिशत से अधिक है। बाद की एचएफआई का सुझाव है कि ग्रामीण मांग की स्थिति में सुधार जारी है, जबकि शहरी मांग में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की,

[11] यह सूचकांक उद्योग, सेवा, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक को निकालता है।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान

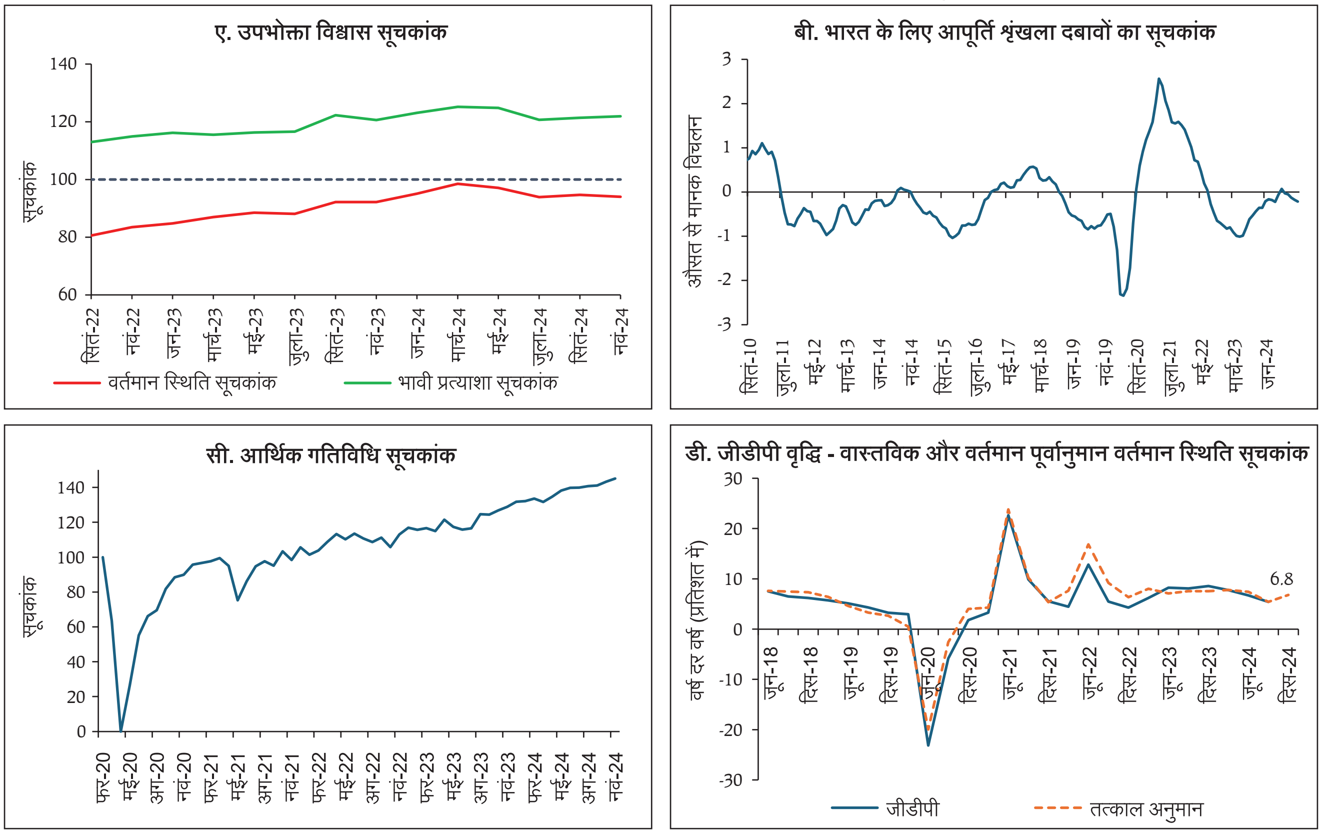

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया जाता है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 पर रखा गया है, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस); आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जो 2023-24 की दूसरी तिमाही के 11.6 प्रतिशत (2024-25 की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत) से कम है। यह नरमी पूंजी निर्माण के संयोग संकेतकों में भी स्पष्ट थी, जिसमें इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और आयात शामिल हैं। पिछली तिमाही में संकुचन के बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में वृद्धि 2024-25 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत हो गई। बाहरी मोर्चे पर, जबकि निर्यात में 2024-25 की दूसरी तिमाही में मामूली रूप से 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयात में 2.9 प्रतिशत की कमी आई। आयात की तुलना में निर्यात वृद्धि अधिक होने के कारण, निवल निर्यात ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 1.5 प्रतिशत अंकों का सकारात्मक योगदान दिया।

सारणी III.1 आधार अनुमान

(प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष)

अवधि	जीडीपी वृद्धि	सीपीआई मुद्रास्फीति
ति3: 2024-25	6.8	5.7
ति4: 2024-25	6.5	4.9
ति1: 2025-26	7.4	4.5
ति2: 2025-26	7.3	3.7
ति3: 2025-26	6.0	3.4
ति4: 2025-26	6.0	3.5
वित्तीय वर्ष 2025-26	6.7	3.8

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान.

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अक्तूबर/नवंबर 2024 में कुल मांग में वृद्धि जारी रहेगी। नवंबर में ई-वे बिल में मात्रा के लिहाज से 16.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.4ए)। नवंबर 2024 में टोल संग्रह में मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.4बी)।

चार्ट III.2: जीडीपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति के फैन चार्ट

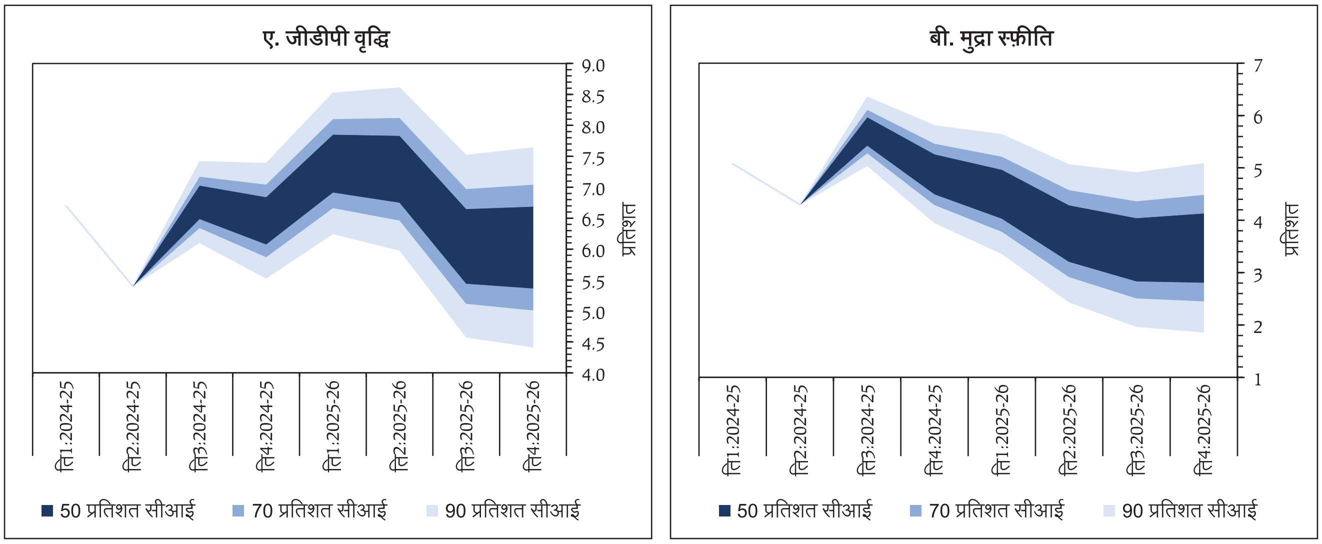

टिप्पणी: सीआई: विश्वास अंतराल।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

ऑटोमोबाइल की बिक्री 16 महीनों में पहली बार साल-दर-साल आधार पर मामूली रूप से घटी है, जो एक साल पहले के उच्च आधार (नवंबर 2023 में 26.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि) के प्रभाव से प्रेरित है [चार्ट III.5ए]। स्कूटर की बिक्री साल-दर-साल बढ़ी है, जबकि अन्य दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टरों की बिक्री में मामूली संकुचन दर्ज किया गया है (चार्ट III.5बी)। नवंबर 2024 में वाहन पंजीकरण दोहरे अंकों (साल-दर-साल) में बढ़ना जारी रहा, जबकि गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण में मामूली तेजी आई है (चार्ट III.5सी)। नवंबर 2024 में भारत की ईंधन खपत में बढ़ोतरी हुई, जो कि खेतों में कटाई, ग्रामीण गतिविधियों में बढ़ोतरी और मजबूत हवाई यात्रा के कारण हुई (चार्ट III.5डी)।

चार्ट III.3: जीडीपी वृद्धि में भारित योगदान

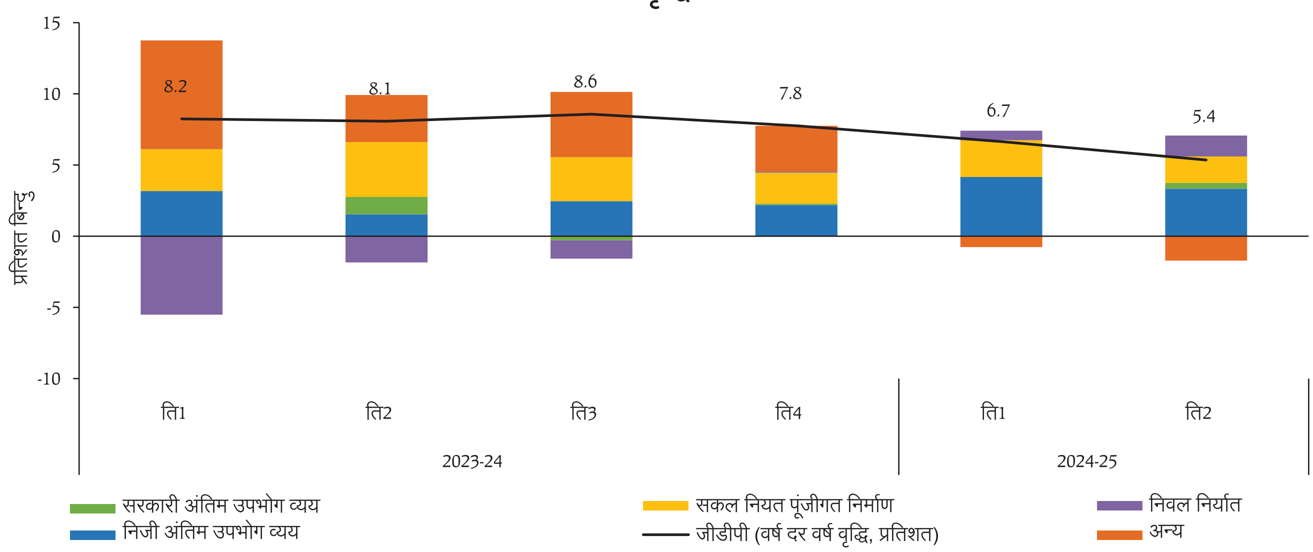

टिप्पणी: अन्य में स्टॉक, कीमती सामान और सांख्यिकीय विसंगतियों में परिवर्तन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट III.4 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

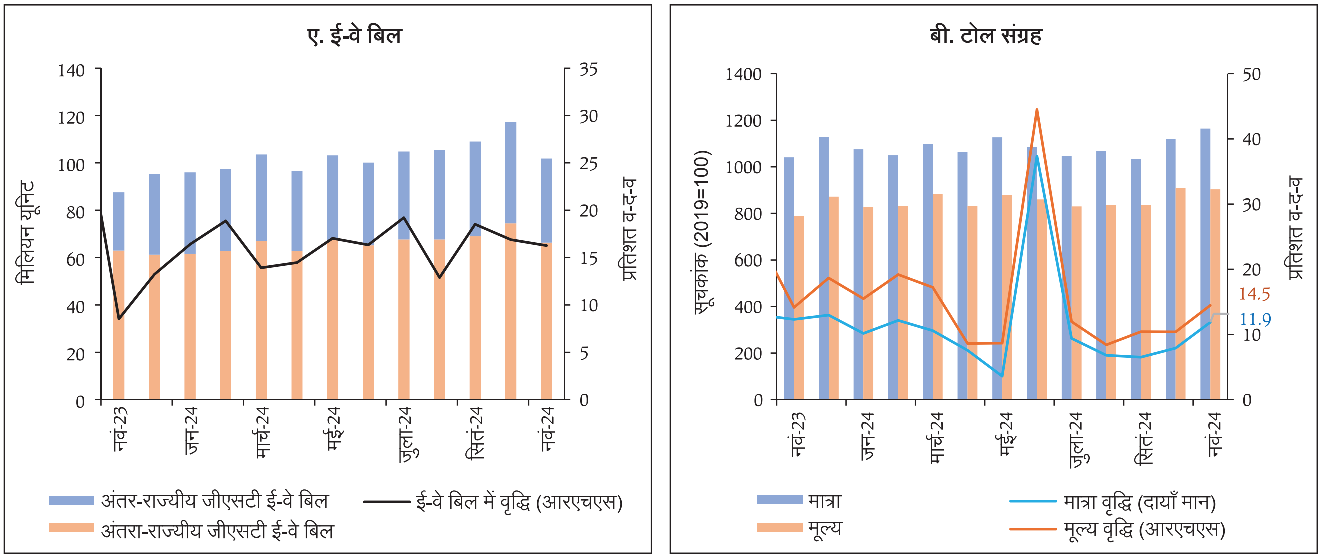

स्रोत: जीएसटीएन; एवं आरबीआई।

नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर, भारत ने हाल के वर्षों में सौर, पवन और जलविद्युत की स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण उल्लेखनीय प्रगति की है (चार्ट III.6)। पीएम सूर्य गृह योजना के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है। फरवरी 2024 में पीएमएसजीएमबीवाई

चार्ट III.5 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

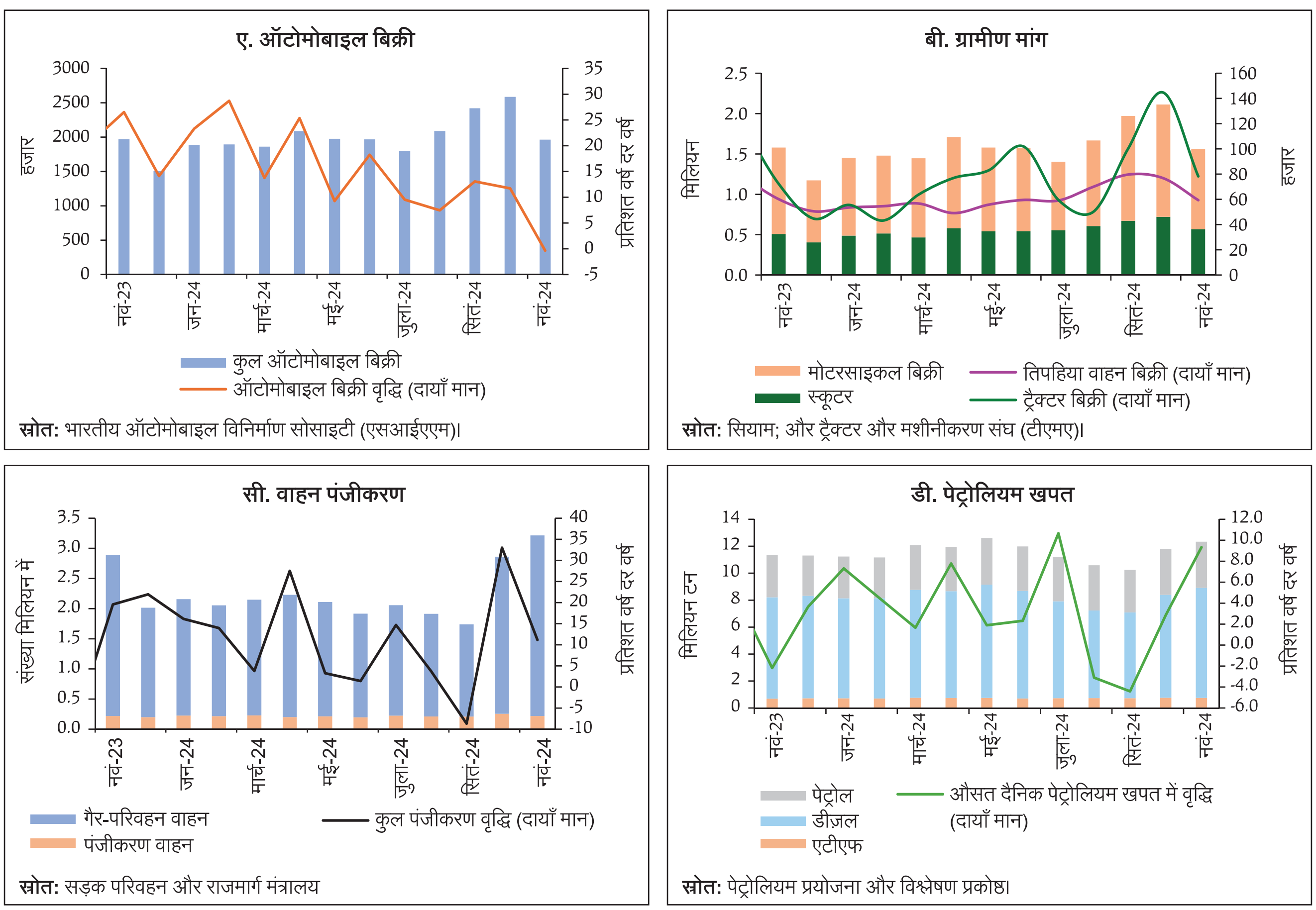

स्रोत: भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माण सोसाइटी (एसआईएएम)।

स्रोत: सियाम; और ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ (टीएमए)।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

स्रोत: पेट्रोलियम प्रयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

चार्ट III.6: नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता

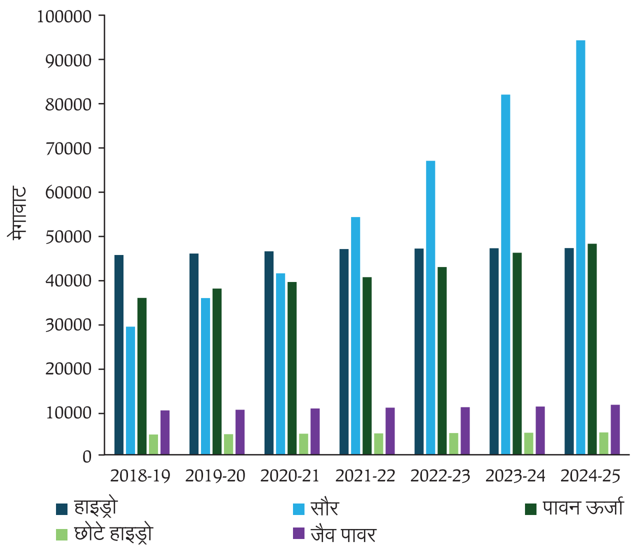

स्रोत: सीईए; तथा नीति आयोग।

चार्ट III.7: नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले राज्य

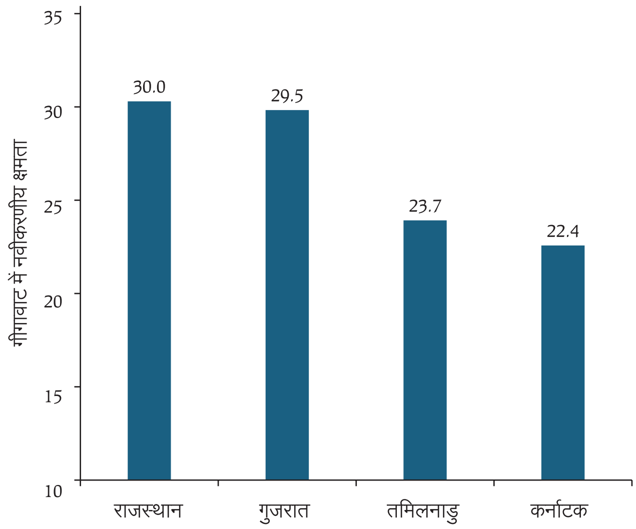

स्रोत: पीआईबी।

के लॉन्च होने के 9 महीनों के भीतर नवंबर 2024 तक 6.3 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए। इस योजना के तहत सब्सिडी[12] के रूप में चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ₹3,100 करोड़ से अधिक का वितरण भी किया गया। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे रूफटॉप सोलर एनर्जी में एक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

नवंबर 2024 में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 205.5 गीगावाट तक पहुंच गई और कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 213.7 गीगावाट पर पहुंच गई, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46 प्रतिशत से अधिक है। राज्यवार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने मिलकर देश की कुल अक्षय क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट III.7)।

भारत वैश्विक स्तर पर 10वें और जी-20 देशों में दूसरे स्थान पर है[13]। भारत 2020 से शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्ताओं में बना हुआ है, जो मुख्य रूप से जलवायु नीति, जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग घटकों (चार्ट III.8) के क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन से प्रेरित है।

सीसीपीआई 2025 ने यह भी रेखांकित किया कि भारत ने प्रति व्यक्ति कम जीएचजी उत्सर्जन बनाए रखा है और हाल के दशकों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में वृद्धि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (चार्ट III.9) की वृद्धि से कम रही है।

चार्ट III.8: विभिन्न वर्षों में भारत की सीसीपीआई रैंक

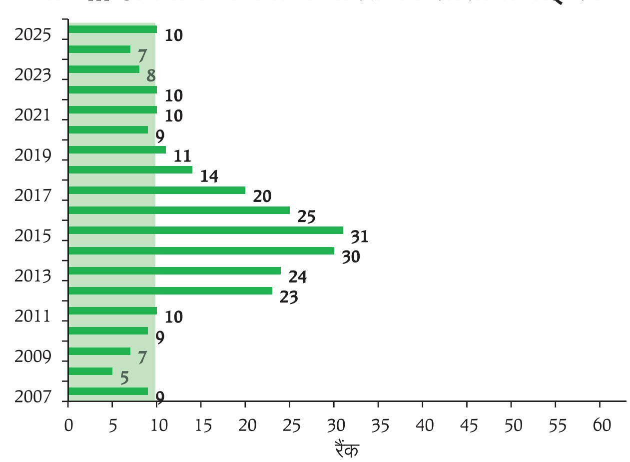

टिप्पणी: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र है जो विभिन्न देशों और समूहों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना चार श्रेणियों में करता है - जीएचजी उत्सर्जन (40 प्रतिशत भार), नवीकरणीय ऊर्जा (20 प्रतिशत भार), ऊर्जा उपयोग (20 प्रतिशत भार) और जलवायु नीति (20 प्रतिशत भार)।
स्रोत: www.ccpi.org

12 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2080833

13 सूचकांक से पता चलता है कि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त हो सके, इस प्रकार सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान रिक्त रह गए हैं, जिससे भारत 7वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सामने आया है।

चार्ट III.9: प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि

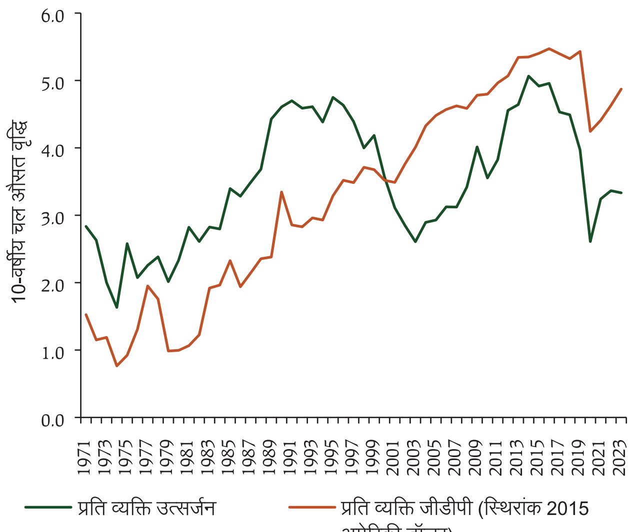

स्रोत: आईईए; और आवर वर्ल्ड इन डेटा।

चार्ट III.10: पीएमआई रोजगार सूचकांक

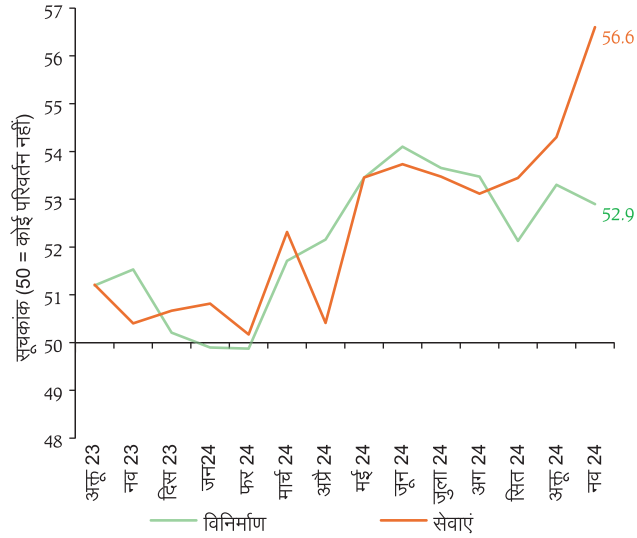

टिप्पणी: 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य विस्तार को दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

पीएमआई के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में लगातार नौवें महीने वृद्धि देखी गई। सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर सबसे तेज़ गति से बढ़ी है (चार्ट III.10)[14] ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग में नवंबर 2024 में मासिक आधार पर 8.2 प्रतिशत और सालाना आधार पर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि रबी की बुवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था। चालू वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल-नवंबर) अधिकांश महीनों में मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले परिवारों की कुल संख्या महामारी के बाद के वर्षों की तुलना में कम रही (चार्ट III.11)।

चार्ट III.11: मनरेगा के तहत परिवारों द्वारा काम की मांग

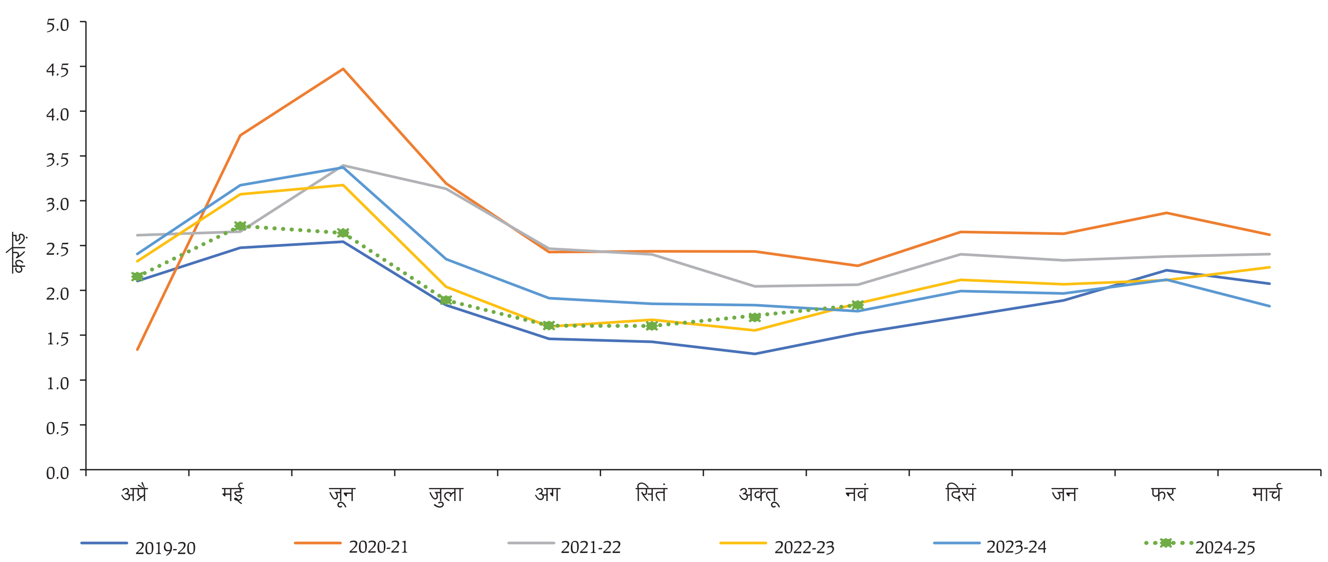

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[14] सर्वेक्षण 2005 में शुरू हुआ।

चार्ट III.12: भारत का पण्य निर्यात

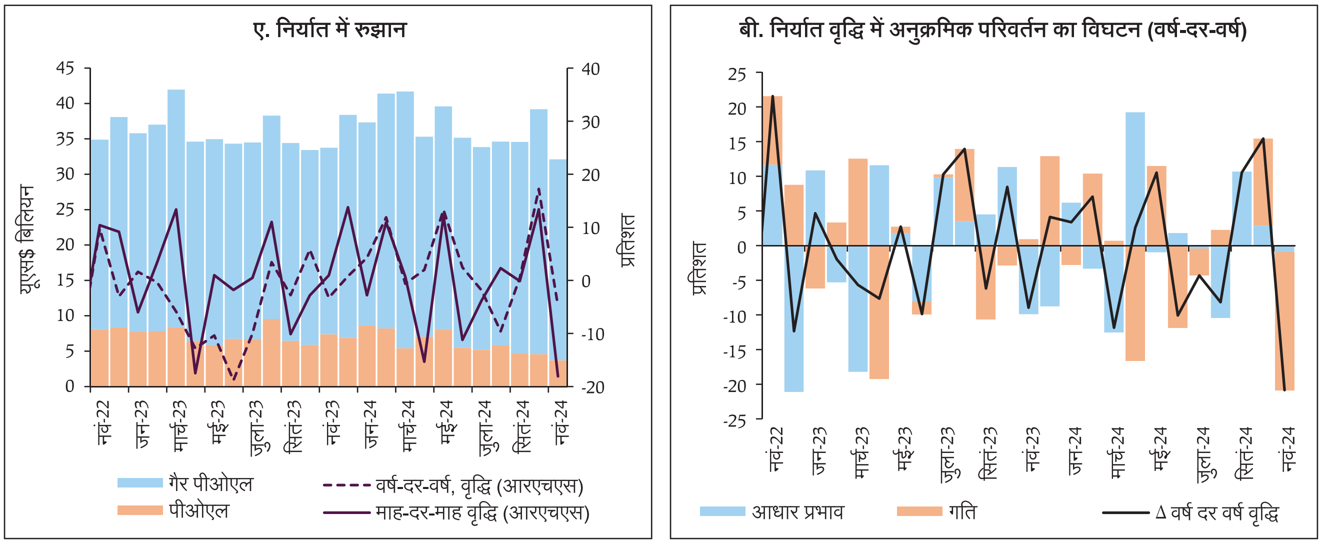

टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

नवंबर 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 4.8 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) घटकर 32.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो ऋणात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव दोनों के कारण हुआ (चार्ट III.12)।

नवंबर में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 9 (निर्यात टोकरी का 38 प्रतिशत हिस्सा) के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर कमी आई। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और तेल भोजन ने महीने में निर्यात वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल, समुद्री उत्पाद, और सभी वस्त्रों में से तैयार वस्त्र (आरएमजी) निर्यात वृद्धि के शीर्ष चालक थे (चार्ट III.13)। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 2.2 प्रतिशत बढ़कर 284.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य नेतृत्व इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और सभी वस्त्रों के आरएमजी ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ, और अन्य अनाज ने निर्यात को नीचे खींच लिया।

नवंबर में 20 में से 9 प्रमुख गंतव्यों को निर्यात में कमी आई। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, 20 में से 12 प्रमुख गंतव्यों को निर्यात में वृद्धि देखी गई, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य रहे।

नवंबर में लगातार आठवें महीने पण्य आयात में वृद्धि हुई और यह 27.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ 70.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो आधार प्रभाव द्वारा समर्थित सकारात्मक गति के कारण हुआ (चार्ट III.14)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 23 वस्तुओं (आयात

चार्ट III.13: भारत का पण्य निर्यात - सापेक्ष योगदान (नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024)

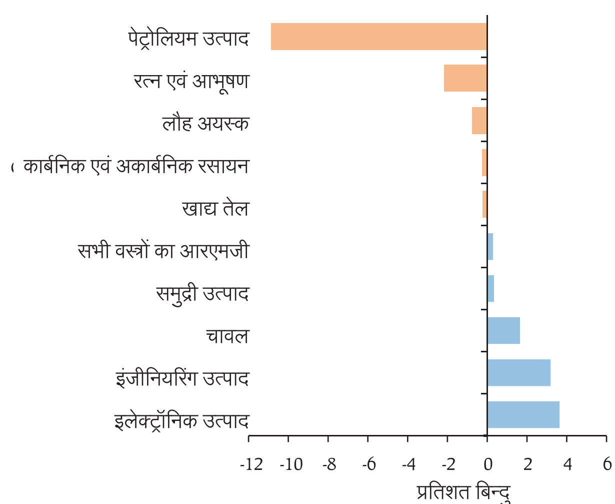

स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.14: भारत का पण्य आयात

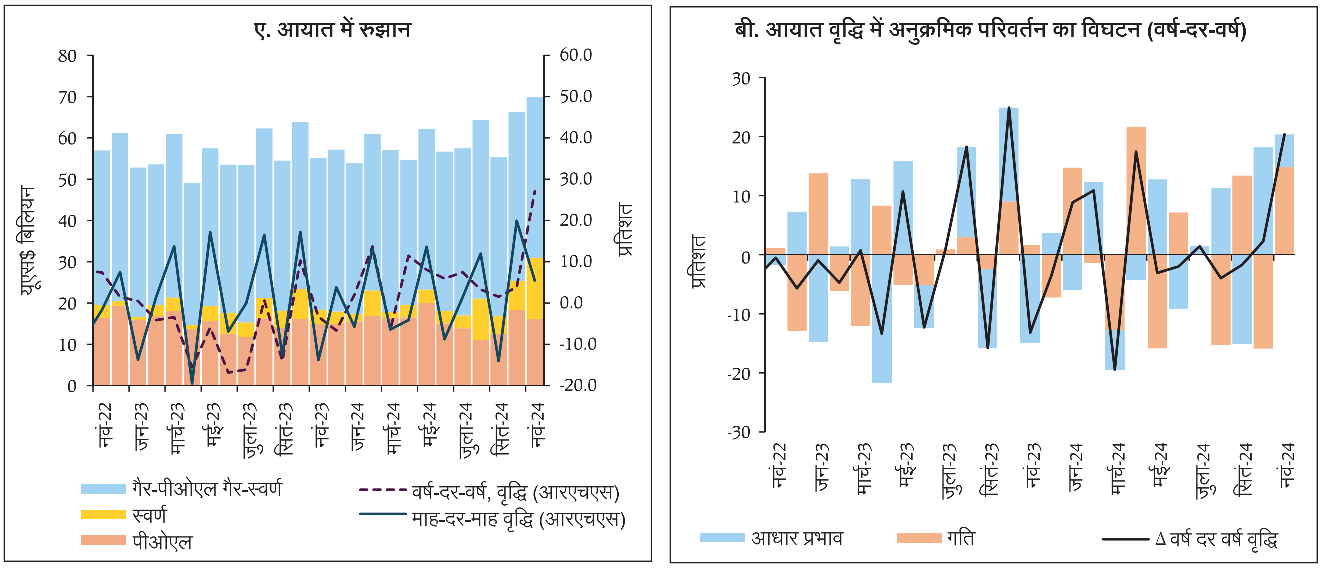

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बास्केट का 76.0 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

सोना, पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल और मशीनरी ने धनात्मक योगदान दिया, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, लोहा और इस्पात, परिवहन उपकरण, चमड़ा और इसके उत्पाद तथा मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने आयात

चार्ट III.15: भारत का पण्य आयात – सापेक्ष योगदान (नवंबर 2023की तुलना में नवंबर 2024)

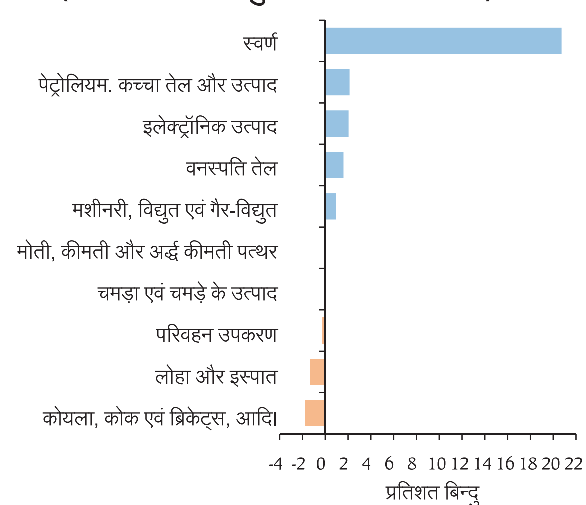

स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.15)। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 8.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 486.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें सोना, पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातु और मशीनरी का योगदान सबसे अधिक रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, उर्वरक और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री ने ऋणात्मक योगदान दिया।

नवंबर में और अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में वृद्धि हुई। प्रमुख स्रोत देशों, अर्थात चीन, यूएई और रूस से आयात में मजबूत वृद्धि देखी गई।

नवंबर 2024 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर में तेल घाटा बढ़कर 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, व्यापार घाटे में तेल घाटे का हिस्सा नवंबर में घटकर 32.8 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 35.4 प्रतिशत था। गैर-तेल घाटा नवंबर में बढ़कर 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.16)।

चार्ट III.16: भारत के व्यापारिक घाटे का विघटन

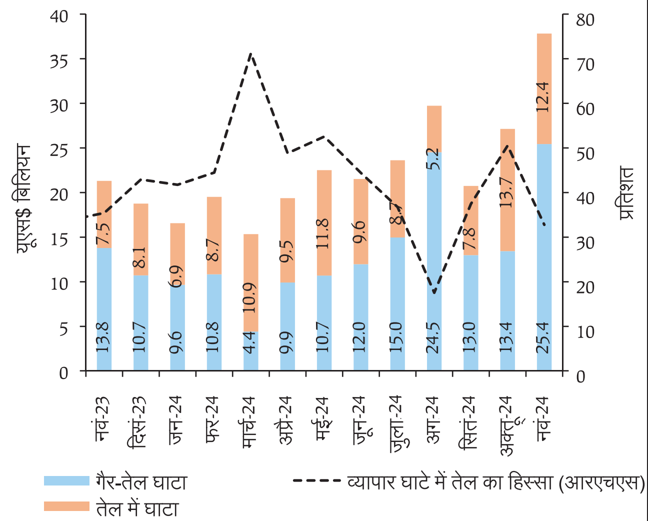

स्रोत: पीआईबी; तथा डीजीसीआईएंडएस।

चार्ट III.17: वस्तु-वार पण्य व्यापार घाटा

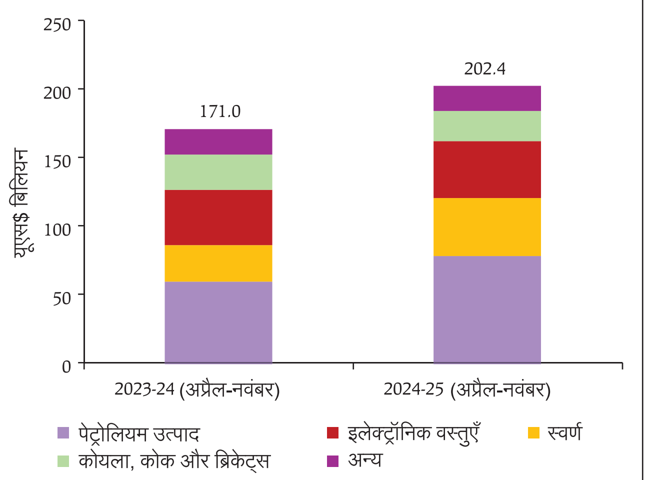

टिप्पणी: नवंबर 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट्स का निर्यात अक्तूबर 2024 के समान स्तर पर माना गया है।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक घाटा एक साल पहले के 171.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 202.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, उसके बाद सोना (चार्ट III.17) था।

अक्तूबर 2024 के दौरान, सेवाओं का निर्यात 34.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 22.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि सेवाओं का आयात 27.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.18)। महीने के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और राजस्व घाटे (आरडी) [बजट अनुमान (बीई) के प्रतिशत के रूप में] में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2024 में वृद्धि देखी गई (चार्ट III.19)। बजटीय घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय के कारण हुई, जो एक साल पहले 6.5 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी ओर, कुल प्राप्तियों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 14.8 प्रतिशत से कम है।

राजस्व व्यय में वृद्धि प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के कारण हुई, जिसमें खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी के कारण अप्रैल-अक्तूबर 2024 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पूंजीगत व्यय में वृद्धि में कमी देखी गई। शीर्ष छह मंत्रालय, जो 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं, ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान अपने पूंजीगत व्यय में गिरावट देखी

चार्ट III.18: सेवा निर्यात और आयात: वृद्धि दर

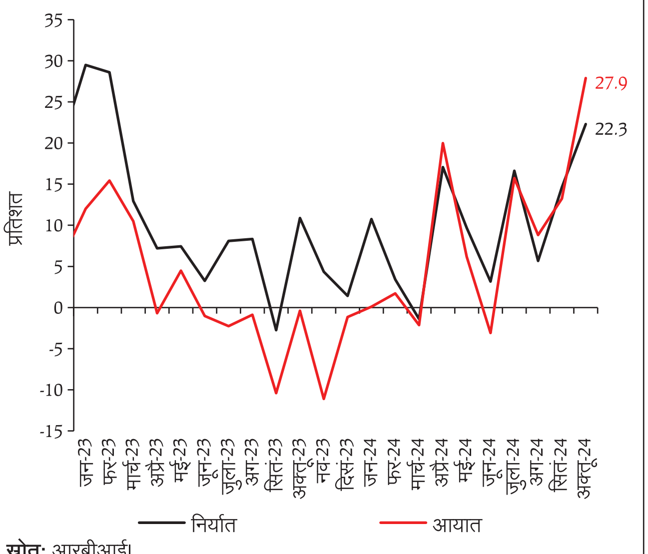

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट III.19: केंद्र सरकार का बजटीय घाटा (अप्रैल-अक्तूबर)

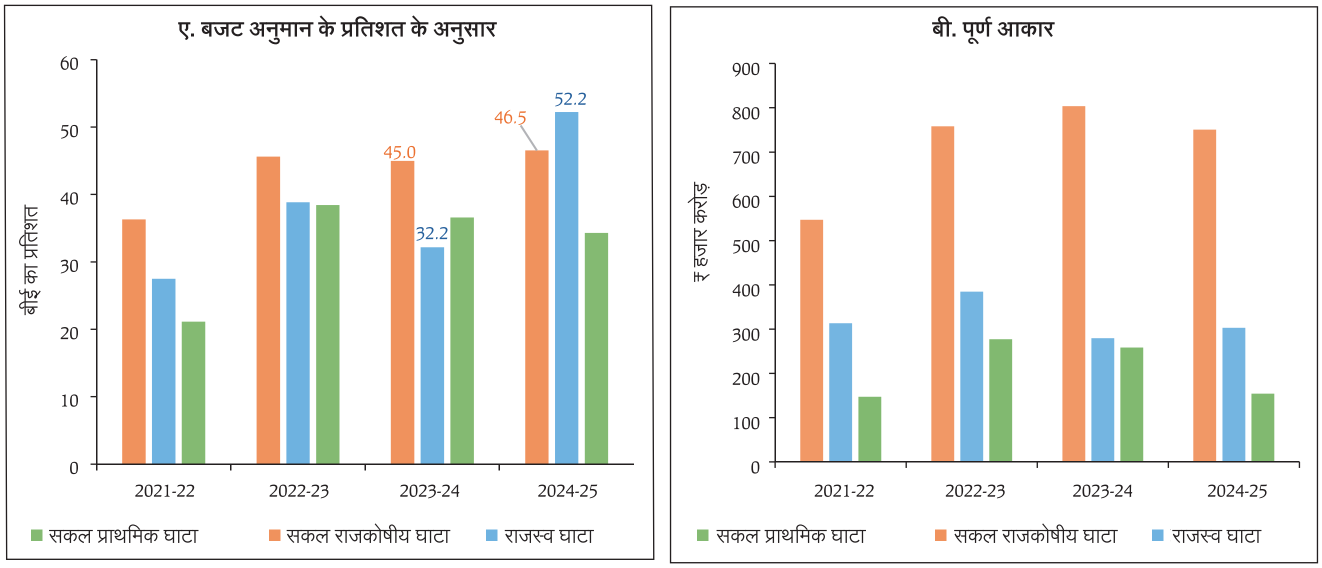

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए)।

(चार्ट III.20)। राजस्व व्यय में वृद्धि ने अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान कुल व्यय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया।

प्राप्तियों के मामले में, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 8.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। आयकर में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष करों में 11.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। हालांकि, कॉरपोरेट कर संग्रह सुस्त रहा। अप्रत्यक्ष करों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जीएसटी और सीमा शुल्क राजस्व में क्रमशः 12.0 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.21 ए)। इसी तरह, रिज़र्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण गैर-

चार्ट III.20: अप्रैल-अक्तूबर के दौरान मंत्रालयवार पूंजीगत व्यय

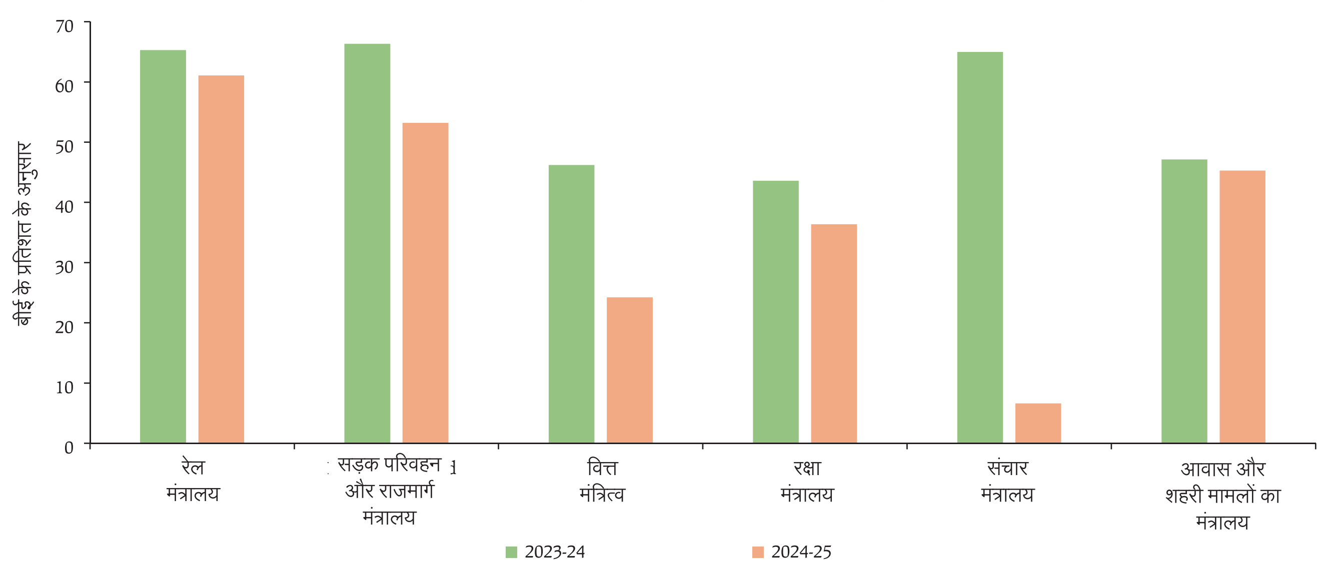

स्रोत: सीजीए।

चार्ट III.21: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-अक्तूबर)

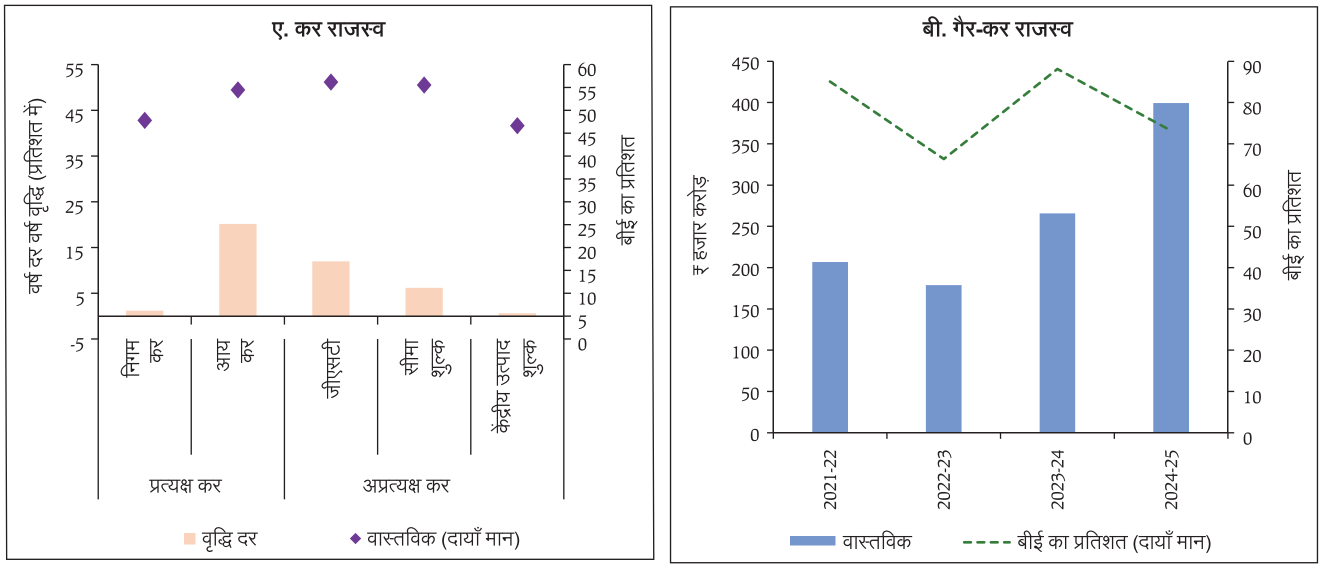

स्रोत: सीजीए

कर राजस्व संग्रह में 50.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.21 बी)। सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बावजूद, इस अवधि के दौरान निवल कर राजस्व में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल मिलाकर, अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान निवल कर राजस्व बजट अनुमान का 50.5 प्रतिशत था।

नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.82 लाख करोड़ रहा, जिससे अप्रैल-नवंबर 2024 के लिए संचयी जीएसटी संग्रह ₹14.57 लाख करोड़ हो गया (अप्रैल-नवंबर 2023 की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक) [चार्ट III.22]।

अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), बजट अनुमानों का 54.4

चार्ट III.22: जीएसटी वसूली

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

चार्ट III.23: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-अक्तूबर)

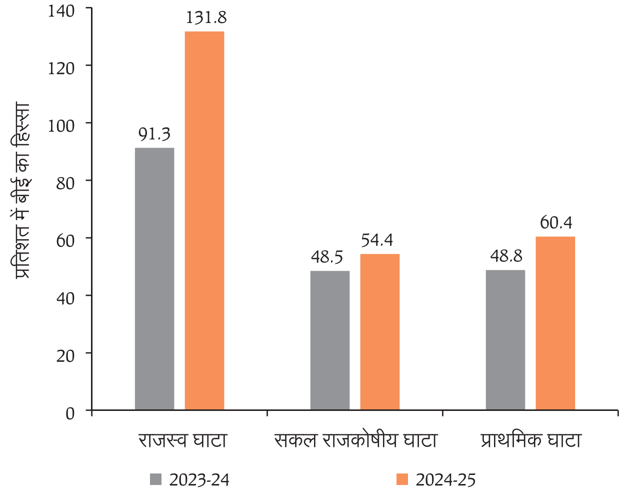

टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित हैं।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

प्रतिशत[15] , पिछले वर्ष के स्तर से अधिक था (चार्ट III.23)। जबकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियां उच्च कर राजस्व से प्रेरित होकर बढ़ीं, गैर-कर राजस्व और अनुदान में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट III.24ए)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, बिक्री कर/वैट संग्रह एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान देखी गई संकुचन से उबर गया, जबकि राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी) और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि धीमी रही।

व्यय पक्ष पर, अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के स्तर से कम रहा (चार्ट III.24बी)। आगे चलकर, पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका आंशिक कारण केंद्र द्वारा ₹1.5 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण की विशेष सहायता का प्रावधान है। 2024-25 के दौरान अब तक (24 नवंबर, 2024 तक), उक्त योजना के तहत पात्र राज्यों को ₹50,571.4 करोड़ की पूंजीगत व्यय राशि जारी की जा चुकी है।[16]

समग्र आपूर्ति

सकल आपूर्ति - जिसे मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापा जाता है - में 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 7.7 प्रतिशत थी (ति1:2024-25 में 6.8 प्रतिशत)। विकास में मंदी मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधि में कमी के कारण थी, जबकि

चार्ट III.24: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-अक्तूबर)

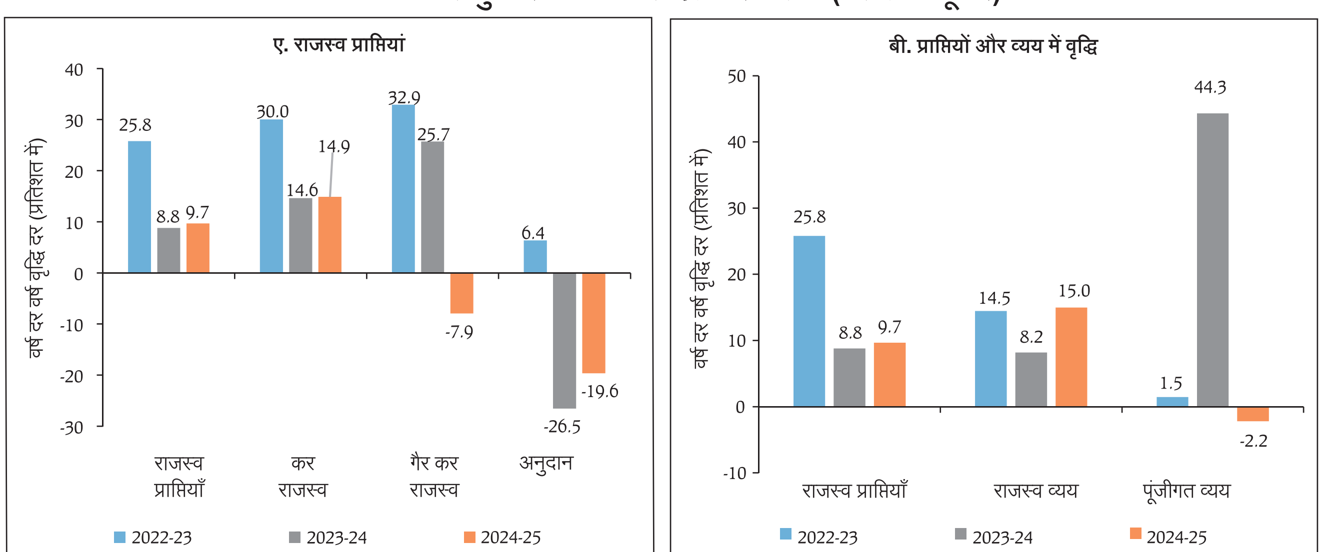

टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित हैं।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

[15] अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार।

[16] डिजिटल संसद , संसद सदस्य (एमपी) दिलीप सैकिया के प्रश्न का उत्तर ।

चार्ट III.25: जीवीए वृद्धि में भारित योगदान

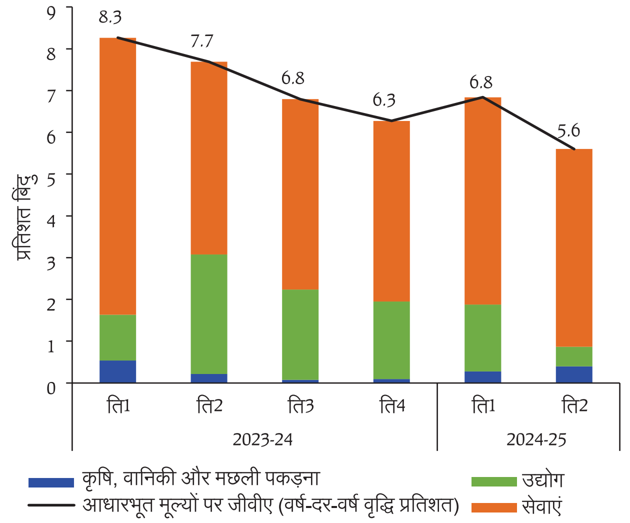

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सेवा क्षेत्र ने सुदृढ़ता दिखाया और कृषि में सुधार दर्ज किया (चार्ट III.25)।

कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में वृद्धि दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 1.7 प्रतिशत थी। यह वृद्धि 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई, जिसे सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून का समर्थन प्राप्त था।[17] औद्योगिक गतिविधि ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 13.6 प्रतिशत के प्रतिकूल आधार पर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र में, भारी वर्षा के कारण खनन और उत्खनन गतिविधि में कमी आई, जबकि विनिर्माण - प्रमुख घटक - में वृद्धि पांच तिमाहियों के निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर आ गई। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में भी वृद्धि धीमी रही। सेवा क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 की दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (2024-25 की पहली तिमाही में 7.7 प्रतिशत)। विनिर्माण गतिविधि में वृद्धि 2023-24 की दूसरी तिमाही में 13.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.7 प्रतिशत हो गई, जो आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय से कम होने को दर्शाती है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं ने साल-दर-साल और क्रमिक आधार पर वृद्धि में तेजी दर्ज की। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत हो गई, क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि में नरमी देखी गई। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

01 अक्तूबर से 19 दिसंबर के दौरान संचयी पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) वर्षा अपने दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 8 प्रतिशत कम रही, जबकि पिछले साल यह एलपीए से 4 प्रतिशत कम थी। चक्रवात फेंगल की असामान्य रूप से लंबी अवधि ने दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधि को तेज कर दिया, जिससे इस वर्ष कुछ हद तक कमी पूरी हो गई। हालांकि, कम/बहुत कम वर्षा वाले उप-विभागों की संख्या एक साल पहले की तुलना में 2024 में अधिक थी (चार्ट III.26ए)।

19 दिसंबर 2024 तक अखिल भारतीय औसत जल संग्रहण (155 प्रमुख जलाशयों के आधार पर) कुल क्षमता का 77 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के संग्रहण और दशकीय औसत से क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.26बी)। 13 दिसंबर 2024 तक कुल रबी बोया गया क्षेत्र एक साल पहले के स्तर से 0.4 प्रतिशत अधिक था।[18] जबकि गेहूं और चावल का रकबा पिछले साल के स्तर को पार कर गया, यह दालों, मोटे अनाज और तिलहन के लिए पिछले साल की तुलना में कम रहा (चार्ट III.26सी)।

16 दिसंबर, 2024 तक, खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के लिए संचयी चावल खरीद पिछले वर्ष की इसी

[17] प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 164.7 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 5.7 प्रतिशत अधिक है।

[18] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर, जिसमें 13 दिसंबर, 2024 तक पूरे सीजन के सामान्य क्षेत्र का 88 प्रतिशत कवर किया गया।

चार्ट III.26: रबी मौसम के लिए परिदृश्य

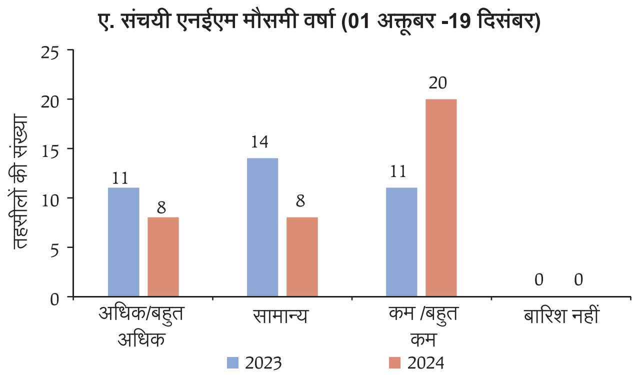

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)।

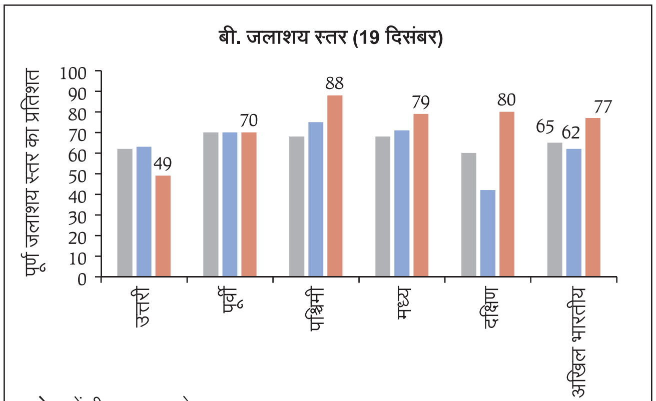

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

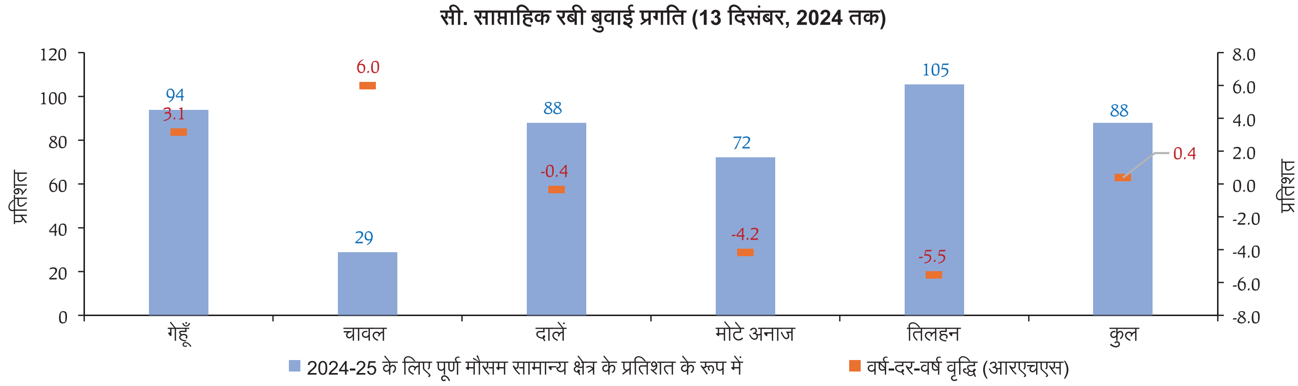

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अवधि की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक थी (चार्ट III.27)। 01 दिसंबर, 2024 तक चावल का बफर स्टॉक 515.6 लाख टन था, जो मानक से 5.0 गुना अधिक था।[19] गेहूं का स्टॉक 206 लाख टन था, जो बफर मानक के लगभग बराबर था।

चार्ट III.27: केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खरीद और भंडारण

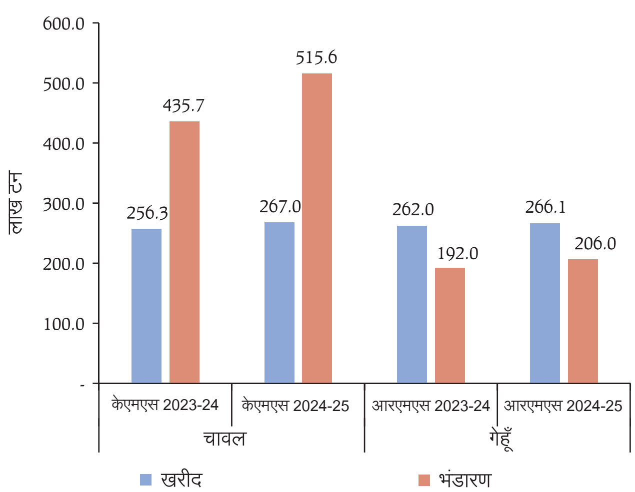

टिप्पणी : *: 19 दिसंबर तक; #: 01 दिसंबर तक।
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम।

28 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और मूल्य दबाव को कम करने के लिए मार्च 2025 तक खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से 2.5 मिलियन टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की।[20] इसके अलावा, 11 दिसंबर, 2024 को सरकार ने बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गेहूं भंडारण संस्थाओं के लिए स्टॉक सीमा को संशोधित किया।[21]

भारत के विनिर्माण पीएमआई ने क्रमिक रूप से नरमी दर्ज की, लेकिन नवंबर के दौरान विस्तार क्षेत्र में रहा क्योंकि

[19] जिसमें बिना पिसाई वाला धान समतुल्य भी शामिल है।

[20] यह बिक्री उचित एवं औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) अनाज के लिए 2,325 रुपये प्रति क्विंटल तथा कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) अनाज के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर होगी।

[21] https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2083178®=3&lang=1

चार्ट III.28: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

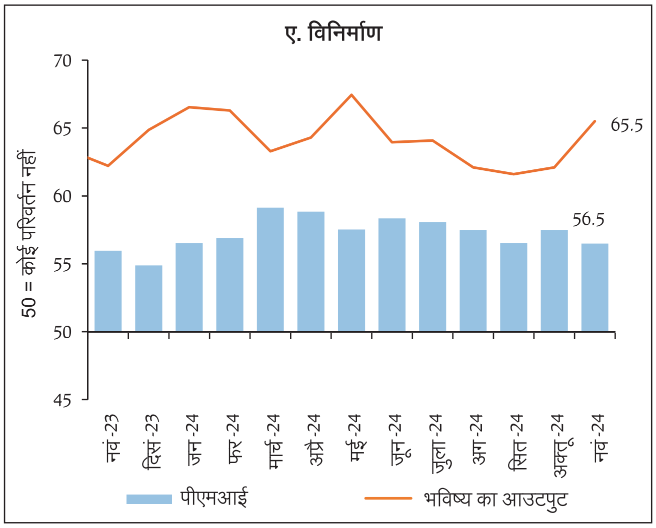

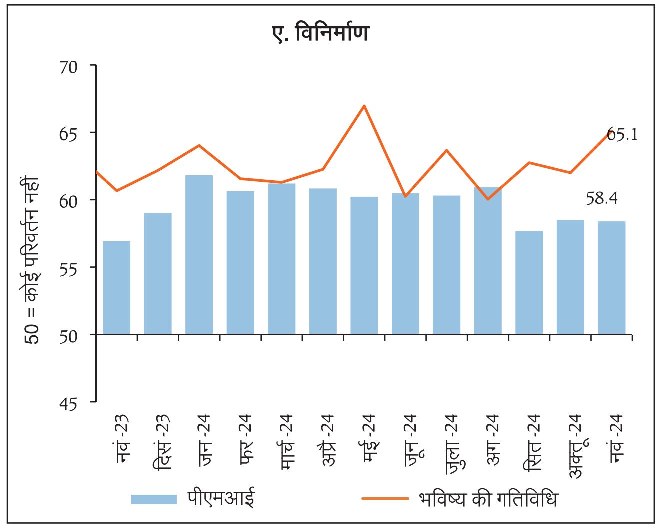

टिप्पणी : 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

बाहरी मांग - जैसा कि निर्यात ऑर्डर में वृद्धि से परिलक्षित होता है - ने समर्थन प्रदान किया (चार्ट III.28ए)। सेवाओं के पीएमआई ने मजबूत मांग और नए व्यावसायिक लाभ (चार्ट III.28बी) द्वारा संचालित मजबूत विस्तार दर्ज करना जारी रखा। विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए व्यावसायिक उम्मीदें आशावादी रहीं, जैसा कि भविष्य के उत्पादन मूल्यांकन से स्पष्ट है।

नवंबर 2024 में बंदरगाह यातायात में कमी आएगी, जिसका कारण लौह अयस्क और पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक हैं (चार्ट III.29)।

निर्माण क्षेत्र में मिश्रित तस्वीर देखने को मिली; नवंबर में इस्पात की खपत में दो अंकों की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई, जबकि अक्तूबर में सीमेंट उत्पादन की वृद्धि में कमी आई (चार्ट III.30)।

चार्ट III.29: पोर्ट कार्गो

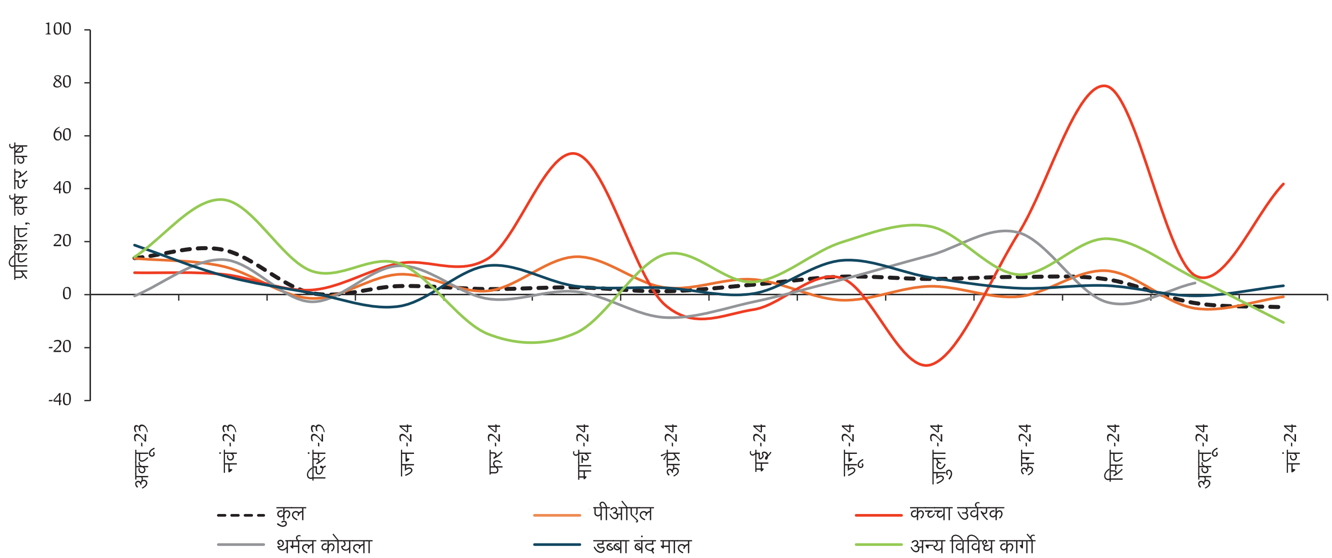

स्रोत: भारतीय बंदरगाह संघ।

चार्ट III.30: स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन

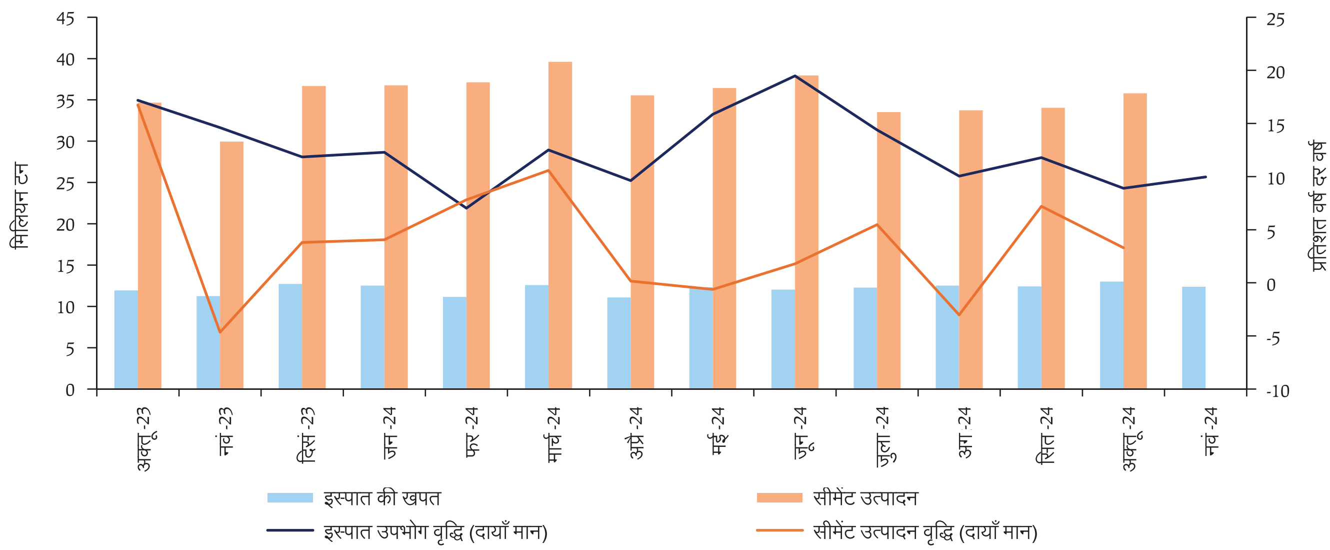

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक अक्तूबर / नवंबर में सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि को दर्शाते हैं (सारणी III.2)।

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएं

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्रक	संकेतक	अक्टू-23	नवं-23	दिसं-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्टू-24	नवं-24
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	33.9	21.0	21.7	31.9	27.0	26.0	1.3	4.0	3.1	-2.5	-1.8	-1.4	0.9	4.4
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहन बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1
	तीन पहिया वाहन बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	7.1	-0.2	-1.3
	ट्रैक्टर बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	3.2			-3.8			3.5			-11.0				
	रेलवे माल यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0		1.5	
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.2	-5.0
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	10.6	9.0	8.7	10.0	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	-28.5
	अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो यातायात*	15.0	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	3.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात *	10.7	8.7	8.1	5.0	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.6
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	17.5	19.8	18.1	17.0	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	8.7
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरा-राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1
	होटल बुकिंग	9.3	-8.6	1.6	2.6	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	
	पर्यटक आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2			
विनिर्माण	निर्माण इस्पात की खपत	15.3	14.5	13.7	12.3	7.0	12.5	11.5	13.0	21.1	13.8	10.3	11.8	8.9	10.0
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	-3.0	7.2	3.3	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4

<< संकुचन ------------------------------------ प्रसार >>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों के आधार पर है। *: नवंबर 2024 के डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएएम: रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर एवं मशीनीकरण संघ: भारतीय बंदरगाह संघ: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: एचवीएस एनारॉक: पर्यटन मंत्रालय: संयुक्त संयंत्र समिति; तथा आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)[22] में साल-दर-साल बदलाव के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत से नवंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत तक गिर गई (चार्ट III.31)। मुद्रास्फीति में लगभग 70 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट, कीमतों में महीने-दर-महीने (एमओएम) लगभग 15 बीपीएस की गिरावट और लगभग 55 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव के कारण हुई। सीपीआई खाद्य और सीपीआई ईंधन समूहों ने महीने के दौरान क्रमशः (-) 50 बीपीएस और (-) 10 बीपीएस की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूह ने लगभग 20 बीपीएस की धनात्मक गति दर्ज की।

नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 8.2 प्रतिशत रह गई, जो अक्तूबर में 9.7 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, दालों और उनके उत्पादों, फलों और चीनी में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी देखी गई, जबकि खाद्य तेलों और वसा, मांस और मछली तथा तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी। अनाज और गैर-अल्कोहल पेय समूह में मुद्रास्फीति स्थिर रही, जबकि मसालों की कीमतों में गिरावट और अधिक हो गई (चार्ट III.32)।

ईंधन और बिजली क्षेत्र में अवस्फीति नवंबर में बढ़कर (-) 1.8 प्रतिशत हो गई, जो अक्तूबर में (-) 1.7 प्रतिशत थी। ऐसा केरोसीन और एलपीजी में अपस्फीति की उच्च दर तथा बिजली में मुद्रास्फीति की कम दर के कारण हुआ।

नवंबर 2024 में कोर मुद्रास्फीति अक्तूबर में 3.8 प्रतिशत से कम होकर 3.7 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों में, परिवहन और संचार, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, तथा पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़े और जूते के लिए मुद्रास्फीति स्थिर रही। हालाँकि, आवास, घूमना-फिरना और मनोरंजन, और घरेलू सामान और सेवाओं में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.33)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, नवंबर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कम हुई, ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत रही जो शहरी मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4 से 6 प्रतिशत के बीच रही (चार्ट III.34)।

दिसंबर के लिए अब तक (19 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा में चावल की कीमतों में गिरावट देखी गई,

चार्ट III.31 : सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक

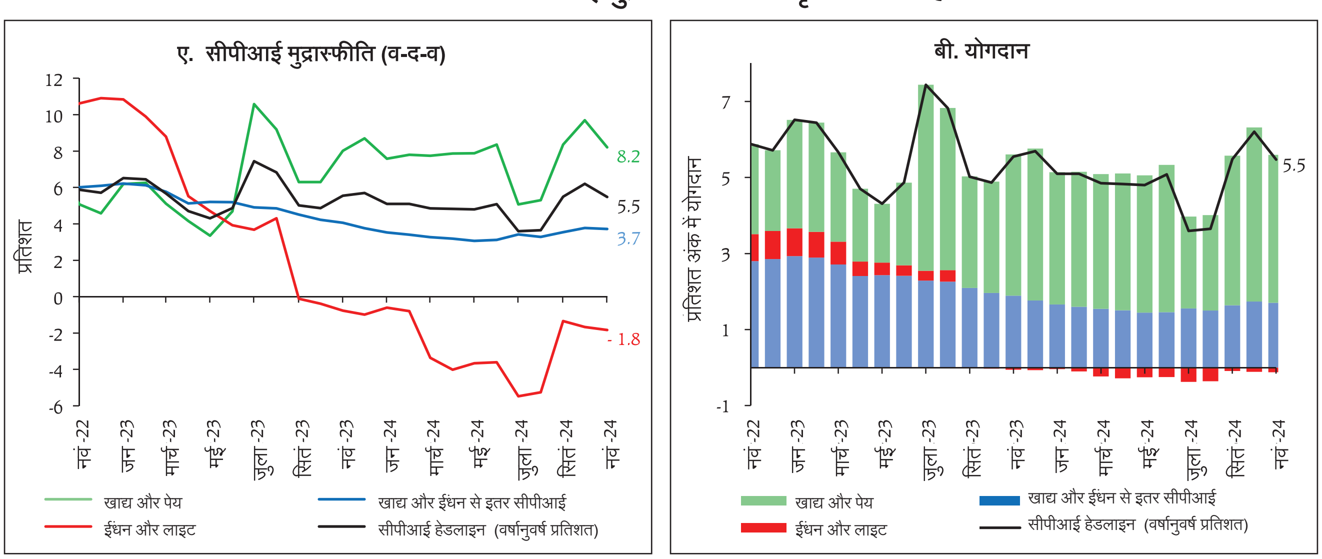

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

22 एनएसओ द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.32: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (माह- दर- माह)

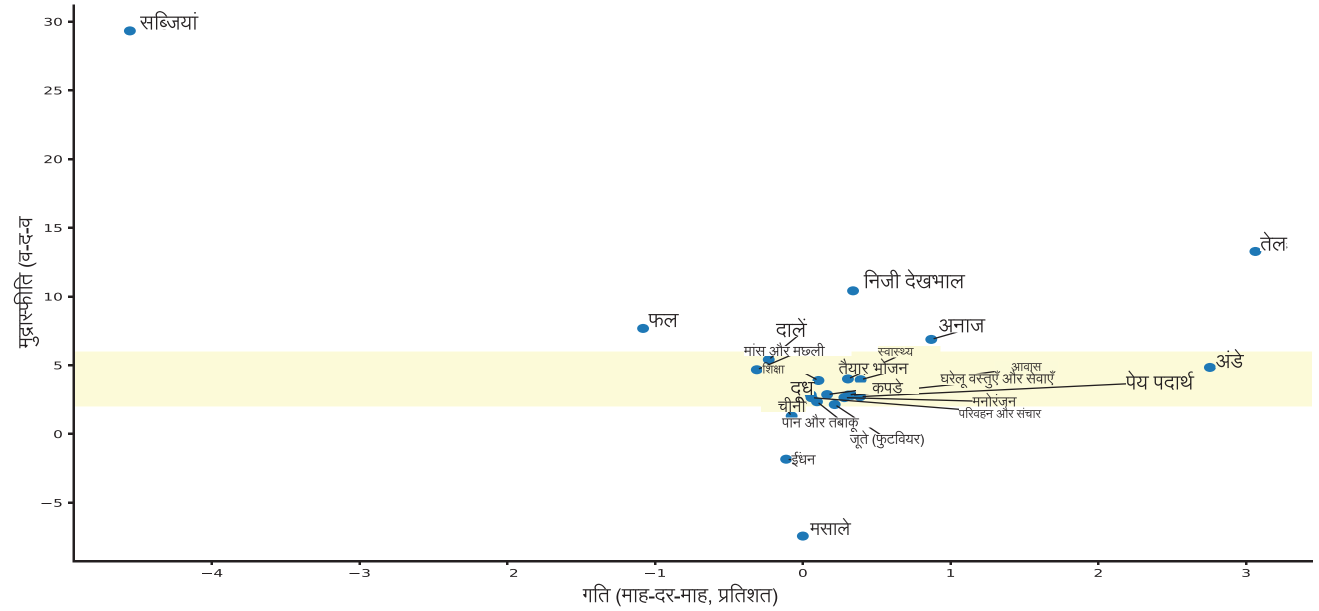

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि गेहूं और आटे की कीमतों में मजबूती जारी रही। खाद्य तेल की कीमतों में भी तेजी का दबाव जारी रहा। हालांकि, दालों की कीमतों में व्यापक गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सब्जियों में प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट आई, जबकि आलू की कीमतें सीमित दायरे में रहीं (चार्ट III.35)।

पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की खुदरा बिक्री कीमतें दिसंबर में अब तक (19 तारीख तक) अपरिवर्तित रहीं। इस अवधि के दौरान एलपीजी की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.2)।

चार्ट III.33: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (नवंबर 2024 बनाम अक्तूबर 2024)

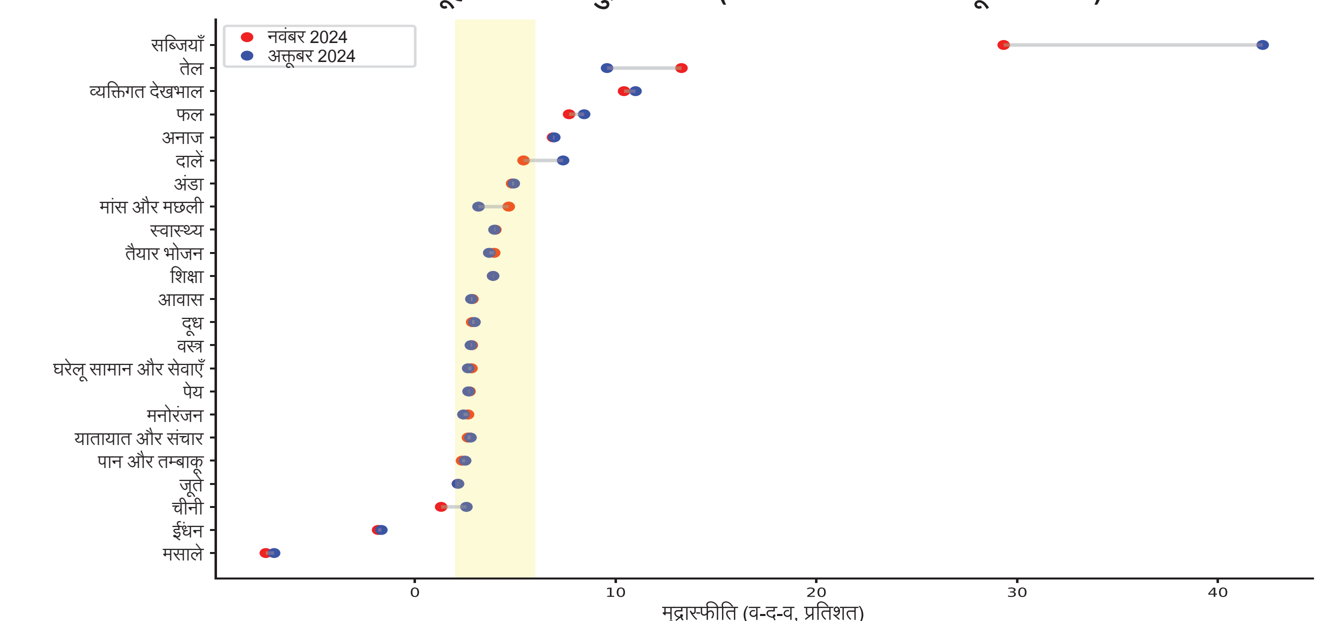

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.34: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण नवंबर 2024 (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष), (प्रतिशत)

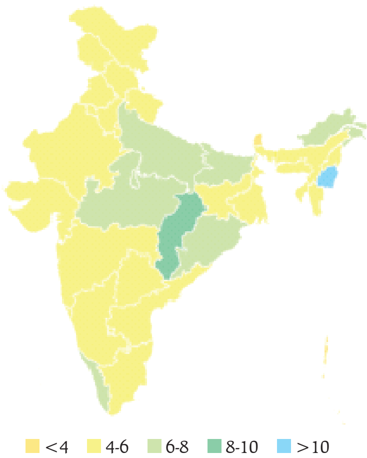

टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरणार्थ है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

Item	Unit	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिस-23	नवं-24	दिस-23	नवं-24	दिस-23
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.99	101.02	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.45	90.48	0.0	0.0
केरोसीन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	52.09	43.95	43.95	2.4	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0.0	0.0

टिप्पणि: 1. ^: 1-19 दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए।
2. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों का औसत दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पीएमआई के अनुसार, नवंबर में विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में तेज़ वृद्धि हुई, जिसमें सेवाओं में इनपुट लागत में पंद्रह महीनों में सबसे बड़ा विस्तार दर्ज किया गया। विनिर्माण और सेवा फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसमें

चार्ट III.35: डीसीए आवश्यक वस्तु मूल्य

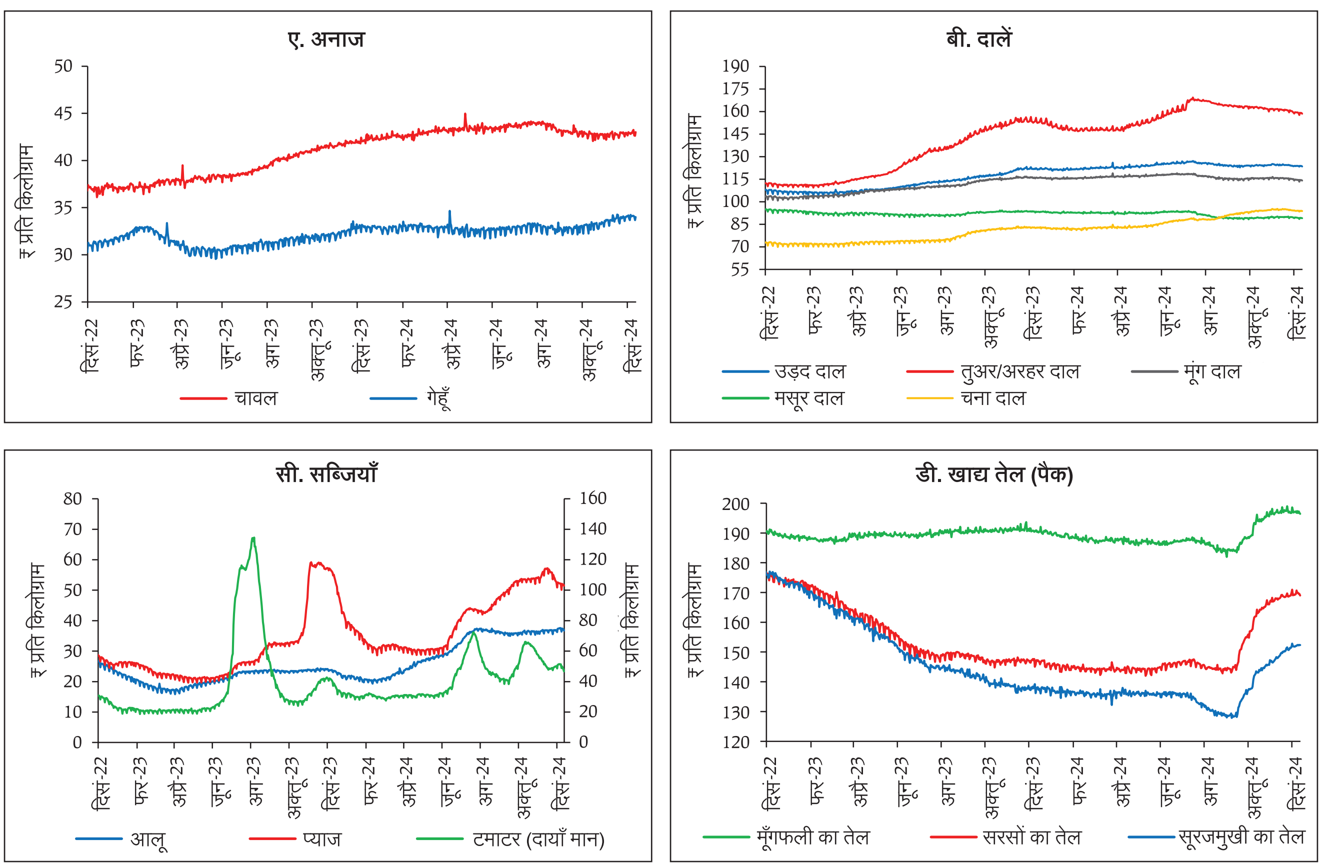

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.36: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य

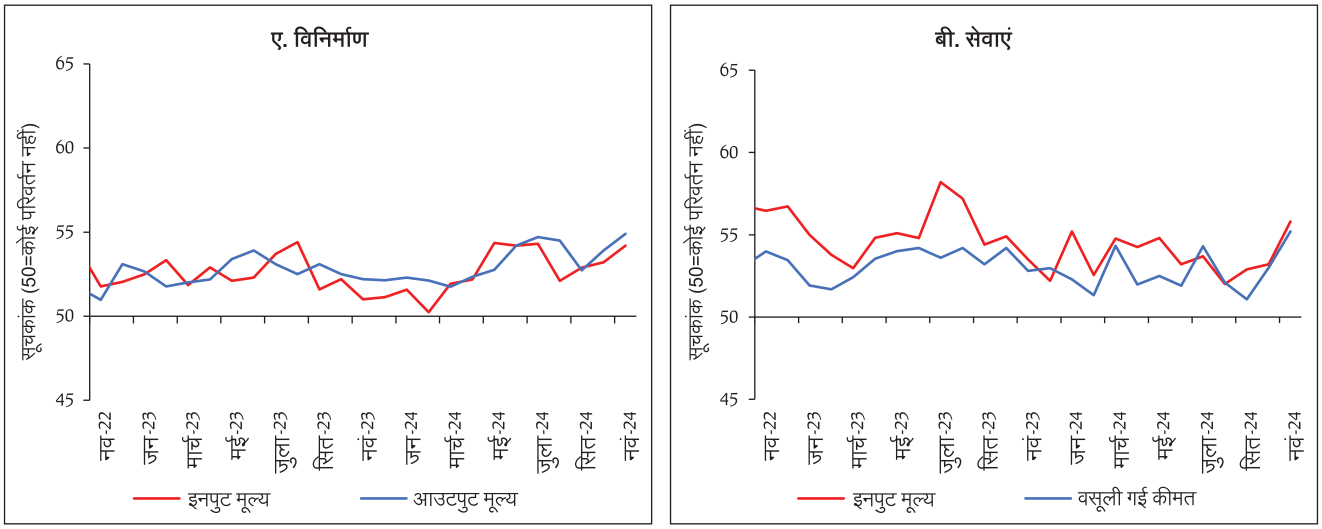

नोट : 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाता है।
स्रोत : एस एंड पी।

विनिर्माण फर्मों ने पिछले ग्यारह वर्षों में उच्चतम दर दर्ज की, और सेवा फर्मों ने लगभग बारह वर्षों में उत्पादन मूल्य वृद्धि की सबसे तेज़ गति दर्ज की (चार्ट III.36)।

मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा सितंबर के स्तर से नवंबर 2024 में 30 आधार अंकों (बीपीएस) तक बढ़ गई। उनकी एक साल आगे की मुद्रास्फीति की उम्मीदें 10 बीपीएस बढ़ गईं, जबकि तीन महीने आगे की उम्मीदें 10 बीपीएस तक गिर गईं (चार्ट III.37)।

10 प्रमुख शहरों से संपत्ति पंजीकरण डेटा के आधार पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) में 2024-25 की दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.3 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 3.5 प्रतिशत थी (चार्ट III.38)।

चार्ट III.37: परिवारों की औसत मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं

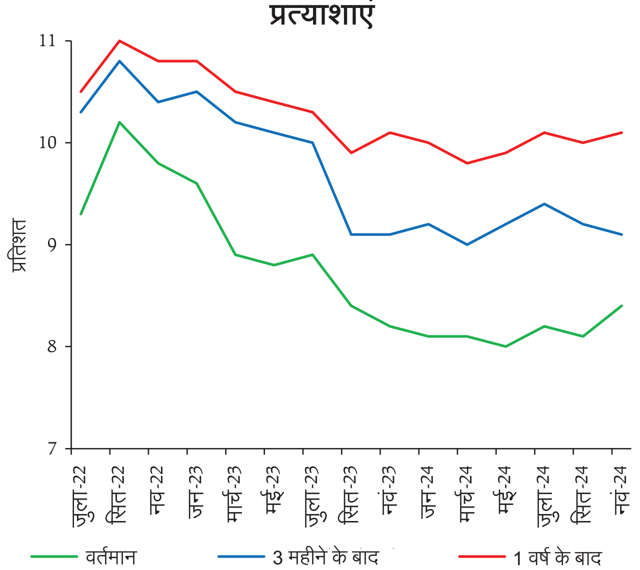

स्रोत: घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट III.38: आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

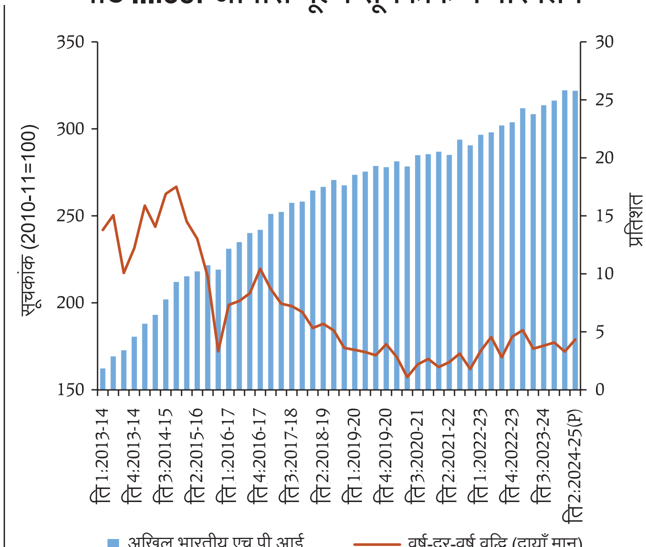

टिप्पणी : पी. डेटा अनंतिम हैं
स्रोत: राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरण; तथा भारतीय रिज़र्व बैंक।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

नवंबर 2024 की दूसरी छमाही में प्रणालीगत चलनिधि में कमी आई, क्योंकि माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि हुई, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि हुई और पूंजी बहिर्वाह हुआ। नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान यह घाटे में बदल गया, इससे पहले कि दिसंबर की शुरुआत में अधिक सरकारी खर्च के कारण इसमें कमी आए। अग्रिम कर भुगतान के कारण 16-19 दिसंबर, 2024 के दौरान प्रणालीगत चलनिधि फिर से घाटे में बदल गई। हालांकि, औसतन, नवंबर की दूसरी छमाही और दिसंबर की शुरुआत में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2024 के दौरान ₹1.72 लाख करोड़ से घटकर 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान ₹0.39 लाख करोड़ हो गया (चार्ट IV.1)। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में एक मुख्य और तीन फाइन-ट्यूनिंग वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन किए गए, जिससे बैंकिंग प्रणाली से कुल मिलाकर ₹0.99 लाख करोड़ की रकम प्राप्त हुई। हालांकि, बड़े जीएसटी बहिर्वाह के कारण अस्थायी नकदी की तंगी को कम करने के लिए, 22-28 नवंबर, 2024 के दौरान 1-6 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले चार फाइन-ट्यूनिंग वेरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) परिचालन किए गए, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर ₹1.0 लाख करोड़ की रकम आई। इसके अलावा, अग्रिम कर भुगतान के कारण नकदी की तंगी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 09-20 दिसंबर, 2024 के दौरान एक मुख्य और छह फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालन किए, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर ₹4.4 लाख करोड़ की रकम आई।

जुलाई-नवंबर के दौरान प्रणाली में चलनिधि पर्याप्त रही, लेकिन करों के बहिर्वाह, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के कारण आगामी महीनों में इसमें कमी आने की संभावना है। संभावित चलनिधि दबाव को कम करने के लिए, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 14 दिसंबर, 2024 और 28 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस प्रत्येक के दो बराबर किस्तों में घटाकर निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया, इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में संचयी रूप से लगभग ₹1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि जारी की गई।

16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान ₹0.92 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का निवेश लगभग 88 प्रतिशत रहा। 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

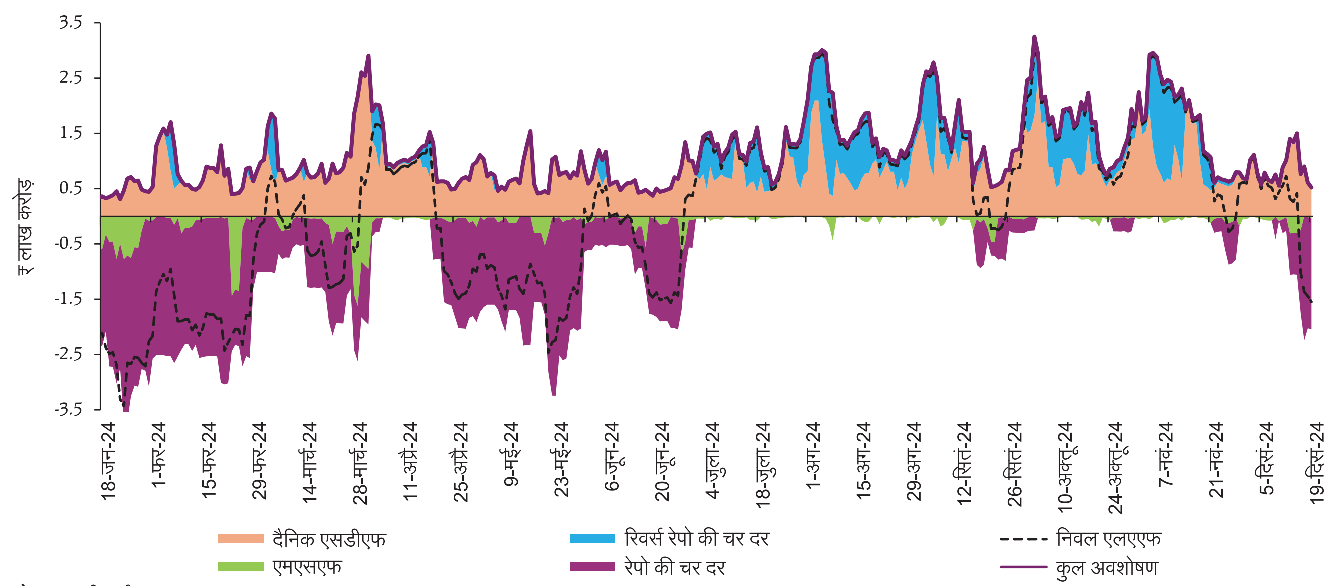

स्रोत: आरबीआई।

(एमएसएफ) का औसत सहारा ₹0.08 लाख करोड़ पर कम रहा।

एकदिवसीय मुद्रा बाजार में, भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) एलएएफ कॉरिडोर के भीतर रही, जो 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान औसतन 6.62 प्रतिशत रही, जो 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2024 के दौरान 6.48 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट IV.2ए)। डबल्यूएसीआर 22-29 नवंबर और 10-19 दिसंबर के दौरान थोड़े समय के लिए मजबूत हुई, हालांकि यह नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही। संपार्श्विकृत्त खंड में, त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो दोनों दरें 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान नीतिगत रेपो दर से क्रमशः 6 आधार अंक (बीपीएस) और 5 बीपीएस अधिक रहीं (चार्ट IV.2बी)। द्वितीयक बाजार में, 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) और सीडी दरों का प्रसार दिसंबर 2024 (19 दिसंबर तक) के दौरान - एक साल पहले 104 बीपीएस और 44 बीपीएस से अधिक क्रमशः 109 बीपीएस और 77 बीपीएस रहा (चार्ट IV.2c)। हालाँकि अधिशेष चलनिधि की अवधि के दौरान प्रसार कम हो जाता है, लेकिन हाल के महीनों में मुख्य रूप से दिसंबर की दूसरी छमाही को छोड़कर 91-दिवसीय टी-बिल दरों में गिरावट के कारण वे बढ़ गए हैं।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से कम हुआ। इस अवधि के दौरान 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दरें सीमित रहीं (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने के सीपी और 91 दिन के टी-बिल दरों के बीच विस्तारित) में 3 बीपीएस की गिरावट आई।

चार्ट IV.2 : नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर

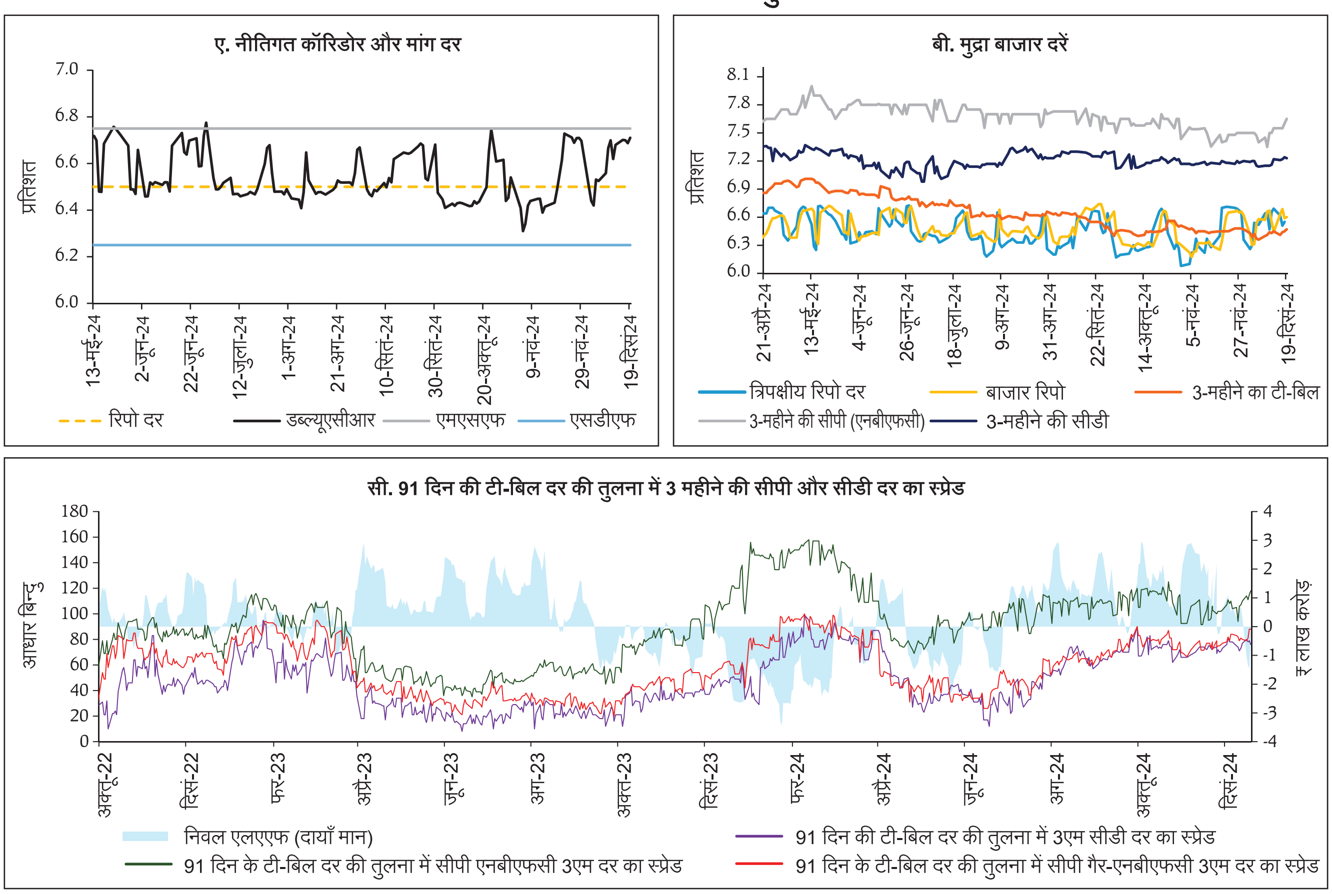

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.3: डब्ल्यूएडीआर और डबल्यूएईआईआर

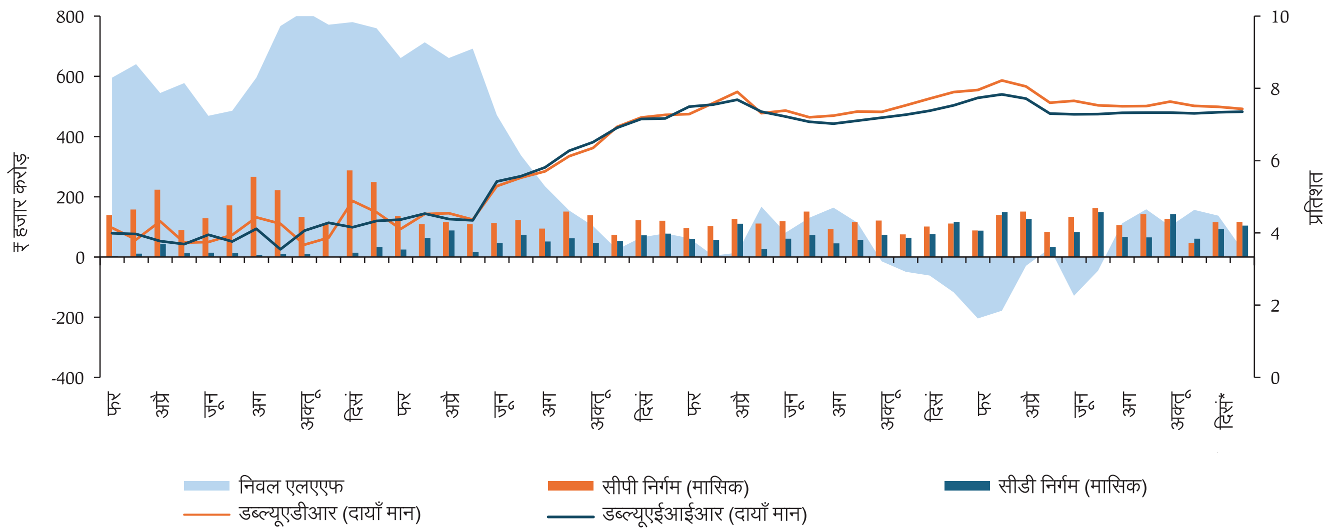

टिप्पणी: *: 19 दिसंबर 2024 तक।
स्रोत: आरबीआई; और सीसीआईएल-एफटीआईआरएसी।

दिसंबर 2024 (19 दिसंबर तक) में सीपी की भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) 7.43 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.89 प्रतिशत से कम है, क्योंकि आगे चलकर ब्याज दरें कम रहने की उम्मीद है (चार्ट IV.3)। साथ ही, सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डबल्यूएईआईआर) एक साल पहले के 7.52 प्रतिशत से कम होकर 7.36 प्रतिशत (19 दिसंबर, 2024 तक) हो गई, क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया।

प्राथमिक बाजार में, अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान सीडी निर्गमन 68 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹6.88 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹4.09 लाख करोड़ से काफी अधिक है, जो बैंकों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को दर्शाता है (चार्ट IV.4)। 2024-25 (नवंबर तक) के दौरान सीपी

चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

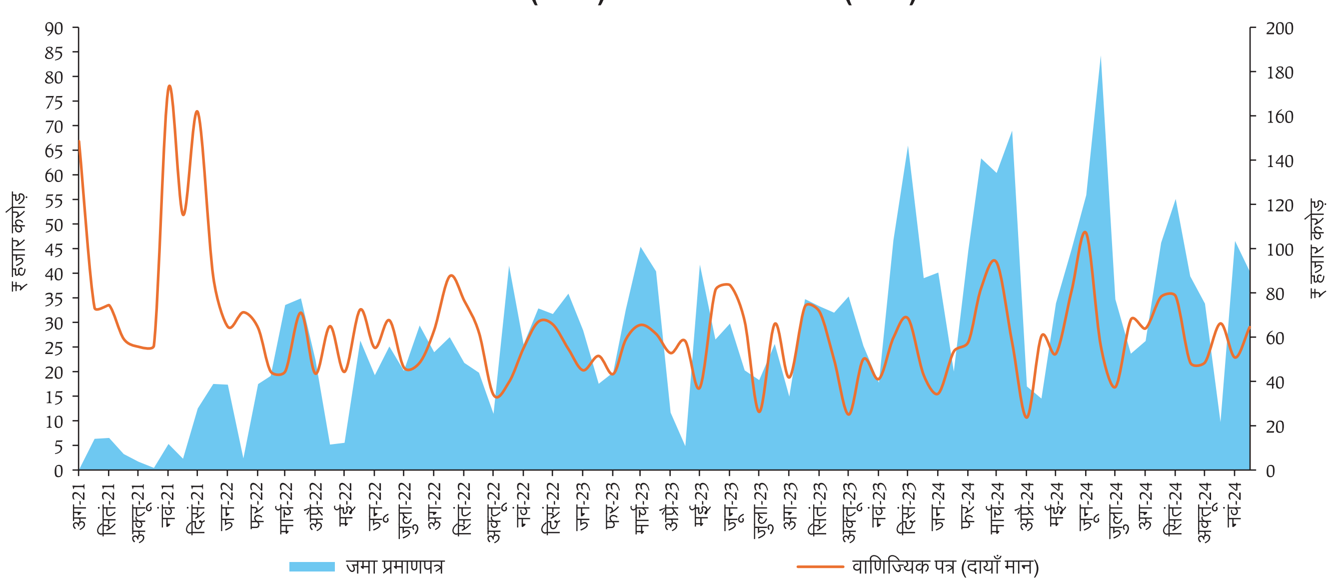

स्रोत: आरबीआई।

निर्गमन ₹9.85 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹8.85 लाख करोड़ से अधिक था। नवंबर 2023 में रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के साथ, ये संस्थाएँ संसाधन जुटाने के लिए वैकल्पिक बाज़ार साधनों पर निर्भर हो गई हैं।

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि अमेरिकी खजाना प्रतिफल में मजबूती आई। 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में अपेक्षा से अधिक मंदी की पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की उम्मीदों पर बेंचमार्क प्रतिफल 4 दिसंबर, 2024 को लगभग तीन वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई (चार्ट IV.5a)। जी-सेक प्रतिफल वक्र अवधि संरचना के मध्य खंड के साथ नीचे की ओर खिसक गया। 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान, औसत अवधि स्प्रेड (10-वर्ष माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 36 बीपीएस (चार्ट IV.5b) पर स्थिर रहा।

10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर प्रसार 19 दिसंबर, 2024 को 222 बीपीएस तक गिर गया, जो सितंबर के मध्य में 310 बीपीएस और एक साल पहले 324 बीपीएस था। 29 नवंबर, 2024 के बाद घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई और दिसंबर की शुरुआत में यह तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। अक्तूबर और नवंबर में निकासी के बाद दिसंबर 2024 में घरेलू ऋण साधनों में एफपीआई प्रवाह धनात्मक हो गया। भारतीय बॉण्ड बाजार में प्रतिफल की अस्थिरता अमेरिकी खजाना के सापेक्ष कम बनी हुई है (चार्ट IV.6)।

हाल के महीनों में कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की गति बढ़ गई है क्योंकि कॉरपोरेट्स ने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने के लिए कम प्रतिफल का लाभ उठाया है। कुल मिलाकर, 2024-25 (नवंबर तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹4.99 लाख करोड़ की तुलना में ₹6.06 लाख करोड़ अधिक था। रेटिंग और अवधि स्पेक्ट्रम में कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में आम तौर पर गिरावट आई, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम आम तौर पर 18 नवंबर से 18 दिसंबर, 2024 के दौरान बढ़ गया (सारणी IV.1)।

13 दिसंबर, 2024 तक रिज़र्व मनी (आरएम) में 6.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 6.4 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 13 दिसंबर, 2024 तक 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 3.9 प्रतिशत थी।

चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में विकास

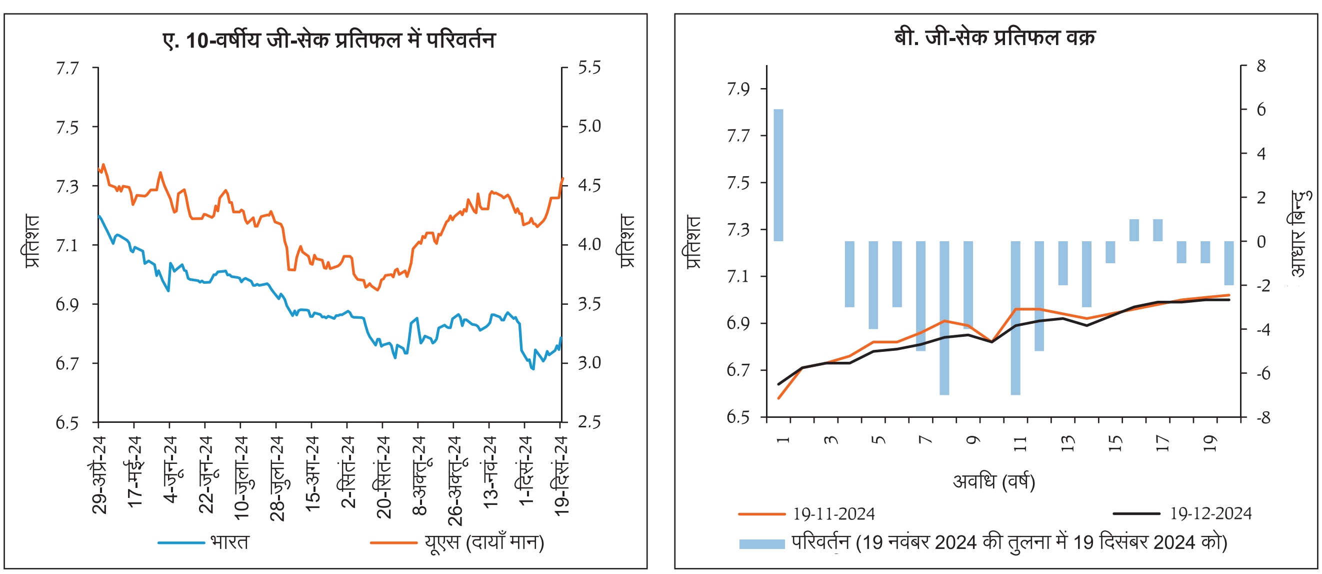

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ आकलन।

चार्ट IV.6: अस्थिरता और स्प्रेड-बॉण्ड बाजार

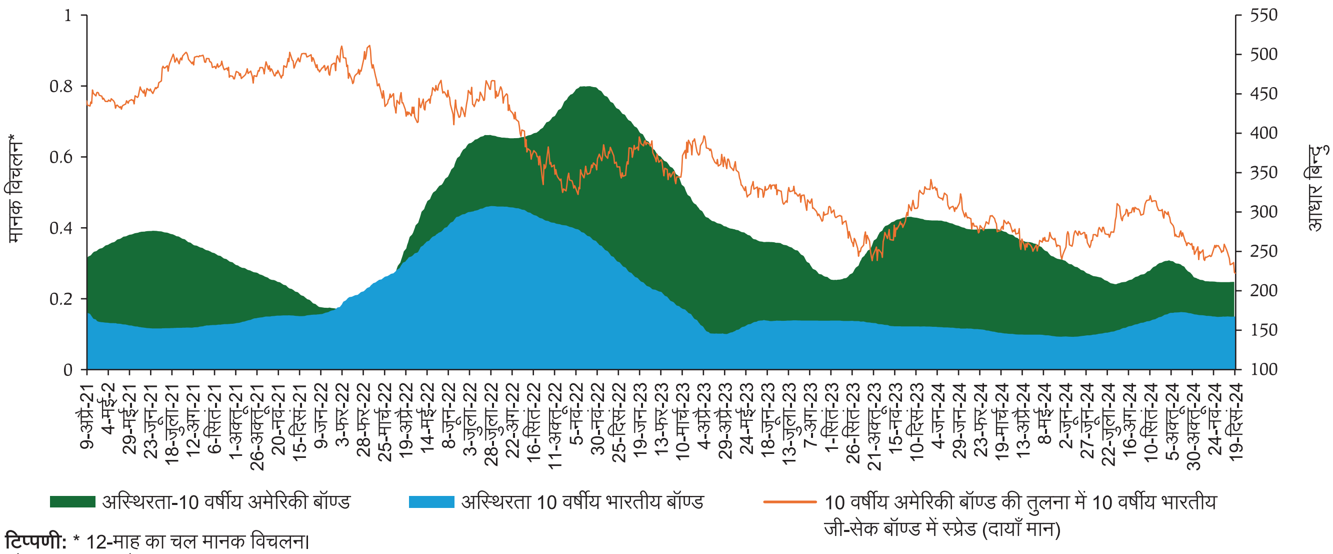

टिप्पणी: * 12-माह का चल मानक विचलन।
स्रोत: ब्लूमबर्ग: और आरबीआई स्टाफ की गणना।

स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 13 दिसंबर, 2024 तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 5.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। सोने - एनएफए का एक प्रमुख घटक - में 46.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सोने की कीमतों से पुनर्मूल्यांकन लाभ था। परिणामस्वरूप, एनएफए में इसकी हिस्सेदारी अक्तूबर 2023 के अंत में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 13 दिसंबर, 2024 तक 10.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.8)।

मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 10.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.2 प्रतिशत)।[23] बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम3 का लगभग 87 प्रतिशत है, में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 12.2 प्रतिशत)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 29 नवंबर 2024 तक 11.8 प्रतिशत तक कम हो गई (एक वर्ष पहले 16.3 प्रतिशत) [चार्ट IV.9]।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और प्रसार

	ब्याज दरें (प्रतिशत)			प्रसार (आधार अंक) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)		
लिखत	18 अक्तू, 2024 – 18 नवं, 2024	18 नवंबर, 2024 18 दिसंबर, 2024	उतार-चढ़ाव	18 अक्तू, 2024 – 18 नवं, 2024	18 नवंबर, 2024 18 दिसंबर, 2024	उतार-चढ़ाव
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.79	7.82	3	111	114	3
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.75	7.68	-7	90	88	-2
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.61	7.60	-1	72	75	3
(iv) एए (3-वर्ष)	8.50	8.47	-3	166	167	1
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.14	12.12	-2	530	533	3

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

[23] किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और संचलन में मुद्रा

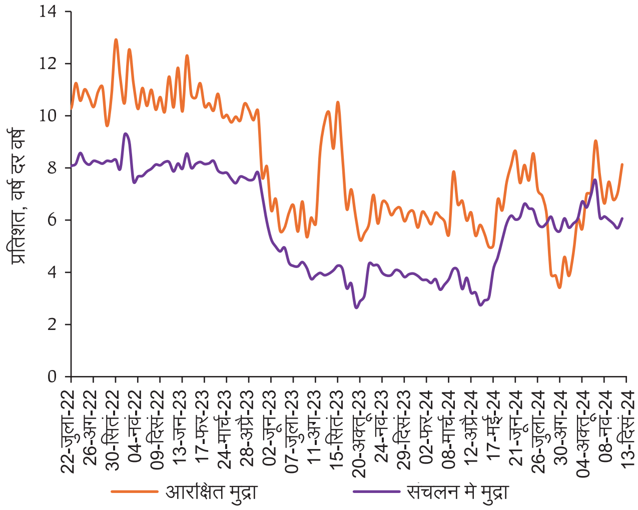

टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 13 दिसंबर 2024 तक का है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि

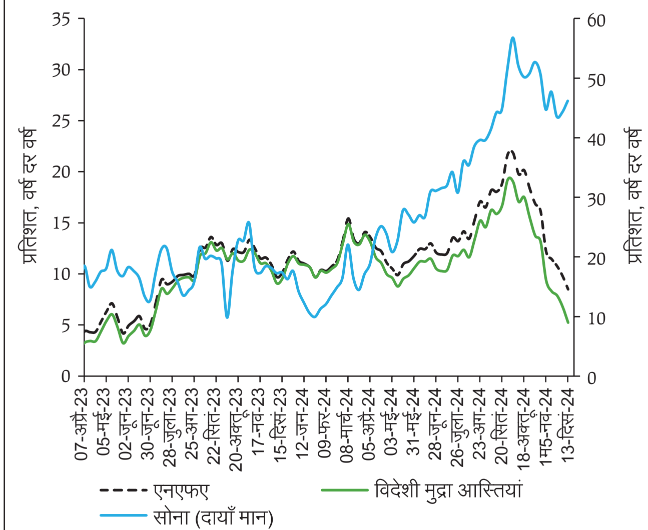

स्रोत: आरबीआई।

व्यक्तिगत ऋण (आवास और गैर-आवास) सितंबर 2024 तक समग्र ऋण विस्तार का प्रमुख चालक बने रहे; उद्योग को ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.10)।

एससीबी द्वारा दिया जाने वाला ऋण, जो कुल बैंक ऋण का लगभग एक चौथाई है, पिछली तिमाही में दर्ज की गई उच्च वृद्धि से 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान कम हो गया (चार्ट IV.11)। जबकि कार्यशील पूंजी ऋणों में वृद्धि लगातार दूसरी तिमाही में तेज हुई, सावधि ऋणों में वृद्धि में कमी जारी रही (चार्ट IV.12)।

चार्ट IV.9: एम3 वृद्धि और एससीबी के ऋण वृद्धि का आधार प्रभाव और गति

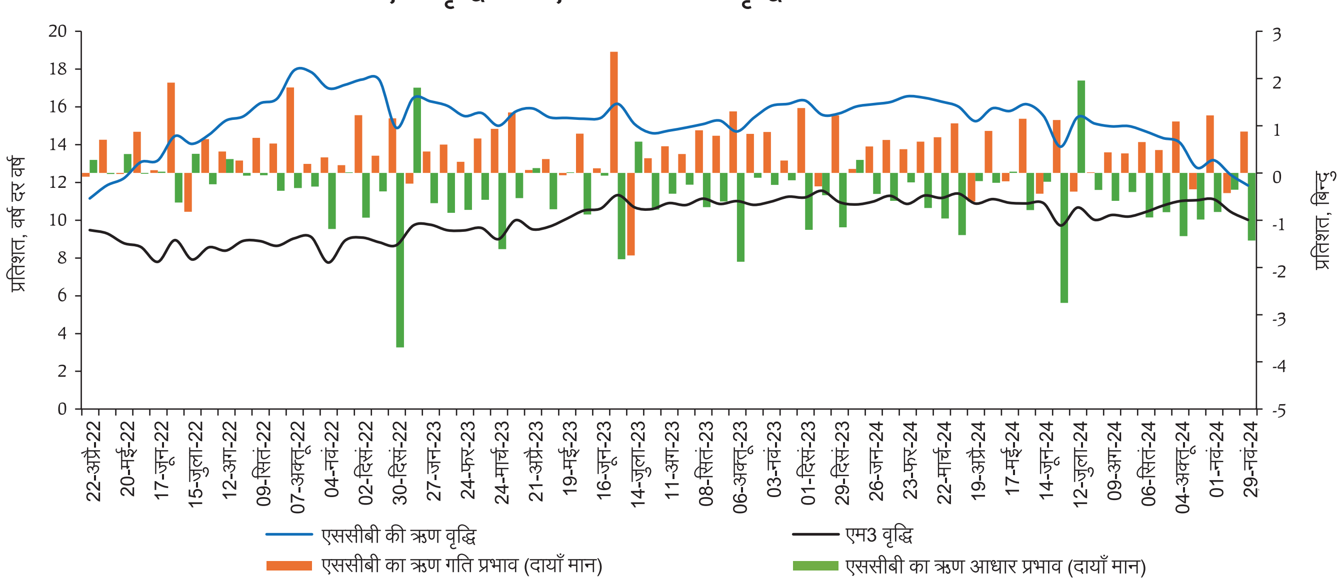

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.10: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि - प्रमुख क्षेत्रक

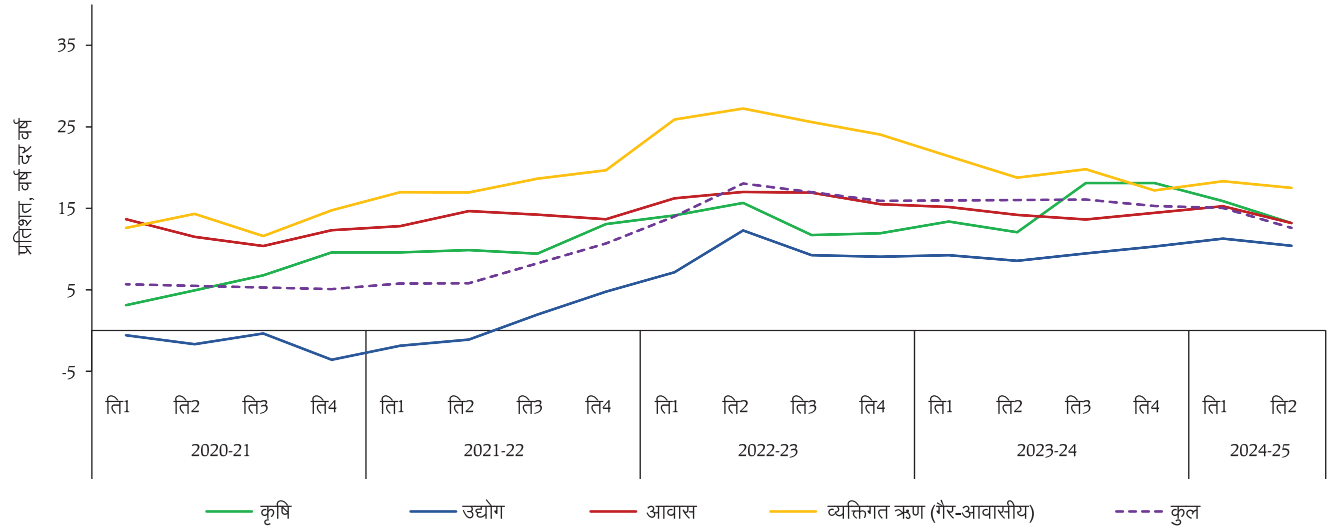

टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।
स्रोत: आरबीआई।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) अगस्त 2024 के अंत में 11.3 प्रतिशत से घटकर 29 नवंबर 2024 को 11.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.13)।

हाल ही में मौद्रिक नीति सख्त करने के चक्र के दौरान, चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों में वृद्धि सावधि जमाराशियों में वृद्धि से आगे निकल गई। कुल जमाराशियों में सावधि जमाराशियों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में बढ़कर 61.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 59.8 प्रतिशत और मार्च 2023 में 57.2 प्रतिशत थी (चार्ट IV.14)। कुल सावधि जमाराशियों में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाली सावधि जमाराशियों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में बढ़कर 68.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 54.7 प्रतिशत, मार्च

चार्ट IV.11: वार्षिक ऋण वृद्धि - उधारकर्ताओं की प्रमुख स्वामित्व श्रेणी

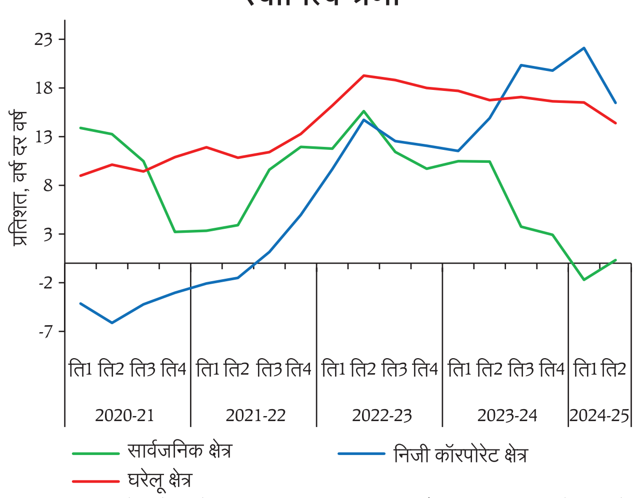

टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.12: वार्षिक ऋण वृद्धि - ऋण प्रकार

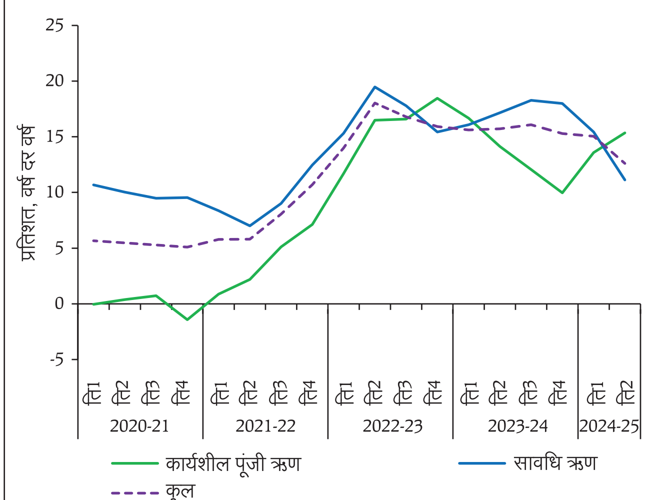

टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.13: एससीबी की जमा वृद्धि - आधार प्रभाव और गति

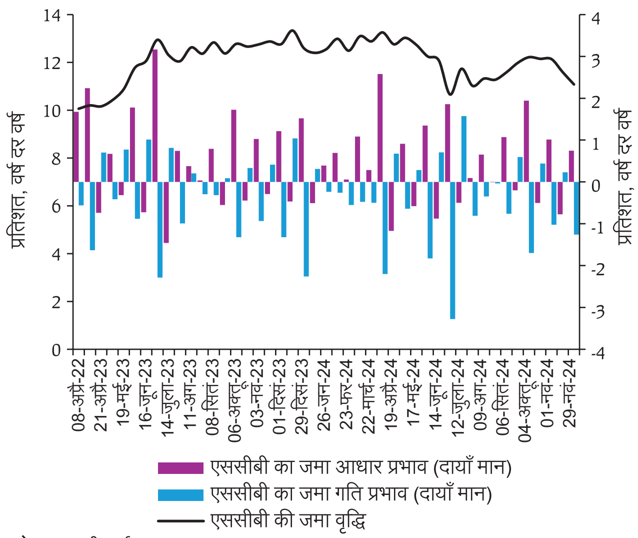

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.14: कुल जमा में वार्षिक वृद्धि - जमा के प्रकार

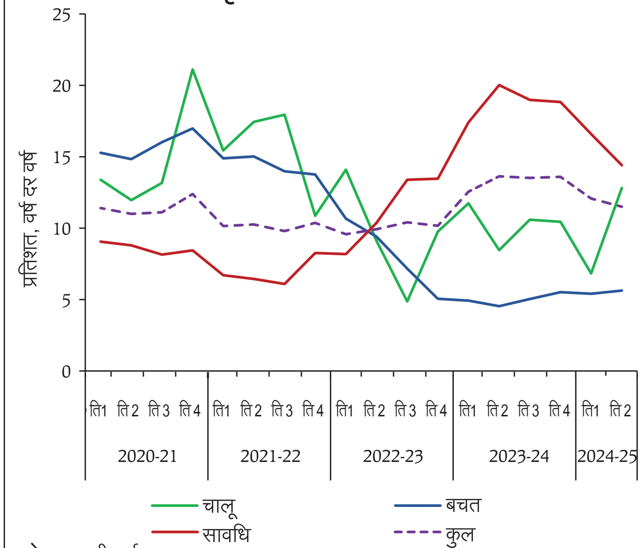

स्रोत: आरबीआई।

2023 में 33.7 प्रतिशत और मार्च 2022 में 4.5 प्रतिशत थी (चार्ट IV.15)।

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 29 नवंबर, 2024 को 82.5 हो गया, जिसमें वृद्धिशील जमा अगस्त-नवंबर 2024 (29 नवंबर तक) के दौरान वृद्धिशील ऋण से आगे निकल गया [चार्ट IV.16]। सीआरआर और एसएलआर के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वैधानिक आवश्यकताओं के साथ, 29 नवंबर, 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास लगभग 77 प्रतिशत जमा उपलब्ध था।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के प्रतिक्रिया में, बैंकों ने अपने रेपो लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को इसी परिमाण से संशोधित किया है। मई 2022 से नवंबर 2024 के दौरान निधि-आधारित

चार्ट IV.15: बैंकों की सावधि जमाओं का ब्याज दर-वार हिस्सा

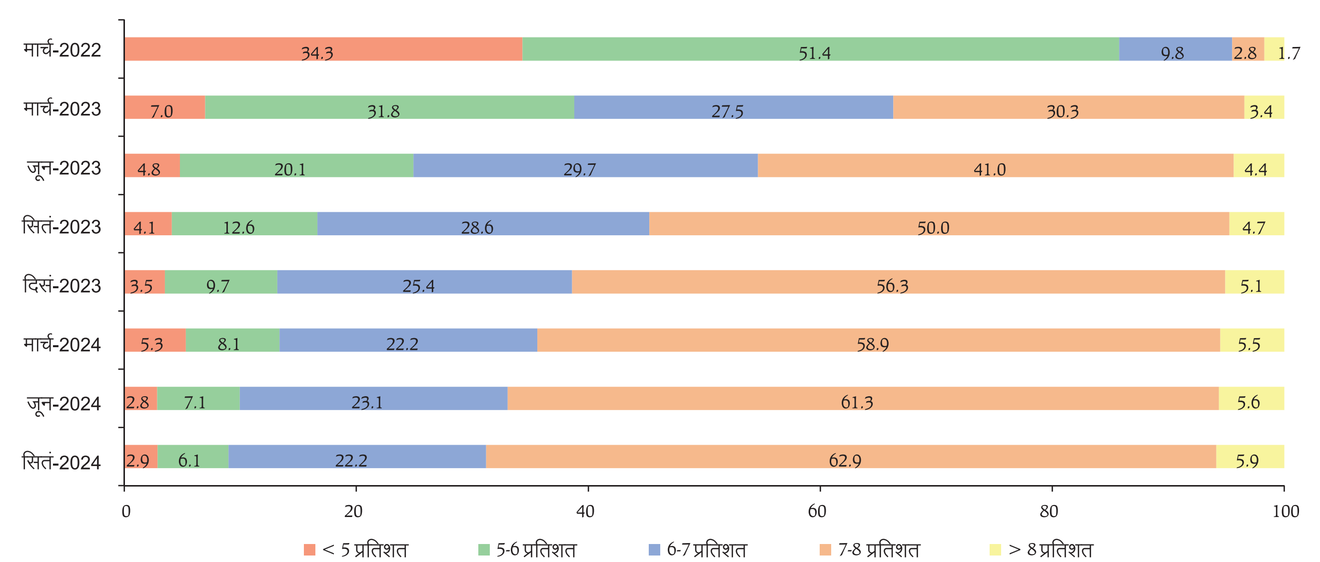

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.16: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

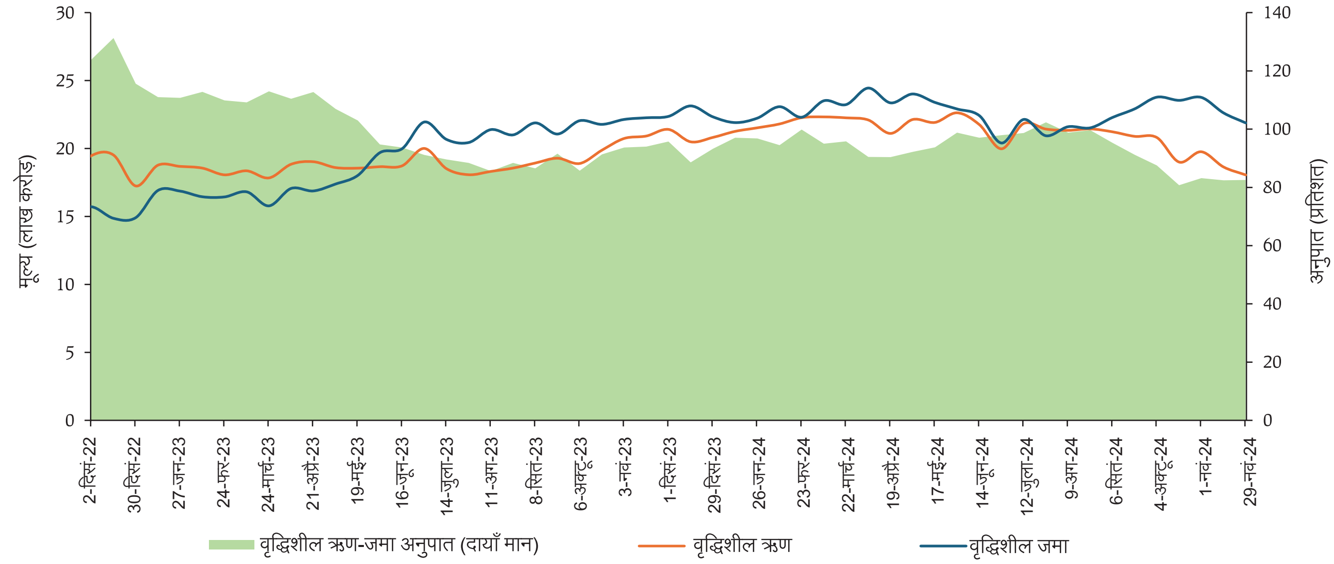

स्रोत: आरबीआई।

उधार दर (एमसीएलआर) की औसत 1-वर्षीय सीमांत लागत में 170 बीपीएस की वृद्धि हुई। नतीजतन, मई 2022 से अक्तूबर 2024 के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 203 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा पक्ष पर, इसी अवधि के दौरान नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 241 बीपीएस और 193 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.17)।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपए ऋणों पर डबल्यूएएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक थी। हालांकि, बकाया ऋणों के मामले में, पीएसबी के बीच संचरण कम था। जमाराशियों में, मई 2022 और अक्तूबर 2024 के दौरान

चार्ट IV.17: एससीबी की जमा और उधार दरों में संचरण

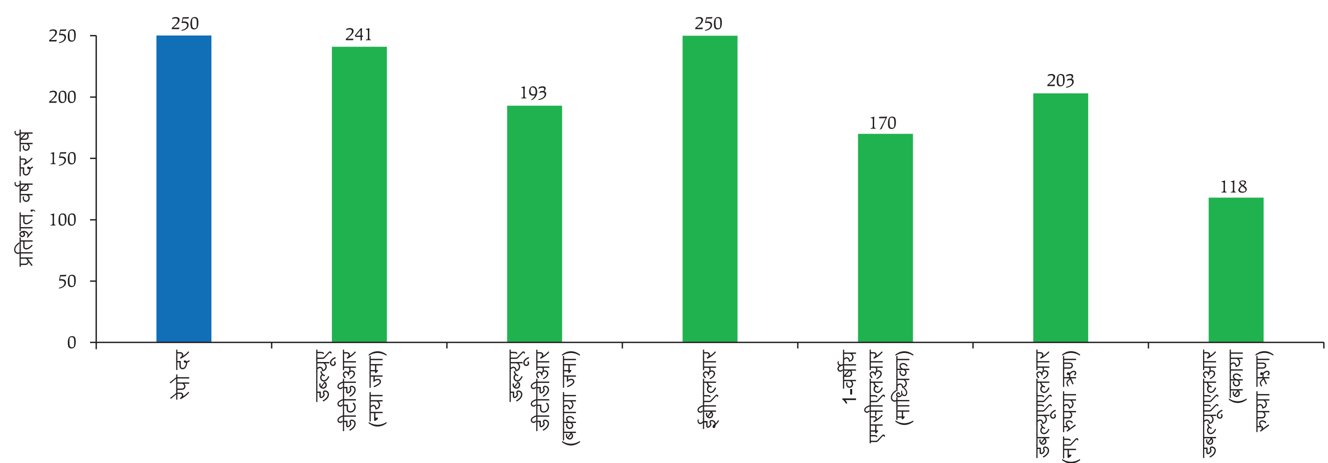

टिप्पणियाँ: 1. ईबीएलआर के आंकड़े 32 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
2. ईबीएलआर और एमसीएलआर के आंकड़े नवंबर 2024 तक के हैं।
3. डबल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर: डब्ल्यूएडीटीडीआर : भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर: एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.18: बैंक समूहों के बीच संचरण (मई 2022 से अक्तूबर 2024)

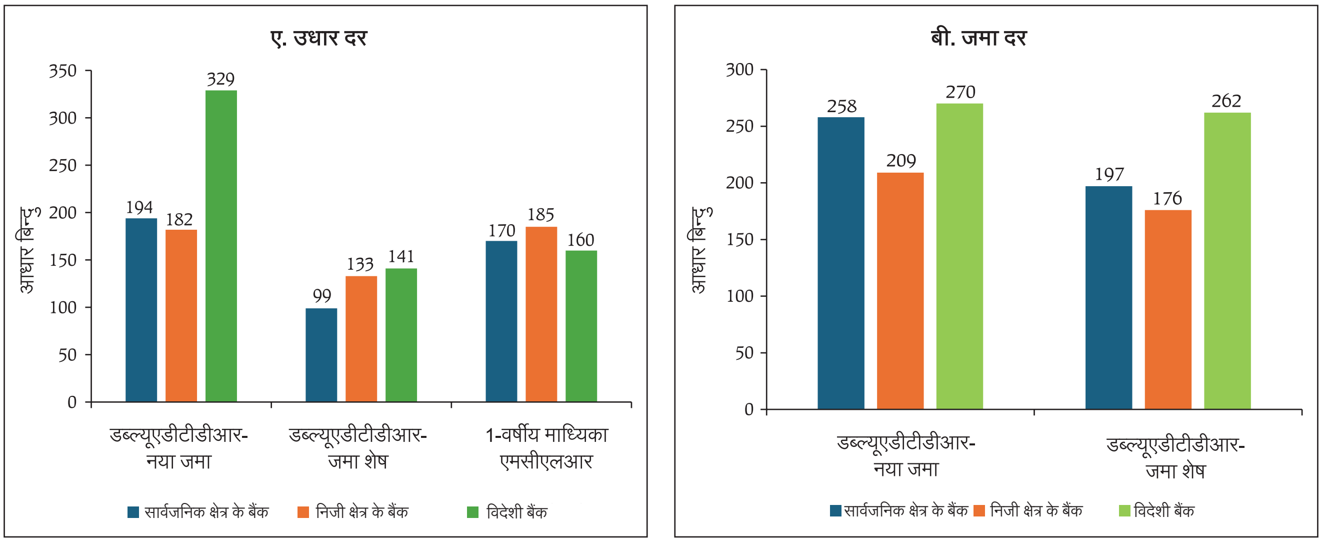

नोट : 1 साल के औसत एमसीएलआर पर डेटा मई 2022 से अक्तूबर 2024 की अवधि से संबंधित है।
स्रोत : आरबीआई।

पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए नए और बकाया दोनों जमाराशियों के डब्ल्यूएडीटीडीआर में संचरण अधिक था (चार्ट IV.18)।

नवंबर के पहले तीन सप्ताहों में भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें कमज़ोर कॉरपोरेट आय, एफपीआई की बिकवाली, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ और मूल्यांकन संबंधी चिंताएँ शामिल थीं। हालाँकि, राज्य चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद महीने के अंत में बाज़ारों में उछाल आया और दिसंबर की शुरुआत सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मज़बूती के साथ हुई। इसके बाद, प्रमुख मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले बाज़ारों में गिरावट देखी गई, जो 2025 में ब्याज दरों में कम कटौती के बारे में यूएस फ़ेड द्वारा दिए गए संकेतों से और बढ़ गई। कुल मिलाकर, 14 नवंबर, 2024 से बीएसई सेंसेक्स में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 19 दिसंबर, 2024 को 79,218 पर बंद हुआ

चार्ट IV.19: इक्विटी बाज़ारों में रुझान

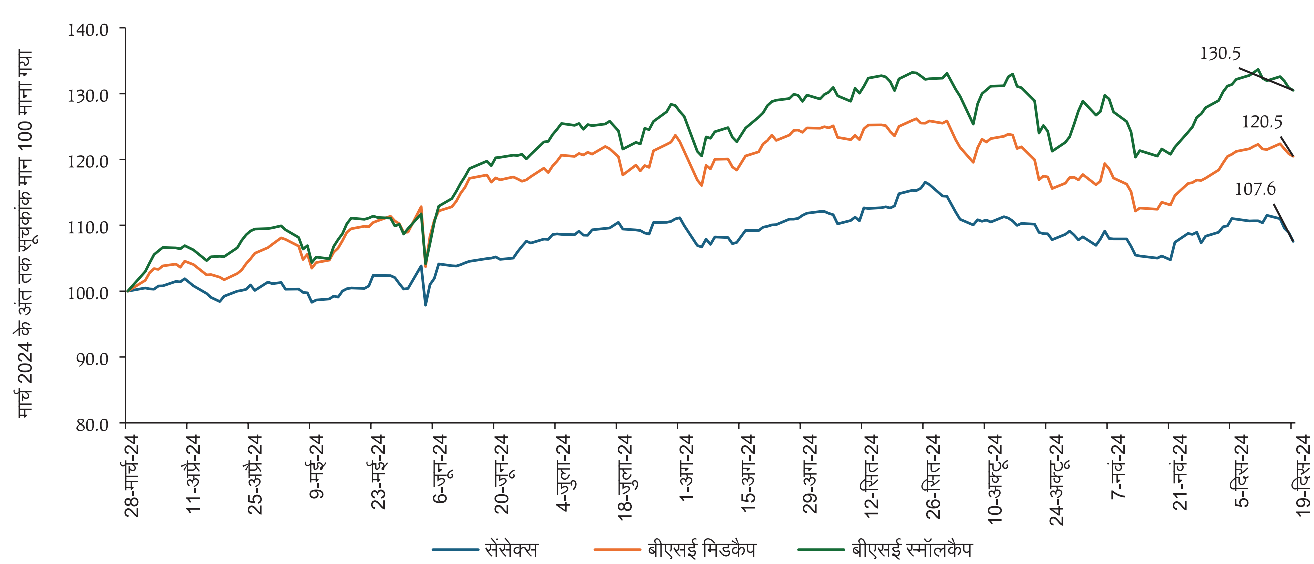

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.20: आईपीओ का औसत लिस्टिंग रिटर्न

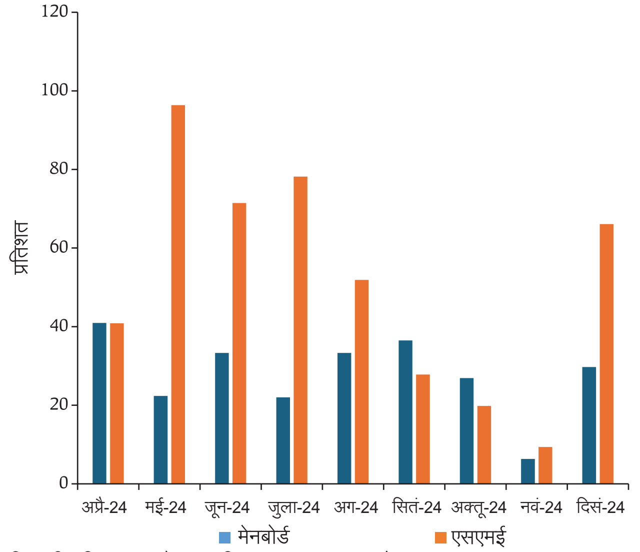

टिप्पणी : दिसंबर का डेटा 18 दिसंबर 2024 तक का है।
स्रोत: प्राइम डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.21: इक्विटी डेरिवेटिव खंड में औसत दैनिक कारोबार (काल्पनिक)

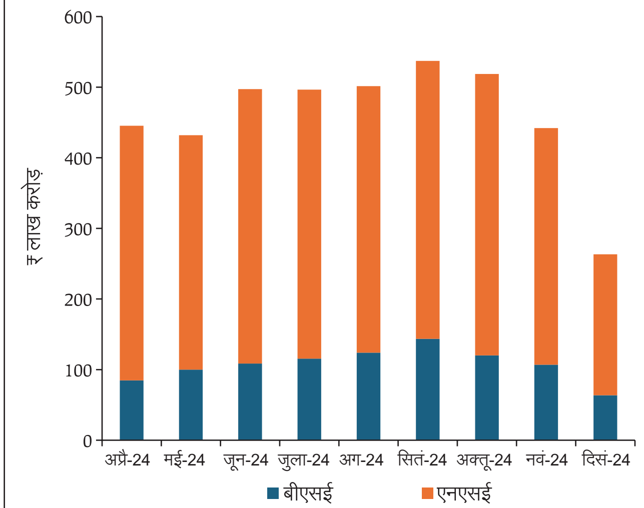

टिप्पणी : दिसंबर का डेटा 19 दिसंबर 2024 तक का है।
स्रोत: बीएसई; और एनएसई।

(चार्ट IV.19)। मिडकैप और स्मॉलकैप खंड बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते रहे।

इक्विटी बाजारों में जारी अस्थिरता, प्राथमिक बाजारों के कामकाज को बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामकीय पहलों [24] के साथ मिलकर, प्राथमिक इक्विटी बाजार में धारणा को प्रभावित किया, जैसा कि नवंबर में कमजोर ग्राहकी स्तर [25] और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के सूचीबद्ध प्रदर्शन से स्पष्ट है (चार्ट IV.20)।

निवेशक संरक्षण और बाजार स्थिरता को बढ़ाने के लिए इक्विटी सूचकांक विपन्नी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई विनियामकीय उपाय - जैसे साप्ताहिक सूचकांक विपन्नी उत्पादों का युक्तीकरण और अनुबंध के आकार में वृद्धि - नवंबर 2024 की दूसरी छमाही में प्रभावी हुए। इसके बाद, इक्विटी विपन्नी खंड में औसत दैनिक कारोबार में नरमी आई है (चार्ट IV.21)।

[24] https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/nov-2024/consultation-paper-on-review-of-sme-segment-framework-under-sebi-icdr- विनियम-2018-और-सेबी-लोड्र-विनियम-2015-पर-एसएमई-कंपनियों-पर-88627.html-के तहत कॉर्पोरेट-गवर्नेंस-प्रावधानों की प्रयोज्यता

[25] https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/ipo-frenzy-cools-down-in-november-as-subscription-levels-take-a-hit-12881753.html

चालू वित्त वर्ष में स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) द्वारा संसाधन जुटाना धीमा रहा है (चार्ट IV.22)। दिसंबर में पहले लघु और मध्यम स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (एसएम आरईआईटी) की शुरुआत हुई। [26]

चार्ट IV.22: आरईआईटी (REITS) और इनवीट्स (InvITs) द्वारा धन जुटाना

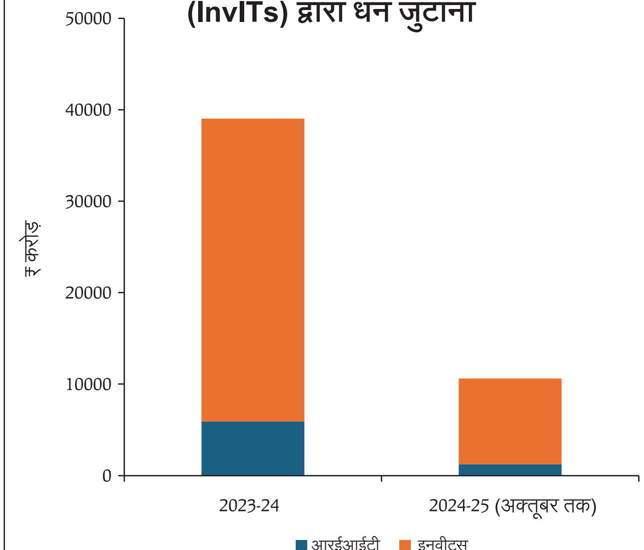

स्रोत: सेबी।

[26] https://www.sebi.gov.in/filings/sm-reit-issues/dec-2024/property-share-investment-trust-propshare-platina_89388.html

चार्ट IV.23: वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)

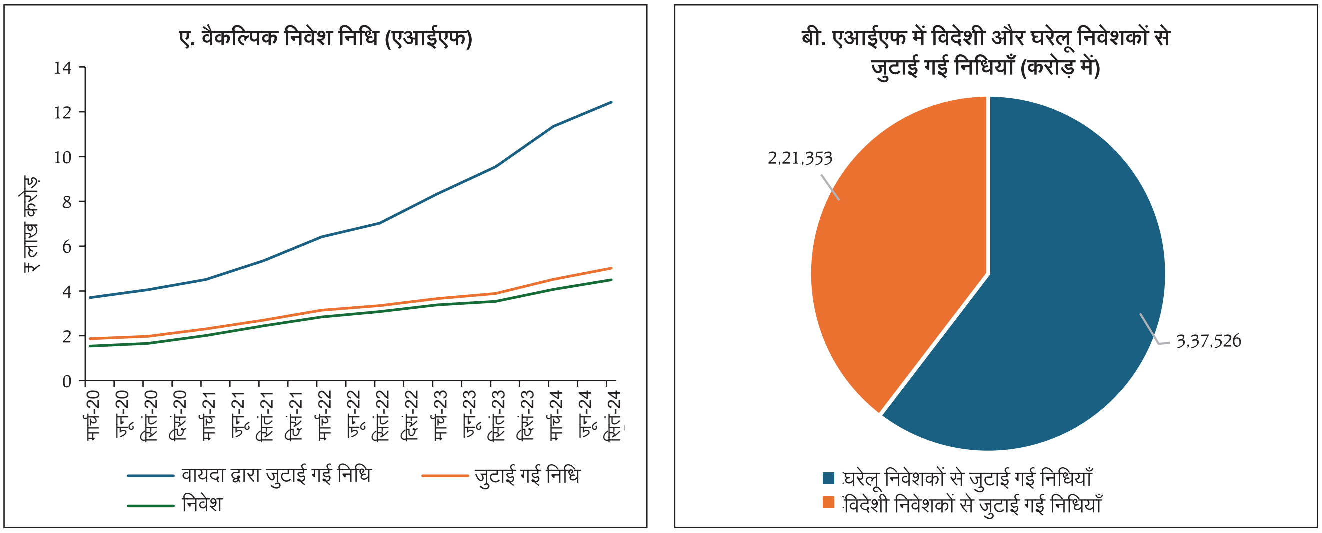

टिप्पणी: चार्ट IV.23ए. में डेटा तिमाही के अंत तक संचयी निवल आंकड़े हैं। चार्ट IV.23बी. में डेटा सितंबर 2024 के अंत तक जुटाई गई सकल निधि है।
स्रोत: सेबी।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) गति पकड़ रहे हैं, जो उच्च जोखिम वाले उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी प्रदान करते हैं[27] (चार्ट IV.23ए)। उल्लेखनीय रूप से, एआईएफ में निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू निवेशकों से प्राप्त किया जा रहा है (चार्ट IV.23बी)।

भारतीय फर्मों ने घरेलू संसाधन जुटाने में मदद करते हुए विदेशी बाजारों से सक्रिय रूप से धन जुटाया है। पिछले दो वर्षों में धीमी गतिविधि के बाद, चालू वित्त वर्ष में विदेशी धन उगाहने में मामूली सुधार देखा गया है (चार्ट IV.24ए)। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में, एक विशिष्ट समूह द्वारा जारी विदेशी बॉण्ड पर प्रतिफल में थोड़ी वृद्धि हुई (चार्ट IV.24बी)। विदेशी बाजारों में अन्य घरेलू कॉरपोरेट्स द्वारा जारी कुछ हरित बॉण्ड में भी

चार्ट IV.24: नवंबर में विदेशी कॉरपोरेट ग्रीन बॉन्ड पर प्रतिफल में क्षणिक वृद्धि हुई

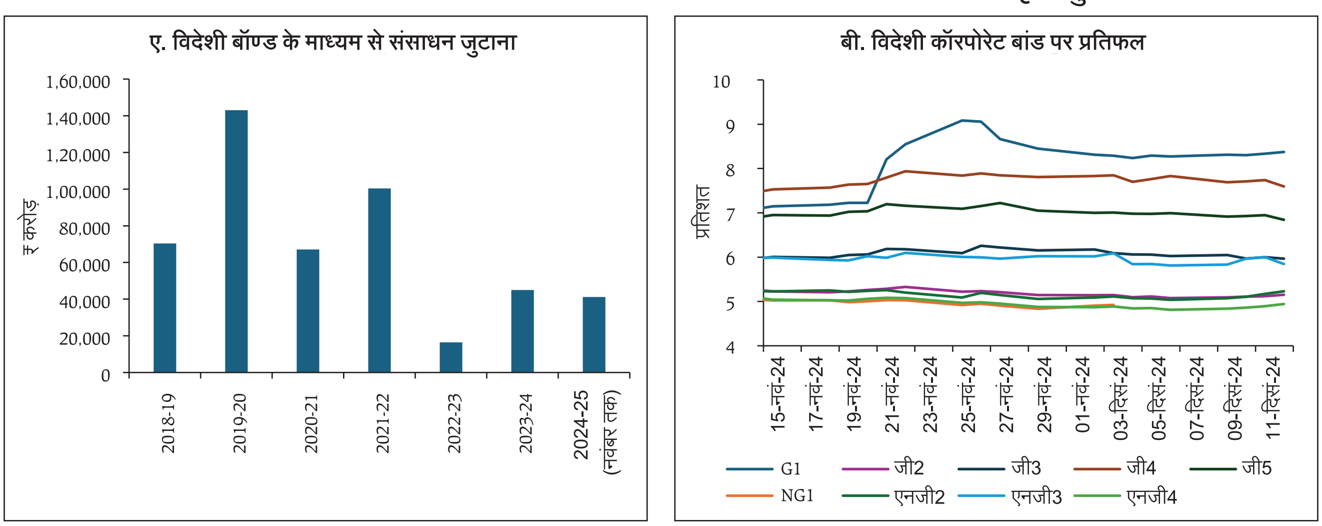

टिप्पणी : जी1 से जी5 चयनित भारतीय कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी विदेशी ग्रीन बॉण्ड पर प्रतिफल हैं। एनजी1 से एनजी4 चयनित भारतीय कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी विदेशी गैर-ग्रीन बॉण्ड पर प्रतिफल हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और प्राइम डेटाबेस।

[27] https://www.business-standard.com/markets/news/alternative-investment-funds-gain-currency-as-fund-raise-tops-rs-5-tillion-124112601117_1.html

चार्ट IV.25: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

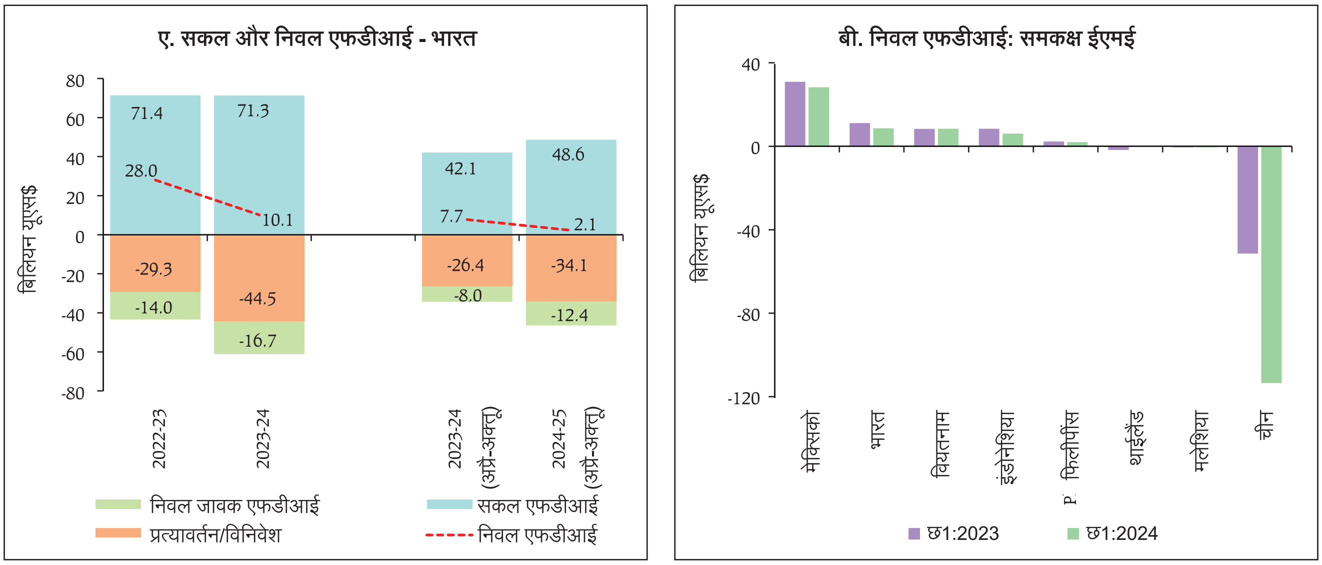

स्रोत: आरबीआई; और आईएमपी।

प्रतिफल में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था और यह जल्दी ही उलट गया।

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़कर 48.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.25ए)। सकल एफडीआई प्रवाह का 60 प्रतिशत से अधिक विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा, तथा खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों में निर्देशित किया गया। प्रमुख स्रोत देशों में सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवाह में तीन-चौथाई से अधिक का योगदान दिया।

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान निवल एफडीआई घटकर 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन और निवल बाह्य एफडीआई में वृद्धि है। जबकि प्रत्यावर्तन अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान एक साल पहले 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, वहीं निवल बाह्य एफडीआई इसी अवधि के दौरान 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एक साल पहले की तुलना में 2024 की पहली छमाही के दौरान अधिकांश सहकर्मी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में निवल एफडीआई में इसी तरह की कमी दिखाई दे रही है (चार्ट IV.25बी)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नवंबर 2024 में भारतीय वित्तीय बाजारों में निवल विक्रेता बने रहे, क्योंकि अमेरिकी चुनावों के बाद बढ़ते अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी प्रतिफल के साथ-साथ उच्च घरेलू स्टॉक मूल्यांकन और विकास मंदी की चिंताओं ने भावनाओं को प्रभावित किया। नवंबर 2024 में निवल एफपीआई बहिर्वाह 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह और ऋण खंड में 0.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह था। हालांकि, दिसंबर (18 दिसंबर तक) के दौरान एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया और 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह हुआ (चार्ट IV.26ए)। क्षेत्रों के भीतर, तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन, और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों ने सबसे अधिक इक्विटी बहिर्वाह दर्ज किया,

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) संवितरण के साथ-साथ नए ऋण पंजीकरण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे (चार्ट IV.27ए)। मूलधन के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह को समायोजित करते

चार्ट IV.26: निवल पोर्टफोलियो निवेश

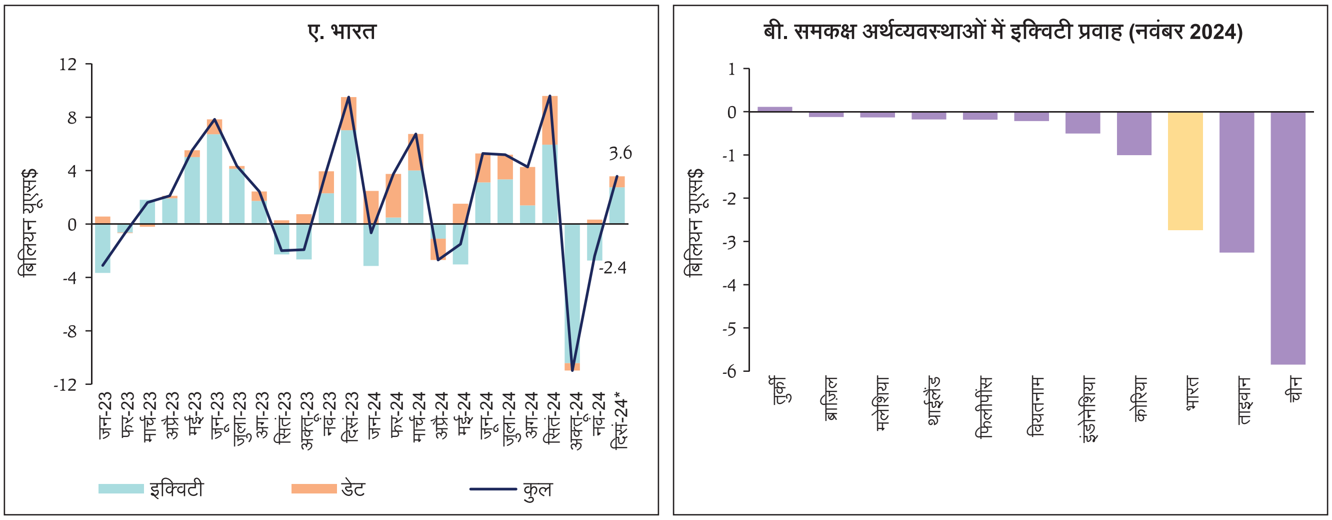

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश भी शामिल है।
2. *:18 दिसंबर 2024 तक का डेटा।

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); तथा भारतीय वित्त संस्थान।

हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक निवल ईसीबी अंतर्वाह एक साल पहले की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत 40 प्रतिशत से अधिक ईसीबी को पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया था,

चार्ट IV.27: बाह्य वाणिज्यिक उधार

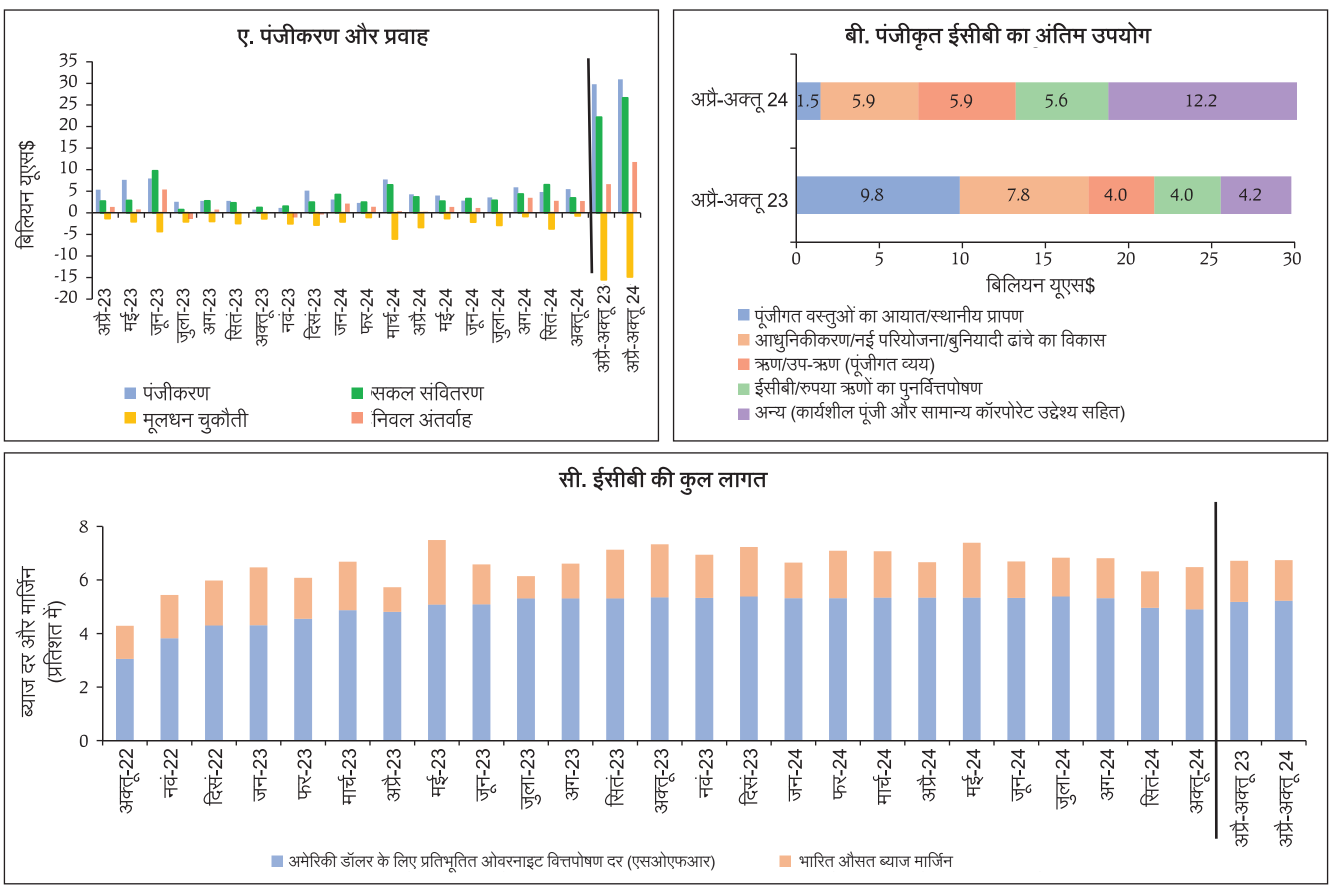

स्रोत: ईसीबी, आरबीआई फॉर्म; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.28: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं में परिवर्तन (नवंबर 2024 से अक्तूबर 2024 तक)

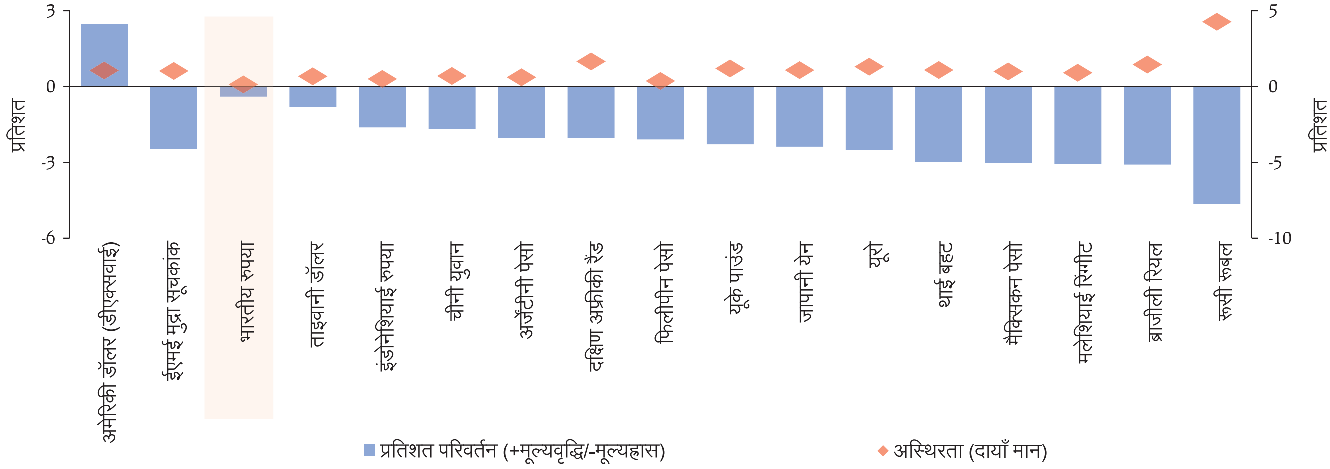

टिप्पणी: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के एक बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन को मापता है।

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

जिसमें आगे उधार देना और उप-उधार देना शामिल है (चार्ट IV.27बी)।

भारित औसत ब्याज मार्जिन (डबल्यूएआईएम) में वृद्धि के कारण अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत नए ईसीबी की कुल लागत में 16 बीपीएस की वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत ईसीबी की कुल लागत 6.7 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के समान ही रही (चार्ट IV.27सी)।

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान अनिवासी जमाराशियों में निवल वृद्धि लगभग दोगुनी होकर 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो एक वर्ष पहले 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ऐसा सभी तीन खातों अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में अधिक वृद्धि के कारण हुआ है।

नवंबर 2024 के दौरान, ईएमई मुद्राओं को मजबूत एफपीआई बहिर्वाह, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती अमेरिकी प्रतिफल से दबाव का सामना करना पड़ा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच, नवंबर 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.4 प्रतिशत (मासिक) की गिरावट आई, जो अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मामूली थी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, प्रमुख मुद्राओं में आईएनआर ने सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की (चार्ट IV.28)।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, नवंबर 2024 में भारतीय रुपये में 0.9 प्रतिशत (मासिक) की वृद्धि होगी, क्योंकि नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये की वृद्धि ऋणात्मक सापेक्ष मूल्य अंतरों की भरपाई से अधिक है (चार्ट IV.29)।

2024-25 के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा भंडार 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 13 दिसंबर, 2024 को 652.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्तमान स्तर पर, यह जून 2024 के अंत में 11 महीने से अधिक के आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया बाहरी ऋण के बराबर है (चार्ट IV.30a)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, जैसा कि रिज़र्व पर्याप्तता मैट्रिक्स के स्थायी स्तरों में परिलक्षित होता है (चार्ट IV.30बी)।

चार्ट IV.29 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में मासिक परिवर्तन

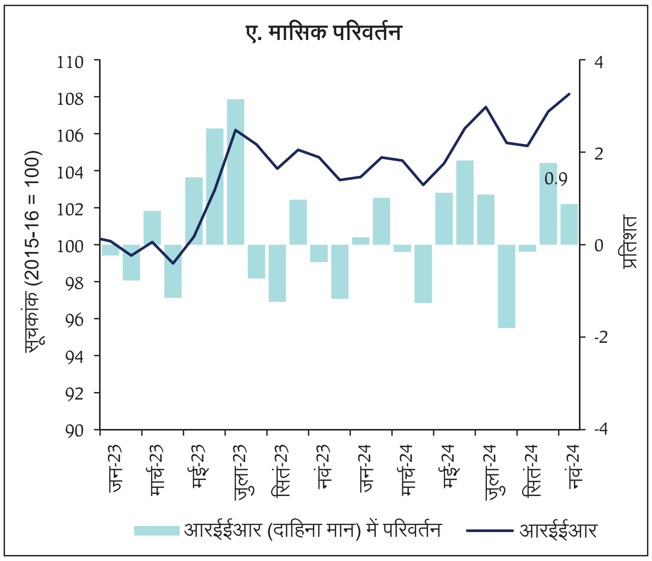

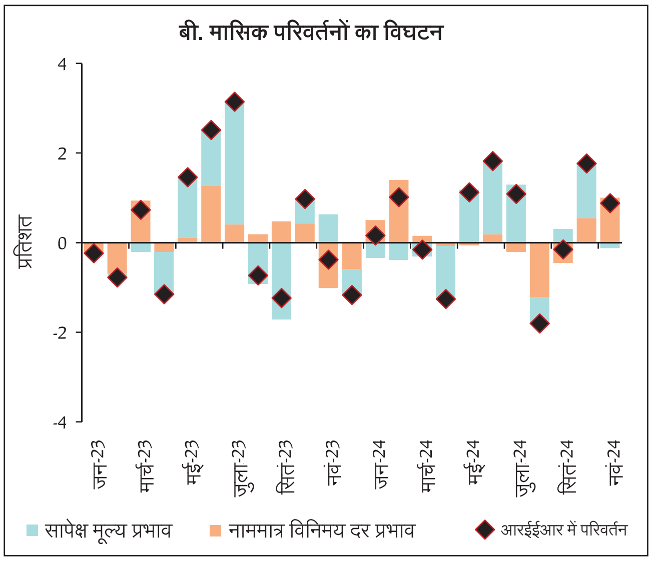

स्रोत : आरबीआई।

भुगतान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान के अधिकांश तरीकों ने नवंबर 2024 में सालाना आधार पर विस्तार दर्ज किया, हालांकि अक्तूबर के त्योहारी महीने से इसमें मंदी आई (सारणी IV.2)। उल्लेखनीय रूप से, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने वाले लेन-देन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली ने नवंबर में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में उच्च वृद्धि (सालाना) प्रदर्शित की।

2024-25 के दौरान अब तक (अक्तूबर 2024 तक), नए कार्ड जारी करने में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से डेबिट कार्ड द्वारा संचालित है। त्योहारी सीज़न (चार्ट IV.31) के कारण अक्तूबर

चार्ट IV.30: विदेशी मुद्रा भंडार

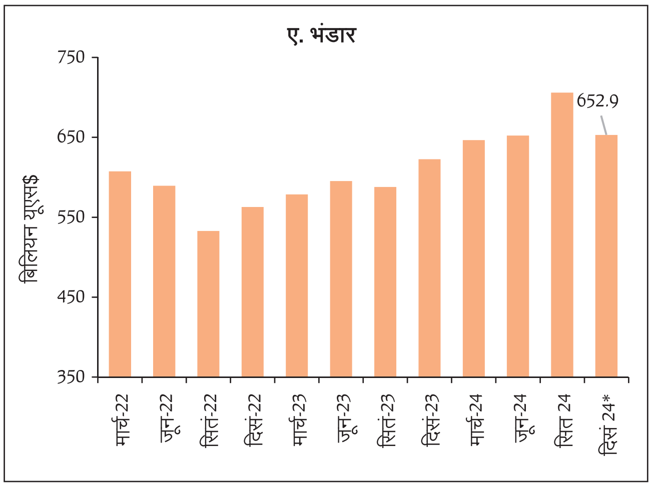

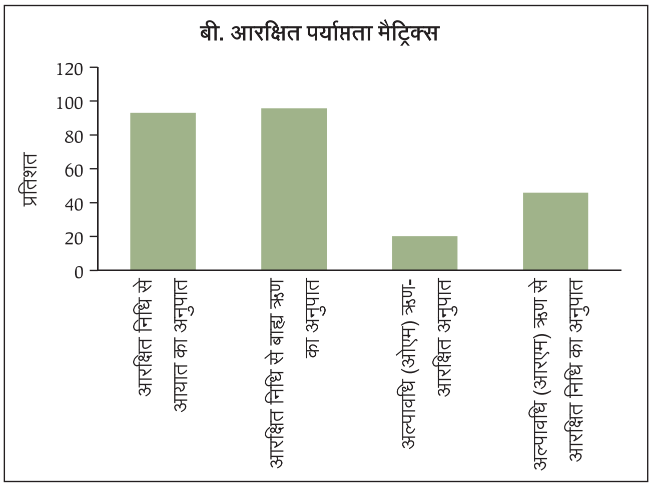

टिप्पणीयाँ: 1.: 13 दिसंबर के आंकड़े हैं।
2. ओएम: मूल परिपक्वता: आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता। जून 2024 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिजर्व डेटा और वार्षिक व्यापारिक आयात और बाहरी ऋण का उपयोग करके आरक्षित पर्याप्तता मैट्रिक्स की गणना की गई है।

स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें; तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 5 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	अक्तू-23	अक्तू-24	नवं-23	नवं-24	अक्तू-23	अक्तू-24	नवं-23	नवं-24
आरटीजीएस	18.0	19.3	6.2	9.6	16.6	26.8	10.6	9.1
एनईएफटी	38.2	45.4	45.7	21.5	19.6	27.3	17.5	5.4
यूपीआई	56.2	45.4	53.7	37.8	41.6	37.0	46.1	23.9
आईएमपीएस	2.2	-5.3	1.9	-13.6	15.5	16.9	17.7	4.4
एनएसीएच	-1.5	64.5	65.9	-9.3	11.9	43.5	27.2	9.9
एनईटीसी	13.0	7.9	12.3	11.9	24.4	10.4	14.1	14.5
बीबीपीएस	26.6	101.0	29.5	88.8	59.2	299.2	66.7	266.4

नोट: **आरटीजीएस**: तत्काल सकल निपटान; **एनईएफटी**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; **यूपीआई**: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; **आईएमपीएस**: तत्काल भुगतान सेवा; **एनएसीएच**: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; **एनईटीसी**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और **बीबीपीएस**: भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत : आरबीआई।

2024 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में गति बनी रही।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने कई नई सुविधाएँ शुरू की हैं, जिनमें भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी (भीम) ऐप की नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योगदान सुविधा शामिल है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और तेज़ प्रक्रिया तथा आसान पहुँच के साथ सेवानिवृत्ति योजना को सरल बनाती है।[28] इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच) लेनदेन के लिए एक नया उत्पाद प्रकार लागू किया गया है, जो 23 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा, जिसमें रिज़र्व बैंक प्रायोजक होगा।[29] राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के सदस्य बैंक, निगम और एग्रीगेटर इन परिवर्तनों में भाग लेंगे। एनपीसीआई ने ऑनलाइन मैंडेट गेटवे सिस्टम (ओएनएमएजीएस) एप्लिकेशन के लिए एडवांस्ड

चार्ट IV.31: कार्ड वृद्धि और लेनदेन गतिविधि में रुझान

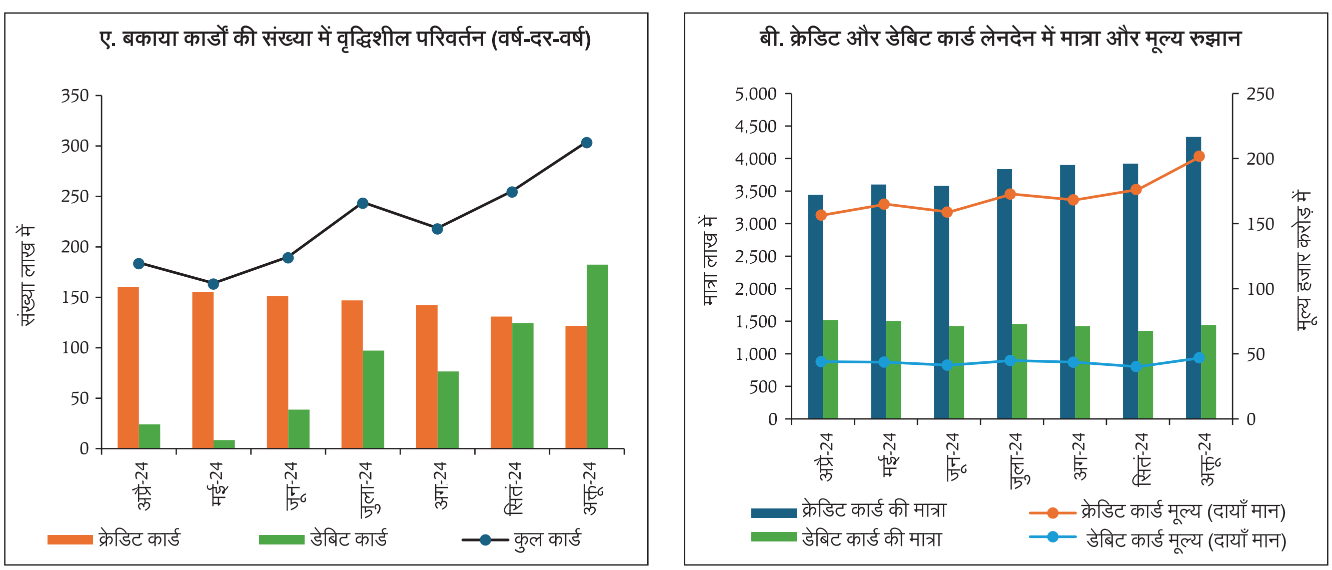

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[28] एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, 13 नवंबर, 2024।

[29] एनपीसीआई परिपत्र, 16 नवंबर, 2024।

एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (एईएस) को भी अनिवार्य बना दिया है, जो आवर्ती भुगतानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट का प्रबंधन करता है। यह तेज़, अधिक कुशल एन्क्रिप्शन और उद्योग मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। [30]

6 दिसंबर, 2024[31] को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई और व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य निर्धारण में पहुँच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत कनेक्ट[32] के साथ एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म (सीसीआईएल द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया) को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। पायलट बैंक और गैर-बैंक प्रणालियों के माध्यम से यूएसडी लेनदेन को सक्षम करेगा, जिसमें व्यापक विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया, जिससे 'न्यू-टू-क्रेडिट' ग्राहकों के लिए छोटी-टिकट, छोटी अवधि के उत्पादों तक पहुँच की सुविधा होगी।

फिनटेक क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में एआई (फ्री-एआई) के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है। डिजिटल धोखाधड़ी का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक "शून्य वित्तीय धोखाधड़ी" नामक एक हैकथॉन आयोजित कर रहा है, जिसमें म्यूल खातों पर एक विशिष्ट समस्या विवरण शामिल है जिसका उद्देश्य उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा संचालित एक एआई/एमएल -आधारित मॉडल, MuleHunter.AI ने म्यूल बैंक खातों का पता लगाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ सफल परीक्षणों के बाद, रिज़र्व बैंक इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआईएच के साथ व्यापक सहयोग के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता है।

V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में सुदृढ़ता के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि वास्तविक आय में सुधार, स्थिर श्रम बाजार और वैश्विक व्यापार में धीरे-धीरे सुधार के कारण मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि, वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते संरक्षणवाद और बड़े सार्वजनिक ऋण के रूप में चुनौतियां बनी हुई हैं। इन घटनाक्रमों का उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी मुद्राएं और इक्विटी 2024 में व्यापार और पूंजी प्रवाह के लिए अत्यधिक अनिश्चित वातावरण में देखी जाने वाली गिरावट के तेज दौर के प्रति संवेदनशील हैं।

भारत की विकास दर 2024-25 की दूसरी छमाही में बढ़ने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से सुदृढ़ घरेलू निजी खपत मांग से प्रेरित है। रिकॉर्ड स्तर के खाद्यान्न उत्पादन से समर्थित, विशेष रूप से ग्रामीण मांग में तेजी आ रही है। बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकारी खर्च से आर्थिक गतिविधि और निवेश को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालाँकि, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ विकास और मुद्रास्फीति के लिए उभरते दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

भारत के सुदृढ़ विकास पथ के बारे में भविष्य की उम्मीदें भी सकारात्मक जलवायु कार्रवाई के मद्देनजर अधिक स्थिर आधार के साथ मिल रही हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने पर नीतिगत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मिलित प्रयास निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में एक आशाजनक मार्ग का संकेत देते हैं। कार्बन ट्रेडिंग के लिए वैश्विक ढाँचों का लाभ उठाना और ग्रीन बॉण्ड सहित जलवायु वित्त को बढ़ाना, विकास और उत्सर्जन के बीच अलगाव को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही, भारत विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार करने और उत्पादों और सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण की लहर पर सवार है, जो अधिक समझदार उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और ऑनलाइन शॉपिंग की गहरी पहुँच, विशेष रूप से छोटे शहरों में, से प्रेरित है। यह उछाल बढ़ते निवेशक विश्वास और भारत के फिनटेक आरोहण को आगे बढ़ाने वाली नवीन ऊर्जा की गति को भी रेखांकित करता है।

[30] एनपीसीआई परिपत्र, 18 नवंबर, 2024।

[31] आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति, 6 दिसंबर, 2024।

[32] पहले इसे भारत बिल भुगतान प्रणाली के नाम से जाना जाता था।

सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा

हर्षिता यादव, आयुषी खंडेलवाल, कोवुरी आकाश यादव, रचित सोलंकी, अनूप के सुरेश, समीर रंजन बेहरा और अत्रि मुखर्जी द्वारा ^

केंद्र और राज्यों दोनों के मामले में, बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में कम हुआ, जिसका मुख्य कारण मजबूत प्राप्तियां, उनके राजस्व व्यय वृद्धि में कमी और पूंजीगत व्यय में कमी है। इससे उन्हें 2024-25 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश मिलती है, जो व्यय की गुणवत्ता में महामारी के बाद के लाभ को बनाए रखने और मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं का समर्थन करने में सहायता करेगी। कई राज्यों ने अपने 2024-25 के बजट में रियायतों की घोषणा की है; इस तरह के खर्च से संसाधन महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर हो सकते हैं।

परिचय

विकसित भारत की दिशा में एक विस्तृत प्रक्षेपवक्र प्रस्तुत करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मध्यम अवधि का रोडमैप तैयार किया है। रोजगार, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ, बजट का उद्देश्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करते हुए उच्च विकास दर को बनाए रखना है। बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर जारी रखते हुए, बजट 2024-25 ने पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.11 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान किया था, जो 2023-24 (अनंतिम खाते, पीए) में हासिल जीडीपी के 3.2 प्रतिशत से अधिक है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय को 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 11.8 प्रतिशत से मामूली रूप से घटाकर 2024-25 (बजट अनुमान, बीई) में जीडीपी के 11.4 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया था, जिससे सरकारी व्यय की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि हुई। इसके अलावा, राज्यों के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आवंटन बढ़ाया गया। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट का लक्ष्य 2024-25 में राजकोषीय समेकन करना है, जो 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। राज्यों ने भी 2024-25 में राजकोषीय समेकन के लिए प्रयास किया है, 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट बनाया है।

कर और गैर-कर दोनों स्रोतों से प्राप्त होने वाले केंद्र के राजस्व संग्रह में 2024-25 की पहली छमाही में उछाल आया, जो मुख्य रूप से आयकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) और रिज़र्व बैंक द्वारा अधिक अधिशेष हस्तांतरण के कारण हुआ। मजबूत प्राप्तियों और अपेक्षाकृत स्थिर सरकारी खर्च के कारण , 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में केंद्र का जीएफडी पिछले एक दशक में सबसे कम था। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि कर राजस्व के कारण हुई, जबकि केंद्र से गैर-कर राजस्व और अनुदान में कमी आई। व्यय के मोर्चे पर, राज्यों ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व व्यय की गति को बनाए रखा, जबकि उनके पूंजीगत व्यय में गिरावट आई।[1, 2]

लेख का शेष भाग इस प्रकार संरचित है: खंड II, 2024-25 की पहली छमाही के लिए केंद्र और राज्यों (तिमाही आवृत्ति पर) की प्राप्ति और व्यय का विश्लेषण करता है। खंड III, केंद्र और राज्यों के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV, 2024-25 की पहली छमाही के लिए सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य) वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है। खंड V, समापन टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

II. पहली और दूसरी तिमाही में राजकोषीय परिणाम

2024-25 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने अपनी कुल बजट प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक एकत्र किया, जो हाल के दिनों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। वर्ष-दर-वर्ष (व-व) आधार पर, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान कुल प्राप्तियां 15.5 प्रतिशत बढ़ीं। दूसरी ओर, केंद्र का कुल व्यय 2024-25

^ यह लेख श्रीमती रेखा मिश्र के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] यह डेटा 22 राज्यों से संबंधित है, जिनके लिए अप्रैल-सितंबर 2024 के डेटा उपलब्ध हैं। जीएफडी-जीडीपी अनुपात का अनुमान उन्हीं 22 राज्यों के जीएसडीपी डेटा का उपयोग करके लगाया गया है।

[2] केन्द्र तथा राज्यों की अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय स्थिति पर विस्तृत विवरण परिशिष्ट सारणी (I से IV) में दिया गया है।

चार्ट 1: पहली छमाही में कुल प्राप्तियां और व्यय

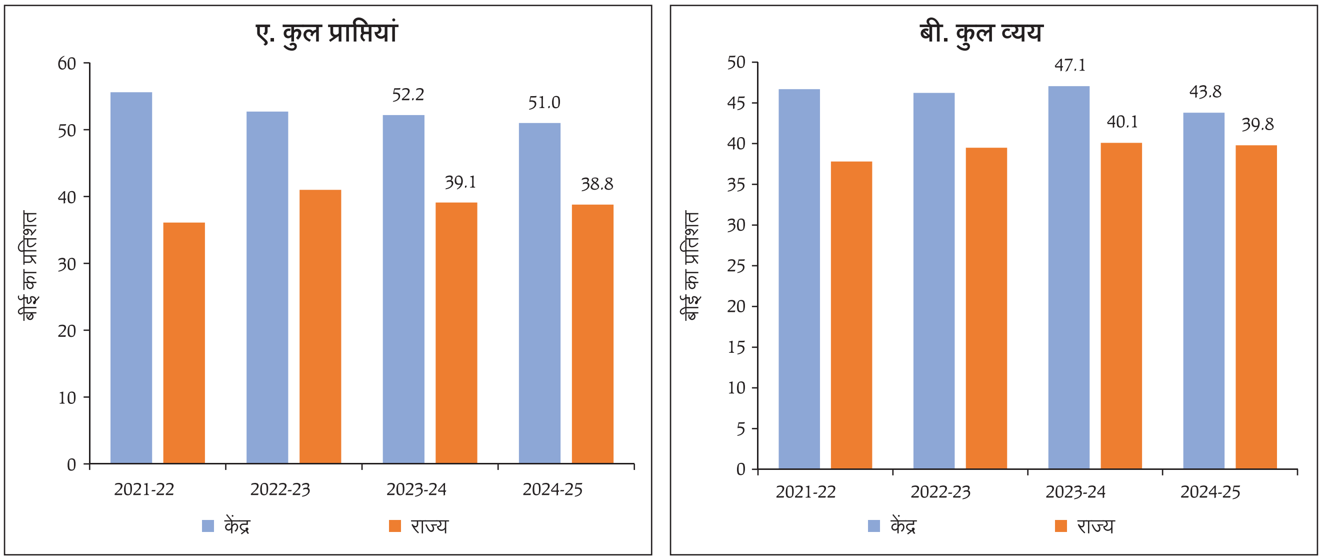

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

की पहली छमाही में बजट अनुमान के 50 प्रतिशत से कम था, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान देखे गए पैटर्न के अनुरूप था (चार्ट 1ए)। राज्यों का जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 43.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम था, मुख्य रूप से कुल व्यय में मंदी के कारण क्योंकि राज्यों ने 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान के 40.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 39.8 प्रतिशत खर्च किया (चार्ट 1बी)।

ए. प्राप्तियाँ

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 16.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मजबूत रहीं। 2024-25 की पहली तिमाही में, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 41.0 प्रतिशत रही, जो कि मजबूत कर वसूली के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा 2.1 लाख करोड़ रुपये के बड़े अधिशेष हस्तांतरण के कारण हुई। 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान, प्रत्यक्ष कर वसूली में गिरावट के कारण राजस्व प्राप्तियों में 2.0 प्रतिशत की कमी आई

चार्ट 2: केंद्र की प्राप्तियों का त्रैमासिक ब्यौरा

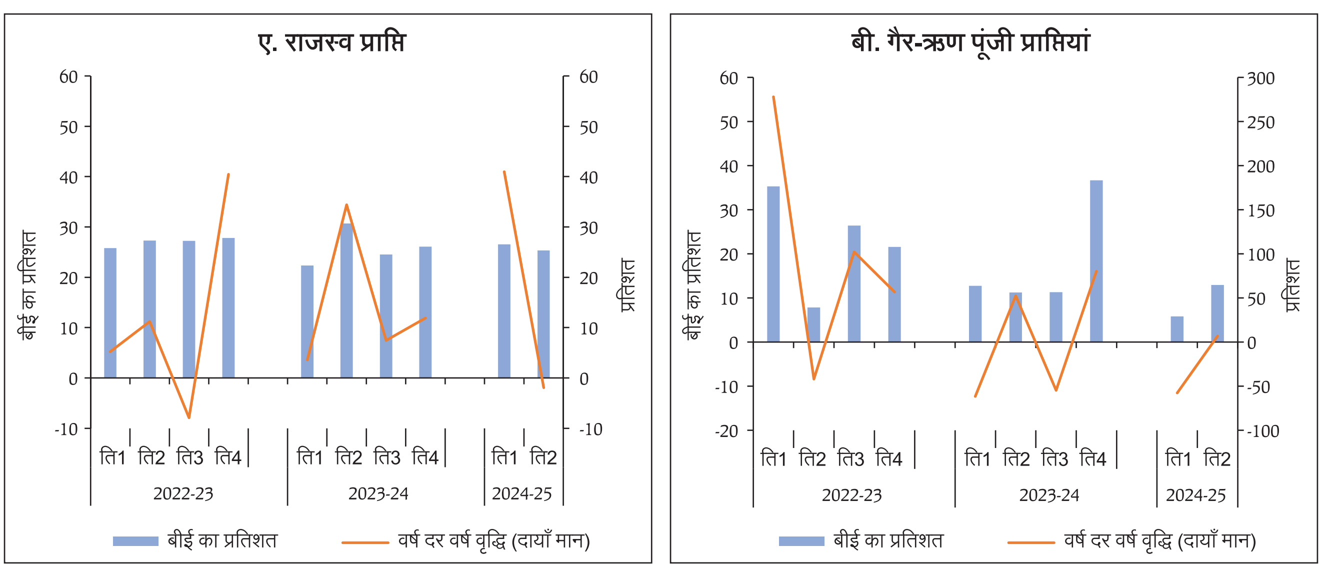

स्रोत: सीजीए; तथा केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

चार्ट 3: राज्यों की प्राप्तियों का त्रैमासिक ब्यौरा

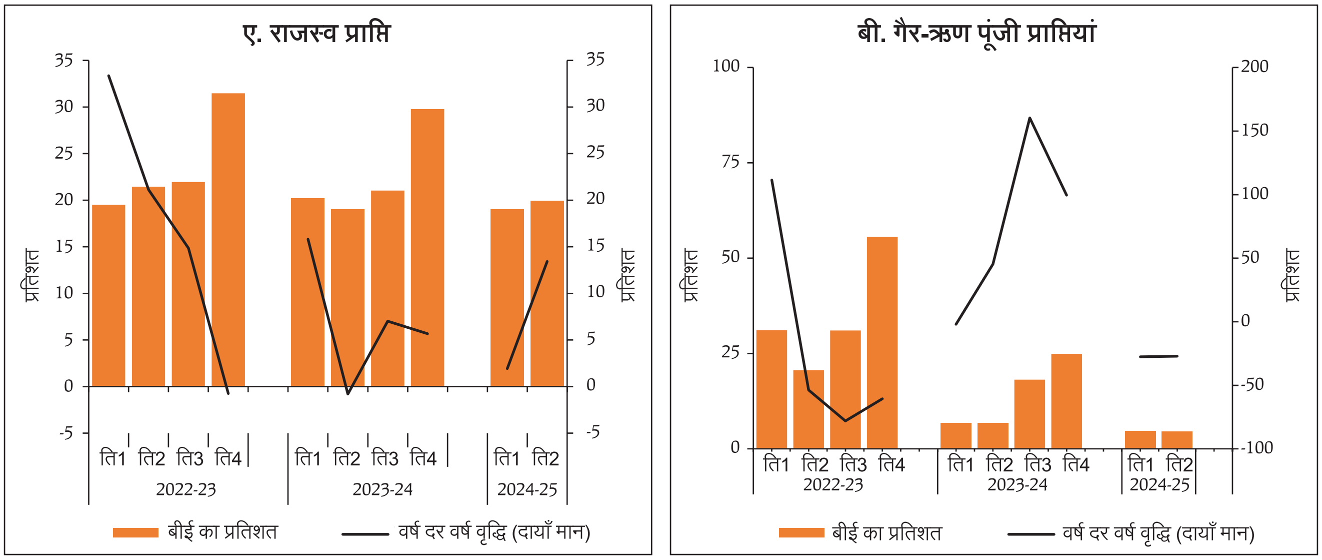

स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

(चार्ट 2ए)। 2024-25 की पहली तिमाही में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रदर्शन धीमा रहा, लेकिन 2024-25 की दूसरी तिमाही में इसमें सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 2बी)[3]

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2024-25 की पहली छमाही में 7.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2023-24 की पहली छमाही में 7.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर राजस्व, जो 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 85.7 प्रतिशत था, ने 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां[4] 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही दोनों में कम हुई (चार्ट 3ए और बी)।

केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2024-25 की पहली छमाही में वर्ष दर वर्ष आधार पर 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आयकर वसूली में 25.0 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह में 2.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 4ए)। 2023-24 की पहली छमाही में देखे गए पैटर्न के समान , 2024-25 की पहली छमाही में आयकर संग्रह कॉरपोरेट कर संग्रह से अधिक हो गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ करदाताओं के अनुपालन में सुधार और कर आधार को व्यापक बनाने की दिशा में किए गए उपायों को दर्शाता है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर वसूली के भीतर, हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि के साथ सुरक्षा लेनदेन कर से प्राप्तियां मजबूत रही हैं (बॉक्स ए)।

बॉक्स ए: सुरक्षा लेनदेन कर - भारतीय अनुभव

प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 2004-05 के दौरान राजस्व सृजन को बढ़ाने, कर चोरी को खत्म करने, शेयर बाजार में सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर प्रदान करने और शोर मचाने वाले व्यापारियों/सट्टेबाजों को दूर भगाकर बाजार में अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, इटली, तुर्की, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी कई जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने निवासियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन पर किसी न किसी तरह का कर लगाया है (मैथेसन, 2012)। दूसरी ओर, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जैसे पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान, इटली और जर्मनी ने वित्तीय

(जारी)

---

3 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली तथा विविध पूंजी प्राप्तियां (अर्थात विनिवेश एवं अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं।

4 राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में उनके द्वारा अधीनस्थ/अर्ध-सरकारी संस्थाओं को वितरित ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा अन्य विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल होती हैं।

चार्ट ए.1: भारत में एसटीटी वसूली का रुझान

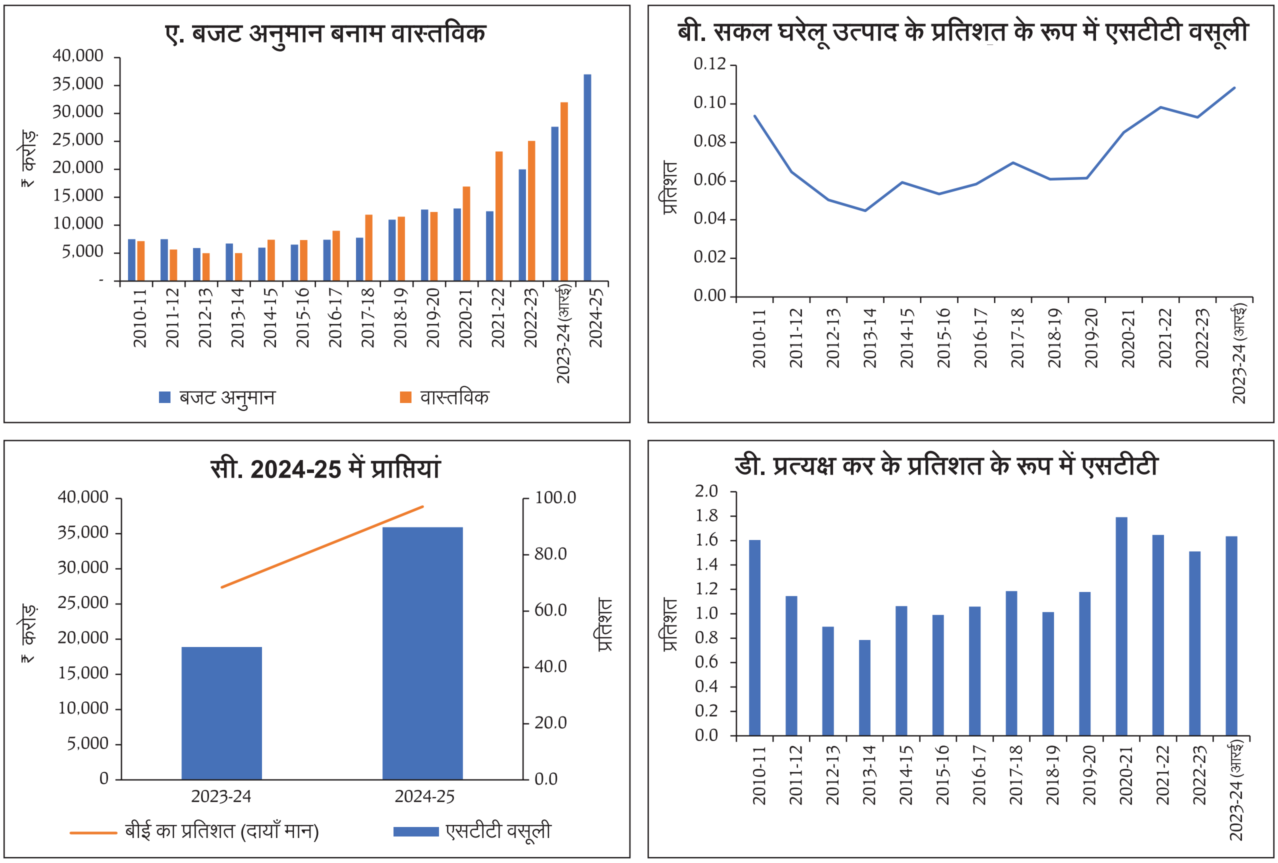

नोट: चार्ट ए.1सी में, 2024-25 और 2023-24 के लिए एसटीटी वसूली क्रमशः 10 नवंबर, 2024 और 10 नवंबर, 2023 तक के हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)।

लेनदेन करों को निरस्त कर दिया है, जो तकनीकी परिवर्तनों और उदारीकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण है, जिसने व्यापार को कम खर्चीले अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है (हिलमैन और एशफोर्ड, 2012; बर्मन एट अल., 2016)। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ तेजी से बढ़ते इक्विटी बाजार के कारण एसटीटी से राजस्व जुटाने में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में और निरपेक्ष रूप से वृद्धि देखी गई है (चार्ट ए.1 ए और 1बी)। 10 नवंबर, 2024 तक, एसटीटी वसूली ने 2024-25 के लिए अपने बजट अनुमान का 97 प्रतिशत प्राप्त करते हुए 90.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है (चार्ट ए.1सी)। महामारी के बाद की अवधि में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में एसटीटी की हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट ए.1डी)।

संदर्भ

Burman, L. E., Gale, W. G., Gault, S., Kim, B., Nunns, J. and Rosenthal, S. (2016). Financial Transaction Taxes in Theory and Practice. *National Tax Journal*, 69(1), 171-216, March.

Hillman, D. and Ashford, C. (2012). *Financial Transaction Tax: Myth-Busting.* Stamp Out Poverty, London, UK.

Matheson, T. (2012). Security Transaction Taxes: Issues and Evidence. *International Tax and Public Finance*, 19(6), 884–912.

राज्यों के स्वयं के प्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें भूमि राजस्व और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं) ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 13.2 प्रतिशत (पहली तिमाही में 12.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 14.2 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन किया (चार्ट 4बी)।

चार्ट 4: तिमाही प्रत्यक्ष कर वसूली

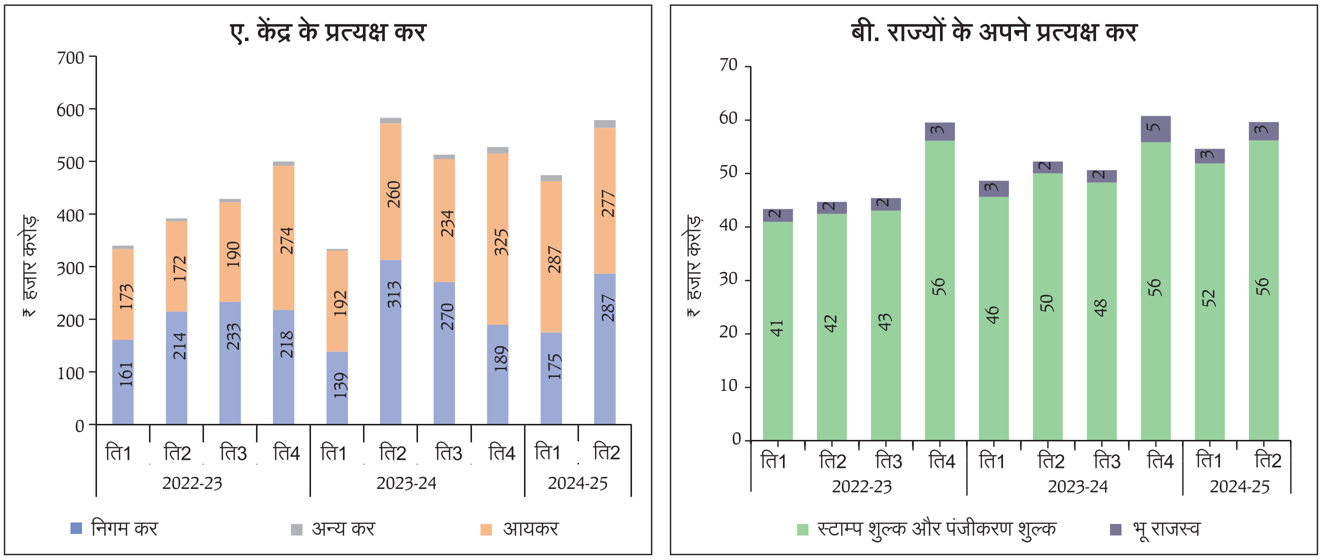

स्रोत: सीएजी।

केंद्र के अप्रत्यक्ष कर वसूली में 2024-25[5] की पहली छमाही में 8.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें जीएसटी की प्रमुखता रही। 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान, अप्रत्यक्ष कर वसूली में 5.6 प्रतिशत (2023-24 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसे जीएसटी वसूली में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि (2023-24 की पहली तिमाही में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि) का समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, 2024-25 की पहली तिमाही में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क वसूली में संकुचन देखा गया। 2024-25 की दूसरी तिमाही में, त्योहारी मांग से उत्साहित, जीएसटी वसूली में 11.8 प्रतिशत (एक साल पहले 6.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह में दूसरी तिमाही में क्रमशः 15.6 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2024-25 की पहली छमाही में जीएसटी वसूली (केंद्र और राज्य) 10.9 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (2023-24 की पहली छमाही में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई), पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक वसूली क्रमशः 1.86 लाख करोड़ रुपये और 1.77 लाख करोड़ रुपये रहा (चार्ट 5)।

राज्यों के मामले में, 2024-25 की पहली छमाही में कर राजस्व में वृद्धि को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और केंद्र से कर हस्तांतरण द्वारा समर्थित किया गया था। एसजीएसटी में मजबूत वृद्धि बढ़ती मांग, उच्च कर दरों और अधिक अनुपालन को दर्शाती है। 2024-25 की पहली छमाही में, राज्यों को आवंटन में पिछले वर्ष की इसी अवधि (चार्ट 6 ए और बी) की तुलना में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्र के गैर-कर राजस्व में 2024-25 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, क्योंकि उच्च लाभांश और मुनाफे के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों[6] की

चार्ट 5: जीएसटी वसूली (केंद्र और राज्य)

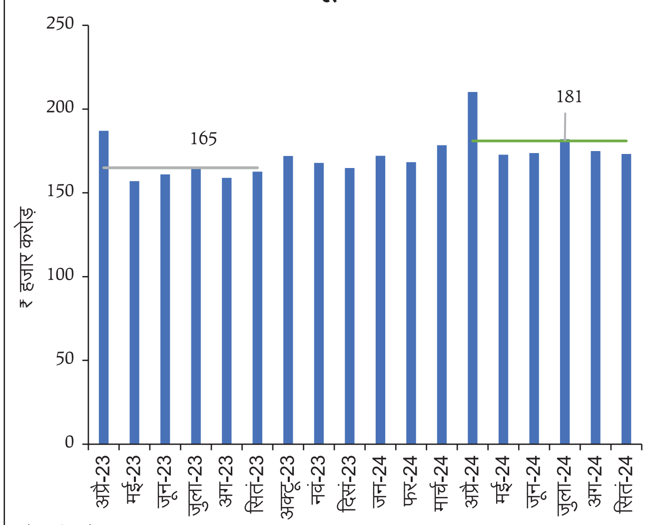

नोट: ग्रे और हरी रेखा क्रमशः 2023-24 की पहली छमाही और 2024-25 की पहली छमाही में औसत जीएसटी वसूली को दर्शाती है।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी वेबसाइट।

[5] 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2022-23 की पहली छमाही की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[6] वर्ष 2024-25 में 'लाभांश और लाभ' तथा 'ब्याज प्राप्तियों' से प्राप्त गैर-कर राजस्व, बजटीय गैर-कर राजस्व का क्रमशः 53.0 तथा 7.0 प्रतिशत होगा।

चार्ट 6: एसजीएसटी और केंद्र से कर हस्तांतरण का तिमाही प्रदर्शन

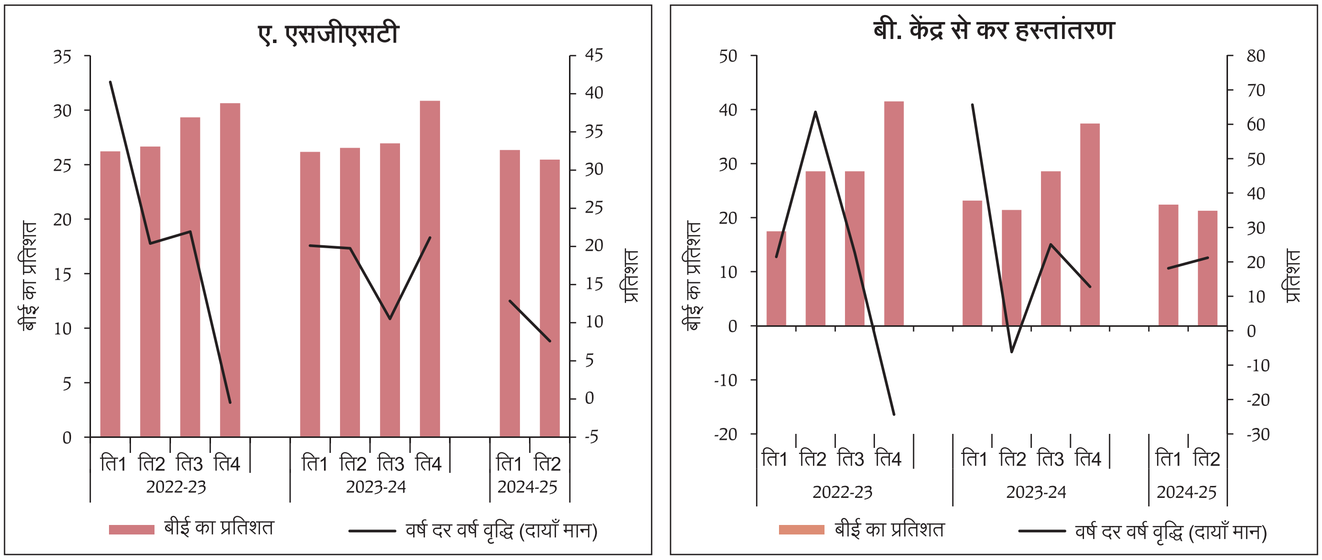

स्रोत: सीजीए; और सीएजी।

भरपाई आर्थिक सेवाओं से राजस्व में गिरावट से हुई।[7] 2024-25 की पहली छमाही में विनिवेश प्राप्तियां धीमी रहीं और बजट राशि का 6.3 प्रतिशत जुटाया गया (2023-24 की पहली छमाही में 11.4 प्रतिशत) (चार्ट 7)।[8]

बी. व्यय

2024-25 (बजट अनुमान) में, केंद्र सरकार के कुल व्यय में 2023-24 (पीए) की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जिसमें राजस्व व्यय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि और

चार्ट 7: केंद्र सरकार का गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियां

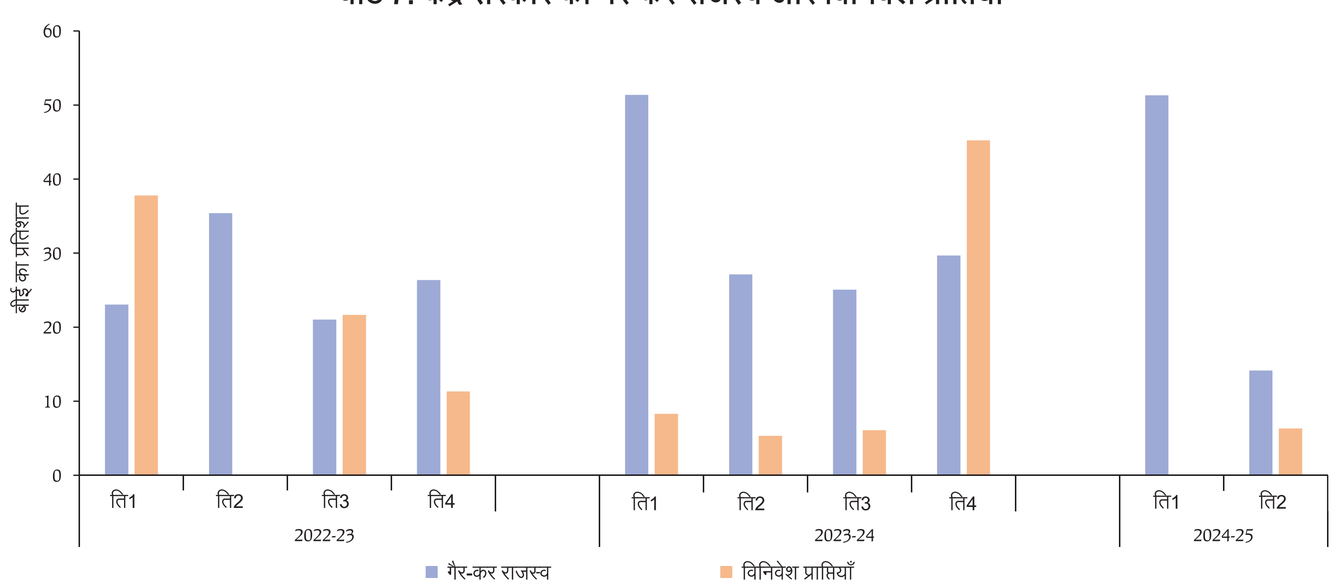

स्रोत: सीजीए

[7] आर्थिक सेवाओं से प्राप्त गैर-कर राजस्व में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियां, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग के लिए शुल्क आदि), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल शक्ति अनुसंधान स्टेशन, पुणे आदि की प्राप्तियां), संचार (दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियां शामिल हैं) आदि शामिल हैं। आर्थिक सेवाओं से प्राप्त गैर-कर राजस्व 2024-25 में बजटीय गैर-कर राजस्व का 33.4 प्रतिशत है।

[8] 2024-25 की पहली छमाही के दौरान सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 3,167 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6,949 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

पूंजीगत व्यय में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है।[9] 2024-25 की पहली छमाही में, बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय मोटे तौर पर पिछले वर्षों के रुझानों के अनुरूप रहा, जबकि पूंजीगत व्यय में कमी दर्ज की गई। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान प्राप्त बजटीय व्यय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा, अन्य बातों के साथ-साथ, 2024-25 की पहली तिमाही में आम चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के कारण है (चार्ट 8)।

शीर्ष 6 मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय,[10] जिसमें 2024-25 के लिए कुल बजटीय पूंजीगत व्यय का 95 प्रतिशत शामिल है, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमान का 37.3 प्रतिशत गिर गया (2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 51.8 प्रतिशत की तुलना में) (चार्ट 9)। इसी तरह, 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत व्यय 2024-25 की पहली छमाही के दौरान ₹30,040 करोड़ हो गया (2023-24 की पहली छमाही के दौरान ₹53,541 करोड़ की तुलना में)।[11] सितंबर 2024 में, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) ने नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों को आसान बना दिया, जिससे 2024-25 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय सहित सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा मिलना चाहिए।[12] इसके अलावा, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी प्रस्तावित किया था, जिसमें 44,143 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय शामिल है (चार्ट 10)।

ईंधन और उर्वरकों सहित प्रमुख सब्सिडी पर केंद्र सरकार का व्यय, 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 56.3 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 55.1 प्रतिशत था, जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में गिरावट (2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 58.2 प्रतिशत जबकि 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 95.9 प्रतिशत) के कारण पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर कम वार्षिक व्यय है। 2024-25 की पहली छमाही में प्रमुख सब्सिडी पर कुल व्यय में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी का हिस्सा क्रमशः 56.6 प्रतिशत और 41.7 प्रतिशत था, जबकि

चार्ट 8: पहली छमाही में व्यय की प्रवृत्ति

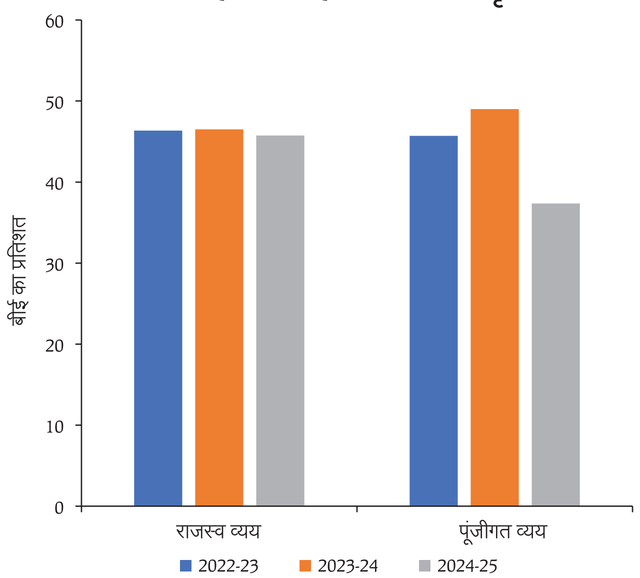

स्रोत: सीजीए

चार्ट 9: पहली छमाही में प्रमुख मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय

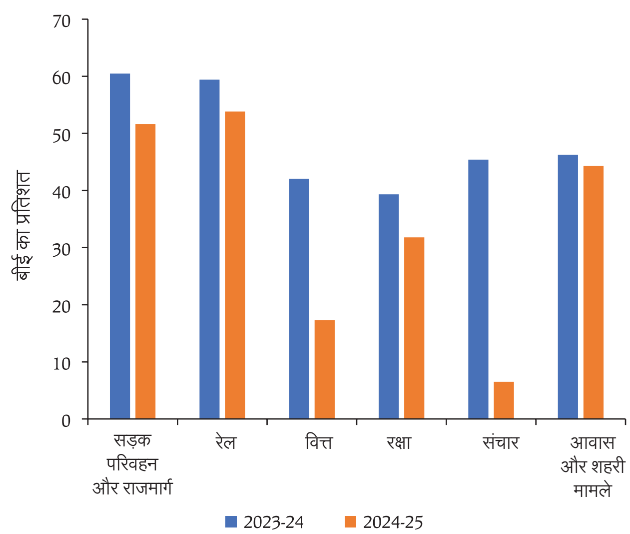

स्रोत: सीजीए

9 पूंजीगत परिव्यय (अर्थात ऋण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 2024-25 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जबकि 2023-24 (पीए) में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

10 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।

11 मासिक सारांश रिपोर्ट, व्यय विभाग।

12 आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा 4 सितंबर, 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बजट को क्रियान्वित करने के लिए परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए बड़ी निर्गमों (₹500 करोड़ या उससे अधिक) से संबंधित शर्तों में अगली सूचना तक ढील दी जाएगी। नई प्रदान की गई छूट एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)/केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) और मासिक व्यय योजना (एमईपी)/तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी) के अनुपालन दिशानिर्देशों के अधीन रहेगी।

चार्ट 10: दूसरी छमाही में व्यय वृद्धि

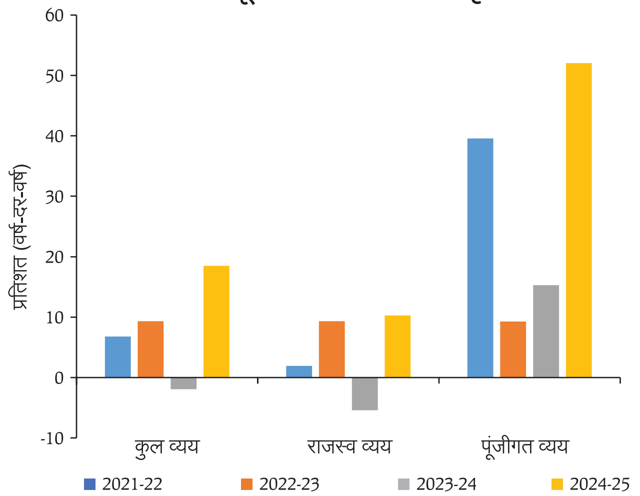

नोट: 2024-25 के लिए व्यय वृद्धि सितंबर 2024 तक के वास्तविक आंकड़ों और 2024-25 के बजट अनुमानों तथा अनुदानों की प्रथम अनुपूरक मांग में व्यय प्रस्तावों के आधार पर निहित वृद्धि दर है।
स्रोत: सीजीए; तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 11: केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सब्सिडी पर तिमाही व्यय

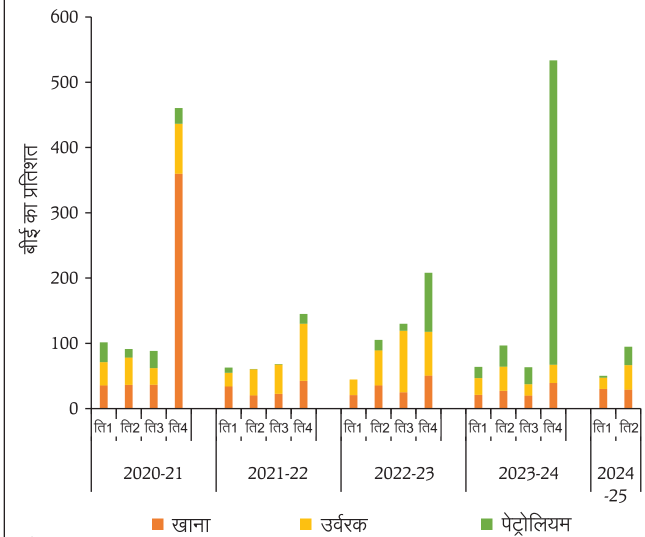

स्रोत: सीजीए; तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह क्रमशः 46.1 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत था (चार्ट 11)।

भारत महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है।[13] महिलाओं के कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के लिए केंद्र का व्यय 2015-16 में ₹81,249 करोड़ से बढ़कर 2024-25 (बजट अनुमान) में ₹3,27,158 करोड़ हो गया है। कुल केंद्रीय बजट में लिंग बजट का हिस्सा 2024-25 (बजट अनुमान) में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है, जो 2005-06 में लिंग बजट विवरण (जीबीएस) की शुरूआत के बाद से सबसे अधिक है (बॉक्स बी)।

बॉक्स बी: भारत में लैंगिक बजटिंग के बीस वर्ष

लैंगिक बजटिंग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों एवं महिलाओं के विकास का समर्थन करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करता है (आईएमएफ, 2016)। यह बजटीय प्रथाओं की लिंग प्रतिक्रियाशीलता का विवरण देकर नीति निर्माण में सहायता करता है। लैंगिक बजट लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रयासों को दर्शाते हैं - एक मान्यता प्राप्त सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)। ऑस्ट्री एवं अन्य (2018) ने अनुमान लगाया कि महिला श्रम बल भागीदारी में बाधाओं को दूर करने से महत्वपूर्ण उत्पादन और कल्याण लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

1984 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से, लैंगिक बजट को 100 से अधिक देशों (यूएन महिला, 2023) द्वारा अपनाया गया है, जो मूल, राजकोषीय नीति घटकों, कानूनी प्रावधानों, शामिल सरकारों के स्तर और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका में विभिन्न प्रथाओं को प्रदर्शित करता है (स्टॉट्स्की , 2016)। 1995 में इसे अपनाने वाला एक प्रारंभिक देश दक्षिण अफ्रीका ने 2019 में लैंगिक उत्तरदायी योजना, बजट, निगरानी, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा रूपरेखा (जीआरपीबीएमईएएफ) की स्थापना की, जो लैंगिक समानता प्रतिबद्धताओं के लिए व्यापक संस्थागत उत्तरदायित्व के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है और सरकार के सभी स्तरों पर लैंगिक उत्तरदायी नीति को बढ़ावा देता है। ब्राजील में, नागरिक समाज ने लैंगिक संवेदनशील बजट के प्रति सरकारी जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (रेस , 2006)। चीन में, कुछ स्थानीय सरकारों ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन उपाय के रूप में लैंगिक बजट को शामिल करने की पहल की है (अलोंसो एवं अन्य., 2021)। बेल्जियम ने कानूनी तौर पर मंत्रालयों को लिंग-विभाजित डेटा बनाए रखने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए लिंग संकेतक विकसित करने का आदेश दिया है। फिनलैंड पूर्वानुमान-विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके तहत मंत्रालयों को बजट प्रस्तावों के अपेक्षित लिंग प्रभाव की

(जारी)

[13] आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24।

रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है (एलोमाकी और यलोस्टालो , 2021)। भारत ने अपना पहला जीबीएस केंद्रीय बजट 2005-06 में पेश किया और लिंग-संवेदनशील प्रथाओं को बढ़ावा देने और रिपोर्ट करने के लिए 2007 में मंत्रालयों में लैंगिक बजटिंग सेल की स्थापना की। ओडिशा 2004-05 में लैंगिक बजटिंग को अपनाने वाला पहला राज्य था।[14] 2024-25 के दौरान, 11 राज्यों ने जीबीएस प्रस्तुत किए।

केंद्र के लैंगिक बजट को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: भाग ए में महिलाओं के कल्याण के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाएं शामिल हैं; भाग बी में ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के कल्याण के लिए निर्देशित हैं; और भाग सी, जिसे 2024-25 में पेश किया गया है, में महिलाओं के कल्याण के लिए 30 प्रतिशत से कम आवंटन वाली योजनाएं शामिल हैं। कुल व्यय में लैंगिक बजट का हिस्सा 2014-15 में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 6.8 प्रतिशत हो गया, जिसमें भाग ए की योजनाएं तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। 2021-25 के दौरान भाग ए के तहत औसत व्यय में तेज वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन के लिए बढ़े हुए आवंटन से प्रेरित है। 2024-25 (बजट अनुमान) के लिए, लैंगिक बजट के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट बी.1ए)।

2022-23 से 2024-25 के बीच, भाग ए मुख्य रूप से आवास, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित था। भाग ए में 19 मंत्रालयों में से शीर्ष तीन - ग्रामीण विकास (63.7 प्रतिशत); आवास और शहरी मामले (23.3 प्रतिशत); और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (8.1

चार्ट बी.1: केंद्रीय लैंगिक बजट - रुझान और संरचना

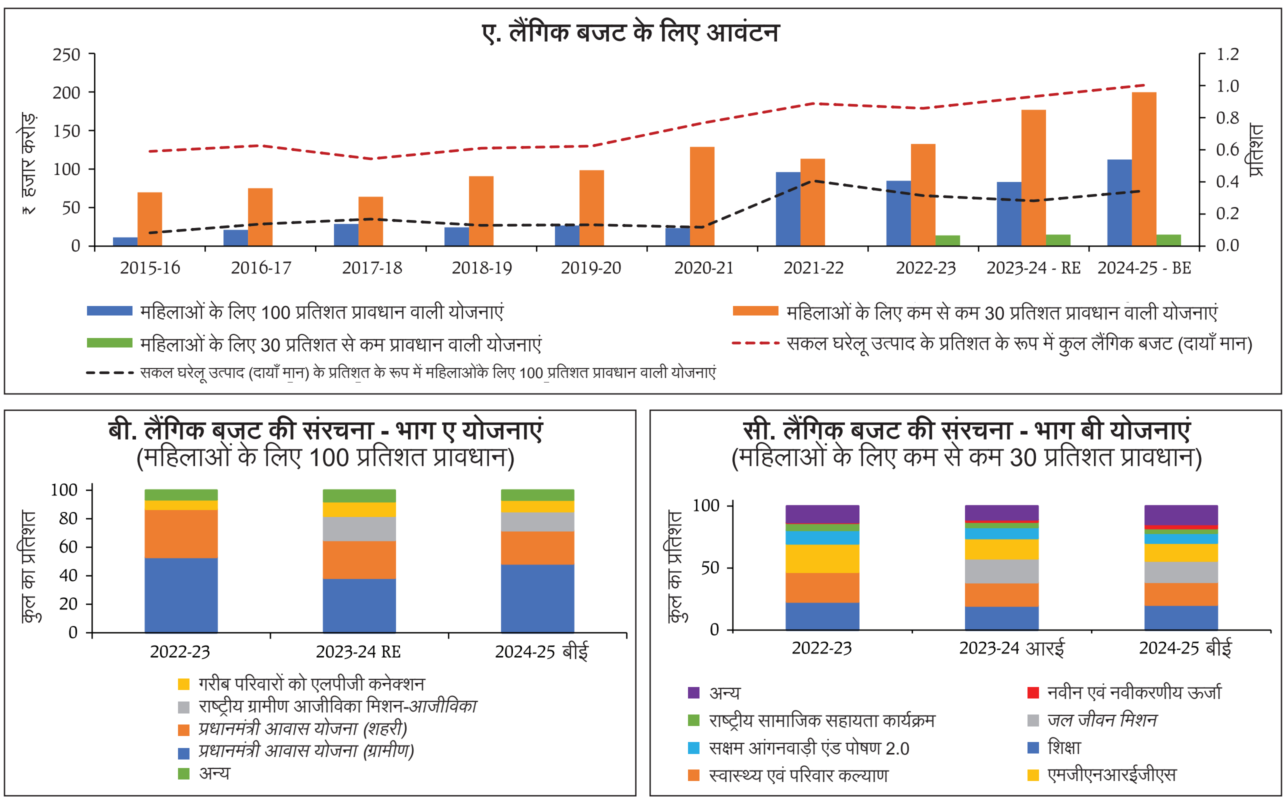

टिप्पणियाँ: 1. शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुल व्यय को दर्शाता है।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीले पूल पर व्यय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए अन्य महिला-उन्मुख व्यय शामिल हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

(Contd.)

[14] सूचना बुलेटिन, अनुसंधान एवं सूचना प्रभाग, लोक सभा सचिवालय, 2016।

प्रतिशत) - 2024-25 (बीई) में बजटीय व्यय का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। भाग बी में लगभग 27 मंत्रालयों के अधिक बिखरे हुए व्यय हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय, स्वच्छ पेयजल के प्रावधान और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित हैं (चार्ट बी.1बी और सी)। 2024-25 में प्रस्तुत भाग सी में चालू वित्त वर्ष के लिए ₹15,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शामिल है।

लैंगिक बजटिंग ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए राजकोषीय नीतियों में बदलाव को प्रेरित किया है, जिससे भारत में लिंग-उन्मुख लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है (स्टॉट्स्की , 2016)। एक वैश्विक सर्वेक्षण ने भारत को 23 देशों में से एक के रूप में पहचाना है, जिसमें प्रमुख लैंगिक बजटिंग प्रयास हैं (स्टॉट्स्की , 2016)। व्यय को वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट तंत्र और लैंगिक बजट के अंतर्गत भारिता निर्दिष्ट करने के लिए पारदर्शी मानदंड स्थापित करने से पारदर्शिता को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2022 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लैंगिक बजटिंग अधिनियम जैसा कानूनी प्रावधान बनाना, इन प्रयासों को निर्देशित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान कर सकता है।

संदर्भ

Elomaki, A. and Ylostalo, H. (2021). Gender Budgeting in the Crossroad of Gender Policy and Public Financial Management: The Finnish case. *Public Money and Management.*

Alonso, V. A., Curristine, T. R., Preston, G., Soler, A., Tchelishvili, N., Weerathunga, S. (2021). Gender Budgeting in G20 Countries. *IMF Working Papers*, 2021/269, International Monetary Fund.

Stotsky, J. G. (2016). Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes. *IMF Working Paper*, No. 16/149, July.

Explainer: What is Gender Responsive Budgeting? (November 2023). UN Women.

Ostry, J., Alvarez, J., Espinoza, R. and Papageorgiou, C. (2018). Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence. Staff Discussion Notes.

Raes, F. (2006). What Can We Expect from Gender Sensitive Budgets? Strategies in Brazil and Chile in a Comparative Perspective', Network Women in Development Europe – WIDE.

2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही में राज्यों के राजस्व व्यय में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2023-24 की इसी तिमाहियों में दर्ज की गई वृद्धि से अधिक थी। राज्यों ने 2024-25 की पहली छमाही में अपने बजटीय राजस्व व्यय का 41.6 प्रतिशत (छ1:2023-24 में 41.3 प्रतिशत) खर्च किया। दूसरी ओर, 2024-25 की पहली छमाही में उनके पूंजीगत व्यय में 6.9 प्रतिशत की कमी आई, जिसमें 2024-25 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की गिरावट और

चार्ट 12: राज्य सरकारों का त्रैमासिक व्यय

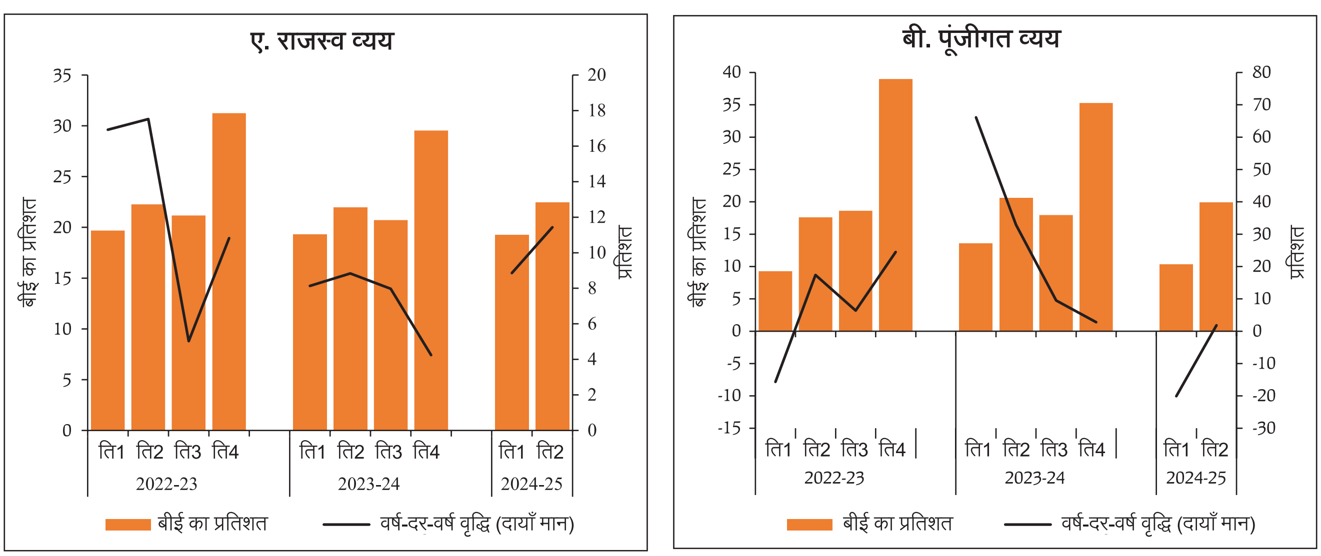

स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2024-25 की दूसरी तिमाही में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 12ए और बी)। परिणामों पर अधिक ध्यान देने से व्यय दक्षता में वृद्धि हो सकती है (बॉक्स सी)।

बॉक्स सी: व्यय प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए परिणाम बजट

भारतीय राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 8.1 प्रतिशत हो गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता बढ़ रही है। हालांकि, इस खर्च की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कितनी अच्छी तरह से ठोस परिणामों में तबदील होती है। सार्वजनिक संसाधनों से 'पैसे का मूल्य' सुनिश्चित करना किसी भी अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है (जेना, 2013)। नीति आयोग और चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों ने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रदर्शन से जुड़े बजट की वकालत की (कुंडू, 2024)। सामाजिक क्षेत्र के व्यय की लागत-प्रभावशीलता में अंतर-राज्यीय भिन्नता परिणामों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है। उदाहरण के लिए एचडीआई सुधार के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर सीमांत प्रतिलाभ में काफी भिन्नता है, जो 0.003 प्रतिशत से लेकर 0.102 प्रतिशत (सामाजिक क्षेत्र के खर्च में प्रतिशत वृद्धि के लिए एचडीआई सूचकांक में प्रतिशत सुधार) तक है [चार्ट सी.1ए]। इसी तरह, स्वास्थ्य पर बढ़ा हुआ खर्च समान रूप से बेहतर नतीजों में तबदील नहीं होता है। उदाहरण के लिए, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी स्वास्थ्य क्षेत्र के खर्च पर सीमांत प्रतिलाभ में महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय असमानताओं को दर्शाती है (चार्ट सी.1बी)। ये भिन्नताएं बजटीय परिव्यय से आगे बढ़कर परिणाम-उन्मुख सार्वजनिक खर्च पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आउटकम बजटिंग (ओबी) सार्वजनिक व्यय को मापने योग्य विकासात्मक आउटपुट और परिणामों से जोड़कर इस चुनौती का समाधान करता है। इनपुट पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक बजटों के विपरीत, ओबी परिणामों पर जोर देता है, अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण को बढ़ावा देता है। 2005 में संघ स्तर पर पेश किए गए, ओबी को तब से 11 राज्यों (सीबीजीए, 2021) द्वारा अपनाया गया है। नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने एक आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है और कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के परिणाम-आधारित बजट बनाए हैं। परिणाम बजट का कार्यान्वयन और ढांचा राज्यों में अलग-अलग है। हालाँकि,

चार्ट सी.1: परिणाम संकेतक बनाम राज्यों द्वारा व्यय

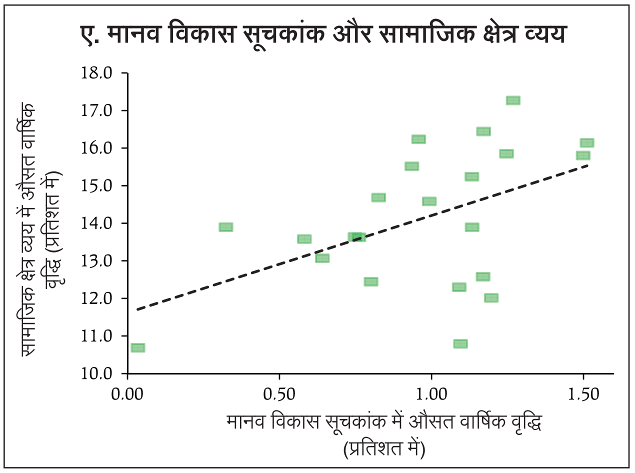

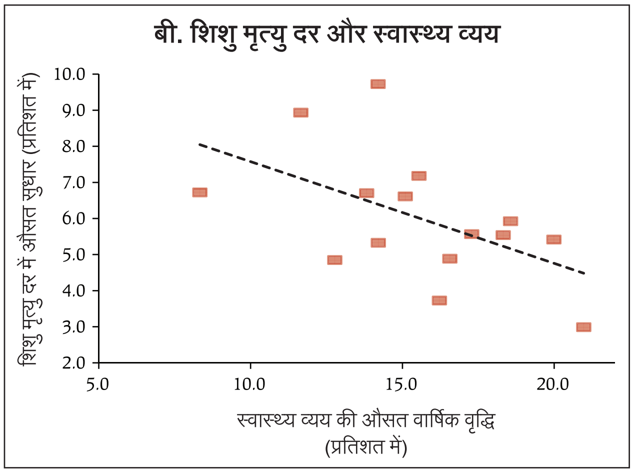

टिप्पणियाँ: 1. जो राज्य 0.6 एचडीआई मूल्य से ऊपर हैं तथा औसत आईएमआर से ऊपर हैं, उन्हें विश्लेषण से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनका आधार ऊंचा है।
2. मानव विकास सूचकांक और सामाजिक क्षेत्र व्यय के लिए 15 वर्ष की अवधि (2005-06 से 2021-22) में औसत की गणना की जाती है।
3. शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य व्यय के लिए औसत की गणना 10 वर्ष की अवधि (2010-11 से 2020-21) में की गई है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें क्षमता निर्माण, बढ़ी हुई पारदर्शिता और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता शामिल है।

सभी राज्यों और क्षेत्रों में ओबी को बढ़ाना, इसके ढांचे को एसडीजी बेंचमार्क के साथ संरेखित करना और मजबूत डेटा सिस्टम में निवेश करना व्यय दक्षता को संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और राज्यों के बीच सहयोगात्मक ज्ञान साझाकरण ओबी के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। सभी राज्यों में ओबी को संस्थागत बनाने से सतत विकास की उपलब्धि और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है।

संदर्भ

Kundu, P. (2024). Issues and Trends in Public Expenditure. *Economic and Political Weekly*, Volume 59, Issue No. 33, August 17, 2024.

Rawal, S and Gupta, M. (2024). Need for SDG-linked outcome budgeting in India: A case of Assam. *Down to Earth*, February 21, 2024.

Jena, P.R. (2013) Improving Public Financial Management in India: Opportunities to Move Forward, *NIPFP Working Paper No 2013–123*, April.

CBGA (2021). Outcome Budgeting in India: The Efforts being made at the Union and State Levels. Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA).

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

केंद्र सरकार

ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा है, जबकि 2023-24 (पीए) में यह 5.6 प्रतिशत था, जो 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम के मध्यम अवधि के जीएफडी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लाइड पथ के अनुरूप है। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र सरकार का जीएफडी बजट अनुमान का 29.4 प्रतिशत रहा, जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 39.3 प्रतिशत से कम था, और यह अनुपात एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर था (चार्ट 13ए और बी)। 2024-25 की पहली छमाही में राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे में भी इसी तरह की कमी देखी गई।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

2024-25 की पहली छमाही में केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए बजट में निर्धारित बाजार उधारी का 52.8 प्रतिशत पूरा कर लिया, जिससे वर्ष की पहली छमाही के दौरान उसके जीएफडी के बड़े हिस्से का वित्तपोषण हुआ। सरकार ने 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए अपने उधारी लक्ष्य पर कायम रहने का फैसला किया है।

चार्ट 13: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा

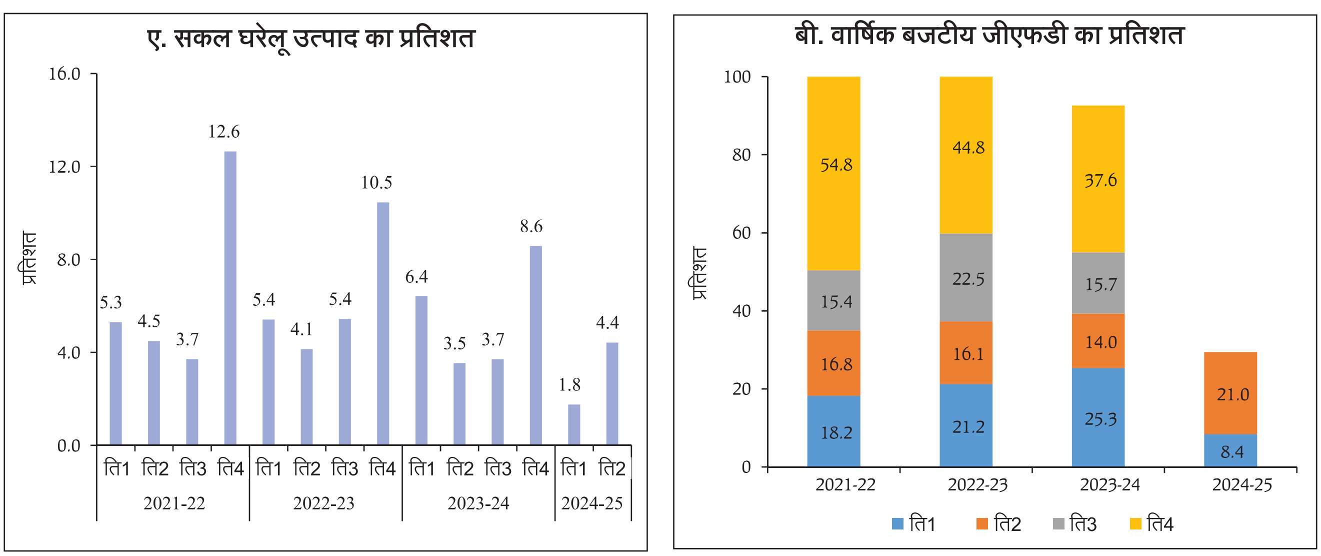

स्रोत: सीजीए; तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 14: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

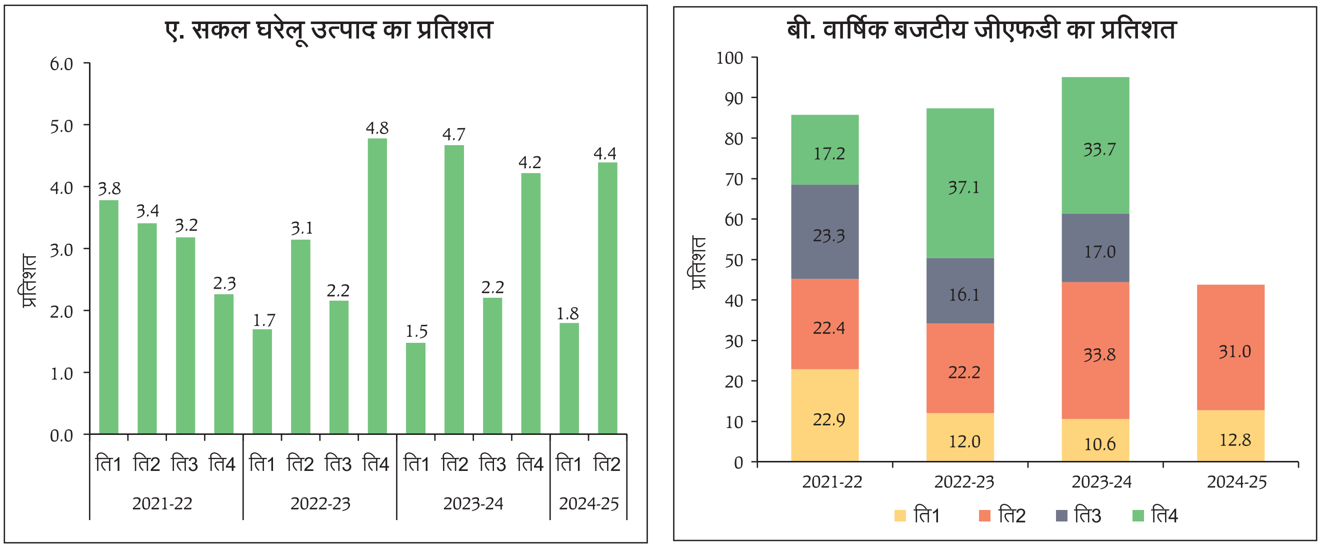

स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य सरकार

ए. राजकोषीय घाटा

राज्यों ने 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट बनाया था, जबकि 2023-24 (पीए) में यह 2.9 प्रतिशत था। 2024-25 के दौरान, राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में अपने बजटीय जीएफडी का कम अनुपात खर्च किया है। तदनुसार, 2024-25 के उत्तरार्ध में राज्यों के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान उनके बजटीय जीएफडी का 56.1 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 55.6 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट 14ए और बी)।

पूंजीगत व्यय में कमी को देखते हुए केंद्र का राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय (आरईसीओ) अनुपात एक साल पहले के 3.9 से बढ़कर 2024-25 की पहली छमाही में 4.7 हो गया। इसी अवधि के दौरान, राज्यों का अनुपात भी 6.6 से बढ़कर 8.3 हो गया (चार्ट 15ए और बी)।

चार्ट 15: केंद्र और राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा और व्यय की गुणवत्ता

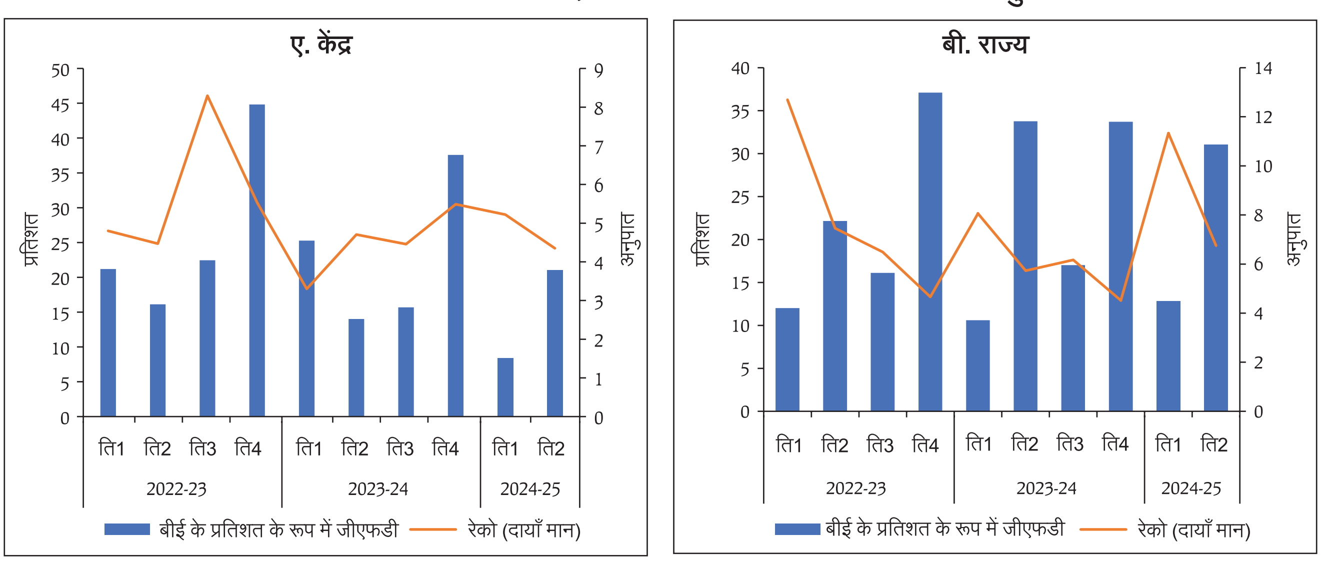

स्रोत: सीजीए: सीएजी; तथा केन्द्र और राज्यों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 16: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बाजार उधार

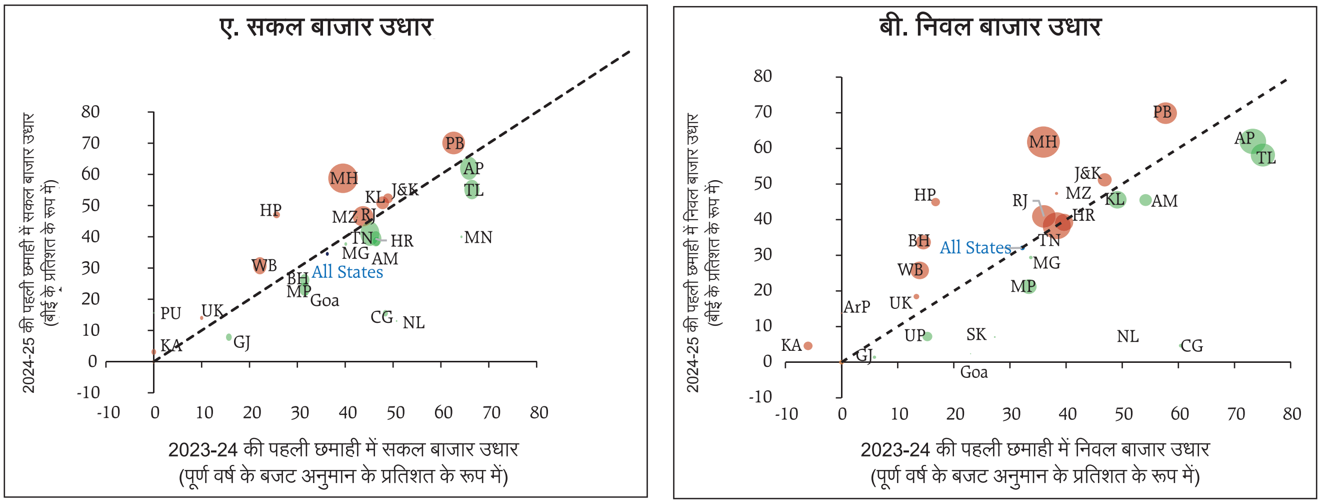

टिप्पणियाँ: 1. बुलबुले का आकार 2024-25 की पहली छमाही बाजार उधार में राज्य की हिस्सेदारी के अनुरूप है।
2. 45 डिग्री रेखा किसी परिवर्तन को नहीं दर्शाती है।

स्रोत: आरबीआई; तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट दस्तावेज।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

2024-25 की पहली छमाही के दौरान राज्यों द्वारा शुद्ध बाजार उधारी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजटीय निवल बाजार उधारी का 32.1 प्रतिशत (2023-24 की इसी अवधि में 32.2 प्रतिशत) उपयोग किया। तेरह राज्यों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अपने बजटीय निवल उधारी का उच्च अनुपात उपयोग किया। सकल बाजार उधारी में पिछले वर्ष की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजटीय राशि का 34.5 प्रतिशत है (चार्ट 16ए और बी)।

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1 जुलाई, 2024 से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा को संशोधित किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल डब्ल्यूएमए सीमा अब ₹60,118 करोड़ है, जो कि पहले की सीमा ₹47,010 करोड़ से 27.9 प्रतिशत अधिक है। परिणामस्वरूप, राज्यों ने 2024-25 की पहली तिमाही में स्वीकार्य डब्ल्यूएमए सीमा का 9.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.8 प्रतिशत उपयोग किया। डब्ल्यूएमए और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत राज्यों द्वारा औसत उपयोग में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 45.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के अंतर्गत उपयोग में 2024-25 की पहली छमाही में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 17ए और बी)।

IV. सामान्य सरकारी वित्त

सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य संयुक्त) के लिए जीएफडी को 2023-24 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 9.0 प्रतिशत से कम करके 2024-25 (बीई) में जीडीपी के 7.6 प्रतिशत पर बजट में रखा गया है। 2024-25 की पहली तिमाही में जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र और राज्यों के कुल व्यय में धीमी वृद्धि और मजबूत कर संग्रह के कारण कम था। 2024-25 की दूसरी तिमाही में केंद्र और राज्यों के व्यय में वृद्धि के साथ ही जीएफडी-

चार्ट 17: रिज़र्व बैंक से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता

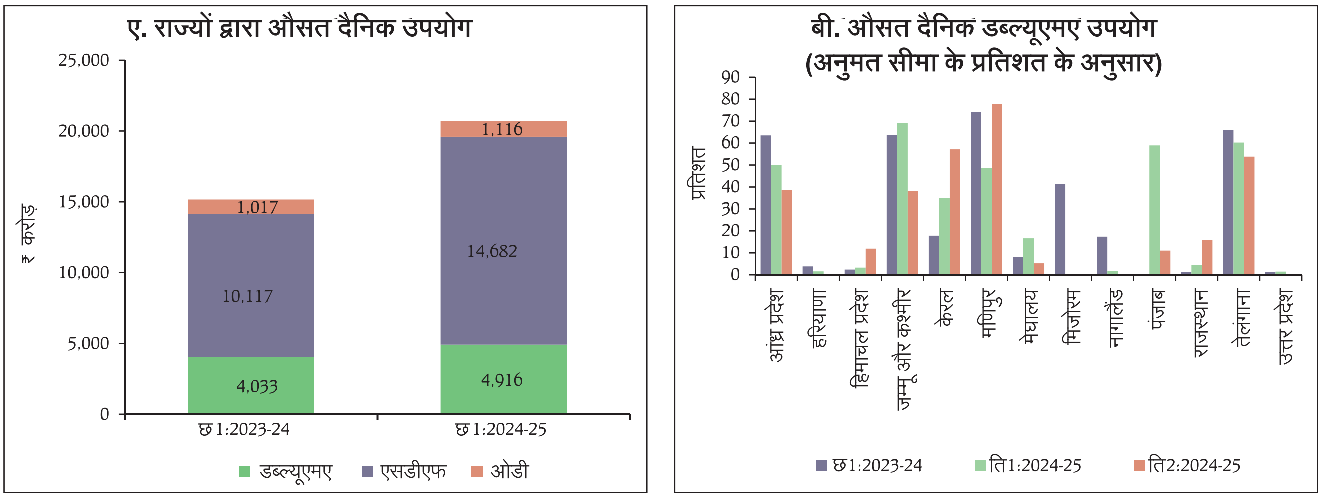

नोट: 2023-24 की पहली छमाही और 2024-25 की पहली तिमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा समान रही, जबकि इसे 2024-25 की दूसरी तिमाही में ऊपर की ओर संशोधित किया गया।
स्रोत: आरबीआई बुलेटिन के विभिन्न अंक; तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

जीडीपी अनुपात अपने पिछले रुझानों के अनुरूप बढ़ गया (चार्ट 18)।

चार्ट 18: सामान्य सरकारी सकल राजकोषीय घाटा

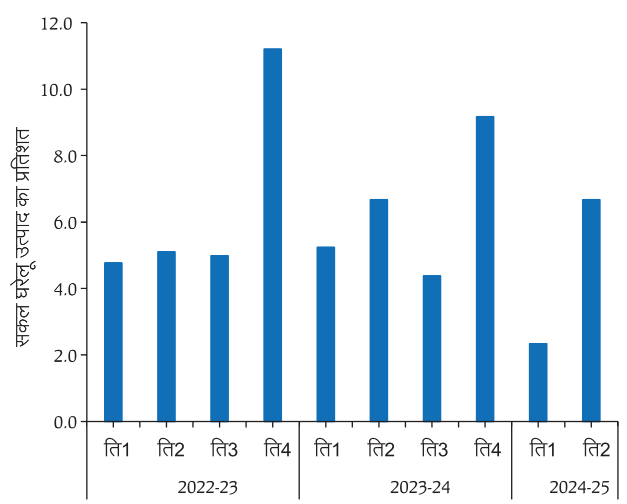

टिप्पणी: चार्ट में दर्शाई गई सभी तिमाहियों के लिए, संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र प्लस 22 राज्य के लिए है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

V. निष्कर्ष

केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की है और उम्मीद है कि यह उछाल जारी रहेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा बड़े अधिशेष हस्तांतरण से केंद्र के गैर-कर राजस्व में वृद्धि हुई है। आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को दर्शाते हुए, केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी खर्च में 2024-25 की पहली छमाही में कमी आई है और 2024-25 की दूसरी छमाही में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, केंद्र ने 2024-25 की पहली छमाही में अपने बजटीय राजस्व का आधे से अधिक हासिल कर लिया है, जबकि अपने व्यय को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के आधे से भी कम पर सीमित रखा है। यह केंद्र के लिए 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के अपने जीएफडी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छा संकेत है। कई राज्यों ने अपने 2024-25 के बजट में कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता सहित रियायतों की घोषणा की है। इस तरह के खर्च से संसाधन महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर हो सकते हैं।

परिशिष्ट सारणी

सारणी I: अप्रैल-सितंबर के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति

वस्तु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	**1622.4**	**1397.1**	**3129.2**	**2632.3**	**51.8**	**53.1**	**16.1**	**19.5**
1.1. निवल कर राजस्व	1265.2	1160.3	2583.5	2330.6	49.0	49.8	9.0	14.7
1.2. गैर-कर राजस्व	357.2	236.8	545.7	301.7	65.5	78.5	50.9	50.2
1.3. ब्याज प्राप्तियां	20.4	17.3	38.2	24.8	53.3	69.7	17.6	38.7
2. पूंजी प्राप्तियां	**14.6**	**20.2**	**78.0**	**84.0**	**18.7**	**24.0**	**-27.6**	**-41.0**
2.1.ऋण की वसूली	11.4	13.2	28.0	23.0	40.8	57.5	-13.5	37.7
2.2. अन्य प्राप्तियां	3.2	7.0	50.0	61.0	6.3	11.4	-54.4	-71.7
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	**1637.0**	**1417.3**	**3207.2**	**2716.3**	**51.0**	**52.2**	**15.5**	**17.7**
4. राजस्व व्यय	**1696.5**	**1628.5**	**3709.4**	**3502.1**	**45.7**	**46.5**	**4.2**	**10.0**
जिसका कि								
(i) ब्याज भुगतान	515.0	484.3	1162.9	1080.0	44.3	44.8	6.3	10.9
5. पूंजीगत व्यय	**415.0**	**490.6**	**1111.1**	**1001.0**	**37.3**	**49.0**	**-15.4**	**43.1**
जिसका कि								
(i) ऋण और अग्रिम	55.4	74.8	192.4	163.8	28.8	45.7	-25.9	217.5
6. कुल व्यय (4+5)	**2111.5**	**2119.1**	**4820.5**	**4503.1**	**43.8**	**47.1**	**-0.4**	**16.2**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**74.2**	**231.4**	**580.2**	**869.9**	**12.8**	**26.6**	**-68.0**	**-25.6**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**474.5**	**701.9**	**1613.3**	**1786.8**	**29.4**	**39.3**	**-32.4**	**13.2**
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	**-40.5**	**217.5**	**450.4**	**706.8**	**-9.0**	**30.8**	**-118.6**	**18.8**

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी II: केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक आंकड़े				बीई का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2024-25	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	**829.7**	**588.6**	**792.7**	**808.5**	**26.5**	**22.4**	**25.3**	**30.7**	**41.0**	**-2.0**
1.1. निवल कर राजस्व	549.6	433.6	715.5	726.7	21.3	18.6	27.7	31.2	26.8	-1.5
1.2. गैर-कर राजस्व	280.0	155.0	77.2	81.8	51.3	51.4	14.1	27.1	80.7	-5.7
1.3. ब्याज प्राप्तियां	11.7	9.5	8.6	7.8	30.6	38.5	22.6	31.3	22.7	11.3
2. पूंजी प्राप्तियां	**4.5**	**10.7**	**10.1**	**9.5**	**5.8**	**12.7**	**12.9**	**11.3**	**-57.8**	**6.5**
2.1.ऋण की वसूली	4.5	6.5	6.9	6.7	16.1	28.1	24.7	29.3	-30.2	2.5
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.0	4.2	3.2	2.7	0.0	6.9	6.3	4.5	-99.9	16.5
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	**834.2**	**599.3**	**802.8**	**818.0**	**26.0**	**22.1**	**25.0**	**30.1**	**39.2**	**-1.9**
4. राजस्व व्यय	**788.9**	**772.2**	**907.7**	**856.3**	**21.3**	**22.0**	**24.5**	**24.5**	**2.2**	**6.0**
जिसका कि										
(i) ब्याज भुगतान	264.1	243.7	251.0	240.6	22.7	22.6	21.6	22.3	8.3	4.3
5. पूंजीगत व्यय	**181.1**	**278.5**	**233.9**	**212.1**	**16.3**	**27.8**	**21.1**	**21.2**	**-35.0**	**10.3**
जिसका कि										
(i) ऋण और अग्रिम	30.0	44.6	25.4	30.2	15.6	27.2	13.2	18.4	-32.7	-16.0
(ii) पूंजीगत परिव्यय	151.0	233.9	208.5	181.9	16.4	27.9	22.7	21.7	-35.4	14.6
6. कुल व्यय (4+5)	**969.9**	**1050.7**	**1141.6**	**1068.5**	**20.1**	**23.3**	**23.7**	**23.7**	**-7.7**	**6.8**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**-40.8**	**183.6**	**115.0**	**47.8**	**-7.0**	**21.1**	**19.8**	**5.5**	**-122.2**	**140.5**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**135.7**	**451.4**	**338.8**	**250.5**	**8.4**	**25.3**	**21.0**	**14.0**	**-69.9**	**35.3**
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	**-128.3**	**207.7**	**87.9**	**9.9**	**-28.5**	**29.4**	**19.5**	**1.4**	**-161.8**	**790.3**

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी III: अप्रैल-सितंबर के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	**1508.4**	**1403.2**	**3869.1**	**3573.7**	**39.0**	**39.3**	**7.5**	**7.1**
1.1. कर राजस्व	1292.7	1156.6	3044.1	2686.9	42.5	43.0	11.8	14.6
1.2. गैर-कर राजस्व	83.9	91.3	276.8	245.5	30.3	37.2	-8.1	18.5
1.3. अनुदान सहायता एवं अंशदान	131.8	155.2	548.2	641.2	24.0	24.2	-15.1	-30.7
2. पूंजी प्राप्तियां	**2.4**	**3.3**	**25.8**	**24.2**	**9.3**	**13.6**	**-27.3**	**16.9**
2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	2.3	3.2	20.2	17.8	11.5	18.0	-27.6	17.8
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.1	0.1	5.6	6.4	1.2	1.3	-16.6	-9.5
3. कुल प्राप्तियां	**1510.8**	**1406.5**	**3894.9**	**3597.9**	**38.8**	**39.1**	**7.4**	**7.1**
4. राजस्व व्यय	**1681.0**	**1525.0**	**4038.9**	**3695.9**	**41.6**	**41.3**	**10.2**	**8.5**
4.1 ब्याज भुगतान	220.8	194.1	503.2	459.2	43.9	42.3	13.7	12.5
5. पूंजीगत व्यय	**233.8**	**251.1**	**777.2**	**734.9**	**30.1**	**34.2**	**-6.9**	**44.4**
5.1 पूंजीगत परिव्यय	202.5	230.3	706.1	658.9	28.7	34.9	-12.1	51.5
6. कुल व्यय	**1914.8**	**1776.1**	**4816.1**	**4430.8**	**39.8**	**40.1**	**7.8**	**12.5**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**172.6**	**121.8**	**169.7**	**122.3**	**101.7**	**99.6**	**41.7**	**27.5**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**404.0**	**369.6**	**921.2**	**833.0**	**43.9**	**44.4**	**9.3**	**38.6**
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	**183.2**	**175.5**	**418.0**	**373.8**	**43.8**	**46.9**	**4.4**	**86.7**

नोट: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; तथा राज्यों के बजट दस्तावेज़।

सारणी IV: राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक आंकड़े				बजट अनुमान				वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2024-25	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	**736.7**	**722.8**	**771.7**	**680.4**	**19.0**	**20.2**	**19.9**	**19.0**	**1.9**	**13.4**
1.1. कर राजस्व	652.7	560.5	640.0	596.1	21.4	20.9	21.0	22.2	16.4	7.4
1.2. गैर-कर राजस्व	40.5	35.9	43.4	55.4	14.6	14.6	15.7	22.6	12.8	-21.7
1.3. अनुदान सहायता एवं अंशदान	43.4	126.4	88.3	28.9	7.9	19.7	16.1	4.5	-65.6	206.0
2. पूंजी प्राप्तियां	**1.2**	**1.7**	**1.2**	**1.6**	**4.6**	**6.8**	**4.6**	**6.7**	**-27.5**	**-27.1**
2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	1.2	1.6	1.2	1.6	5.8	8.9	5.7	9.0	-26.9	-28.3
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.3	-45.3	67.8
3. कुल प्राप्तियां	**737.9**	**724.5**	**772.9**	**682.0**	**18.9**	**20.1**	**19.8**	**19.0**	**1.9**	**13.3**
4. राजस्व व्यय	**776.3**	**713.1**	**904.7**	**811.9**	**19.2**	**19.3**	**22.4**	**22.0**	**8.9**	**11.4**
4.1 ब्याज भुगतान	95.3	80.8	125.5	113.3	18.9	17.6	24.9	24.7	17.9	10.8
5. पूंजीगत व्यय	**79.7**	**99.7**	**154.1**	**151.4**	**10.3**	**13.6**	**19.8**	**20.6**	**-20.1**	**1.8**
5.1 पूंजीगत परिव्यय	68.5	88.5	134.0	141.8	9.7	13.4	19.0	21.5	-22.6	-5.5
6. कुल व्यय	**855.9**	**812.8**	**1058.8**	**963.3**	**17.8**	**18.3**	**22.0**	**21.7**	**5.3**	**9.9**
7. राजस्व घाटा	**39.6**	**-9.7**	**133.0**	**131.5**	**23.3**	**-8.0**	**78.3**	**107.6**	**-506.8**	**1.1**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**118.1**	**88.3**	**285.9**	**281.3**	**12.8**	**10.6**	**31.0**	**33.8**	**33.7**	**1.7**
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	**22.8**	**7.5**	**160.4**	**168.0**	**5.4**	**2.0**	**38.4**	**44.9**	**203.7**	**-4.5**

नोट: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; तथा राज्यों के बजट दस्तावेज़।

बैंकों का दैनिक मुद्रा रिज़र्व संधारण व्यवहार

*सुजीश कुमार^, मंजूषा सेनापति^, और प्रज्ञा दास**

यह लेख पिछले एक दशक में विभिन्न आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीति परिवर्तनों में भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के दैनिक आरक्षित संधारण व्यवहार का विश्लेषण करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि (i) लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) व्यवस्था और स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा की शुरुआत एससीबी द्वारा संधारित औसत दैनिक अतिरिक्त रिज़र्व के निचले स्तर से जुड़ी हुई है, जिससे वृद्धिशील संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग बैंकों द्वारा उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; (ii) एएसआईएसओ के बाद दैनिक आरक्षित निधियों के संधारण के उतार-चढ़ाव में कमी आई है, जिससे बैंक अपनी दैनिक आरक्षित निधियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में समर्थ हो गए हैं; और (iii) बैंक अपने रिज़र्व का बेहतर प्रबंधन तब करते हैं जब दैनिक न्यूनतम संधारण आवश्यकताएं 90 प्रतिशत होती हैं, कम आवश्यकताएं होने पर उच्च अस्थिरता होती है।

परिचय

आरक्षित मुद्रा संबंधी अनिवार्यता पारंपरिक रूप से किसी बैंक की जमा देनदारियों के अनुपात को संदर्भित करती हैं जो आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग से जुड़ी चिंता को रोकने और / या मौद्रिक नीति में परिवर्तनों को निष्पादित करके सार्वजनिक हित बढ़ाने के लिए लागू की जाती हैं। इन अनिवार्यताओं में परिवर्तन भी ऋण आपूर्ति में बदलाव लाते हैं। एक आधुनिक वित्तीय प्रणाली में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अनिवार्यताएं कई भूमिकाएं निभाती हैं – (i) वित्तीय संस्थानों (माइक्रोप्रूडेंशियल) के लिए चलनिधि बफर आवश्यक करते हुए विवेकपूर्ण विनियमन किया जाता है, और इस तरह प्रणालीगत आघातों (मैक्रोप्रूडेंशियल) का सामना करने के लिए प्रणालीगत लचीलापन बढ़ता है; (ii) विभिन्न परिचालनगत ढांचों में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन; और (iii) चलनिधि प्रबंधन (वैले एवं अन्य. 2022; और ग्रे, 2011)। न्यूनतम आरक्षित मुद्रा अनिवार्यताएं ओवरनाइट दरों को निर्देशित करने और स्थिर करने में मदद कर सकती हैं। रिज़र्व अनिवार्यताओं को जब एक अतिरिक्त साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था में नीति परिणामों में काफी सुधार हो सकता है जहां वित्तीय बाधाएं मौजूद हैं, और केंद्रीय बैंक का वित्तीय स्थिरता उद्देश्य है। आरक्षित अनिवार्यताओं में वृद्धि होने से ऋण और आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि बैंक उच्च लागत को आगे पारित करते हैं और वित्तपोषण शर्तों को प्रतिबंधित करते हैं; जबकि दूसरी ओर, यह वित्तीय दबाव की घटनाओं और तीव्रता को भी कम करता है। तत्काल क्रेडिट/ आउटपुट हानि की भरपाई वित्तीय दबाव की कम संभावना से हो जाती है; इस प्रकार मुद्रा रिज़र्व अनिवार्यताओं का उपयोग वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन के निर्माण और वित्तीय दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक लाभकारी है (ग्लोकर और टॉबिन, 2012 और कैंटू एवं अन्य., 2024)।

भारत में सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अनुसार सीआरआर बनाए रखना आवश्यक है। अधिनियम के अंतर्गत, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरबीआई के पास सीआरआर शेष के रूप में रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत आधार पर अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का एक विनिदष्ट अनुपात बनाए रखें। एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में रिज़र्व का औसत पखवाड़े के दौरान न्यूनतम दैनिक शेष (वास्तविक नियामक आवश्यकताओं के अनुपात के रूप में निर्धारित) के संधारण के अधीन है। एक आरक्षित औसत प्रणाली में, बैंकों की रिज़र्व की मांग दैनिक आधार पर लचीली होती है, लेकिन स्थायी सुविधाओं (स्टैंडिंग फैसिलिटी) की उपलब्धता के कारण दीर्घकालिक आधार पर ब्याज बेलोचदार होता है। समीक्षाधीन पखवाड़े में बैंक अपने दैनिक संधारण स्तर का चयन स्थायी सुविधाओं पर ब्याज दर अपेक्षाओं के लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर करते हैं। मौद्रिक नीति परिचालनों के शोधन और आरबीआई द्वारा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाने के दौरान सीआरआर साधन में कई बदलाव हुए हैं।

---

^ लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग से हैं।

* लेखक मौद्रिक नीति विभाग से हैं।

इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेखक बहुमूल्य सुझावों के लिए श्री जॉयस जॉन और श्री बी. ए. तलवार के प्रति तथा डेटा उपलब्ध कराने के लिए श्री रोहित गमे के प्रति आभारी हैं।

बैंकों को दिन के अंत में अपने सीआरआर शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए आरबीआई ने अगस्त 2020 में एक वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान की, जिसके तहत बैंक के लिए एक ऐसी विशिष्ट राशि (या सीमा) पूर्व-निर्धारित थी जिसे वे दिन के अंत में स्वेच्छा से बनाए रखना चाहते थे। बैंकों की इस राशि में किसी भी कमी या अतिरिक्त शेष राशि से एएसआईएसओ सुविधा के तहत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) या स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)/रिवर्स रेपो बोलियां स्वतः ही क्रियान्वित होने की सुविधा है।

नकदी रिज़र्व बनाए रखने में बैंकों के भिन्न व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इस लेख के दो व्यापक उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से यह लेख एफआईटी दौर के पहले और एफआईटी दौर के तहत बैंकों के रिज़र्व संधारण व्यवहार का विश्लेषण करता है। दूसरे, यह एएसआईएसओ और 24x7 भुगतान प्रणाली सुविधाओं के लागू होने और बैंकों के रिज़र्व संधारण के उतार-चढ़ाव पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इस तरह के उपायों से बेहतर चलनिधि योजना बनने की उम्मीद है और इसलिए बैंकों द्वारा औसत दैनिक संधारण में कम अस्थिरता के साथ अधिक कुशल दैनिक रिज़र्व संधारण होगा। यह विश्लेषण आरबीआई द्वारा किए गए इन उपायों की प्रभावकारिता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

इस पृष्ठभूमि के साथ, इस लेख को छह खंडों में संरचित किया गया है। अगला खंड सीआरआर की विनियामक आवश्यकताओं और समय के साथ इसके विकासक्रम का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करता है। खंड III में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए रखे जाने वाले सीआरआर पर कुछ आदर्शित (स्टायलाइज़्ड) तथ्यों को दर्शाया गया है। खंड IV में सीआरआर में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है, जबकि खंड V बैंकों के दैनिक रिज़र्व संधारण में उतार-चढ़ाव का एक अनुभवजन्य विश्लेषण देता है; खंड VI समापन खंड है।

II. भारत में सीआरआर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में रिज़र्व संधारण प्रणाली समय के साथ-साथ विकसित होती गई है। प्रारंभ में, आरबीआई अधिनियम की धारा 42 (1) के अनुसार रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए उनकी मांग और मीयादी देनदारियों के कुल 3 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच सीआरआर निर्धारित कर सकता था। 2006 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए गए जिसके अनुसार आरबीआई को सीआरआर निर्धारण पर न्यूनतम या उच्चतम सीमा को हटाकर रिज़र्व प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में किए गए संशोधन (धारा 42 की उपधारा (1ख) को हटाकर) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संधारित सीआरआर शेष पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं करता है।

सितंबर 1962 से पहले, मांग और मीयादी देनदारियों के लिए दो अलग-अलग रिज़र्व अनुपात थे। मांग और मीयादी देनदारियों के लिए निर्धारित सीआरआर संधारण क्रमशः 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत था। 16 सितंबर 1962 से मांग और समय देनदारियों दोनों के लिए 3 प्रतिशत का एक समान सीआरआर निर्धारण लागू किया गया। 1980 तक, विनियामक सीआरआर अनिवार्यता स्तर 6 प्रतिशत से नीचे था। 1980 के दशक के दौरान राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण उत्तरोत्तर मौद्रिक नीति के संचालन में विचार के लिए एक प्रमुख घटक बन गया, जिसे प्राथमिक बजट वित्तपोषण द्वारा मौद्रिक विस्तार के माध्यमिक दौर के साथ संघर्ष करना पड़ा। परिणामस्वरूप, सीआरआर मौद्रिक नीति के प्रमुख साधनों में से एक के रूप में विकसित हुआ और सीआरआर का स्तर 1992 तक उत्तरोत्तर बढ़कर 15.0 प्रतिशत हो गया। इस उच्च स्तर के सीआरआर को बैंकिंग प्रणाली पर दंडात्मक कर के रूप में देखा गया, जिससे उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। आगामी अवधि में, सीआरआर को धीरे-धीरे 1998 तक 10 प्रतिशत के करीब और 2002-2006 के दौरान 4 से 5 प्रतिशत के बीच लाया गया। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के उत्पन्न होने से पहले चलनिधि स्थितियों को सख्त बनाने की दृष्टि से सीआरआर को जनवरी 2007 से अगस्त 2008 के बीच 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया था लेकिन बाद में इसे तेजी से घटाकर नवम्बर 2008 में 5.5 प्रतिशत और फरवरी 2013 में 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद, उस समय से जब आरबीआई ने 2016 में एफआईटी को अपनाया था, 2020 में कोविड-19 महामारी तक, सीआरआर 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

मार्च 2020 में महामारी संकट आने पर प्रणालीगत चलनिधि के पूरक के रूप में रिज़र्व अनिवार्यता को घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। मई 2021 में सीआरआर को 4.0 प्रतिशत के पूर्व-महामारी स्तर पर दो चरणों में वापस सामान्य किया गया। बाद

चार्ट 1 विनियामक सीआरआर में अब तक के उतार-चढ़ाव

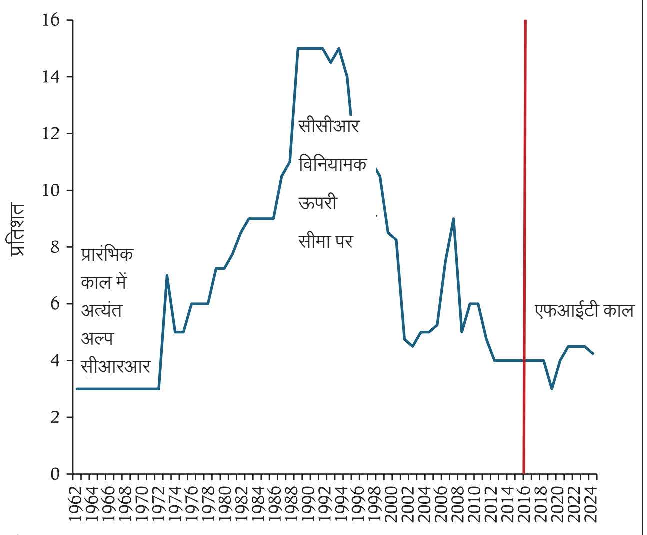

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई।

में मई 2022 में इसे बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया क्योंकि मौद्रिक नीति का रुख समायोजन को वापस लेने में बदल गया। दिसंबर 2024 में तटस्थ नीति रुख के अनुरुप, सीआरआर को 14 दिसंबर और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस, प्रत्येक की दो समान किस्तों में, सक्रिय रूप से 50 आधार अंकों से घटाकर एनडीटीएल का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया (दास, एस., 2024) (चार्ट 1)।

III. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संधारित सीआरआर पर आदर्शित तथ्य

III.1 संधारित सीआरआर का स्वरूप

व्यवहारिक रूप से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) कई कारणों से दैनिक अनिवार्यताओं से अधिक रिज़र्व बनाए रखते हैं। इस तरह के चलनिधि बफर उन्हें अप्रत्याशित नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने में मदद करते हैं, बेहतर जोखिम प्रबंधन को सक्षम करते हैं और बेहतर परिचालन दक्षता हासिल करते हुए आसान भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे वे पखवाड़े के दौरान औसत संधारण को समायोजित करने में भी सक्षम होते हैं क्योंकि बैंकों को औसतन अनिवार्य रिज़र्व का 100 प्रतिशत बनाए रखना होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संधारित नकद रिज़र्व उनके दैनिक संधारण में उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं। मुख्य रूप से चलनिधि प्रबंधन और मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में परिशोधन के कारण एनडीटीएल के अनुपात के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संधारित दैनिक अतिरिक्त रिज़र्व में उतार-चढ़ाव एफआईटी अवधि के दौरान कम हुआ है (चार्ट 2)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दैनिक नकद रिज़र्व संधारण स्वरूप से पता चलता है कि रिज़र्व राशि को फ्रंटलोडिंग करने की प्रवृत्ति थी (अर्थात, पखवाड़े के पहले सप्ताह के दौरान अधिक

चार्ट 2 एससीबी द्वारा अतिरिक्त सीआरआर संधारण

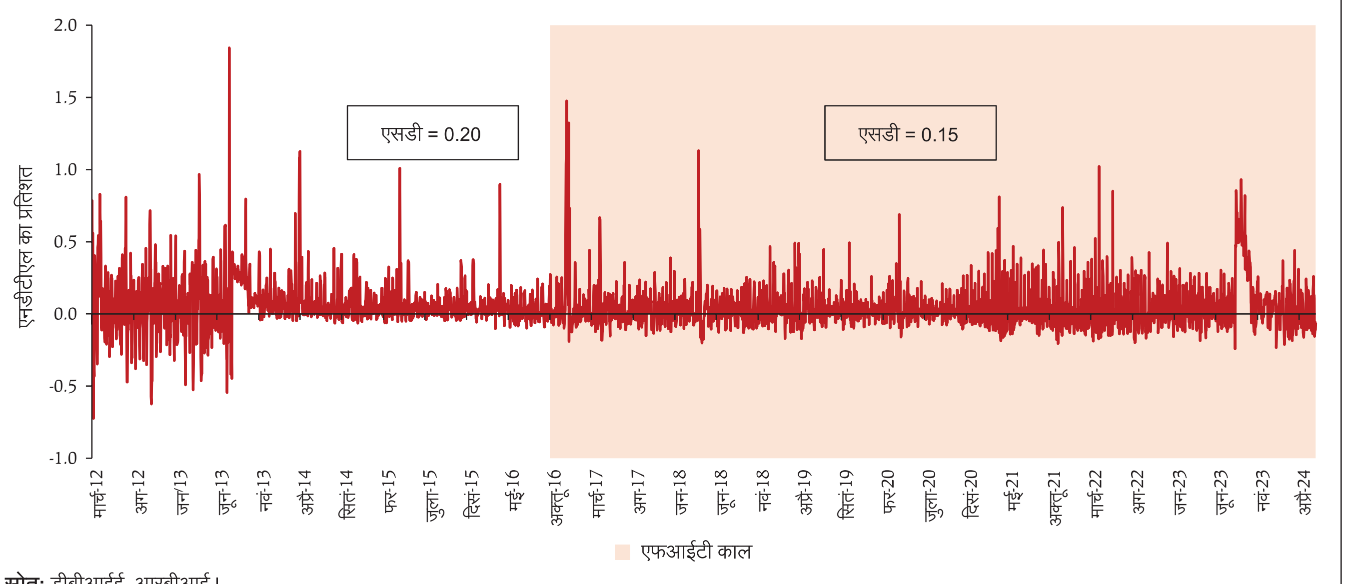

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई।

चार्ट 3 : विभिन्न समय में अनिवार्यता के प्रतिशत (सप्ताह-1 की तुलना में सप्ताह-2) के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औसत सीआरआर संधारण का स्वरूप

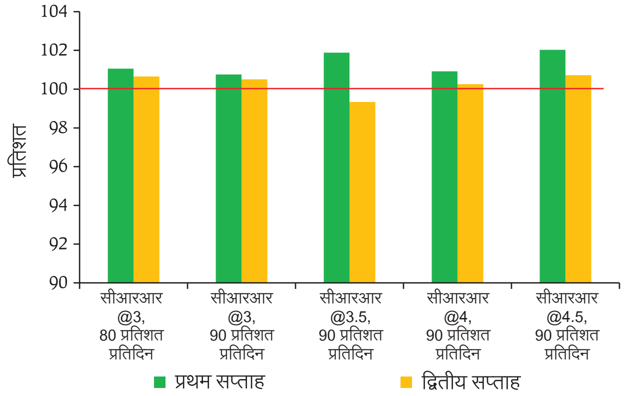

टिप्पणी: (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दैनिक आरक्षित निधि संधारण (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) 02 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2024 तक।
(ii) लाल रेखा पखवाड़े के दौरान 100 प्रतिशत दैनिक संधारण को दर्शाती है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; एवं लेखकों की गणनाएं

रिज़र्व बनाए रखा रखना)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नकद रिज़र्व की फ्रंटलोडिंग का मुख्य उद्देश्य औसत संधारण अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन होना था। सीआरआर का दैनिक संधारण ब्याज दर के उभरते परिदृश्य के आधार पर बैंकों की व्यावसायिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, प्रणालीगत स्तर पर, यदि रिज़र्व संधारण अवधि के पहले सप्ताह के दौरान चलनिधि अधिशेष में है, तो यह पूरे पखवाड़े के लिए औसत आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो सकती है यदि दूसरे सप्ताह में चलनिधि की कमी होती है। इसके अलावा बैंक अवकाश/सप्ताहांतों से पहले भी अधिशेष रिज़र्व रखते हैं ताकि अप्रत्याशित नकदी बहिर्वाहों को पूरा किया जा सके। अप्रत्याशित नकदी बहिर्वाह रिज़र्व को कम कर सकता है जिससे आवश्यक रिज़र्व के दैनिक न्यूनतम संधारण पर प्रभाव पड़ सकता है। छुट्टियों के दौरान, जब बैंकों के पास संसाधन जुटाने के लिए अधिक रास्ते नहीं होते हैं, तो अतिरिक्त रिज़र्व बनाए रखा जाता है (चार्ट 3)।

III.2 निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में सीआरआर के दैनिक संधारण का वितरण

सितंबर 2016 में अपनाई गई एफआईटी व्यवस्था में आरबीआई को संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत की ऊपरी सह्य सीमा और 2 प्रतिशत की निचली सह्य सीमा के साथ 4 प्रतिशत पर लक्षित करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) लक्ष्य हासिल करने के लिए नीतिगत रेपो दर तय करती है। मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे का उद्देश्य परिचालन लक्ष्य, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) को नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित करना है। आरबीआई का सक्रिय चलनिधि प्रबंधन नीतिगत रेपो दर से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचरण की सुविधा प्रदान करता है, जो बदले में, बढ़ती मांग को प्रभावित करता है जो मुद्रास्फीति और संवृद्धि को संतुलित करने के लिए प्रमुख निर्धारक है।

भारत में पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर रिज़र्व बनाए रखना जरूरी है; लेकिन, पखवाड़े के दौरान किसी एक निर्धारित दिन को सीआरआर आवश्यकता का एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे बैंकों को निधियों की मांग में अनपेक्षित उतार-चढ़ाव से बचने के साथ-साथ अप्रत्याशित प्रवाहों को पाटने के लिए अपने दिन-प्रतिदिन के चलनिधि प्रबंधन में सहायता मिली है। बैंकों का रिज़र्व संधारण चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप भी है। एफआईटी पूर्व अवधि और एफआईटी अवधि में निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में सभी एससीबी द्वारा दैनिक रिज़र्व शेष का वितरण मुख्य रूप से चलनिधि प्रबंधन ढांचे के विकास और परिशोधन के कारण दैनिक संधारण स्वरूप में एक स्पष्ट संक्रमण का संकेत देता है (चार्ट 4)।

चार्ट 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों लिए निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में दैनिक आरक्षित निधि संधारण का वितरण(एफआईटी पूर्व काल की तुलना में एफआईटी)

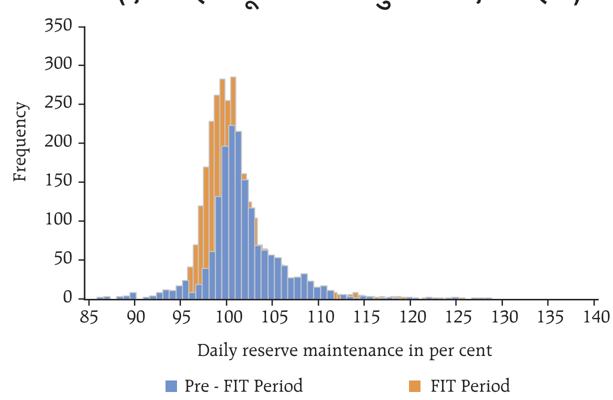

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा 2 जनवरी 2012 से 30 सितंबर 2016 तक का दैनिक आरक्षित निधि संधारण एफआईटी-पूर्व-अवधि और 1 अक्टूबर 2016 से 30 अप्रैल 2024 तक एफआईटी अवधि संधारण।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; एवं लेखकों की गणनाएं

एफआईटी पूर्व अवधि में एससीबी ने पॉजिटिव स्किवू के साथ-साथ निर्धारित अनिवार्यता के 85 से 120 प्रतिशत की सीमा में रिज़र्व बनाया रखा था। एफआईटी अवधि के दौरान, दैनिक रिज़र्व शेष की सीमा, कुछ अपवादों को छोड़कर, कम (95 से 115 प्रतिशत की सीमा में) हो गई है ।

दैनिक रिज़र्व संधारण के वितरण में बदलाव स्किवनेस और कुर्टोसिस में हुए परिवर्तन में परिलक्षित होता है। एफआईटी अवधि में कई बैंक पखवाड़े के कुछ दिनों में 100 प्रतिशत से नीचे संधारण किए हुए थे। एफआईटी अवधि के दौरान चलनिधि प्रबंधन ढांचे में सुधार के साथ, बैंक अपने इंट्रा-डे कैश फ्लो और मनी मार्केट भागीदारी के आधार पर रिज़र्व रखने की एक इष्टतम रणनीति निर्धारित करने लगे जिससे उन्हें दैनिक रिज़र्व आवश्यकताओं के प्रबंधन में अधिक लचीला होने में मदद मिली। एफआईटी अवधि में कम कुर्टोसिस मूल्य भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अधिकांश बैंकों ने एफआईटी पूर्व अवधि की तुलना में औसत दैनिक रिज़र्व के करीब संधारण बनाए रखा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की दैनिक रिज़र्व निधि अनिवार्यता में उतार-चढ़ाव (मानक विचलन के संदर्भ में मापी गई) एफआईटी अवधि में कम हो गई है, जो यह दर्शाता है कि चलनिधि पर अनिश्चितता एफआईटी पूर्व अवधि की तुलना में कम हो गई है (चार्ट 4 और सारणी 1) ।

अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में माध्य (मीन) दैनिक रिज़र्व संधारण एफआईटी पूर्व अवधि की तुलना में एफआईटी अवधि के दौरान कम हो गया। उतार-चढ़ाव (मानक विचलन द्वारा मापी गई) भी जो एफआईटी पूर्व अवधि में 4.4 था, से घटकर 3.5 हो गया। एफआईटी अवधि के तहत साधनों और भिन्नताओं में अंतर के सांख्यिकीय महत्व का परीक्षण निम्नलिखित दो परिकल्पनाओं को तैयार करके एफआईटी पूर्व अवधि की तुलना में किया गया।

सारणी 1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में सीआरआर के दैनिक संधारण के वर्णनात्मक आंकड़े

(प्रतिशत में)	एफआईटी-पूर्व	एफआईटी
माध्य	101.9	100.9
माध्यिका	101.2	100.3
अधिकतम	146.1	128.3
न्यूनतम	86.1	94.6
मानक विचलन	4.4	3.5
स्किवनेस	1.6	2.1
कुर्टोसिस	13.6	10.7

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा 2 जनवरी 2012 से 30 सितंबर 2016 तक दैनिक आरक्षित निधि संधारण एफआईटी पूर्व की अवधि और 1 अक्टूबर 2016 से 30 अप्रैल 2024 तक की एफआईटी अवधि का प्रतिनिधित्व करता है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई।

एच01: एफआईटी-पूर्व और एफआईटी व्यवस्थाओं के बीच एससीबी के औसत दैनिक रिज़र्व संधारण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं।

एच02: एफआईटी-पूर्व और एफआईटी व्यवस्थाओं के बीच एससीबी के दैनिक रिज़र्व संधारण के प्रसरण (वेरिएंस) (उतार-चढ़ाव) में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं ।

उपर्युक्त परिकल्पनाओं का परीक्षण कुछ सांख्यिकीय परीक्षणों के माध्यम से किया गया। दोनों परिकल्पनाएं महत्व के 1 प्रतिशत स्तर पर खारिज कर दी गईं, जो दर्शाता है कि एफआईटी-पूर्व और एफआईटी व्यवस्था के संबंध में सीआरआर के दैनिक संधारण में महत्वपूर्ण अंतर है (सारणी 2)। एफआईटी दौर में कम रिज़र्व संधारण करने से बैंकों के वृद्धिशील संसाधनों को मुक्त करने में मदद होगी जिन्हें उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दैनिक रिज़र्व निधि संधारण के संबंध में उतार-चढ़ाव एफआईटी पूर्व और एफआईटी अवधि में कम होने से अन्य बातों के साथ-साथ नकदी उपलब्धता के बारे में कम अनिश्चितता होने का संकेत मिलता है, जिससे बेहतर रिज़र्व संधारण किया जा सकता है।

सारणी 2: माध्य और प्रसरण की समानता के परीक्षण के परिणाम

माध्य परीक्षण			प्रसरण परीक्षण		
परीक्षण का नाम	परीक्षण आँकड़ा	पी-मूल्य	परीक्षण का नाम	परीक्षण आँकड़ा	पी-मूल्य
टी-परीक्षण	7.92***	0.00	एफ-परीक्षण	1.57***	0.00
वेल्च एफ-परीक्षण	56.51***	0.00	बार्टलेट	111.24***	0.00

टिप्पणी: सभी परीक्षण आँकड़े महत्व के एक प्रतिशत स्तर पर शून्य परिकल्पना को खारिज करने के पक्ष में हैं, जिसे *** द्वारा इंगित किया गया है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

III.3 विभिन्न दैनिक न्यूनतम सीआरआर अनिवार्यता व्यवस्थाओं के तहत अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में सीआरआर के दैनिक संधारण का वितरण

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, विवेकपूर्ण और मौद्रिक भूमिका के अलावा, सीआरआर का उपयोग चलनिधि प्रबंधन के लिए एक साधन के रूप में भी किया जाता है। सीआरआर का उपयोग एफआईटी-पूर्व दौर में मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन के साधन के रूप में किया गया था, और यह एफआईटी दौर में भी मौद्रिक नीति साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। सीआरआर के पूर्ण स्तर के अलावा, इसके दैनिक न्यूनतम संधारण संबंधी मानदंड भी एक दिवसीय बाज़ार दरों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दैनिक न्यूनतम सीआरआर अनिवार्यता विभिन्न अवसरों पर 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न रही है। कोविड-19 संकट के दौरान प्रणालीगत चलनिधि को अधिशेष में रखने के लिए, कर्मचारियों की सामाजिक-दूरी और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर परिणामी दबाव के संदर्भ में बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए, सीआरआर का दैनिक न्यूनतम संधारण 90 प्रतिशत की अनिवार्यता से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था (28 मार्च 2020 से 25 सितंबर 2020)। इसके विपरीत, विनिमय दर की मौद्रिक रक्षा के उपायों के हिस्से के रूप में 27 जुलाई 2013 से 30 सितंबर 2013 तक 2013 के टेपर टैंट्रम के दौरान चलनिधि स्थिति को सख्त करने के लिए दैनिक न्यूनतम सीआरआर शेष अनिवार्यता को बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया गया था (कवेडिया और पटनायक, 2016)।

दैनिक न्यूनतम शेष सीआरआर संधारण के विभिन्न निर्धारणों के तहत बैंकों के दैनिक रिज़र्व संधारण व्यहार से पता चलता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में अंतर-पखवाड़ा परिवर्तनशीलता में बदलाव हुए थे (चार्ट 5)।

दैनिक रिज़र्व अनिवार्यताओं में उस समय अस्थिरता विशेष रूप से अधिक थी जब दैनिक न्यूनतम निर्धारित राशियां कम थीं। तीन अलग-अलग परिदृश्यों के तहत, अर्थात, दैनिक न्यूनतम निर्धारित राशि 90 प्रतिशत से कम, 90 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से अधिक, एससीबी के सीआरआर की अस्थिरता और औसत दैनिक संधारण की तुलना करने पर पाया गया कि एससीबी ने 90 प्रतिशत निर्धारित राशि के लिए कम अस्थिरता प्रदर्शित की, जबकि अन्य दो निर्धारित राशि (90 प्रतिशत से अधिक और 90 प्रतिशत से कम) के मामले में रिज़र्व संधारण में उच्च अस्थिरता दिखाई (सारणी 3)।

चार्ट 5: विभिन्न दैनिक न्यूनतम सीआरआर शर्तों के तहत एससीबी के दैनिक सीआरआर संधारण के वितरण का स्वरूप

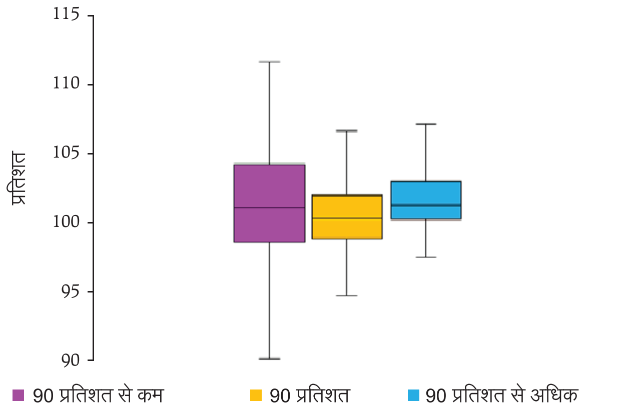

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा जनवरी 2012 से अप्रैल 2024 की अवधि के लिए दैनिक आरक्षित संधारण।आउटलेयर को चार्ट से बाहर रखा गया है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; एवं लेखकों की गणनाएं।

इस प्रकार, दोनों प्रकार के चरम निर्धारण, अर्थात बहुत अधिक लचीलापन या बहुत अधिक कठोरता - बैंकों के दैनिक रिज़र्व संधारण व्यवहार में बढ़ती अस्थिरता से जुड़े थे। चुनौतीपूर्ण समय में अनिवार्यता को बढ़ाया गया और हो सकता है कि इसके कारण भी एससीबी के रिज़र्व संधारण में अधिक अस्थिरता आई हो। विभिन्न न्यूनतम दैनिक रिज़र्व अनिवार्यता शर्तों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की दैनिक रिज़र्व निधि अनिवार्यता के वितरण स्वरूप से पता चलता है कि जब दैनिक निर्धारण में छूट दी जाती है तो रिज़र्व निधि संधारण की परिवर्तनशीलता बढ़ती प्रतीत होती है। तीन अलग-अलग परिदृश्यों के लिए सांख्यिकीय परीक्षण एससीबी के दैनिक रिज़र्व संधारण की अस्थिरता में उल्लेखनीय अंतर की पुष्टि करते हैं। परीक्षण के आंकड़े तीन अलग-अलग परीक्षण मानदंडों के लिए 1 प्रतिशत के स्तर पर

सारणी 3: अपेक्षित आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में दैनिक आरक्षित निधि रखरखाव

दैनिक सीआरआर अनिवार्यताएं		माध्य	माध्यिका	मानक विचलन
परिदृश्य 1	90 प्रतिशत से कम	101.4	101.0	5.4
परिदृश्य 2	90 प्रतिशत	100.7	100.2	3.1
परिदृश्य 3	90 प्रतिशत से अधिक	102.3	101.2	3.6

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

सारणी 4: प्रसरण की समानता के लिए परीक्षण

परीक्षण विधि	परीक्षण मूल्य
बार्टलेट	411.36***
लेवेन	117.45***
ब्राउन-फोर्सिथे	113.98***

नोट: *** 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को इंगित करता है।
शून्य परिकल्पना, एचओ: सारणी-3 में दिए गए तीन परिदृश्यों के तहत दैनिक रिज़र्व संधारण के प्रसरण (अस्थिरता) में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

उल्लेखनीय थे तथा अस्थिरता में कोई अंतर नहीं होने की शून्य परिकल्पना को खारिज करते हैं (सारणी-4).

उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि सीआरआर के लिए 90 प्रतिशत दैनिक न्यूनतम संधारण का निर्धारण एससीबी के लिए इष्टतम स्तर है। एफआईटी अवधि के 90 प्रतिशत न्यूनतम दैनिक संधारण परिदृश्य में, एससीबी द्वारा चलनिधि योजना और रिज़र्व संधारण में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया (आरबीआई, 2021)।

IV. सीआरआर में हाल के घटनाक्रम

हाल के वर्षों के दौरान, सीआरआर साधन के विभिन्न पहलुओं का उपयोग सक्रिय और विवेकपूर्ण तरीके से किया गया है। बैंकों को कोविड-19 से संबंधित चलनिधि संबंधी बाधाओं से निपटने में मदद करने के लिए, सीआरआर के स्तर को 28 मार्च 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए एनडीटीएल का 100 बीपीएस घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया ताकि ₹1.37 लाख की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध हो सके (दास, एस., 2020)। इसके अलावा, न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष संधारण की आवश्यकता को निर्धारित सीआरआर के 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सीआरआर संधारण हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुछ छूटें दी गई थीं। विशेष रूप से, एससीबी सीआरआर संधारण के लिए 31 जनवरी 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत में ऑटोमोबाइल, आवास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण के संबंध में उनके द्वारा वितरित वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि को अपने एनडीटीएल से घटा सकते थे। इसके अलावा, नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को 1 अक्टूबर 2021 तक दिए गए उधार के लिए प्रति उधारकर्ता ₹ 25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए सीआरआर संधारण से छूट दी गई थी, जो एक ऐसा उदाहरण है जहां सीआरआर का उपयोग ऋण के क्षेत्रीय प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 3.0 प्रतिशत सीआरआर को धीरे-धीरे दो चरणों में बढ़ा कर मई 2021 तक 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। अप्रैल 2022 में आरबीआई ने समायोजन की वापसी के एमपीसी के रुख को ध्यान में रखते हुए, सीआरआर को एनडीटीएल का 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया, और सीआरआर को हाल ही में दिसंबर 2024 में एनडीटीएल के 50 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया (चार्ट 6).

1990 के दशक की शुरुआत में, विशेष रूप से संकट की अवधि के दौरान, कुल मांग प्रबंधन के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा वृद्धिशील सीआरआर (आईसीआरआर) शुरू किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत निर्धारित शेष के अतिरिक्त, बैंक की कुल मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) की अधिकता के संदर्भ में परिकलित अतिरिक्त औसत दैनिक शेष, जिसे आईसीआरआर कहा जाता है, का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए कभी-कभी किया जाता रहा है। एक साधन के रूप में आईसीआरआर को आरबीआई द्वारा नवंबर 2016 (सितंबर 16 और 11 नवंबर 2016 के बीच) में प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए नोटबंदी के दौरान अर्थात जब ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की वैध मुद्रा स्थिति को समाप्त कर दिया गया था, प्रयोग किया गया

चार्ट 6: रेपो और सीआरआर में उतार-चढ़ाव

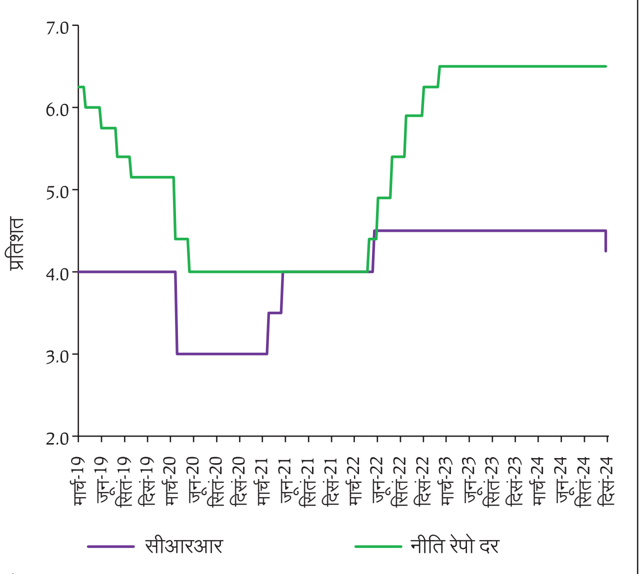

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई;

था क्योंकि इन बैंक नोटों की वापसी के कारण बैंक जमा बढ़ गया था। आईसीआरआर का प्रयोग जुलाई 2022 में प्रतिचक्रीय रूप से किया गया था – जबकि सभी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को एनडीटीएल की गणना के लिए शामिल किया जाता है, 30 जुलाई और 4 नवंबर 2022 के दौरान जुटाए गए वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमा को सीआरआर संधारण के लिए एनडीटीएल में शामिल करने से छूट दी गई थी। आईसीआरआर का प्रयोग अगस्त-अक्टूबर 2023 के दौरान अस्थायी रूप से, ₹2000 बैंकनोटों की वापसी, आरबीआई के सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के साथ-साथ सरकारी खर्च और पूंजी प्रवाह में वृद्धि के कारण प्रणाली से अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए भी किया गया था।

IV.1 दिन के अंत के एलएएफ संचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा

एक महत्वपूर्ण पहल, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के संदर्भ में, बैंकों के लिए एक वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा के माध्यम से दिन के अंत में सीआरआर शेष का प्रबंधन करने के लिए, मौजूदा मैनुअल बिडिंग के अलावा, एक स्वचालित बोली सुविधा की शुरुआत थी। इस सुविधा ने बैंकों को स्वेच्छा से एक पूर्व-निर्धारित राशि या राशि की एक सीमा निर्धारित करने में सक्षम बनाया, जिसे वे ई-कुबेर[1] प्रणाली के माध्यम से दिन के अंत में आरबीआई के पास अपने चालू खातों में शेष राशि के रूप में रख सकते थे। पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और रिवर्स रेपो बोलियां दिन के अंत[2] में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से उत्पन्न होती थीं।

यद्यपि यह सुविधा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मानव संसाधन उपयोग को कम करने के लिए शुरू की गई थी, बैंकों ने कुछ हद तक चलनिधि अनिश्चितता को कम करने के लिए अपने दैनिक नकदी शेष के प्रबंधन में एएसआईएसओ सुविधा का उपयोग करना जारी रखा है। 06 अगस्त 2020 से एएसआईएसओ की शुरुआत के बाद, बैंकों द्वारा संधारित नकदी रिज़र्व का दैनिक औसत स्तर कम हो गया है (सारणी 5)।

एएसआईएसओ से पूर्व की अवधि की तुलना में एएसआईएसओ अवधि के दौरान औसत (माध्य) दैनिक रिज़र्व संधारण कम हो गया (सारणी 5)। पूर्व-एएसआईएसओ अवधि में अस्थिरता (मानक विचलन द्वारा मापा गया) स्किवनेस और कुर्टोसिस के साथ 3.6 से घटकर 2.6 हो गई है। एससीबी के दैनिक रिज़र्व शेष पर एएसआईएसओ के प्रभाव के सांख्यिकीय महत्व का परीक्षण करने के लिए, एएसआईएसओ से पूर्व की अवधि की तुलना में एएसआईएसओ अवधि का परीक्षण निम्नलिखित दो परिकल्पनाओं के लिए कुछ सांख्यिकीय परीक्षणों के माध्यम से किया गया।

सारणी 5: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में दैनिक रिज़र्व संधारण के वर्णनात्मक आंकड़े

नमूना अवधि	माध्य	माध्यिका	अधिकतम	न्यूनतम	मानक विचलन	स्किवनेस	कुर्टोसिस
एएसआईएसओ पूर्व (01 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020)	101.2	100.5	122.9	94.6	3.6	2.8	15.6
एएसआईएसओ अवधि (01 अगस्त 2020[3] से 10 दिसंबर 2020)	100.7	100.2	108.9	96.5	2.6	1.1	4.1

नोट: 01 मार्च 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा दैनिक रिज़र्व संधारण। बेहतर तुलना के लिए एएसआईएसओ पूर्व और एएसआईएसओ पश्चात अवधि के लिए समान संख्या में दिनों पर विचार किया गया है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

[1] ई-कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी सदस्य (वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित यूसीबी, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां और भविष्य निधि, जो आरबीआई के पास चालू खाता और प्रतिभूति खाते रखते हैं) इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी में अपनी बोली लगा सकते हैं।

[2] यदि किसी बैंक का चालू खाता शेष निर्धारित न्यूनतम शेष से कम है, तो सिस्टम चालू खाता शेष और निर्धारित न्यूनतम शेष सीमा के बीच अंतर के लिए एमएसएफ बोली को ऑटो ट्रिगर करेगा। बैंक के रेपो घटक खाते में प्रतिभूतियों की किसी भी कमी के मामले में, ऑटो-ट्रिगर एमएसएफ बोली बैंक के रेपो घटक खाते में उपलब्ध प्रतिभूतियों के शेष के आधार पर कम राशि के लिए होगी। यदि किसी प्रतिभागी का चालू खाता शेष निर्धारित अधिकतम शेष से अधिक है, तो सिस्टम निर्धारित अधिकतम शेष सीमा और चालू खाता शेष के बीच अंतर के लिए रिवर्स रेपो बोली को स्वतः ट्रिगर करेगा।

[3] हालांकि एएसआईएसओ को 06 अगस्त 2020 से लागू किया गया था, 01 अगस्त 2020 के आंकड़ों को तुलना के लिए लिया गया था ताकि पूरे पखवाड़े को शामिल किया जा सके।

सारणी 6: माध्य और प्रसरण की समानता के लिए परीक्षण के परिणाम

माध्य परीक्षण			प्रसरण परीक्षण		
परीक्षण का नाम	परीक्षण आँकड़ा	पी-मूल्य	परीक्षण का नाम	परीक्षण आँकड़ा	पी-मूल्य
टी-परीक्षण	1.040	0.292	F-test	1.952***	0.00
वेल्च एफ-परीक्षण	1.116	0.290	Bartlett	10.195**	0.00

टिप्पणी: ** और *** क्रमशः 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को इंगित करता है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

एच01: एएसआईएसओ-पूर्व और एएसआईएसओ-पश्चात की अवधि के बीच एससीबी के औसत दैनिक रिज़र्व संधारण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं।

एच02: एएसआईएसओ-पूर्व और एएसआईएसओ-पश्चात कार्यान्वयन के बीच एससीबी के दैनिक रिज़र्व संधारण के परिवर्तन (अस्थिरता) में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं।

पहली परिकल्पना एएसआईएसओ-पूर्व और एएसआईएसओ-पश्चात अवधि के बीच सीआरआर के दैनिक संधारण में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाती है। एससीबी के दैनिक संधारण स्वरूप के प्रसरण में अंतर से दूसरी परिकल्पना (एच02) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है जो दर्शाती है कि एएसआईएसओ अवधि में रिज़र्व संधारण में अस्थिरता कम हुई है (सारणी 6)।

IV.II. भुगतान और निपटान प्रणाली तथा रिज़र्व संधारण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दैनिक रिज़र्व संधारण आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का औसत दैनिक सीआरआर संधारण तब मामूली रूप से कम हो गया जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों की चौबीसों घंटे (24x7) सेवाएं शुरू कीं – जो लगभग 101.0 प्रतिशत से घटकर 100.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 7)।

एससीबी द्वारा सीआरआर के दैनिक संधारण के संबंध में कर्नेल डेन्सिटी प्लॉट यह दर्शाता है कि 24x7 भुगतान और निपटान प्रणाली की शुरुआत के बाद बैंकों के व्यवहार स्वरूप में बदलाव आया है और कुर्टोसिस और स्किवनेस, दोनों में गिरावट दिखाई देती है (चार्ट 7)।

V. सीआरआर के दैनिक संधारण में अस्थिरता – अनुभवजन्य विश्लेषण

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, औसत अतिरिक्त संधारण और एससीबी द्वारा रिज़र्व के दैनिक संधारण में अस्थिरता विशेष रूप से एफआईटी अवधि के दौरान और बाद में एएसआईएसओ सुविधा की शुरुआत के साथ गिरावट आई है। औपचारिक रूप से इसकी जांच करने के लिए जनरलाइज़्ड ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनली हेटेरोसेडैस्टिक (जीएआरसीएच) मॉडल का प्रयोग करके एक अनुभवजन्य अभ्यास किया गया। चलनिधि स्थितियों में भिन्नता या चलनिधि आघातों का एससीबी के दैनिक रिज़र्व संधारण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ऋणात्मक चलनिधि आघात एससीबी के रिज़र्व संधारण स्तर पर दबाव डालेंगे - वे चलनिधि की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीआरआर से आहरित करेंगे। इसके अलावा, रिज़र्व निधि

सारणी 7: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में दैनिक रिज़र्व संधारण के वर्णनात्मक आँकड़े

नमूना अवधि	माध्य	माध्यिका	अधिकतम	न्यूनतम	मानक विचलन	स्किवनेस	कुर्टोसिस
24x7 भुगतान प्रणाली पूर्व (01 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक)	101.0	100.7	128.3	95.0	2.8	2.4	16.8
24x7 भुगतान प्रणाली पश्चात (11 दिसंबर 2020 से 30 अप्रैल 2024)	100.7	99.7	125.5	94.7	3.8	1.8	8.8

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) के 02 जनवरी 2017 से 10 दिसंबर 2020 तक के दैनिक रिज़र्व निधि संधारण को 24x7 प्रणाली की पूर्व अवधि के लिए और 11 दिसंबर 2020 से 06 अक्टूबर 2023 तक के संधारण को 24x7 भुगतान प्रणाली पश्चात अवधि के लिए विचार में लिया गया है। तुलना के लिए 90 प्रतिशत दैनिक अनिवार्यता अवधि के रिज़र्व संधारण को विचार में लिया गया है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों की गणना।

चार्ट 7: कर्नेल घनत्व अनुमान: एससीबी के लिए निर्धारित अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में दैनिक रिज़र्व संधारण

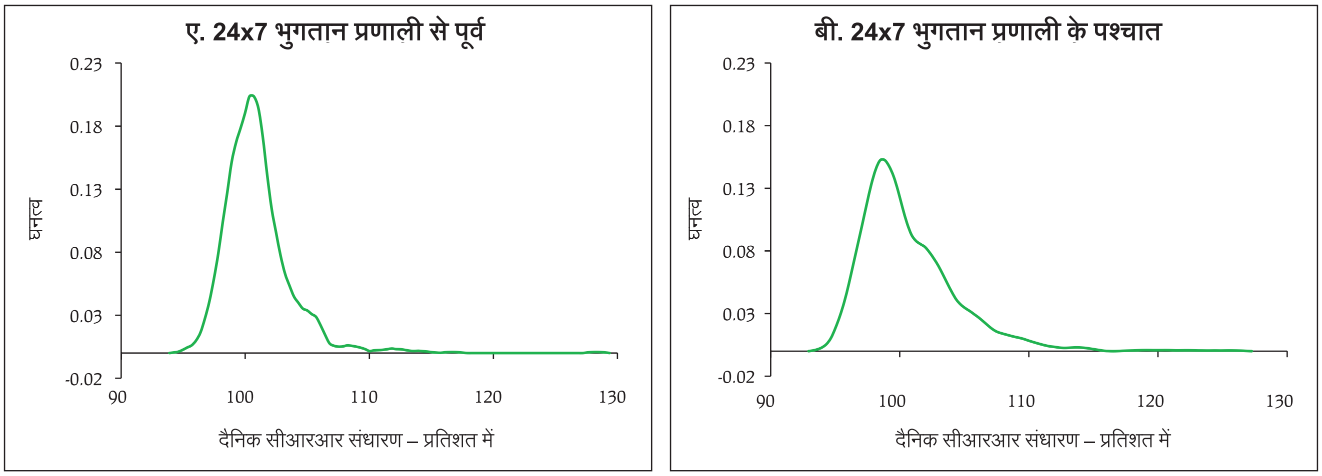

नोट: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा 02 जनवरी 2017 से 10 दिसंबर 2020 तक शुरू होने वाले दैनिक आरक्षित निधि संधारण को 24x7 प्रणाली पूर्व अवधि के लिए और 11 दिसंबर 2020 से 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि को 24x7 भुगतान प्रणाली अवधि के लिए माना गया है। समान दैनिक अनिवार्यता (90 प्रतिशत) के तहत रिज़र्व संधारण अवधि को विचार में लिया गया है।
स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; एवं लेखकों की गणनाएं।

अनिवार्यताओं के लिए दैनिक निर्धारित न्यूनतम संधारण मानदंड भी एससीबी द्वारा संधारित सीआरआर को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, रिज़र्व संधारण की अस्थिरता एएसआईएसओ और 24x7 भुगतान और निपटान सुविधाओं के शुरू होने से प्रभावित होने की उम्मीद है।

यह विश्लेषण अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2024 की अवधि के दौरान एससीबी द्वारा संधारित सीआरआर के दैनिक आंकड़ों का उपयोग करता है। सप्ताहांत को बाहर रखा गया है क्योंकि सभी चरों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। दैनिक संधारण पर विषम प्रभावों का परीक्षण सांख्यिकीय रूप से ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनली हेटेरोसेडैस्टिक (एआरसीएच) परीक्षण का उपयोग करके किया गया, जिसने अस्थिरता क्लस्टरिंग होने की पुष्टि की। इसलिए, विश्लेषण के लिए एक जीएआरसीएच मॉडल नियोजित किया गया था। मजबूती जांच के लिए, जीएआरसीएच मॉडल मापदंडों का अनुमान एआरसीएच और जीएआरसीएच संदर्भों [जीएआरसीएच (1,1), जीएआरसीएच (1,2), जीएआरसीएच (2,1) और जीएआरसीएच (2,2)][4] के विभिन्न मानदंडों के साथ लगाया गया।

मॉडल में प्रयुक्त आश्रित चर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके एनडीटीएल के अनुपात के रूप में संधारित दैनिक सीआरआर है। व्याख्यात्मक चर एक दिवसीय मुद्रा बाजार दरों और नीति रेपो दर के बीच अंतर से परोक्ष चलनिधि की स्थिति है। चूंकि बैंक मुख्य रूप से संपार्श्विक खंड में धन उधार लेते हैं, इसलिए भारित औसत मुद्रा बाजार दर का उपयोग संपार्श्विक और गैर-संपार्श्विक दोनों खंडों में उधार लेने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, मुद्रा बाजार दर (एमएमआर) स्प्रेड (संयुक्त भारित औसत बाजार दरों में से रेपो दर घटाकर) का प्रयोग किया गया है। दैनिक सीआरआर अनिवार्यताओं (सीआरआर मानदंड[5]) का उपयोग माध्य समीकरण में व्याख्यात्मक चर के रूप में भी किया गया है।

प्रसरण समीकरण में एनईएफटी (24x7), एएसआईएसओ, आरटीजीएस (24x7) और कोविड महामारी को शामिल करने के लिए अलग-अलग डमी चरों को एआरसीएच और जीएआरसीएच असर के साथ उन प्रभावों को प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया। जीएआरसीएच मॉडल स्पेसिफिकेशन समीकरण (1) और (2) में दिया गया है। चयनित जीएआरसीएच (1,2) मॉडल का माध्य और प्रसरण समीकरण इस प्रकार दिया गया है:

[4] जीएआरसीएच मॉडल की वशिष्टिता सूचना मानदंडों के आधार पर चुनी गई है।

[5] यद्यपि, सीआरआर को पखवाड़े के लिए औसत आधार पर एनडीटीएल के निर्धारित प्रतिशत पर बनाए रखा जाना है, वर्तमान में अनिवार्य दैनिक आवश्यकता 90 प्रतिशत है (पूर्व में 70-80-90-95-99 के बीच भिन्न-भिन्न रही है)।

$$CRR_Daily_t = \omega + \alpha_0 CRR_Daily_{t-1} + \beta_0 Daily_CRR_Norms_t + \Phi MMR_Spread_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

and

$$\sigma_t^2 = \omega_1 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + +\beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \beta_2 \sigma_{t-2}^2 + \vartheta_NEFT(24X7) + \mu_ASISO + \pi_RTGS(24X7) + \lambda_COVID \quad (2)$$

जहां CRR_Daily एससीबी द्वारा उनके एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में दैनिक रिज़र्व निधि संधारण है। Daily_CRR_Norm प्रतिशत में सीआरआर की दैनिक निर्धारित न्यूनतम अनिवार्यताएं हैं, MMR_Spread (संयुक्त भारित औसत मुद्रा दरों में से रेपो दर घटाते हुए है) चलनिधि स्थितियों का प्रॉक्सी है और ε_t रेसीड्यूअल एरर टर्म है। कंडीशनल प्रसरण समीकरण (2) में, α_1 ARCH पद के गुणांक को दर्शाता है और β_1 और β_2 GARCH पदों के गुणांक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ϑ, μ, π और λ अस्थिरता पर डमी चर प्रभाव को प्राप्त करते हैं। जीएआरसीएच (1,2) मॉडल के अनुमानित मानदंड सारणी 8 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 8: जीएआरसीएच (1,2) मॉडल के अनुमानित मानदंड

माध्य समीकरण	
चर	**मानदंड**
स्थिरांक	85.178*** (3.387)
CRR_ Daily (-1)	0.128*** (0.025)
MMR_Spread	-0.415*** (0.090)
Daily CRR_Norms	0.031 (0.022)
प्रसरण समीकरण	
स्थिरांक	1.557*** (0.164)
आरसीएच (1)	0.309*** (0.018)
जीएआरसीएच (1)	0.051 (0.041)
जीएआरसीएच (2)	0.488*** (0.038)
डमी एनईएफटी (24x7)	-0.323 (0.447)
डमी एएसआईएसओ	-0.569* (0.373)
डमी आरटीजीएस (24x7)	1.444*** (0.400)
डमी कोविड	0.320 (0.500)
डीडब्ल्यू-आँकड़े	1.817
एलएम परीक्षण (एफ-सांख्यिकी)	0.039

टिप्पणियाँ: (i) आश्रित चर दैनिक सीआरआर संधारण है।
(ii) *, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत स्तरों पर महत्व दर्शाता है।
(iii) कोष्ठक में दी गई मानक त्रुटियां।

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों के अनुमान।

उसी मॉडलिंग ढांचे में, रिज़र्व संधारण की अस्थिरता पर व्यक्तिगत दर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वैकल्पिक मॉडल स्पेसिफिकेशन्स में व्यक्तिगत मुद्रा बाजार दरों अर्थात भारित औसत कॉल मनी दरों, भारित औसत त्रिपक्षीय दर, और बाजार रेपो दरों का उपयोग किया गया । परिणाम परिशिष्ट में दिए गए हैं।

मुद्रा बाजार दरों और रेपो दर के बीच स्प्रेड के गुणांक सीआरआर संधारण की अस्थिरता पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे पता चलता है कि जब चलनिधि की स्थिति सख्त हो जाती है, तो बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए अपने अतिरिक्त सीआरआर को कम/आहरित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तथापि, विनियामक दैनिक सीआरआर मानदंडों/अनिवार्यताओं का एफआईटी पश्चात की अवधि में रिज़र्व निधि संधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बैंकों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ 24X7 आरटीजीएस और एनईएफटी के कारण आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक रिज़र्व रखने के कारण हो सकता है, जिससे एससीबी द्वारा रिज़र्व निधियों की एहतियाती मांग बढ़ सकती थी।

कंडीशनल प्रसरण मॉडल में एनईएफटी डमी को महत्वहीन पाया गया है जो दर्शाता है कि एनईएफटी 24x7 को शामिल किया जाना रिज़र्व संधारण की अस्थिरता में कोई परिवर्तन नहीं करता। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एनईएफटी लेनदेन मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन हैं, जो आकार में छोटे हैं, और हो सकता है कि वे बैंकों के पास उपलब्ध समग्र चलनिधि को प्रभावित नहीं करते।

प्रसरण समीकरण मॉडल ने एससीबी के लिए लागू एएसआईएसओ सुविधा के महत्व की पुष्टि की। एएसआईएसओ वेरिएबल गुणांक ऋणात्मक और महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है कि एएसआईएसओ सुविधा ने बैंकों के रिज़र्व संधारण में अस्थिरता को काफी कम कर दिया है और उन्हें अपने दैनिक रिज़र्व का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम बनाया है।

24x7 आरटीजीएस की शुरुआत सीआरआर संधारण में अस्थिरता में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है जैसा कि प्रसरण समीकरण

में आरटीजीएस के लिए सकारात्मक गुणांक में परिलक्षित होता है। आरटीजीएस चौबीसों घंटे कार्य करता है, जिससे किसी भी समय निधि की निकासी हो सकती है, जिससे उच्च अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है और इसलिए बड़े अंतरबैंक अंतरण होने पर रिज़र्व संधारण में अधिक अस्थिरता होती है। बैंक आमतौर पर अनिश्चित नकदी प्रवाह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों या सप्ताहांत से पहले अधिक रिज़र्व बनाए रखते हैं।

30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं के रिवर्सल की अनुमति दी गई । इससे बैंकों की चलनिधि संबंधी अनिश्चितता कम होने से उनके चलनिधि प्रबंधन में सुविधा होगी और इस प्रकार आगे चलकर रिज़र्व निधि के संधारण में अस्थिरता कम होगी।

VI. निष्कर्ष

रिज़र्व अनिवार्यता और उससे जुड़े अन्य प्रावधान (सीआरआर स्तर, दैनिक न्यूनतम संधारण, वृद्धिशील रिज़र्व अनिवार्यताएं और रिज़र्व देनदारियों पर छूट) प्रभावी चलनिधि प्रबंधन साधन हैं। मौद्रिक नीति के रुख के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में समग्र चलनिधि स्थितियों को समायोजित करने के लिए सीआरआर के स्तर को अपने आप में बढ़ाया या घटाया जाता है। यह अध्ययन रिज़र्व अनिवार्यता के अन्य पहलुओं में परिवर्तन के नीतिगत निहितार्थ पर केंद्रित है – एफआईटी अपनाने के बाद और एएसआईएसओ सुविधा की शुरुआत के बाद बैंकों का दैनिक रिज़र्व संधारण और दैनिक न्यूनतम रिज़र्व संधारण अनिवार्यता के विश्लेषण से पता चलता है कि (i) आरबीआई द्वारा एफआईटी को अपनाने के बाद और एएसआईएसओ सुविधा की शुरुआत के साथ, एससीबी द्वारा बनाए रखा गया औसत दैनिक रिज़र्व कम हो गया है, जिससे बैंकों के वृद्धिशील संसाधन उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं जिन्हें उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है; (ii) एएसआईएसओ व्यवस्था आने के बाद अनिवार्यता के प्रतिशत के रूप में दैनिक रिज़र्व संधारण में अस्थिरता काफी कम हुई है, जिससे बैंक अपने दैनिक रिज़र्व का प्रभावी प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं; और (iii) दैनिक न्यूनतम रिज़र्व संधारण अनिवार्यता का वर्तमान 90 प्रतिशत उपयुक्त है – 90 प्रतिशत से कम की न्यूनतम दैनिक संधारण अनिवार्यता रिज़र्व संधारण में उच्च परिवर्तनशीलता उत्पन्न करती है। इस अध्ययन का निष्कर्ष, जो इस विषय पर पहला ऐसा ज्ञात कार्य है, नीतिगत साधन के रूप में रिज़र्व अनिवार्यताओं के विभिन्न पहलुओं के भविष्य के उपयोग के लिए सीख प्रदान करता है।

संदर्भ:

Cantu, C., Gondo,R. and Martinez, B(2024), "Reserve requirements as a financial stability instrument", BIS Working Papers, No 1182, April.

Das, Shaktikanta (2020), Governor's Statement: March 27, 2020.

Das, Shaktikanta (2024), Governor's Statement: December 6, 2024.

Glocker, C. and Towbin, P. (2012). "Reserve Requirements for Price and Financial Stability: When Are They Effective?", *International Journal of Central Banking 8 (1): 65-113.*

Gray, S. (2011). "Central Bank Balances and Reserve Requirements". IMF Working Paper 11/36, International Monetary Fund.

Kavediya, R. and Pattanaik.S. (2016). "Operating Target Volatility: Its Implications for Monetary Policy Transmission", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, Vol. 37, No. 1 and 2.

Mishkin, F. S. (1997). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fifth edition, Addison-Wesley, Massachusetts, Boston.

Reserve Bank of India (2021). Report on Currency and Finance 2020-21: Reviewing the Monetary Policy Framework.

Valle, G.D., King, D. and Veyrune, R. (2022). "Monetary Operations and Domestic Market Development: Reserve Requirements, Monetary and Capital Markets Department", *Technical Assistance Handbook*, International Monetary Fund.

परिशिष्ट

लेख में बताए गए मॉडल 1 और 2 में प्रयुक्त समान नोटेशन को अपनाते हुए, तीन अलग-अलग बाजार दरों पर विचार करने वाले तीन अलग-अलग मॉडल नीचे दिए गए हैं:

Model1- Mean equation

$$CRR_Daily_t = \omega + \alpha_0 CRR_Daily_{t-1} + \beta_0 Daily_CRR_Norms_t + \Phi_1 call\ rate_Spread_t + \varepsilon_t$$

Model 2- mean equation

$$CRR_Daily_t = \omega + \alpha_0 CRR_Daily_{t-1} + \beta_0 Daily_CRR_Norms_t + \Phi_2 Triparty\ \ rate_Spread_t + \varepsilon_t$$

Model3- mean equation

$$CRR_Daily_t = \omega + \alpha_0 CRR_Daily_{t-1} + \beta_0 Daily_CRR_Norms_t + \Phi_3 Market\ repo\ rate_Spread_t + \varepsilon_t$$

Variance equation

$$\sigma_t^2 = \omega_1 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + +\beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \beta_2 \sigma_{t-2}^2 + \vartheta_NEFT(24X7) + \mu_ASISO + \pi_RTGS(24X7) + \lambda_COVID$$

उपरोक्त तीन मॉडलों के अनुमानित मानदंड सारणी-1 में दिए गए हैं।

सारणी 1: जीएआरसीएच (1,2) मॉडल के अनुमानित मानदंड

चर	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
माध्य समीकरण			
स्थिरांक	84.800*** (3.067)	82.067*** (3.092)	84.548*** (3.456)
CRR_ Daily (-1)	0.131*** (0.024)	0.124*** (0.024)	0.128*** (0.025)
Call rate Spread	-0.977*** (0.154)		
Triparty rate Spread		-0.810*** (0.079)	
Market repo rate Spread			-0.482*** (0.104)
Daily CRR_Norms	0.030 (0.019)	0.069*** (0.019)	0.023* 1.677)
प्रसरण समीकरण (वेरिएंस इक्वेशन)			
स्थिरांक	1.488*** (0.160)	1.706*** (0.170)	1.568*** (0.165)
एआरसीएच (1)	0.319*** (0.019)	0.341*** (0.020)	0.310*** (0.018)
जीएआरसीएच (1)	0.037 (0.035)	0.035 (0.040)	0.056 (0.042)
जीएआरसीएच (2)	0.507*** (0.034)	0.462*** (0.038)	0.481*** (0.039)
डमी एनईएफटी (24x7)	-0.540 (0.369)	-0.280 (0.509)	-0.354 (0.446)
डमी एएसआईएसओ	-0.737** (0.408)	-0.581* (0.405)	-0.616* (0.382)
डमी आरटीजीएस (24x7)	1.157*** (0.398)	1.499*** (0.421)	1.420*** (0.400)
डमी कोविड	0.719* (0.434)	0.135 (0.550)	0.375 (0.504)
डीडब्ल्यू-आँकड़े	1.792	1.789	1.815
एलएम परीक्षण (एफ-सांख्यिकी)	0.109	0.075	0.046

टिप्पणियाँ: (i) आश्रित चर दैनिक सीआरआर संधारण है।
(ii) *, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत स्तरों पर महत्व दर्शाता है।
(iii) कोष्ठक में दी गई मानक त्रुटियां।
(iv) कॉल रेट स्प्रेड = कॉल रेट माइनस रेपो रेट, ट्राइपार्टी रेट स्प्रेड = ट्राईपार्टी रेट माइनस रेपो रेट और मार्केट रेपो रेट स्प्रेड = मार्केट रेपो रेट माइनस रेपो रेट

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और लेखकों का अनुमान।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव

श्रीजाश्री सरदार, दीपक आर. चौधरी, प्रियंका प्रियदर्शिनी, अंशुल और संगीता दास द्वारा ^

यह आलेख नॉन-लिनियर ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (NARDL) मॉडल का उपयोग करके भारत के पण्य व्यापार संतुलन पर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव की जांच करता है। अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि आरईईआर में मूल्यह्रास व्यापार संतुलन को बेहतर बनाता है जबकि मूल्यवृद्धि से इसमें कमी आती है। व्यापार संतुलन पर आरईईआर मूल्यह्रास का प्रभाव, अल्पावधि में समतुल्य आरईईआर मूल्यवृद्धि से अधिक होता है और दीर्घावधि में इसके विलोमतः होता है। अंतर-देशीय अनुमान दर्शाते हैं कि आरईईआर उत्पादकता अंतर, व्यापार की शर्तों, सरकारी व्यय और निवल विदेशी आस्तियों से प्रभावित होता है।

परिचय

विनिमय दर, देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले संकेतकों में से एक है। इस संबंध में एक मुद्दा यह है कि क्या वास्तविक विनिमय दर (आरईआर) इस उद्देश्य के लिए एक उपयोगी उपाय है। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) विदेशी मुद्राओं के एक समूह के संदर्भ में घरेलू मुद्रा की एक व्यापार भारित औसत विनिमय दर है, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) अपने व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा का मुद्रास्फीति-समायोजित व्यापार-भारित औसत मूल्य है। अल्पावधि में, आरईईआर में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से सांकेतिक विनिमय दर में परिवर्तन को दर्शा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अल्पावधि में कीमतें स्थिर रहती हैं (दारवास, 2021)। हालांकि त्रुटिपूर्ण होने के बाद भी, आरईईआर काफी हद तक बड़े अधिमूल्यन/न्यून मूल्यांकन (अंडरवैल्यूएशन) का संकेत देता है और इसे नीति निर्माताओं के लिए शुरुआती चेतावनी साधनों में से एक बनाता है (सेनेडेस और स्टॉपर, 2012)।

आरईईआर और व्यापार संतुलन के बीच संबंध अस्पष्ट हो सकता है। व्यापार चैनल में, आरईईआर मूल्यह्रास निवल निर्यात के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि वित्त चैनल इन लाभों को प्रभावहीन कर सकता है और जीडीपी वृद्धि को कम कर सकता है (बीआईएस, 2018)। कार्डारिली और रेबुची (2007) ने व्यय स्विचिंग चैनल के माध्यम से आरईईआर और व्यापार संतुलन के बीच एक स्थिर संबंध पाया; बाद के अध्ययनों से पता चलता है कि संबंध असममित और गैर-रैखिक हो सकता है। मुद्रा मूल्यह्रास का व्यापार संतुलन पर समान परिमाण के मुद्रा मूल्यह्रास की तुलना में अधिक प्रभाव हो सकता है (बहमनी-ओस्कूई और आफताब, 2017; और एरीज़, 2017)। जे-वक्र प्रभाव के प्रमाण निम्न हैं - आरईईआर का मूल्यह्रास समय के साथ प्रतिवर्तन के साथ व्यापार संतुलन में तुरंत गिरावट ला सकता है, जिससे व्यापार संतुलन में सुधार होता है। भट्ट और भट्ट (2021) को भारत के मामले में जे-वक्र घटनाक्रम का कोई प्रमाण नहीं मिला; लेखकों ने पाया कि मूल्यवृद्धि से व्यापार संतुलन में ह्रास होता है, जबकि मूल्यह्रास अल्पावधि में इसे बेहतर बनाता है। हालांकि, दीर्घावधि में केवल मूल्यह्रास ही व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। यह व्यापार संतुलन पर आरईईआर संचलन के असममित प्रभाव को इंगित करता है। पार्रे, वानी और यास्मीन (2022) ने उदारीकरण के बाद की अवधि का उपयोग करते हुए भारत में ‹जे-वक्र› प्रभाव और ‹मार्शल-लर्नर› स्थितियों का कोई सबूत नहीं पाया। अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि अन्य समष्टि-आर्थिक चरों में से, विनिमय दर भारत के व्यापार संतुलन में एक अत्यधिक प्रभावशाली कारक है।

इस पृष्ठभूमि में, खंड II संतुलनकारी विनिमय दर (ईईआर) अनुमान के दृष्टिकोणों पर चर्चा करता है। खंड III आठ देशों के पैनल के लिए संतुलनकारी वास्तविक विनिमय दर का अनुभवजन्य अनुमान लगाता है। खंड IV भारत में आरईईआर अनुमान का सिंहावलोकन प्रदान करता है। खंड V नॉन-लिनियर ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल (एनएआरडीएल) का उपयोग करके भारत के व्यापार संतुलन पर आरईईआर के असममित प्रभाव की अनुभवजन्य जांच करता है, जबकि खंड VI समापन प्रेक्षण प्रदान करता है।

---

^ दीपक आर. चौधरी, अंशुल और संगीता दास वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) से हैं। श्रीजश्री सरदार वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी) से हैं और प्रियंका प्रियदर्शिनी पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से हैं। श्री जी. सेषसाई, मुमप्र, एफएमओडी और अनाम समीक्षक की बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों के लिए लेखक आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

II. वास्तविक विनिमय दर का अनुमान लगाने के तरीके

वास्तविक विनिमय दर का अनुमान लगाने के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि

एक सामान्य संतुलन विनिमय दर दृष्टिकोण, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) प्रस्ताव से विनिमय दर के विचलन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो यह मानता है कि दो देशों के बीच संतुलनकारी विनिमय दर उनकी संबंधित क्रय शक्तियों और, बदले में, उनकी मुद्रास्फीति दरों द्वारा निर्धारित होती है।

पीपीपी से विचलन का अर्थ है कि, $q = s - (p - p^*) = \varepsilon \neq 0$ जहां q वास्तविक विनिमय दर है, s सांकेतिक विनिमय दर है, और p और p* क्रमशः घरेलू और विदेशी कीमतें हैं (सभी लॉग टर्म में)। ε उन कारकों को दर्शाता है जो q की गैर-स्थिर गति को समझा सकते हैं। व्यवहारगत संतुलनकारी विनिमय दर (बीईईआर) दृष्टिकोण, q और ε के बीच एक सह-एकीकरण संबंध मानता है, जिससे संतुलनकारी वास्तविक विनिमय दर (ईआरईआर) का एक निम्न रूप अनुमान प्राप्त होता है। संक्षिप्त नाम बीईईआर का प्रयोग प्रायः, विस्तार से, उन मॉडलों के पूरे समूह को इंगित करने के लिए किया जाता है जो समान पद्धतियों का पालन करते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण ईआरईआर की गणना उस रूप में करता है जो मध्यम अवधि के आंतरिक और बाह्य संतुलन[1], दोनों पर खरा उतरता है और इसे मूलभूत संतुलनकारी विनिमय दर (फंडामेंटल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट - FEER) के नाम से जाना जाता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में, पात्र एवं अन्य (2024) ने भारत के संदर्भ में संतुलनकारी विनिमय दरों का अनुमान लगाने के लिए दृष्टिकोणों का एक समूह तैयार किया और बताया कि वैकल्पिक दृष्टिकोण, आरईईआर जैसे स्थिर संकेतकों या अन्य जो सरल पीपीपी ढांचे की शैली से संबंधित हैं, के लिए बेहतर हैं।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आरईईआर मुख्य रूप से आर्थिक मूल-तत्व, ब्याज दर अंतर और व्यापार की शर्तों द्वारा संचालित होती है (राउत, 2021)। क्लार्क और मैकडॉनाल्ड (1999) ने पाया कि दीर्घावधि में बीईईआर, व्यापार की शर्तों, व्यापारित वस्तुओं की तुलना में गैर-व्यापारित वस्तुओं की सापेक्ष कीमत, निवल विदेशी आस्तियों के स्टॉक और ब्याज दर अंतर द्वारा निर्धारित होता है। क्लार्क और मैकडॉनाल्ड (पहले से उद्धृत कार्य) के अनुसार, एफईईआर और बीईईआर दोनों दृष्टिकोणों में गुण और कमजोरियाँ हैं: बीईईआर दृष्टिकोण मिसअलाइनमेंट का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करता है और मॉडल मिसस्पेसिफिकेशन के जोखिम के अधीन, अल्पकालिक विश्लेषण के लिए उपयोगी है; इसके विपरीत, एफईईआर दृष्टिकोण अधिक सुदृढ़ है लेकिन पूर्ण रोजगार और पूंजी खाता धारणीयता की मान्यताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

संतुलनकारी आरईईआर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न पर निर्भर करता है - i) निवल विदेशी आस्तियां: देनदार देशों (विदेशी आस्तियों से अधिक विदेशी देयताएँ), यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें, अपनी बाह्य देनदारियों की चुकौती के लिए आवश्यक व्यापार अधिशेष उत्पन्न करने के लिए अधिक मूल्यह्रास वाली वास्तविक विनिमय दर की आवश्यकता होती है; ii) उत्पादकता अंतर: उच्च उत्पादकता आरईईआर में वृद्धि से संबंधित है; iii) व्यापार की शर्तें: व्यापार की अनुकूल शर्तें आय या धन प्रभाव के माध्यम से आरईईआर की वृद्धि कर सकती हैं; और iv) सरकारी खपत: उच्च सरकारी खपत आरईईआर की वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि ऐसी खपत ज्यादातर व्यापार योग्य क्षेत्र की तुलना में गैर-व्यापार योग्य क्षेत्र से संबंधित होती है जिससे उच्च सापेक्ष कीमतें देखने को मिलती हैं (ली एवं अन्य, 2008)।

व्यवहार में आरईईआर का आकलन

व्यवहार में, आरईईआर गणना में चार प्रमुख घटकों को ध्यान में रखना चाहिए: विदेशी व्यापार साझेदारों की श्रेणी, उनके सापेक्ष भार, मूल्य सूचकांक और आधार वर्ष का चयन। बीआईएस, ओईसीडी, विश्व बैंक और आईएमएफ सहित अंतरराष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों के लिए आरईईआर घोषित करते हैं। ये डेटाबेस विभिन्न गणना पद्धतियों, देश और मुद्रा संरचना का उपयोग करते हैं, जिससे आरईईआर के लिए अलग-अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व मासिक आवृत्ति पर विभिन्न देश भार के आधार पर छह प्रकार के आरईईआर सूचकांक संकलित करता है।[2] बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्तमान में दैनिक, मासिक और त्रैमासिक आवृत्तियों पर स्टर्लिंग विनिमय दर सूचकांक की गणना करता

[1] यहां आंतरिक संतुलन की विशेषता उत्पादन का पूर्ण रोजगार स्तर तथा निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति है, जबकि बाह्य संतुलन भुगतान संतुलन की धारणीयता है।

[2] https://www.federalreserve.gov/releases/h10/summary/

[3] https://www.bankofengland.co.uk/statistics/details/further-details-about-effective-exchange-rate-indices-data

है।[3] एक व्यापक मुद्रा सूचकांक बड़ी संख्या में मुद्राओं को शामिल करके वैश्विक तस्वीर प्रदान करता है, जबकि एक लघु सूचकांक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है (फंग एवं अन्य, 2006)। पसंदीदा सूचकांक का आधार, अध्ययन के संदर्भ पर निर्भर हो सकता है (क्लाऊ और फंग, 2006)।

III. संतुलनकारी वास्तविक विनिमय दर: अंतर-देशीय विश्लेषण

आरईईआर के संभावित निर्धारकों को समझने के लिए, इस खंड में निम्नलिखित देशों को कवर करते हुए एक पैनल प्रतिगमन अनुभवजन्य अभ्यास किया गया है: भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, 27 वर्षों के वार्षिक आंकड़ों के साथ - 1994 से 2021। जैसे कि पिछले खंड में चर्चा की गई है, सीपीआई-आधारित आरईईआर को दीर्घावधि में निम्नलिखित चार मूल तत्वों द्वारा निर्धारित किए जाने की उम्मीद है: निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए), उत्पादकता अंतर, व्यापार की पण्य शर्तें (टीओटी) और सरकारी उपभोग व्यय। एनएफए डेटा को लेन और माइल्सी-फेरेटी (2018), डेटाबेस से प्राप्त किया गया है। उत्पादकता अंतर, एक देश के वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में उसके 64 व्यापारिक भागीदारों के मुकाबले उनके संबंधित व्यापार भार से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड (टीओटी) का अनुमान ग्रस और केभज (2019) - लॉग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स (जून 2012=100) के अनुसार लगाया गया था, जो कमोडिटी नेट एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स (कुल कमोडिटी ट्रेड में निवल निर्यात द्वारा भारित) है। जीडीपी (जीईएक्सपीआर/जीडीपी) के अनुपात के रूप में सरकारी उपभोग व्यय के आंकड़े विश्व बैंक से लिए गए थे। पैनल यूनिट रूट टेस्ट (लेविन एवं अन्य, 2002) के परिणाम दर्शाते हैं कि सभी चर, फर्स्ट डिफ्रेंस स्टेशनरी हैं (सारणी 1)।

सारणी 1: पैनल यूनिट रूट परीक्षण के परिणाम

चर	स्तर	पहला अंतर
	एलएलसी टी-स्टैट	एलएलसी टी-स्टैट
एलआरईईआर	-1.55 (0.06)	-9.11*** (0.00)
जीईएक्सपीआर/जीडीपी	-1.54 (0.06)	-4.16*** (0.00)
उत्पादकता अंतर	-1.21 (0.11)	-3.39*** (0.00)
एनएफए/जीडीपी	-0.43 (0.33)	-4.99*** (0.00)
टीओटी	-1.68 (0.06)	-7.29*** (0.00)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पी-मान हैं; *** 1 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाता है।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

सारणी 2: दीर्घकालीन सह-एकीकरण संबंध के डीओएलएस (DOLS) अनुमान

चर	गुणांक	पी-मान
आश्रित चर: REER का लॉग (LREER)		
जीईएक्सपीआर/जीडीपी	1.99*** (4.24)	0.00
एनएफए/ जीडीपी	-0.16*** (-4.99)	0.00
उत्पादकता अंतर	1.74*** (13.29)	0.00
टीओटी	0.27*** (7.81)	0.00
समायोजित R2	0.79	
प्रेक्षण	184	

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-स्टैटिस्टिक्स हैं; *** 1 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाता है।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

पैनल सह-एकीकरण का साक्ष्य - एलआरईईआर और मूलभूत सिद्धांतों के समूह के बीच दीर्घकालिक संबंध - चर के बीच काओ (1999) परीक्षण द्वारा इंगित किया गया है। स्टॉक और वॉटसन (1993) द्वारा विकसित डायनेमिक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर (डीओएलएस) पद्धति के परिणामों को सारणी 2 में संक्षेपित किया गया है।

ईआरईआर दृष्टिकोण इस बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है कि संतुलन को बहाल करने के लिए विनिमय दर कितनी जल्दी समायोजित होगी। इसलिए, त्रुटि-सुधार विनिर्देश के साथ दीर्घकालिक मॉडल का अनुमान लगाया गया था। परिणाम बताते हैं कि चयनित देशों और समय अवधि के लिए वास्तविक और संतुलन विनिमय दरों के बीच अंतर को आधा करने में औसतन लगभग चार वर्ष लगते हैं (सारणी 3)।

सारणी 3: एरर करेक्शन टर्म गुणांक

	गुणांक	पी-मान
एरर करेक्शन टर्म	-0.12*** (-3.84)	0.00

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-स्टैटिस्टिक्स हैं; *** 1 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाता है।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

IV. भारत के लिए आरईईआर अनुमान

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दो आरईईआर सूचकांकों की गणना करता है - 40-मुद्रा (व्यापक) और 6-मुद्रा (संकीर्ण) - जो क्रमशः भारत के व्यापार के 88 प्रतिशत (गुरिया और सोकल, 2021) और 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूचकांक, साझेदार देशों (चालीस/छह देश) के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के 3-वर्षीय चल ज्यामितीय माध्य व्यापार भार का उपयोग करते हैं। यह विधि भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ विदेशी व्यापार के गतिशील रूप से बदलते स्वरूप को उपयुक्त रूप से दर्शाती है। 40-मुद्रा आरईईआर/एनईईआर दो श्रृंखलाओं में उपलब्ध है - व्यापार भारित और निर्यात भारित। 6-मुद्रा की गणना केवल व्यापार भारित आधार पर की जाती है; हालाँकि, यह 2015-16 आधार वर्ष के अलावा रोलिंग बेस ईयर सीरीज़ पर भी उपलब्ध है।

40-मुद्रा और 6-मुद्रा आरईईआर/एनईईआर सूचकांकों की तुलना, दीर्घकालिक सह-संचलन (चार्ट 1) को इंगित करती है। जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान 40-मुद्रा और 6-मुद्रा आरईईआर में क्षणिक विचलन, बाकी देशों (-6मुद्रा को छोड़कर) में उच्च मुद्रास्फीति के कारण था।

आरईईआर गणना में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) है क्योंकि यह समय पर उपलब्ध होता है (एलिस, 2001) [चार्ट 2]।

चार्ट 2: चुनिंदा देशों में सीपीआई सह-संचलन

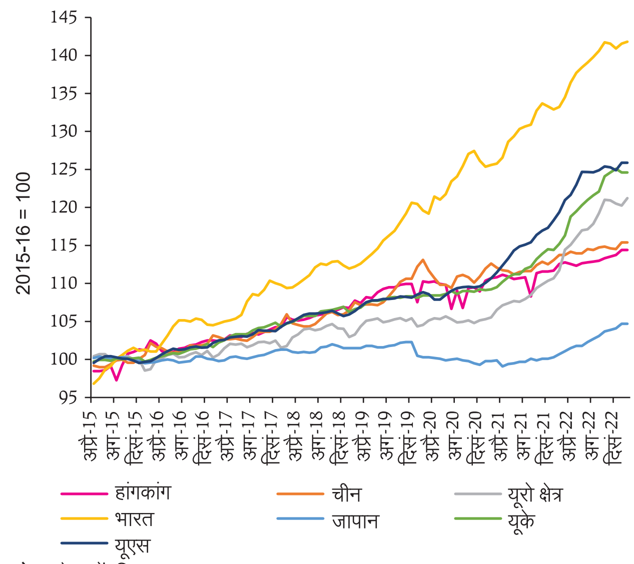

स्रोत: लेखकों की गणना।

6-मुद्रा आरईईआर में, यूएसडी और चीनी रेनमिनबी में से प्रत्येक का भार 28 प्रतिशत है, यूरो का 26 प्रतिशत, हांगकांग डॉलर का 8 प्रतिशत, जबकि यूके पाउंड और जापानी येन का भार 5 प्रतिशत पर बराबर है। इनमें से पांच मुद्राएं, मुद्रा व्यापार

चार्ट 1: आरईईआर/ एनईईआर उतार-चढ़ाव

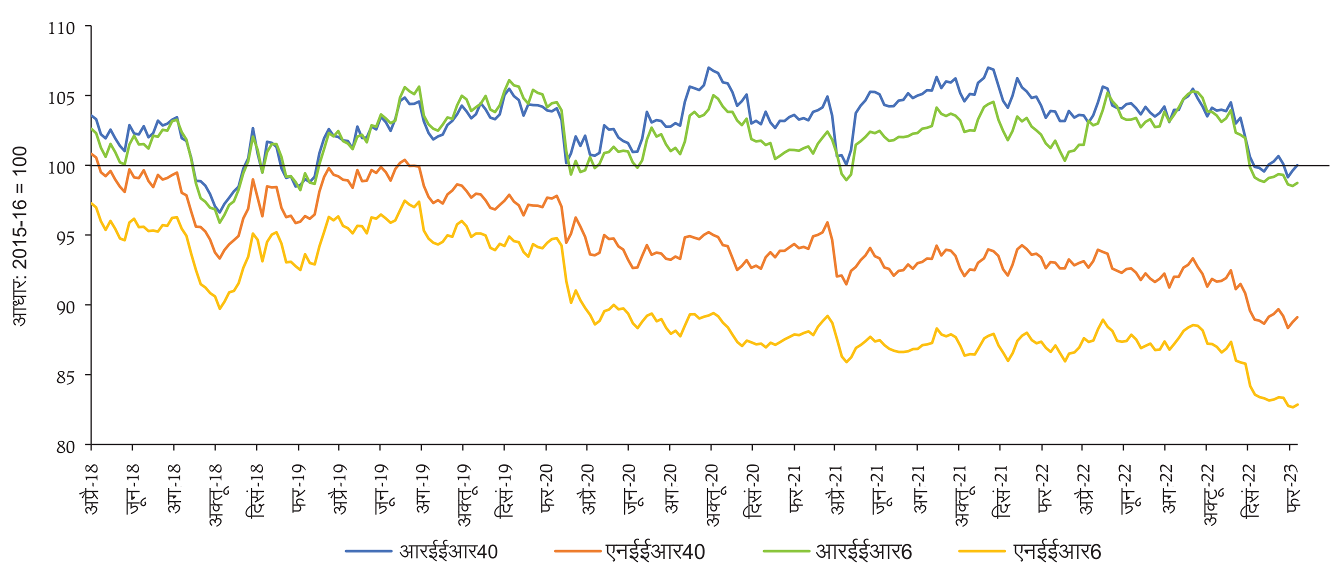

स्रोत: लेखकों की गणना।

सारणी 4: वैश्विक शीर्ष पाँच मुद्राएँ

स्थान	मुद्रा	ओटीसी एफएक्स ट्रेडिंग में हिस्सा	दैनिक मुद्रा व्यापार की राशि (यूएसडी बिलियन)	आधिकारिक रिजर्व संरचना में हिस्सा
1	USD	88	6,641	58.36
2	EUR	31	2,293	20.47
3	JPY	17	1,253	5.51
4	GBP	13	969	4.95
5	CNY	7	526	2.69

स्रोत: वैश्विक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार पर बीआईएस त्रैवार्षिक सर्वेक्षण, अक्टूबर 2022 और आईएमएफ, सीओएफईआर दिनांक 31 मार्च 2023।

और केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक भंडार के मामले में वैश्विक शीर्ष पांच में हैं (सारणी 4)।[4] हालांकि, केंद्रीय बैंकों के खजाने में अभी भी यूएसडी शीर्ष स्थान पर है।

वर्ष 2021-22 में भारत के पण्य निर्यात में चुनिंदा 6 मुद्राओं की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत और व्यापारिक आयात में 37 प्रतिशत थी। कुल व्यापार में 6-मुद्रा आरईईआर और एनईईआर का कवरेज 2012-13 में 33 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 43 प्रतिशत हो गया, जो कोविड-जनित व्यवधानों के कारण 2021-22 में घटकर 39 प्रतिशत रह गया। इन 6 अर्थव्यवस्थाओं से आयात का हिस्सा बढ़ रहा है, जो अन्य बातों के अलावा सहायक इनपुट की उत्पाद गुणवत्ता के कारण व्यापारिक आयात में संकेंद्रण को दर्शा सकता है (सारणी 5)।

सारणी 5: भारत का द्विपक्षीय पण्य व्यापार (निर्यात + आयात) हिस्सा

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	5-वर्षों का औसत
चीन	11.66	10.31	10.39	12.59	11.19	11.18
यूएसए	9.69	10.42	11.28	11.73	11.54	10.95
यूरो क्षेत्र	10.17	10.72	10.41	10.66	10.13	10.40
संयुक्त अरब अमीरात	6.49	7.10	7.50	6.31	7.04	6.92
सऊदी अरब	3.57	4.03	4.20	3.21	4.14	3.87
हांगकांग	3.30	3.67	3.54	3.69	2.91	3.39
सिंगापुर	2.30	3.30	3.00	3.20	2.91	2.94
इराक	2.48	2.86	3.25	2.30	3.32	2.89
कोरिया आरपी	2.71	2.54	2.60	2.54	2.47	2.57
इंडोनेशिया	2.65	2.50	2.44	2.55	2.53	2.53
स्विट्ज़रलैंड	2.60	2.28	2.30	2.84	2.39	2.46
जापान	2.04	2.09	2.15	2.24	1.99	2.09
ऑस्ट्रेलिया	2.34	1.97	1.60	1.79	2.42	2.05
मलेशिया	1.91	2.04	2.05	2.10	1.88	1.99
यूके	1.89	2.00	1.96	1.91	1.69	1.88

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस); लेखकों की गणना।

पिछले कुछ वर्षों में कोविड महामारी और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण भारत के व्यापारिक साझेदारों की दिशा और हिस्सेदारी में बदलाव आया है। भारत के निर्यात की दिशा उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका की ओर बढ़ गई है, जिसका संयुक्त हिस्सा 2009-10 में 17.3 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 27 प्रतिशत हो गया है (अनुबंध चार्ट 1ए और 1बी)। एशिया से आयात का हिस्सा 2009-10 में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 36.6 प्रतिशत हो गया है, जो मुख्य रूप से चीन द्वारा संचालित है जबकि यूरोपीय संघ का हिस्सा 2009-10 में 13.3 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.4 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, भारत के चालू खाते की संरचना समय के साथ बदल रही है और पण्य निर्यात की तुलना में सेवा निर्यात को महत्व मिल रहा है। भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में सेवा निर्यात का हिस्सा 2011-12 में 31 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 44 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल आयात में सेवाओं का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 13 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3ए और 3बी)। इसके अलावा, पिछले 30 वर्षों (1993-2022) में भारत की औसत सेवा निर्यात वृद्धि 14 प्रतिशत रही है, जब 2022 में विश्व सेवा निर्यात वृद्धि केवल 4.3 प्रतिशत थी, जो भारत जैसी कुशल श्रम अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्चतर क्षमता का संकेत देती है (गजभिये एवं अन्य, 2024)। सेवा निर्यात में, 'दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं' और 'अन्य कारोबारी सेवाएं' भारतीय निर्यात की अगुवाई करती हैं। इस संदर्भ में, बैंक ऑफ इंग्लैंड और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक भी अपने आरईईआर संकलन में सेवाओं में व्यापार को शामिल करते हैं। हालांकि, सेवाओं संबंधी आंकड़ों में द्विपक्षीय व्यापार की डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता सेवाओं को आरईईआर संकलन में शामिल करने के लिए मुख्य मुद्दे हैं। इस प्रकार बीआईएस, ओईसीडी और केंद्रीय बैंक जैसी कई संस्थाएं आरईईआर संकलन में सेवाओं का उपयोग नहीं करती हैं (क्लाऊ और फंग, 2006)। हालाँकि, इन सीमाओं के बावजूद, पण्य व्यापार-

[4] वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के लिए आईएमएफ की आधिकारिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (सीओएफईआर) की मुद्रा संरचना के अनुसार, यूएसडी का हिस्सा घटकर 58.36 प्रतिशत रह गया, जो 25 वर्षों में सबसे कम है, जो यूक्रेन-रूस संघर्ष और अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंधों के कारण यूएसडी की कमजोरी को दर्शाता है (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/05/05/blog-us-dollar-share-of-global-foreign-exchange-reserves-drops-to-25-year-low)

चार्ट 3: भारत के विदेशी व्यापार की संरचना

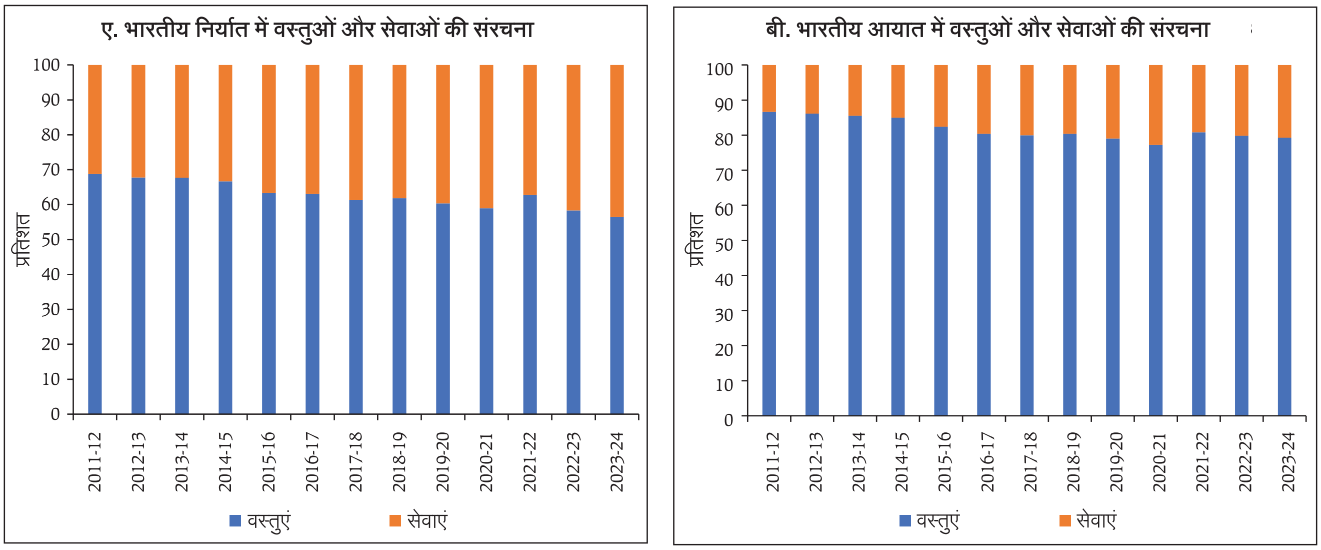

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआईई)।

आधारित आरईईआर प्रतिस्पर्धात्मकता के एक उपयोगी संकेतक के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख मुद्रा प्रतिमान

व्यापार-भारित आरईईआर और एनईईआर यह मानते हैं कि विश्व व्यापार में किसी देश की मुद्रा का उपयोग, विश्व व्यापार में उसके हिस्से से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, सभी व्यापार साझेदारों के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्यह्रास से घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ जाती है, जिससे आयात महंगा हो जाता है और इस प्रकार विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। साथ ही, इससे गंतव्य देश में निर्यात की कीमत भी कम हो जाती है जिससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस संदर्भ में, "प्रमुख मुद्रा प्रतिमान" की उपस्थिति में - जब व्यापार प्रवाह के उद्गम या गंतव्य की परवाह किए बिना प्रमुख देश की मुद्रा (यथा यूएसडी, यूरो) में व्यापार का चालान किया जाता है - पारंपरिक व्यय स्विचिंग प्रभाव कमजोर हो सकता है (बोज एवं अन्य, 2020; गोपीनाथ, 2015)। अमेरिकी डॉलर और यूरो में व्यापार चालान की उच्च हिस्सेदारी के साथ, व्यापार शेयरों के आधार पर आरईईआर की गणना, मुद्रा प्रतिस्पर्धात्मकता को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकती है। बोज एवं अन्य. ने (पहले से उद्धृत कार्य में) पाया कि यूएसडी में व्यापार चालान के अधिक हिस्से वाले देश के लिए आयात में द्विपक्षीय विनिमय दरों की तुलना में यूएसडी विनिमय दर पासथ्रू अधिक है। इसके अलावा, शोधपत्र में यह भी पाया गया है कि द्विपक्षीय विनिमय दर की तुलना में यूएसडी के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास से व्यापार की मात्रा में अधिक कमी आती है।

V. भारत के व्यापार संतुलन पर आरईईआर का प्रभाव: अनुभवजन्य विश्लेषण

भारत के मामले में साहित्य समान निष्कर्षों को दर्शाता है जैसा कि ऊपर दिए गए अंतर-देशीय विश्लेषण में देखा गया था (घोष एवं अन्य, 2023; राउत, 2021)। इस आलेख में अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए, अप्रैल 2012 से जून 2024 की अवधि को कवर करते हुए त्रैमासिक आवृत्ति के साथ पांच चरों का एक सेट उपयोग किया जाता है। पूरी अवधि के दौरान आश्रित चर व्यापार संतुलन (टीबी) घाटे में था। टीबी को निर्यात और आयात यानी |निर्यात-आयात| के बीच अंतर के पूर्ण आंकड़े के रूप में व्यक्त किया जाता है। टीबी में वृद्धि (गिरावट) व्यापार संतुलन में गिरावट (सुधार) का संकेत देती है। यह आरईईआर संरचना के अनुरूप भी है, क्योंकि आरईईआर में गिरावट मूल्यह्रास और व्यापार संतुलन में सुधार को दर्शाती है (भट्ट और भट्ट, 2021)। भारत की जीडीपी और ओईसीडी-जीडीपी को क्रमशः घरेलू मांग और विदेशी मांग के रूप में माना जाता है। विनिमय दर की गतिशीलता को समझने के लिए 40-मुद्रा आरईईआर (व्यापक सूचकांक) और 6-मुद्रा आरईईआर (संकीर्ण सूचकांक), दोनों का उपयोग दो अलग-अलग मॉडलों

में किया जाता है। भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए मॉडल में शामिल किया गया है (गजभिये, *एवं अन्य*, 2024)।

मौसम-तत्वों को ध्यान में रखते हुए, सभी चरों को X-13 ARIMA का उपयोग करके मौसमी रूप से समायोजित तिमाही श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है और फिर लॉगरिदमिक स्केल में परिवर्तित किया जाता है। 40-मुद्रा और 6-मुद्रा आरईईआर (आधार वर्ष 2015-16) के लिए एक वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (वीईसीएम) के बाद एक नॉन-लिनियर ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (एनएआरडीएल) मॉडल का उपयोग किया गया है ताकि व्यापार संतुलन और आरईईआर के बीच असममित संबंध की तुलना और जांच की जा सके।

व्यापार संतुलन पर आरईईआर के असममित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित फंक्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है:

$$LnTB_t = \alpha + \beta_1 LnREER_t [+] + \beta_2 LnREER_t [-] + \gamma LnYD_t + \delta LnYF_t + \theta LnGPR_t + e_t$$

यहां, व्यापार संतुलन (टीबी) आरईईआर [+] (मूल्यवृद्धि), आरईईआर [–] (मूल्यह्रास), घरेलू मांग (YD) और विदेशी मांग (YF), भू-राजनीतिक जोखिम (GPR) और अन्य कारकों (e_t) द्वारा निर्धारित किया जाता है। एआरडीएल सह-एकीकरण तकनीक का उपयोग, विभिन्न एकीकरण क्रम वाली श्रृंखलाओं के बीच दीर्घकालिक संबंध निर्धारित करने के लिए किया जाता है (पेसरन और शिन, 1999, और पेसरन और अन्य, 2001)। पुनः पैरामीटरीकृत परिणाम चयनित चरों की अल्पावधि गतिशीलता और दीर्घकालिक संबंध देता है। यहां, टीबी के आरईईआर एवं भारत की घरेलू मांग और विदेशी मांग के साथ सह-एकीकरण संबंध का अनुमान लगाने के लिए जोहान्सन परीक्षण का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के तहत चरों के स्रोत और वर्णनात्मक आंकड़े अनुबंध (सारणी 1ए और 2ए) में दिए गए हैं। इस मामले में, मानक संवर्धित डिकी-फुलर (एडीएफ) इकाई मूल परीक्षण और फिलिप्स-पेरोन इकाई मूल परीक्षण बताते हैं कि विचाराधीन कोई भी श्रृंखला क्रम 2 या उच्चतर क्रम के लिए एकीकृत नहीं है (अनुबंध सारणी 3ए) जो एआरडीएल मॉडल के लिए चरों की उपयुक्तता की पुष्टि करता है।

सारणी 6: बाउंड्स टेस्ट का परिणाम

मॉडल	I(0)	I(1)	एफ-स्टैटिस्टिक	स्थिति
एम1 (40-मुद्रा आरईईआर)	3.740	4.303	4.671	सहएकीकृत
एम2 (6-मुद्रा आरईईआर)	3.777	4.320	4.982	सहएकीकृत

टिप्पणी: I(0) और I(1) क्रमशः 5 प्रतिशत महत्व स्तर पर स्थिर और गैर-स्थिर सीमाएँ हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

अनुभवजन्य परिणाम:

सहएकीकरण परीक्षण

40-मुद्रा आरईईआर/6-मुद्रा आरईईआर के रूप में रिग्रेशर पर विचार करने वाले दोनों मॉडलों के लिए सीमा परीक्षण के परिणाम चयनित चरों के बीच सह-एकीकरण संबंध की पुष्टि करते हैं (सारणी 6)।

सममिति परीक्षण

इसके अलावा, टीबी और आरईईआर (दोनों 40-मुद्रा और 6-मुद्रा) के बीच असममित संबंध का पता लगाने के लिए, एनएआरडीएल मॉडल का उपयोग किया गया है। गुणांक समरूपता परीक्षण, व्यापक और संकीर्ण, दोनों सूचकांकों के लिए व्यापार संतुलन और आरईईआर के बीच दीर्घकालिक और अल्पकालिक असममित संबंध के अस्तित्व को इंगित करता है (सारणी 7)।

अल्पावधि और दीर्घावधि संबंध

व्यापार संतुलन पर चरों का अल्पावधि प्रभाव यह दर्शाता है कि विदेशी मांग (जीडीपी_ओईसीडी) को छोड़कर, मॉडल एम1 (40-मुद्रा आरईईआर) के अन्य सभी गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि एम2 (6-मुद्रा आरईईआर) में, विदेशी

सारणी 7: गुणांक समरूपता परीक्षण

	दीर्घावधि		अल्पावधि	
	एफ-स्टैटिस्टिक	संभाव्यता	एफ-स्टैटिस्टिक	संभाव्यता
एम1 (40-मुद्रा आरईईआर के साथ)	11.487***	0.002	4.356**	0.044
एम2 (6-मुद्रा आरईईआर के साथ)	12.293***	0.001	7.431***	0.010

टिप्पणी: *** और ** क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

मांग और 6-मुद्रा आरईईआर [+], यानी अधिमूल्यन कारक को छोड़कर सभी संकेतक महत्वपूर्ण हैं (सारणी 8)। दोनों मॉडलों में $\Delta lnYD$ के महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक दर्शाते हैं कि भारत के जीडीपी में विस्तार से अल्पावधि में व्यापार संतुलन बिगड़ता है क्योंकि आय में उत्पादकता-संचालित वृद्धि से आयात की अधिक मांग हो सकती है।

परिणाम दर्शाते हैं कि आरईईआर अवमूल्यन का प्रभाव, आरईईआर (व्यापक और संकीर्ण) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और आरईईआर अधिमूल्यन से अधिक मजबूत है, हालांकि 6-मुद्रा आरईईआर के लिए मूल्यवृद्धि सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है। इस प्रकार, इन दो चरों के बीच संबंध असममित है, अर्थात, मुद्रा अवमूल्यन, अल्पावधि में समतुल्य मुद्रा अधिमूल्यन की तुलना में व्यापार संतुलन को अधिक प्रभावित करता है, जो अन्य अध्ययनों (भट्ट और भट्ट, 2021; पार्रे एवं अन्य, 2022) के अनुरूप है और राउत (2021) के प्रतिकूल है। एरर करेक्शन टर्म (ईसीटी) क्रमशः 40-मुद्रा आरईईआर और 6-मुद्रा आरईईआर के लिए -0.545 और -0.483 के संबद्ध गुणांक अनुमान के साथ ऋणात्मक हैं, और अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

दीर्घावधि में, आरईईआर परिवर्तनों का असममित प्रभाव - मूल्यवृद्धि (+) और मूल्यह्रास (-) - मॉडल एम1 में भी स्पष्ट है, हालांकि यहां मुद्रा मूल्यवृद्धि का प्रभाव, अल्पावधि गतिशीलता के विपरीत समतुल्य मुद्रा मूल्यह्रास से अधिक सुदृढ़ है (सारणी 9)। खरीद-बिक्री योग्य वस्तुओं के क्षेत्र में बढ़ती उत्पादकता ने आरईईआर में मूल्यवृद्धि की निरंतर प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (पात्र, एवं अन्य, 2024)। विदेशी मांग (YF) भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें अपेक्षित संकेत हैं कि विदेशी मांग में वृद्धि से भारत की निर्यात मांग में वृद्धि होती है और व्यापार संतुलन में सुधार होता है।

घरेलू मांग के गुणांक (YD), दोनों मॉडलों में दीर्घावधि में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। रेसिडुअल

सारणी 8: एनएआरडीएल एरर करेक्शन अनुमान - अल्पावधि गुणांक

	एम1: 40-मुद्रा आरईईआर		एम2: 6-मुद्रा आरईईआर	
चर	गुणांक	पी-मान	गुणांक	पी-मान
ECT	-0.545*** (0.127)	0.000	-0.483*** (0.123)	0.000
$\Delta lnTB_{t-1}$	0.393*** (0.088)	0.000	0.303*** (0.080)	0.001
$\Delta lnYD_t$	-4.555*** (1.252)	0.001	-4.262*** (1.209)	0.001
$\Delta lnYF_t$	-1.881 (2.757)	0.499	-1.557 (2.655)	0.561
$\Delta lnREER_t[+]$	3.583* (2.425)	0.101	2.442 (1.959)	0.219
$\Delta lnREER_t[-]$	-5.871*** (2.425)	0.003	-5.460*** (1.534)	0.001
C	30.021*** (6.998)	0.000	25.413*** (6.478)	0.000

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं। कोष्ठक में दिए गए **आंकड़े मानक त्रुटियाँ हैं।**

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

सारणी 9: एनएआरडीएल - दीर्घावधि विषमता परीक्षण अनुमान

आश्रित चर: lnTB

नियतात्मक: अप्रतिबंधित स्थिरांक और प्रतिबंधित प्रवृत्ति

	एम1: 40-मुद्रा आरईईआर		एम2: 6-मुद्रा आरईईआर	
चर	गुणांक	पी-मान	गुणांक	पी-मान
$lnTB_{t-1}$	-0.545*** (0.150)	0.001	-0.483*** (0.145)	0.002
$lnYD_t$	0.784 (1.379)	0.574	0.241 (1.394)	0.864
$lnYF_t$	-7.237* (4.009)	0.079	-5.969* (3.916)	0.076
$lnREER_t[+]$	5.504** (2.086)	0.012	2.815** (1.214)	0.026
$lnREER_t[-]$	-2.900** (1.835)	0.022	-2.218 (1.391)	0.120
$lnGPR_t$	0.060 (0.126)	0.637	0.059 (0.123)	0.542
C	30.021** (14.420)	0.045	25.413* (14.016)	0.078
प्रवृत्ति	-0.047** (0.020)	0.026	-0.021* (0.012)	0.093

रेसिडुअल डायगनोस्टिक्स

	एम1	एम2
लॉग लाइकलीहूड	31.22	32.46
रैमसे रीसेट टेस्ट	0.60 (0.55)	0.10 (0.92)
समायोजित R^2	0.76	0.73
अकाइके सूचना मानदंड	-0.744	-0.794
डर्बिन-वॉटसन स्टैट	2.104	2.055

टिप्पणी: ***, **, * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व को दर्शाते हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियाँ हैं।

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

डायगनोस्टिक्स चेक, मॉडल की स्थिरता को दर्शाती है (अनुबंध, चार्ट 1सी)।

VI. निष्कर्ष

अन्य घरेलू और वैश्विक चरों के साथ-साथ मुद्रा संचलन, निर्यात और आयात को प्रभावित करते हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक चरों और उनके पूर्वानुमानों सहित अंतर्निहित कारकों की गतिशील प्रकृति पर विचार करते हुए मुद्रा मूल्य के उचित स्तर का अनुमान लगाना मुश्किल है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर), अपने व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा का मुद्रास्फीति-समायोजित व्यापार-भारित औसत मूल्य है, जिसकी बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतकों में से एक के रूप में विभिन्न केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा गणना की जाती है। हालाँकि, व्यापार संतुलन और 'जे-कर्व' घटना पर आरईईआर के प्रभाव पर अंतर-देशीय साक्ष्य एकमत नहीं हैं। भारत पर आधारित हमारे अनुभवजन्य निष्कर्ष, भारत के व्यापार संतुलन पर आरईईआर के संचलन के एक विषम प्रभाव का सुझाव देते हैं, जिसमें व्यापार संतुलन पर आरईईआर मूल्यह्रास प्रभाव अल्पावधि में आरईईआर मूल्यवृद्धि से अधिक है और दीर्घावधि में इसके विलोमतः है।

संदर्भ

Arize, A. C. (2017). A convenient method for the estimation of ARDL parameters and test statistics: USA trade balance and real effective exchange rate relation. *International Review of Economics and Finance*, 50, 75-84.

Bahmani-Oskooee, M., and Aftab, M. (2017). On the asymmetric effects of exchange rate volatility on trade flows: New evidence from US-Malaysia trade at the industry level. *Economic Modelling*, 63, 86-103.

Bhat S. A, and Bhat J. A. (2021). Impact of exchange rate changes on the trade balance of India: an asymmetric nonlinear cointegration approach. *Foreign Trade Review*, 2021, vol. 56, issue 1, 71-88.

BIS (2018). *The Price, Real and Financial Effects of Exchange Rates.* Papers No 96.

Boz, E., Casas, C., Georgiadis, G., Gopinath, G., Le Mezo, H., Mehl, A., and Nguyen, T. (2020), "Patterns in Invoicing Currency in Global Trade," *IMF Working Paper* 20/126.

Cardarelli, R., and Rebucci, A. (2007). Exchange rates and the adjustment of external imbalances. *World economic outlook*, 81-120.

Cenedese, G., and Stolper, T. (2012). Currency fair value models. *Handbook of exchange rates*, 313-342.

Clark, P. B., and MacDonald, R. (1999). Exchange rates and economic fundamentals: a methodological comparison of BEERs and FEERs. In Equilibrium exchange rates (pp. 285-322). *Dordrecht: Springer Netherlands.*

Darvas, Z. (2021). Timely Measurement of Real Effective Exchange Rates. *Bruegel Working Paper*, 15/2012.

Ellis, L. (2001). Measuring the Real Exchange Rate: Pitfalls and Practicalities. *Reserve Bank of Australia Research Discussion Papers*, 1–36.

Fung, S. S., Klau, M., Ma, G., and McCauley, R. N. (2006). Estimation of Asian Effective Exchange Rates: A Technical Note. *BIS Working Papers* (Issue 217).

Gajbhiye, D., Kundu, S., Saroy, R., Rawat, D., George, A., Vinherkar, O., and Sinha, K. (2024). What drives India's services exports? *Reserve Bank of India Bulletin*, April.

Ghosh, S., Nath, S., and Srivastava, S. (2023). Productivity and real exchange rates for India: does Balassa-Samuelson effect explain? *Indian Growth and Development Review.*

Gopinath, G. (2015). *The international price system* (No. w21646). *National Bureau of Economic Research.*

Gruss, B., and Kebhaj, S. (2019). Commodity terms of trade: A new database. *International Monetary Fund.*

Guria J., and Sokal J., (2021). Effective exchange rate indices of the Indian Rupee. *Reserve Bank of India Bulletin*, January.

Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of econometrics*, 90(1), 1-44.

Klau, M., and Fung, S. S. (2006). The new BIS effective exchange rate indices. *BIS Quarterly Review*, March.

Lane, P. R., and Milesi-Ferretti, G. M. (2018). The external wealth of nations revisited: international financial integration in the aftermath of the global financial crisis. *IMF Economic Review*, 66, 189-222.

Lee, J., Milesi-Ferretti, G. M., Ostry, J., Prati, A., and Ricci, L. A. (2008). Exchange rate assessments: CGER methodologies. *IMF Occasional Papers*, 261.

Levin, A., Lin, C. F., and Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

Parray, W. A., Wani, S. H., and Yasmin, E. (2022). Determinants of the Trade Balance in India. Evidence from a Post-Liberalisation Period. *Studia Universitatis, Vasile Goldis Arad–Economics Series*, *32*(4), 16-37.

Patra, M.D., Behera, H., Gajbhiye D., Kundu, S. and Saroy, R (2024). A suite of approaches for estimating equilibrium exchange rates for India. *Reserve Bank of India Bulletin*, October, 81-90.

Pesaran MH, and Shin Y. (1999). *An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis.* Chapter 11 in Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Strom S (ed.). Cambridge University Press: Cambridge.

Pesaran MH, Shin Y, and Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Econometrics* 16(3): 289-326.

Raut, D. K. (2021). Behavioural equilibrium exchange rates in emerging market economies. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 42(2), 37–66.

Stock, J. H., and Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 783-820.

अनुबंध

चार्ट 1ए: निर्यात की दिशा

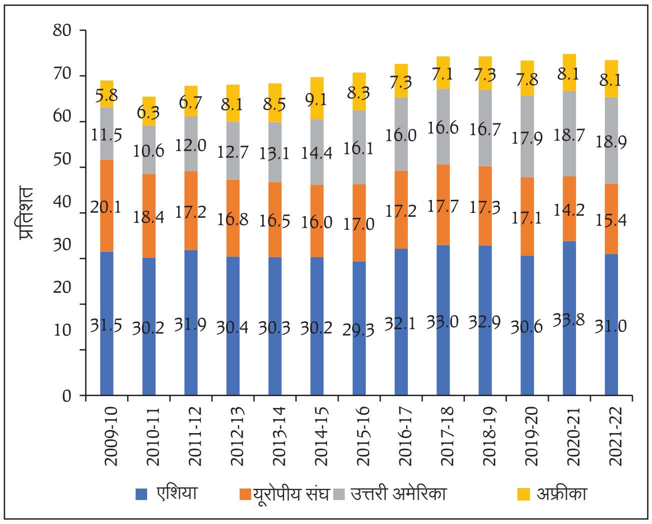

चार्ट 1बी: आयात की दिशा

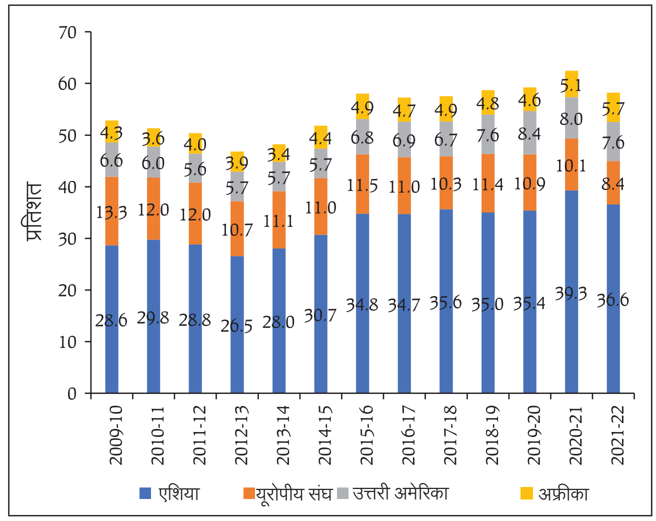

स्रोत: डीबीआईई।

सारणी 1ए: वर्णनात्मक सांख्यिकी

चर	आवृत्ति	स्रोत
व्यापार संतुलन	त्रैमासिक*	आरबीआई डीबीआईई
जीडीपी_ओईसीडी	त्रैमासिक	ओईसीडी
जीडीपी_भारत	त्रैमासिक	एमओएसपीआई
40-मुद्रा आरईईआर	त्रैमासिक*	आरबीआई डीबीआईई
6-मुद्रा आरईईआर	त्रैमासिक*	आरबीआई डीबीआईई
भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर)	त्रैमासिक*	आर्थिक नीति अनिश्चितता

टिप्पणी: * त्रैमासिक श्रृंखला की गणना, मासिक श्रृंखला का औसत निकालकर की गई है।

सारणी 2ए: वर्णनात्मक सांख्यिकी

	एलएनटीबी	एलएन40आरईईआर	एलएन6आरईईआर	एलएनजीपीआर	एलएनवाईडी	एलएनवाईएफ
माध्य	2.198	4.612	4.607	4.594	3.469	4.652
माध्यिका	2.184	4.624	4.618	4.544	3.508	4.662
अधिकतम	3.043	4.669	4.677	5.336	3.813	4.761
न्यूनतम	0.972	4.502	4.486	4.220	3.112	4.540
मानक विचलन	0.432	0.044	0.044	0.228	0.203	0.070
स्क्यूनेस	-0.175	-0.926	-1.068	0.985	-0.197	-0.056
कर्टोसिस	3.112	2.883	3.807	3.946	1.932	1.798
जार्क-बेरा	0.282	7.171	10.867	9.947	2.698	3.038
संभाव्यता	0.869	0.028	0.004	0.007	0.260	0.219

स्रोत: लेखकों की गणना।

सारणी 3ए: एडीएफ परीक्षण और फिलिप्स-पेरोन परीक्षण के परिणाम (फर्स्ट डिफ्रेंस पर)

शृंखला	संभाव्यता	
	एडीएफ परीक्षण	फिलिप्स-पेरोन परीक्षण
D(lnTB)	0.0000	0.0001
D(lnREER_40C)	0.0000	0.0000
D(lnREER_6C)	0.0000	0.0000
D(lnYD)	0.0001	0.0001
D(lnYF)	0.0001	0.0001
D(lnGPR)	0.0001	0.0001

स्रोत: लेखकों के अनुमान। .

चार्ट 1सी: स्थिरता परीक्षण (CUSUM परीक्षण)

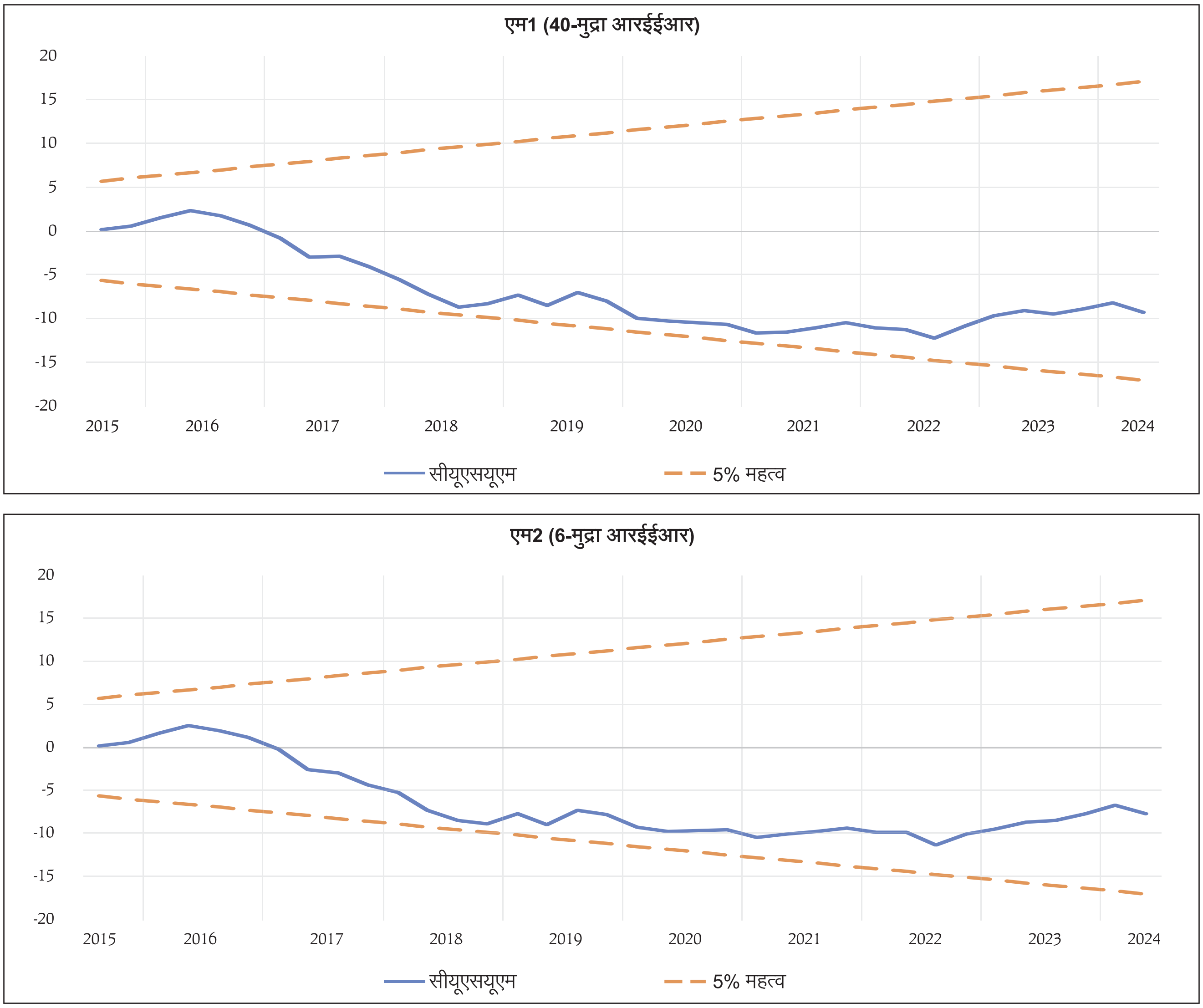

स्रोत: लेखकों की गणना।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	159
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	160
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	161
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	162
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	163
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	163
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	164
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	165
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	166
9	कुल चलनिधि राशियाँ	167
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	168
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	168
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	169
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	169
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	170
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	171
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	172
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	173
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	174
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	174
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	174
21	थोक मूल्य सूचकांक	175
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	179
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	179
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	180
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	180
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	181
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	182
28	वाणिज्यिक पत्र	182
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	182
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	183

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	184
32	विदेशी मुद्रा भंडार	184
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	184
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	185
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	185
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	186
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	187
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	188
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	189
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	190
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	191
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	192
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	193
	आवसरिक शृंखलाएं	
44	लघु बचत	195
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	196
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	197
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	198
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	199
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	200
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	201
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	204

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2023-24		2024-25	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	8.3	7.7	6.8	5.6
1.1.1 कृषि	1.4	3.7	1.7	2.0	3.5
1.1.2 उद्योग	9.3	5.0	13.6	7.4	2.1
1.1.3 सेवाएं	7.9	10.4	6.9	7.7	7.1
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	4.6	4.1	6.3	5.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	8.5	11.6	7.5	5.4
	2023-24	2023		2024	
		सितं	अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	6.4	11.9	3.1	3.5
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9	11.5	12.5	10.8	11.9
	(13.5)	(12.3)	(13.2)	(10.4)	(11.5)
2.1.2 ऋण#	16.3	13.0	15.8	13.7	13.1
	(20.2)	(17.6)	(20.4)	(12.3)	(11.8)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3	13.1	16.0	13.7	13.1
	(20.2)	(17.6)	(20.5)	(12.4)	(11.8)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1	16.7	16.8	7.7	9.2
	(12.8)	(18.9)	(18.9)	(6.8)	(8.1)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.4	5.5	6.0	9.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	10.9	10.8	10.8	11.1
	(11.6)	(11.5)	(11.4)	(10.4)	(10.7)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	5.4	5.2	5.1	5.2
	(5.0)	(5.4)	(5.1)	(5.1)	(5.2)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1	75.3	76.7	77.3	77.5
	(80.3)	(77.8)	(79.2)	(79.2)	(79.4)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8	69.7	88.7	64.6	69.2
	(113.4)	(99.5)	(119.5)	(61.6)	(66.2)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	30.3	30.4	29.4	29.7
	(29.8)	(30.6)	(30.8)	(29.6)	(29.9)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8	33.2	36.1	27.6	32.5
	(28.4)	(37.0)	(40.2)	(26.2)	(30.6)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.85/10.10	8.95/10.10	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.45	7.95/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.75	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.75	6.74	6.61	6.63
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.86	6.93	6.65	6.51
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.08	7.14	6.72	6.64
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.08	7.16	6.70	6.60
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.22	7.35	6.78	6.81
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	83.06	83.25	83.67	84.08
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	87.94	87.90	93.46	90.96
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	1.00	1.88	1.02	1.65	1.49
3-माह (%)	1.11	1.69	1.33	1.74	1.69
6-माह (%)	1.31	1.75	1.71	2.11	2.01
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.0	4.9	5.5	6.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	4.7	4.5	4.2	4.4
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	-0.1	-0.3	1.9	2.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	4.4	2.3	6.5	8.1
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-3.3	-1.6	-3.9	-5.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-1.3	-1.1	1.1	1.5
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	-14.0	10.3	1.5	3.6
7.2 निर्यात	-3.1	-2.8	5.8	0.4	17.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है। कोष्टकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2023-24	2023	2024				
		नवं	नवं 01	नवं 08	नवं 15	नवं 22	नवं 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3323212	3527267	3531647	3526683	3522024	3511550
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	14	15	16	15	14	14
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3482344**	**3323226**	**3527282**	**3531663**	**3526698**	**3522038**	**3511564**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	162996	145478	209424	203652	196661	201838	200142
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3177439	3317503	3327709	3329781	3320008	3311092
1.2.3 रुपया सिक्का	463	309	355	302	256	193	330
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1623298	1657709	1631529	1538908	1504093	1441830
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	100	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	43	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	931741	991970	985702	1008450	1004627	1023815
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	8115	8314	8076	8248	8232	8311
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	4644	5501	5261	5274	5214	5297
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	49647	50483	50437	50489	50482	50545
2.1.1.8 अन्य	545400	506029	460768	439066	313086	294163	232464
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	122979	140531	142843	153217	141233	121255
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1628598	1915994	1916373	1829501	1859836	1914051
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3587080**	**3251896**	**3573704**	**3547901**	**3368409**	**3363929**	**3355881**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	14	15	17	15	14	14
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1274744	1680295	1648867	1517215	1504608	1532888
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	11817	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	16275	31294	37124	28634	22714	16465
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	207355	9032	15981	6623	32892	21293
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	3169	7470	7202	7202	8428	8428
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	124108	139077	140946	151391	139508	120491
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1373135	1312814	1312676	1270354	1269831	1272720
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	253095	393708	385089	375157	385934	383580
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	240882	377097	368543	358260	368906	365807

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्तू 1, 2024	-	-	-	93815	2209	151065	-484	20	-	-243175
अक्तू 2, 2024	-	-	-	-	691	114749	-	-	-	-114058
अक्तू 3, 2024	-	-	-	48120	636	181857	-762	-	-	-230103
अक्तू 4, 2024	-	-	-	44275	3536	250753	-399	-	-	-291891
अक्तू 5, 2024	-	-	-	-	2912	140551	-	-	-	-137639
अक्तू 6, 2024	-	-	-	-	758	131358	-	-	-	-130600
अक्तू 7, 2024	-	-	-	36825	2730	89452	-	-	-	-123547
अक्तू 8, 2024	-	-	-	9398	5308	88739	-550	-	-	-93379
अक्तू 9, 2024	-	-	-	-	4085	53102	642	-	-	-48375
अक्तू 10, 2024	-	-	-	-	2180	56656	-	-	-	-54476
अक्तू 11, 2024	-	-	-	45260	1303	102686	275	-	-	-146368
अक्तू 12, 2024	-	-	-	-	435	81735	-	-	-	-81300
अक्तू 13, 2024	-	-	-	-	360	83165	-	-	-	-82805
अक्तू 14, 2024	-	-	-	24070	1982	94487	-	-	-	-116575
अक्तू 15, 2024	-	-	-	26060	1528	76656	-975	-	-	-102163
अक्तू 16, 2024	-	-	-	38133	5872	73858	980	-	-	-105139
अक्तू 17, 2024	-	-	-	40385	5717	82925	-	-	-	-117593
अक्तू 18, 2024	-	-	-	74828	4216	148845	-	-	-	-219457
अक्तू 19, 2024	-	-	-	-	6591	88873	-	-	-	-82282
अक्तू 20, 2024	-	-	-	-	2464	57488	-	-	-	-55024
अक्तू 21, 2024	-	-	-	-	18597	88775	-	-	-	-70178
अक्तू 22, 2024	-	-	-	-	2603	67234	166	-	-	-64465
अक्तू 23, 2024	-	-	-	-	4620	54112	1208	-	-	-48284
अक्तू 24, 2024	-	-	-	-	6800	66081	-	-	-	-59281
अक्तू 25, 2024	-	-	25005	-	2403	68481	102	-	-	-40971
अक्तू 26, 2024	-	-	-	-	521	71862	-	-	-	-71341
अक्तू 27, 2024	-	-	-	-	534	75425	-	-	-	-74891
अक्तू 28, 2024	-	-	-	-	1648	103800	-2	-	-	-102154
अक्तू 29, 2024	-	-	-	-	4514	121659	-1227	-	-	-118372
अक्तू 30, 2024	-	-	-	35525	2005	138324	-	-	-	-171844
अक्तू 31, 2024	-	-	-	24697	2350	142255	-	-	-	-164602

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	-310	9639	-9275
1.1 क्रय (+)	194296	36650	28930	27503
1.2 विक्रय (-)	153025	36960	19291	36778
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	-3604	80549	-77969
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	17377	8547	-728
(₹ करोड़)	339528	141063	70945	-7023
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	-14608	-14580	-49180

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	1948	2149	2531
1.2 विक्रय (-)	7930	1948	2149	2531
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	-4187	-200	-3229

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 अक्तूबर 2024 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	28180	-28180
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	21000	-21000
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	0	0
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**0**	**49180**	**-49180**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2023-24	2023	2024					
		नवं 17	जून 28	जुला 26	अग 23	सितं 20	अक्तू 18	नवं 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	111386	46848	2021	1818	21731	4216	18513
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	4900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	3181	9061	9062	8541	8547	7223	8428
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	114567	55909	11083	10359	30278	11439	26941

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	**2023**	**2024**		
		अक्तू 20	**सितं 20**	**अक्तू 04**	**अक्तू 18**
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3201682	3392284	3385407	3415233
1.1 संचलन में नोट	3477795	3272342	3455216	3457952	3482799
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	30906	33851	34090	34090
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	102379	98253	108126	103162
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2463354	2735069	2831531	2786278
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2390414	2640984	2735673	2687986
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72940	94085	95858	98292
3 एम1 (1+2)	**6091700**	**5665036**	**6127353**	**6216938**	**6201510**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	195777	211685	199017	199017	199017
5 एम2 (3+4)	**6287477**	**5876721**	**6326370**	**6415955**	**6400527**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	17940702	19751495	20077665	20015200
	(18848160)	(18074897)	(19826970)	(20151734)	(20087772)
7 एम3 (3+6)	24831618	23605738	25878848	26294604	26216711
	(24939860)	(23739933)	(25954324)	(26368673)	(26289282)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1313366	1235171	1361211	1361211	1361211
9 एम4 (7+8)	26144984	24840909	27240059	27655815	27577922
	(26253226)	(24975104)	(27315535)	(27729884)	(27650493)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 04	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**7512016**	**7264124**	**7562614**	**7825013**	**7862266**
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7375380)	(7626155)	(7888568)	(7923856)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	1018574	921112	1127976	1132433
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1392816	1340430	1348304	1336185
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1372589	1313984	1312495	1312788
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	20227	26447	35809	23398
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	374243	419318	220328	203752
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	374200	419275	220286	203710
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6245550	6641501	6697038	6729833
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6356807)	(6705043)	(6760593)	(6791423)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**16672145**	**15606774**	**17412955**	**17596094**	**17539625**
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(16193204)	(17889364)	(18063790)	(18005269)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5245	10589	8715	9175
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	15601529	17402366	17587379	17530449
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(16187959)	(17878775)	(18055074)	(17996094)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	14871457	16648643	16830083	16772030
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(15457887)	(17125052)	(17297778)	(17237674)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	712806	734471	737766	737425
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	17266	19252	19530	20994
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(17266)	(19252)	(19530)	(20994)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**5567245**	**5046813**	**5995690**	**6097395**	**5996912**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5240824	4686133	5628983	5730688	5630205
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4686386	5629252	5730956	5630473
3.1.2 विदेशी देयताएं	259	254	269	268	268
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	326421	360680	366707	366707	366707
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**33432**	**31649**	**34594**	**34833**	**34833**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**4953219**	**4343621**	**5127005**	**5258732**	**5216925**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5467219)	(4907113)	(5591480)	(5715913)	(5671588)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1789875	1472881	1957063	1975781	1926354
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3163344	2870740	3169942	3282950	3290572
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3677343)	(3434232)	(3634417)	(3740132)	(3745234)
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**24831618**	**23605738**	**25878848**	**26294604**	**26216711**
एम$_3$ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(23739933)	(25954324)	(26368673)	(26289282)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 04	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5665036	6127353	6205106	6174216
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1)	14424855	13655165	14895519	15116396	15057715
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(13715553)	(14929483)	(15149727)	(15090372)
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	24244761	26491792	26863711	26780721
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(24378956)	(26567267)	(26937780)	(26853293)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3201682	3392284	3374087	3390372
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	20146256	22125797	22538540	22429094
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(20280451)	(22201272)	(22612609)	(22501665)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2390414	2640984	2735673	2687986
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	17755843	19484812	19802867	19741107
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(17890038)	(19560288)	(19876936)	(19813679)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	7990129	8768166	8911290	8883498
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(8050517)	(8802130)	(8944621)	(8916155)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	306354	467853	593488	1138455
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	9765713	10716647	10891577	10857609
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(9839521)	(10758158)	(10932315)	(10897523)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72940	94085	95346	95858
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	823882	879626	855738	865397
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25295986	23974822	26153058	26417079	26580505
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(24672509)	(26693009)	(26948329)	(27107740)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7264124	7562614	7654383	7857809
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7375380)	(7626155)	(7717938)	(7919399)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1018574	921112	957345	1127976
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6245550	6641501	6697038	6729833
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6356807)	(6705043)	(6760593)	(6791423)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	16710698	18590445	18762696	18722697
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(17297128)	(19066853)	(19230391)	(19188341)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5245	10589	10556	8715
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	16705453	18579856	18752140	18713981
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(17291883)	(19056265)	(19219835)	(19179626)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1089184	1089235	1162164	1152524	1171485
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31649	34594	34833	34833
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5110820	4695347	5546300	5581039	5595422
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4686133	5628983	5742984	5730688
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-130004	9214	-82683	-161946	-135266
2.4 पूंजी खाता	3912897	3873660	4437226	4468336	4450085
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653576	1146888	1269410	1158085	1434618

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2023	2024		
		अक्तू.	अग	सितं	अक्तू.
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**25387764**	**24244761**	**26360365**	**26491792**	**26780721**
	(25496006)	(24378956)	(26439312)	(26567267)	(26853293)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	697675	724264	724264	724264
3 एल$_1$ (1 + 2)	**26117010**	**24942436**	**27084629**	**27216056**	**27504985**
	(26225252)	(25076631)	(27163576)	(27291531)	(27577557)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	12676	68118	68824	68842
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	67084	395	94	31
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	1148	54670	55520	55520
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	53260	13054	13210	13291
5 एल$_2$ (3 + 4)	**26202160**	**25009520**	**27152748**	**27284880**	**27573827**
	(26310403)	(25143715)	(27231695)	(27360355)	(27646398)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	..	..	102994	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**26305155**	**..**	**..**	**27387874**	**..**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 04	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3304061	3490538	3482214	3493534
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	978509	1018975	1083333	1049286
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	917856	956255	1020447	985504
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72940	94085	95346	95858
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4355510	4603598	4660892	4638678
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1110609	897083	883253	848938
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1018574	921112	957345	1127976
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	998389	894708	932975	1092209
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1372232	1313609	1314645	1312034
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1363369	1372232	1313609	1314645	1312034
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	357	375	305	460
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	374200	419275	381974	220286
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	20185	26404	24370	35767
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	86791	-34618	-84648	-287753
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	86791	-34618	-84648	-287753
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5245	10589	10556	8715
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3181	8547	8496	6851
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31649	34594	34833	34833
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4686133	5628983	5742984	5730688
2.3.1 स्वर्ण	439319	377545	531633	550741	552160
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4801522	4308605	5097367	5192261	5178546
2.4 पूंजी खाता	1589134	1599957	1874081	1899968	1868537
2.5 अन्य मदें (निवल)	200741	-127076	82982	100211	107244

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2023-24	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2023	2024				
		अक्तू 27	सितं 27	अक्तू 4	अक्तू 11	अक्तू 18	अक्तू 25
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4345605	4660892	4638678	4666693	4664487	4738791
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3303821	3482214	3493534	3523196	3518394	3534780
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	967229	1083333	1049286	1046572	1047801	1107212
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	74556	95346	95858	96925	98292	96799
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	966714	957345	1127976	1084120	1132433	1060149
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	98814	-84648	-287753	-187351	-215806	-57604
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	5244	10556	8715	9254	9175	10761
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4734666	5742984	5730688	5646393	5630205	5605044
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31939	34833	34833	34833	34833	35180
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1789875	1491772	2000178	1975781	1920556	1926354	1914738

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 04	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188	19196756	21163509	21571259	21461667
	(20253430)	(19330951)	(21238985)	(21645328)	(21534239)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2248738	2498373	2591898	2544608
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334	16948018	18665136	18979362	18917060
	(17809577)	(17082213)	(18740611)	(19053430)	(18989631)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7626608	8399311	8540713	8512677
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	306354	467853	593488	1138455
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	9321410	10265825	10438649	10404383
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	823882	879626	855738	865397
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	23019606	21908853	24156294	24378899	24374654
	(23641847)	(22606540)	(24696244)	(24910150)	(24901888)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054	5941476	6338211	6392075	6427051
	(6105610)	(6052733)	(6401753)	(6455630)	(6488641)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551	15967377	17818082	17986824	17947603
	(17536238)	(16553808)	(18294491)	(18454519)	(18413248)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477	14871457	16648643	16830083	16772030
	(16432164)	(15457887)	(17125052)	(17297778)	(17237674)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397	14851616	16628718	16812281	16753376
	(16409083)	(15438046)	(17105126)	(17279977)	(17219020)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	14953	15588	12500	12311
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	696	649	680	741
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1080272	1153202	1143561	1162522
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	9214	-82683	-161946	-135266
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	241661	307346	358411	296215	312870
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	184860	266682	274798	274093
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	149868	113272	174411	183363	174043
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	921868	1077119	1201275	1364526
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	917856	956255	1020447	985504
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	90803	86246	96180	91269
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	86791	-34618	-84648	-287753
2.4 पूंजी खाता	2299592	2249532	2538975	2544198	2557377
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	569765	568620	447033	719472
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	786851	856786	784675	776573
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	171368	131836	130446	120447

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2023	2024		
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 04	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6106558	6053429	6402402	6456310	6489381
	(6015003)	(5942172)	(6338860)	(6392755)	(6427792)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	179196	157582	158164	158963
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	52425	63049	60808	63266
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	9137	13615	13742	14005
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	82998	97368	96230	96674
4.3 अन्य	5624	5484	6834	7425	7500
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	92111	123351	122464	118817
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	293530	250152	241746	232102
5.3 अन्य	124690	107552	146237	145161	148322
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	75975	111561	109990	137470
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	183337	183453	187833	185401

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3)में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2023	2024		2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	210	208	208	137	137	135	135
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**554117**	**513463**	**453177**	**461959**	**549351**	**508338**	**448404**	**456793**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	235644	298150	299445	294471	232079	293853	294684
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	204553	131578	138138	182429	203787	131408	138074
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	73267	23449	24377	72452	72472	23143	24034
2 अन्य के प्रति देयताएं	**22664868**	**21715840**	**24067308**	**24168976**	**22190597**	**21267483**	**23597567**	**23695315**
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	19992340	22197886	22268274	20475226	19560877	21746608	21811286
	(20823825)	(19859128)	(22123057)	(22196282)	(20366984)	(19427665)	(21671779)	(21739295)
2.1.1 माँग	2492916	2338952	2630676	2576598	2443853	2293187	2582832	2527554
2.1.2 मीयादी	18439151	17653388	19567210	19691676	18031373	17267690	19163776	19283733
2.2 उधार	782260	842859	905313	922304	777942	837715	900827	917220
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	880641	964109	978397	937428	868891	950132	966808
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**222716**	**160738**	**33302**	**30948**	**222716**	**160738**	**33302**	**30948**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	160738	33302	30948	222716	160738	33302	30948
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	1043272	1024881	1132310	1156513	1020916	1003049	1110006	1133410
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	98703	92085	93424	89433	96056	89559	90430
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	926178	1040225	1063089	931483	906993	1020447	1042981
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**455057**	**408298**	**400518**	**415954**	**374474**	**353220**	**333625**	**347173**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	222223	253200	267325	198327	182491	201534	214836
5.1.1 चालू खाते में	12010	11658	15512	11859	8971	8952	12452	8521
5.1.2 अन्य खातों में	234373	210565	237687	255466	189357	173540	189082	206314
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	38379	27376	31346	12355	26277	16083	18904
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	52436	45009	47217	48368	51793	44328	46589
5.4 अन्य आस्तियां	117734	95260	74933	70066	115424	92659	71681	66845
6 निवेश	**6256962**	**6173361**	**6589114**	**6666871**	**6106558**	**6024145**	**6439289**	**6514977**
	(6165407)	(6064025)	(6525561)	(6613035)	(6015003)	(5914808)	(6375736)	(6461140)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	6167013	6580833	6657864	6105610	6023428	6438770	6513979
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6348	8281	9007	949	717	519	998
7 बैंक ऋण	**16866336**	**15890756**	**17661371**	**17768822**	**16432164**	**15488344**	**17215335**	**17315981**
	(16335650)	(15305241)	(17190229)	(17304521)	(15901477)	(14902828)	(16744193)	(16851679)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	69256	69694	72843	23081	20829	19075	22204
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	15619626	17344195	17451631	16134303	15220100	16901348	17002083
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	46713	67186	69489	60467	46701	65696	67977
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	184831	211015	209055	197358	182597	209905	207905
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	16327	15988	15841	16412	16096	15793	15597
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	23259	22987	22807	23624	22849	22592	22419

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 18	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**16432164**	**15457887**	**17125371**	**17238250**	**4.9**	**11.5**
	(15901477)	(14871457)	(16648962)	(16772605)	(5.5)	(12.8)
II. खाद्यान्न ऋण	**23081**	**19841**	**19926**	**18654**	**-19.2**	**-6.0**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**16409083**	**15438046**	**17105445**	**17219596**	**4.9**	**11.5**
	(15878397)	(14851616)	(16629037)	(16753951)	(5.5)	(12.8)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2071251**	**1909689**	**2167287**	**2205299**	**6.5**	**15.5**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3652804**	**3498502**	**3801604**	**3774252**	**3.3**	**7.9**
	(3635810)	(3480987)	(3786279)	(3759186)	(3.4)	(8.0)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	681618	750825	749790	3.2	10.0
2.2 मध्यम	303998	280699	334412	335822	10.5	19.6
2.3 बड़े	2622490	2536185	2716366	2688640	2.5	6.0
3. सेवाएं	**4592227**	**4245994**	**4736957**	**4784938**	**4.2**	**12.7**
	(4490467)	(4122802)	(4654649)	(4704550)	(4.8)	(14.1)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	214259	245008	246407	7.1	15.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	24665	29760	30581	18.0	24.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	77513	75612	78753	79732	2.9	5.4
3.4 शिपिंग	7067	6620	7166	7782	10.1	17.6
3.5 विमानन	43248	39419	44458	46168	6.8	17.1
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	153150	177730	186251	11.4	21.6
3.7 व्यापार	1025752	960414	1072493	1079498	5.2	12.4
3.7.1 थोक व्यापार[1]	538744	499225	567242	571159	6.0	14.4
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	461188	505251	508339	4.4	10.2
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	445596	497333	507671	8.2	13.9
	(400470)	(359499)	(441714)	(452869)	(13.1)	(26.0)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1548027	1444263	1529006	1536655	-0.7	6.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	325626	322128	324354	321110	-1.4	-0.3
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	190547	203257	198320	-12.6	4.1
3.10 अन्य सेवाएं[3]	998281	881996	1055250	1064193	6.6	20.7
	(978198)	(858939)	(1037408)	(1046715)	(7.0)	(21.9)
4. व्यक्तिगत ऋण	**5331290**	**5002636**	**5596719**	**5647476**	**5.9**	**12.9**
	(4919468)	(4557230)	(5219246)	(5278594)	(7.3)	(15.8)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	22178	23764	23640	-0.3	6.6
4.2 आवास	2718715	2561961	2845505	2871845	5.6	12.1
	(2331935)	(2144011)	(2490574)	(2525138)	(8.3)	(17.8)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	114983	125694	127533	1.8	10.9
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7812	9546	9060	6.7	16.0
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	240635	271813	281392	9.5	16.9
4.6 शिक्षा	119380	110852	129116	130309	9.2	17.6
4.7 वाहन ऋण	589251	553141	617180	616405	4.6	11.4
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	98747	147081	154282	50.4	56.2
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921	1292327	1427020	1433009	3.3	10.9
	(1362113)	(1265407)	(1404553)	(1410905)	(3.6)	(11.5)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	2081856	1934682	2164159	2200460	5.7	13.7
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1974191	1849829	2057867	2076956	5.2	12.3
(iii) मध्यम उद्यम[6]	490703	461739	543388	557829	13.7	20.8
(iv) आवास	755222	743033	750223	752216	-0.4	1.2
	(660572)	(643177)	(663719)	(665965)	(0.8)	(3.5)
(v) शिक्षा ऋण	62235	61110	62389	62673	0.7	2.6
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	5007	6778	7122	18.9	42.2
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2607	1124	1120	-57.1	-57.0
(viii) निर्यात ऋण	11774	11844	11290	12094	2.7	2.1
(ix) अन्य	61336	59553	58561	58045	-5.4	-2.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1555743	1711473	1742896	5.8	12.0

टिप्पणियाँ:

(1) डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।

(2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

(3) 1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियां" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अक्तू 20	सितं 20	अक्तू 18	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3652804	3498502	3801604	3774252	3.3	7.9
	(3635810)	(3480987)	(3786279)	(3759186)	(3.4)	(8.0)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	53476	52560	50116	-7.5	-6.3
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	173180	192363	190283	-8.9	9.9
2.2.1 चीनी	26383	14666	18789	17191	-34.8	17.2
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	18117	17113	17331	-12.0	-4.3
2.2.3 चाय	5692	6172	6157	6429	12.9	4.2
2.2.4 अन्य	157089	134226	150304	149332	-4.9	11.3
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	26257	31690	31286	0.5	19.2
2.4 वस्त्र	256048	243278	256793	256840	0.3	5.6
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	93930	93859	92827	-6.4	-1.2
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	4176	4155	4253	-0.6	1.8
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	42899	46812	47416	5.1	10.5
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	102272	111967	112344	4.5	9.8
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	12212	12788	12639	0.4	3.5
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	22514	25229	25319	6.2	12.5
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	46426	45266	49765	50089	7.9	10.7
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक ईंधन	132356	119637	169289	152974	15.6	27.9
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	230650	263369	259944	4.2	12.7
2.9.1 उवर्रक	37569	30621	32556	31511	-16.1	2.9
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	77182	86061	88499	9.2	14.7
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	19315	30677	25848	11.6	33.8
2.9.4 अन्य	107584	103532	114075	114086	6.0	10.2
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	85895	94633	95674	5.8	11.4
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	11022	12447	12483	3.3	13.3
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59757	60562	59806	60805	1.8	0.4
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	366382	422794	422883	10.0	15.4
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	251807	300521	300263	9.7	19.2
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	114575	122273	122621	10.8	7.0
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	191489	218183	219320	11.5	14.5
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	43175	44029	50514	49889	15.6	13.3
2.14.2 अन्य	153468	147460	167669	169431	10.4	14.9
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	113185	110017	114310	113603	0.4	3.3
2.16 रत्न और आभूषण	84860	95702	91172	92443	8.9	-3.4
2.17 निर्माण	133520	129624	141905	138635	3.8	7.0
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1277597	1299854	1298577	-0.4	1.6
2.18.1 बिजली	644042	618733	641606	646057	0.3	4.4
2.18.2 दूरसंचार	138192	138008	124047	121495	-12.1	-12.0
2.18.3 सड़क	318072	318483	325928	325803	2.4	2.3
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7960	8428	8117	11.5	2.0
2.18.5 बंदरगाह	6681	7292	6702	5823	-12.8	-20.1
2.18.6 रेलवे	13062	12047	11940	11230	-14.0	-6.8
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	175075	181203	180051	1.9	2.8
2.19 अन्य उद्योग	259016	243743	292655	290339	12.1	19.1

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2023	2024						
		सितं 29	जूला 26	अग 09	अग 23	अग 30	सितं 06	सितं 20	सितं 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	34	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**138788.9**	**139499.8**	**134816.8**	**133835.2**	**133649.7**	**133771.9**	**133484.9**	**131009.0**	**133236.7**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**30226.7**	**30578.4**	**28112.2**	**27873.9**	**27398.4**	**27177.9**	**28015.9**	**27871.3**	**27646.4**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	7067.1	8204.5	7890.8	7972.0	7554.0	8324.4	8039.9	7743.1
2.1.1.2 अन्य	15000.4	16389.1	13980.0	14068.5	13618.3	13721.9	13695.0	13761.7	13473.1
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0		179.9	299.8					179.9
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	7122.2	5747.8	5614.8	5808.1	5902.0	5996.5	6069.7	6250.3
2.2 मीयादी देयताएं	**198141.8**	**179527.1**	**183917.4**	**182003.8**	**181518.0**	**181698.8**	**181365.2**	**180677.8**	**181476.5**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	53493.1	61265.5	60102.2	58935.4	59084.4	59157.2	59278.4	59406.1
2.2.1.2 अन्य	123788.5	123110.7	120836.7	119766.7	120031.4	120050.0	119789.9	117247.3	119763.6
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	1364.0	653.8	940.7	1263.8	1235.0	1123.9	2852.3	1143.3
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1559.3	1161.3	1194.2	1287.4	1329.4	1294.2	1299.8	1163.5
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0								
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	71616.1	86318.6	84421.5	82219.7	84199.0	84699.7	87192.9	87696.9
4.1 मांग	27317.7	18837.6	24467.9	25452.2	24027.2	23957.2	23942.2	23761.2	23412.8
4.2 मीयादी	68596.8	52778.5	61850.7	58969.3	58192.5	60241.8	60757.5	63431.7	64284.1
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**16263.7**	**12007.1**	**13611.0**	**13590.9**	**11787.9**	**11195.1**	**11754.2**	**12126.7**	**12368.8**
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	709.5	687.9	780.2	679.8	699.1	683.4	822.3	780.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	11297.6	12923.1	12810.7	11108.1	10496.0	11070.8	11304.4	11587.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**2088.1**	**2034.4**	**1700.0**	**1709.6**	**1586.6**	**1607.4**	**1697.0**	**1841.0**	**1658.2**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77700.5**	**72473.9**	**75409.2**	**75025.8**	**74867.2**	**75232.9**	**75681.3**	**73803.6**	**73488.7**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**34355.3**	**22621.2**	**18960.1**	**16731.3**	**14985.4**	**14673.7**	**14683.1**	**14879.4**	**15615.3**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**135141.9**	**119241.1**	**136993.2**	**136583.7**	**138287.3**	**136830.6**	**138748.4**	**138876.6**	**138973.3**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**134936.8**	**119187.8**	**136836.3**	**136416.6**	**138117.1**	**136641.1**	**138544.2**	**138702.8**	**138795.8**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	142185.2	119129.5	134692.9	135559.1	137049.5	137902.0	139259.2	141899.6	143516.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	53.3	156.9	167.1	170.2	189.5	204.2	173.8	177.5

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	नवं 23	अक्तू 24	नवं 24 (अ)	नवं 23	अक्तू 24	नवं 24 (अ)	नवं 23	अक्तू 24	नवं (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**185.9**	**192.7**	**188.4**	**190.2**	**206.7**	**206.2**	**196.6**	**214.1**	**212.3**	**192.6**	**209.4**	**208.4**
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	184.8	196.3	198.1	184.2	194.1	195.5	184.6	195.6	197.3
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	210.9	221.6	220.9	219.6	230.5	229.8	214.0	224.7	224.0
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	190.4	194.1	199.3	194.8	199.0	204.7	192.1	196.0	201.4
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	182.2	186.9	187.2	182.3	187.9	187.8	182.2	187.3	187.4
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	162.6	181.0	186.8	156.7	168.2	172.8	160.4	176.3	181.7
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	174.6	192.5	190.7	182.7	196.1	193.8	178.4	194.2	192.1
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	199.9	270.5	259.9	246.0	333.9	315.2	215.5	292.0	278.7
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	202.9	215.0	214.5	209.3	220.1	219.4	205.1	216.7	216.2
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	129.7	131.3	131.1	130.9	133.0	133.2	130.1	131.9	131.8
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	249.8	229.7	230.0	239.7	225.0	224.3	246.4	228.1	228.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	181.8	185.4	186.0	169.0	174.0	174.8	176.5	180.6	181.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	193.7	199.6	200.5	201.8	210.2	210.8	197.5	204.5	205.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**202.0**	**207.1**	**203.3**	**202.9**	**207.4**	**208.1**	**208.5**	**213.5**	**212.2**	**204.4**	**209.0**	**209.2**
3 कपड़ा और जूते	**192.9**	**181.5**	**188.4**	**193.7**	**198.3**	**199.0**	**182.4**	**187.1**	**187.4**	**189.2**	**193.9**	**194.4**
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	194.4	199.2	200.0	184.5	189.2	189.6	190.5	195.3	195.9
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	189.8	192.9	193.4	171.0	175.2	175.4	182.0	185.5	185.9
4 आवास	--	**176.7**	**176.7**	--	--	--	**177.9**	**182.7**	**183.0**	**177.9**	**182.7**	**183.0**
5 ईंधन और बिजली	**183.0**	**178.9**	**181.4**	**182.4**	**181.1**	**180.8**	**175.8**	**169.7**	**169.6**	**179.9**	**176.8**	**176.6**
6 विविध	**181.7**	**173.7**	**177.8**	**182.5**	**189.9**	**190.4**	**174.4**	**181.5**	**181.8**	**178.6**	**185.8**	**186.2**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	182.0	185.8	186.4	172.3	177.4	178.0	177.4	181.8	182.4
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	191.9	198.6	199.3	186.2	193.6	194.0	189.7	196.7	197.3
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	171.7	176.4	176.6	161.7	165.5	165.6	166.4	170.7	170.8
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	176.4	180.4	181.0	171.8	176.0	176.4	173.8	177.9	178.4
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	185.2	191.8	192.0	180.4	187.6	187.8	182.4	189.3	189.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	186.7	205.1	206.0	187.9	207.3	207.7	187.2	206.0	206.7
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**185.6**	**182.4**	**184.1**	**188.2**	**199.5**	**199.4**	**184.2**	**193.7**	**193.1**	**186.3**	**196.8**	**196.5**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2023	2024	
				अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	138.4	143.3	144.5
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1241	1304	1315
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1251	1316	1326

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	58773	72878	76713
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	70084	86187	93352

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			नवं	सितं	अक्तू (अ)	नवं (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**151.4**	**153.1**	**154.7**	**156.1**	**156.0**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**183.0**	**187.6**	**195.5**	**200.3**	**197.9**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**191.3**	**197.0**	**210.8**	**218.0**	**214.0**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	200.0	212.4	213.7	214.8
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	226.1	264.1	291.8	273.2
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	181.5	185.3	185.6	185.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	167.8	172.6	171.0	173.1
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	246.0	243.2	242.9	244.5
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	199.3	207.9	219.3	215.4
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**162.4**	**163.8**	**162.2**	**161.3**	**162.2**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	166.6	163.8	160.1	159.0
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	185.0	184.6	185.5	185.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	134.9	136.0	140.2	139.2	138.9
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	304.7	244.7	247.3	270.0
1.1.3 खनिज	**0.833**	**217.7**	**215.8**	**223.2**	**223.8**	**228.5**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	205.8	213.8	214.6	220.1
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	250.6	256.4	256.0	258.1
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**153.6**	**159.0**	**146.1**	**146.7**	**146.1**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**152.0**	**156.2**	**147.2**	**146.5**	**147.1**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**136.4**	**136.7**	**135.6**	**135.5**	**135.5**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	258.1	232.0	229.5	229.5
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**159.0**	**162.5**	**154.3**	**152.9**	**154.0**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**145.0**	**153.3**	**136.7**	**137.4**	**137.3**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**140.2**	**140.2**	**141.9**	**142.5**	**143.0**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**160.5**	**162.0**	**171.0**	**173.3**	**177.3**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	145.1	152.2	152.8	153.2
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	145.2	144.9	146.0	148.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	131.8	132.8	133.2	132.7
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	142.2	162.8	169.9	182.0
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	180.2	180.0	180.9	182.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	180.0	186.6	187.3	190.2
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	157.5	174.6	173.5	169.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	166.0	169.6	170.1	172.8
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	140.0	138.2	139.0	138.4
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	140.6	160.5	162.2	160.7
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	155.1	153.8	155.7	158.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	180.0	204.5	199.9	193.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	198.1	192.8	192.9	190.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	146.7	151.7	151.3	152.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	180.0	186.2	186.9	191.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	212.7	211.4	209.4	206.3
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**131.5**	**131.7**	**134.3**	**134.5**	**134.9**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	133.3	134.5	136.0	136.4	137.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	135.4	138.6	139.0	139.2
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	124.7	128.3	128.2	128.5
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**173.5**	**175.0**	**177.5**	**176.1**	**177.4**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	175.0	177.5	176.1	177.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			नवं	सितं	अक्तू (अ)	नवं (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**134.6**	**134.2**	**135.8**	**135.9**	**135.9**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	120.0	121.6	121.1	120.6
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	156.4	156.4	157.3	158.4
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	118.1	123.4	125.3	123.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	156.7	160.9	161.2	159.9
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	137.1	141.1	142.1	143.2
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	131.2	136.1	135.0	135.4
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**150.8**	**151.4**	**153.6**	**153.9**	**153.8**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	148.8	150.9	151.0	151.0
1.3.5.2 बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	158.4	160.9	161.6	161.5
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**124.1**	**124.0**	**125.0**	**125.2**	**125.7**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	106.7	104.9	106.4	106.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	141.3	142.8	142.9	143.8
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	127.6	129.7	129.4	130.1
1.3.7 लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**146.6**	**147.7**	**148.6**	**148.9**	**148.4**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	136.8	142.2	142.1	141.9
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	147.9	147.1	147.8	147.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	206.4	208.7	216.4	216.2	214.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	139.6	140.9	140.3	139.8
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**140.3**	**138.4**	**139.8**	**139.9**	**139.0**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	145.7	144.6	144.2	143.7
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	140.8	146.9	148.0	148.6
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	124.4	124.6	124.6	121.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**182.3**	**184.0**	**185.3**	**185.4**	**186.7**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	184.0	185.3	185.4	186.7
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.9**	**136.0**	**136.5**	**136.3**	**136.1**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	139.0	138.1	137.2	138.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	143.0	142.7	143.2	143.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	129.1	134.0	134.2	133.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.8	132.8	128.8	130.3	129.5
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	144.6	141.3	139.7	137.8
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	138.8	138.9	138.8	139.7
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	133.1	136.5	136.6	135.3
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	102.8	104.6	102.9	102.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**142.9**	**142.4**	**144.1**	**143.5**	**144.1**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	142.4	144.1	143.5	144.1
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**127.5**	**126.8**	**128.7**	**129.2**	**128.6**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.5	115.0	116.6	116.8
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	107.3	113.7	113.6	112.2
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	136.3	137.4	137.6	136.8
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**134.7**	**134.6**	**130.6**	**130.1**	**130.6**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	163.4	163.4	162.4	162.2
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	119.5	119.8	118.8	123.6
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	118.5	123.9	126.0	127.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	122.6	124.5	124.7	124.6
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	137.5	128.9	128.3	128.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			नवं	सितं	अक्तू (अ)	नवं (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	137.9	138.7	138.1	138.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	132.2	135.4	135.2	135.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	100.1	97.2	94.5	93.8
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**141.0**	**140.2**	**137.7**	**139.0**	**138.6**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	138.8	130.4	134.3	132.2
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	151.8	138.3	145.2	139.9
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	118.3	114.1	114.8	117.7
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	141.2	138.9	140.1	139.6
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	142.7	132.5	131.9	132.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	137.0	132.9	134.6	133.7
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	133.8	130.7	128.1	126.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	170.2	163.3	163.9	163.4
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	143.6	155.6	157.5	157.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	143.3	144.9	144.7	144.5
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	175.1	170.8	172.7	172.8
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**138.6**	**139.3**	**136.3**	**135.3**	**135.3**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	133.2	131.5	129.9	129.6
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	157.7	150.1	147.2	147.0
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	106.3	105.9	111.2	112.9	112.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	145.3	138.9	139.9	140.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	109.2	102.0	101.9	102.4
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	143.5	144.0	143.5	144.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**119.3**	**120.0**	**121.7**	**121.7**	**121.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	115.0	117.6	117.1	117.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.1	135.4	135.3	133.6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	139.4	145.1	145.7	145.9
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	104.4	101.0	101.1	100.5
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	113.8	120.9	120.9	120.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	158.6	167.5	167.5	167.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	107.1	117.7	117.0	115.2
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	103.6	107.0	107.0	108.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**131.4**	**131.2**	**133.4**	**133.5**	**133.8**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	130.3	131.6	131.6	132.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	137.8	138.6	141.3	141.3	141.7
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	125.6	121.2	121.2	116.5
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	146.1	144.7	153.2	154.6	153.8
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	116.2	118.7	118.0	118.7
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	132.5	131.7	131.6	130.7
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	120.2	123.2	124.1	124.9
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**129.0**	**129.2**	**130.9**	**131.0**	**130.8**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	129.5	133.2	133.9	133.6
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	132.3	133.8	134.1	134.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	117.0	118.5	118.3	118.6
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	126.5	127.6	128.0	127.2
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	83.2	85.8	86.3	87.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	128.7	129.5	129.7	130.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			नवं	सितं	अक्तू (अ)	नवं (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	145.0	148.5	146.7	147.1
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	143.2	145.2	145.3	145.6
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.9	122.8	123.1	123.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	88.8	88.8	89.1	89.5
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.2	126.1	126.3	126.0
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	137.9	142.8	142.8	138.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	144.9	144.7	144.5	144.6
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	70.6	68.5	68.6	68.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**128.4**	**128.2**	**129.6**	**129.6**	**129.4**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	128.7	130.0	129.9	129.6
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	127.6	129.1	129.2	129.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**143.1**	**143.8**	**144.4**	**145.2**	**145.5**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	177.9	177.9	177.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	108.9	110.0	109.5	107.8
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	145.4	145.2	146.4	146.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	138.5	133.7	133.3	133.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	163.0	163.0	164.1	162.9
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**159.6**	**159.2**	**159.4**	**159.5**	**162.6**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	159.2	159.4	159.5	162.6
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**158.2**	**161.3**	**178.9**	**184.0**	**183.8**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	161.3	180.1	185.5	185.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	186.0	204.7	199.7	205.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	155.3	164.4	168.0	167.8
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	159.6	159.3	162.7	163.6	162.4
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	162.2	159.7	158.6	158.6
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**179.8**	**183.9**	**195.9**	**201.2**	**200.3**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रैल-अक्तूबर		अक्तूबर	
				2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	143.7	149.4	144.9	149.9
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	119.4	123.7	127.4	128.5
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	141.9	147.3	142.1	147.9
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	204.8	215.9	203.8	207.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	144.4	150.3	146.1	149.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	104.4	108.5	106.1	109.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	155.1	161.3	157.5	163.4
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	172.8	182.5	175.9	183.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	118.4	128.1	123.0	130.2
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	148.3	147.3	142.4	146.3

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-अक्तूबर			
	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3129200**	**1704267**	**1567722**	**54.5**	**59.6**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2583499	1304973	1301957	50.5	55.9
1.2 करेतर राजस्व	545701	399294	265765	73.2	88.1
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**78000**	**18807**	**22990**	**24.1**	**27.4**
2.1 ऋण की वसूली	28000	13275	14990	47.4	65.2
2.2 अन्य प्राप्तियां	50000	5532	8000	11.1	13.1
3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	**3207200**	**1723074**	**1590712**	**53.7**	**58.6**
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3709401	2007353	1847488	54.1	52.8
4.1 ब्याज भुगतान	1162940	596347	545086	51.3	50.5
5 पूंजी व्यय	1111111	466545	546924	42.0	54.6
6 कुल व्यय (4+5)	**4820512**	**2473898**	**2394412**	**51.3**	**53.2**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**580201**	**303086**	**279766**	**52.2**	**32.2**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1613312**	**750824**	**803700**	**46.5**	**45.0**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**450372**	**154477**	**258614**	**34.3**	**36.6**

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		अक्तू 27	सितं 20	सितं 27	अक्तू 4	अक्तू 11	अक्तू 18	अक्तू 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	10711	3475	5662	3677	3099	3987	4445
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	21650	8242	5698	7262	8191	8176	7867
1.3 राज्य सरकारें	5701	20974	71688	69688	70088	63073	75533	94683
1.4 अन्य	88670	99139	94083	90440	89862	88511	84636	84488
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	78300	51781	44787	42339	40097	38664	39780
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	91001	37767	30674	32794	35358	31454	30680
2.3 राज्य सरकारें	4070	13556	13909	13909	14647	11983	14467	13595
2.4 अन्य	102311	81399	79152	78239	78367	77046	79882	81040
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	82167	84627	84526	84887	84987	85022	82642
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	187124	117499	122233	118548	112750	113087	115669
3.3 राज्य सरकारें	41487	48417	31022	28145	30738	32439	34933	34600
3.4 अन्य	165095	152709	183873	173241	173565	176263	172892	169689
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	126331	175422	167512	91586	221354	188558	162948
4.4 अन्य	442	831	811	449	107	338	4325	547
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	887147	777119	747242	746773	733795	742733	759178

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
अक्तू 3	7000	76	23192	2478	44	6822	2478	9300	98.41	6.4739
अक्तू 9	7000	87	23189	6572	45	6913	6572	13485	98.42	6.4300
अक्तू 16	7000	78	21113	24058	40	6942	24058	31000	98.42	6.4515
अक्तू 23	7000	98	24300	26210	47	6940	26210	33150	98.41	6.4797
अक्तू 30	7000	82	16356	878	51	6972	878	7850	98.40	6.5116
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
अक्तू 3	6000	68	14035	1565	43	5973	1565	7538	96.83	6.5630
अक्तू 9	6000	65	13434	21	42	5979	21	6000	96.84	6.5424
अक्तू 16	6000	80	17881	2721	27	5986	2721	8707	96.84	6.5493
अक्तू 23	6000	90	13089	2513	58	5987	2513	8500	96.82	6.5970
अक्तू 30	6000	71	10555	258	54	5986	258	6244	96.80	6.6404
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
अक्तू 3	6000	93	19584	2921	38	5956	2921	8877	93.87	6.5487
अक्तू 9	6000	119	26630	1815	58	5974	1815	7789	93.89	6.5283
अक्तू 16	6000	93	23167	2526	41	5974	2526	8500	93.87	6.5438
अक्तू 23	6000	76	19741	358	48	5983	358	6341	93.83	6.5991
अक्तू 30	6000	73	21019	694	29	5986	694	6680	93.83	6.5991

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
अक्तूबर 01 ,2024	5.10-6.55	6.47
अक्तूबर 03 ,2024	5.10-6.55	6.44
अक्तूबर 04 ,2024	5.10-6.50	6.41
अक्तूबर 05 ,2024	5.50-6.50	6.09
अक्तूबर 07 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 08 ,2024	5.10-6.75	6.42
अक्तूबर 09 ,2024	5.10-6.60	6.43
अक्तूबर 10 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 11 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 14 ,2024	5.10-6.50	6.42
अक्तूबर 15 ,2024	5.00-6.50	6.42
अक्तूबर 16 ,2024	5.10-6.50	6.44
अक्तूबर 17 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 18 ,2024	5.10-6.60	6.44
अक्तूबर 19 ,2024	5.50-6.55	6.23
अक्तूबर 21 ,2024	5.10-6.90	6.49
अक्तूबर 22 ,2024	5.10-6.90	6.65
अक्तूबर 23 ,2024	5.10-6.90	6.74
अक्तूबर 24 ,2024	5.10-6.85	6.68
अक्तूबर 25 ,2024	5.10-6.75	6.61
अक्तूबर 28 ,2024	5.10-6.75	6.61
अक्तूबर 29 ,2024	5.10-6.50	6.44
अक्तूबर 30 ,2024	5.10-6.60	6.45
अक्तूबर 31 ,2024	5.75-6.65	6.54
नवंम्बर 04 ,2024	5.10-6.50	6.41
नवंम्बर 05 ,2024	5.10-6.40	6.31
नवंम्बर 06 ,2024	5.10-6.40	6.34
नवंम्बर 07 ,2024	5.10-6.50	6.41
नवंम्बर 08 ,2024	5.10-6.55	6.44
नवंम्बर 11 ,2024	5.10-6.55	6.45
नवंम्बर 12 ,2024	5.10-6.55	6.45
नवंम्बर 13 ,2024	5.10-6.72	6.39
नवंम्बर 14 ,2024	5.10-6.51	6.41

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2023	2024			
	अक्तू 20	सितं 6	सितं 20	अक्तू 4	अक्तू 18
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	313142.07	463005.01	474683.60	468063.51	484133.94
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	35271.26	55104.80	67552.42	39383.42	33814.44
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.95-7.70	7.02-7.56	7.11-7.83	6.96-7.75	6.93-7.65

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2023	2024			
	अक्तू 31	सितं 15	सितं 30	अक्तू 15	अक्तू 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (र करोड़)	413685.30	440945.45	397590.45	438134.20	445104.90
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	50039.65	78418.60	48447.90	48517.65	66159.85
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.00-11.89	7.09-12.88	7.07-14.72	6.95-12.60	6.99-12.53

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		अक्तू 27	सितं 20	सितं 27	अक्तू 4	अक्तू 11	अक्तू 18	अक्तू 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	16651	11343	18628	14262	15954	15675	16926
2 नोटिस मुद्रा	2550	336	5874	208	5246	912	4919	252
3 मीयादी मुद्रा	871	935	281	805	1625	424	1287	723
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	568927	605817	678781	727994	616134	761709	682726
5 बाजार रेपो	574534	483808	486193	548987	645890	498845	589584	497243
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	1096	2839	5566	5622	4519	3892	4146
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	84618	126154	140598	98443	105600	104189	110857
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	51094	168177	156651	151917	187506	103217	116577
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	2423	8231	11412	9122	9820	8944	7471
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	4968	900	2522	10153	4170	4250	3130
10.2 182-दिवसीय	6079	5373	2727	5341	5057	2871	4966	4174
10.3 364-दिवसीय	4307	1837	4404	4387	9976	4695	3875	3138
10.4 नकदी प्रबंधन बिल			0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	65694	184439	180314	186226	209062	125251	134490
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	713	788	586	187	22	216	7

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रैल-अक्तू)		2024-25 (अप्रैल-अक्तू) *		अक्तू 2023		अक्तू 2024 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**339**	**80942**	**181**	**36446**	**302**	**121633**	**34**	**5288**	**47**	**35653**
1ए प्रीमियम	328	76319	172	34120	287	100410	34	5058	45	35077
1.1 पब्लिक	272	65832	139	30058	215	109257	30	5158	29	34983
1.1.1 प्रीमियम	272	62791	139	28923	215	89670	30	4957	29	34662
1.2 राइट्स	67	15110	42	6388	87	12376	4	130	18	670
1.2.1 प्रीमियम	56	13527	33	5198	72	10740	4	100	16	415
2 अधिमान शेयर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**44**	**16342**	**25**	**10654**	**25**	**5526**	**5**	**2972**	**4**	**670**
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	44	16342	25	10654	25	5526	5	2972	4	670
3.1.1 पब्लिक	44	16342	25	10654	25	5526	5	2972	4	670
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 कुल (1+2+3)	**383**	**97284**	**206**	**47100**	**327**	**127159**	**39**	**8260**	**51**	**36323**
4.1 पब्लिक	316	82174	164	40712	240	114783	35	8130	33	35653
4.2 राइट्स	67	15110	42	6388	87	12376	4	130	18	670

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24	2023	2024				
			अक्तू	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	278285	293508	282611	290042	289627	329333
	मिलियन यूएस $	437072	33434	35163	33807	34572	34558	39193
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	48981	45824	43227	48456	39522	38518
	मिलियन यूएस $	84157	5885	5490	5171	5776	4716	4584
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	229304	247684	239384	241586	250105	290815
	मिलियन यूएस $	352915	27549	29673	28636	28796	29843	34609
2 आयात	₹ करोड़	5616042	531559	473149	480405	539789	463567	556140
	मिलियन यूएस $	678215	63862	56684	57468	64340	55313	66184
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	134366	125581	115934	92408	104676	153725
	मिलियन यूएस $	178733	16143	15045	13869	11015	12490	18294
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	397193	347569	364471	447381	358891	402415
	मिलियन यूएस $	499482	47719	41640	43600	53325	42823	47890
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-253274	-179641	-197794	-249747	-173940	-226807
	मिलियन यूएस $	-241143	-30429	-21521	-23661	-29769	-20755	-26991
3. 1 तेल	₹ करोड़	-783382	-85385	-79757	-72707	-43952	-65155	-115207
	मिलियन यूएस $	-94576	-10258	-9555	-8698	-5239	-7774	-13710
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-167889	-99884	-125087	-205794	-108785	-111600
	मिलियन यूएस $	-146567	-20170	-11966	-14963	-24530	-12980	-13281

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2023	2024					
		दिसं 01	अक्तू 25	नवं 01	नवं 08	नवं 15	नवं 22	नवं 29
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**₹ करोड़**	**5031468**	**5757912**	**5735915**	**5700945**	**5552871**	**5545695**	**5560661**
	यूएस $ मिलियन	**604042**	**684805**	**682130**	**675653**	**657892**	**656582**	**658091**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4444765	4992326	4959943	4939271	4809631	4787282	4806616
	यूएस $ मिलियन	533610	593751	589849	585383	569835	566791	568852
१.२ स्वर्ण	₹ करोड़	394231	576181	586521	572194	554921	570744	565949
	यूएस $ मिलियन	47329	68527	69751	67814	65746	67573	66979
	मात्रा (मीट्रिक टन)	803.58	866.85	867.79	870.59	874.32	876.18	876.18
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13688	13702	13702	13702	13705	13705	13705
	₹ करोड़	152019	153190	153198	153217	152470	151906	152152
	यूएस $ मिलियन	18250	18219	18219	18159	18064	17985	18007
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	40452	36215	36254	36263	35849	35763	35945
	यूएस $ मिलियन	4853	4307	4311	4298	4247	4232	4254

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।

टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2023	2024		2023-24	2024-25
		अक्तू	सितं	अक्तू (अ)	अप्रै-अक्तू	अप्रै-अक्तू (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**151879**	**143481**	**161623**	**162693**	**6112**	**11897**
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	21427	31080	31871	2064	6138
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	96566	100924	100873	1950	3090
1.3 एनआरओ	27522	25487	29619	29949	2099	2669

अ: अनंतिम।

अप्रै-अक्तू **अप्रै-अक्तू (अ)**

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (P)	2023	2024 (अ)	
		अप्रै-अक्तू	अप्रै-अक्तू	अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**10129**	**7699**	**2130**	**3805**	**-3061**	**-1335**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**26807**	**15674**	**14489**	**5276**	**-1042**	**181**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**71279**	**42103**	**48638**	**8591**	**5984**	**6536**
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	27602	34693	6459	4118	4344
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	193	529	2	3	149
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	31826	17934	24149	2757	2487	3524
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	8699	9337	3578	1516	550
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	776	679	121	111	121
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	10999	11355	1718	1580	1718
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5694	3503	2590	414	286	474
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**44472**	**26429**	**34149**	**3316**	**7026**	**6356**
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	24552	32923	2924	6934	6234
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	1877	1226	392	92	122
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**16678**	**7975**	**12359**	**1470**	**2019**	**1516**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	4504	7111	956	695	624
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	3375	3429	482	482	482
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	2637	3696	220	1022	591
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	2541	1876	189	179	181
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**44081**	**18936**	**9161**	**-1741**	**9659**	**-10876**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	19520	8979	-1855	9595	-10975
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	584	-182	-114	-64	-99
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**54210**	**26635**	**11291**	**2064**	**6598**	**-12211**

अ: अनंतिम।

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023	2024		
		अक्तू	अग	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**31735.74**	**2176.98**	**3211.54**	**2758.25**	**2408.01**
1.1 जमाराशियाँ	916.45	26.28	45.56	43.00	39.06
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	11.02	22.49	25.47	24.96
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	83.86	125.30	135.08	149.34
1.4 उपहार	3580.27	184.79	244.41	221.67	216.30
1.5 दान	11.31	0.96	0.67	0.87	0.66
1.6 यात्रा	17006.27	1368.98	2013.30	1713.06	1454.66
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	4611.53	206.16	315.40	281.24	283.75
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	8.53	7.65	7.89	8.49
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	269.19	416.39	320.10	221.18
1.10 अन्य	298.24	17.22	20.36	9.88	9.62

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2022-23	2023-24	2023	2024	
			नवं	अक्तू	नवं
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	91.20	90.73	90.76	90.89	91.80
1.2 रीर	102.78	103.70	104.72	107.20	108.14
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.01	93.11	93.19	93.45	94.23
2. 2 रीर	101.10	101.21	102.16	104.24	104.97
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	85.93	83.62	83.57	81.99	82.79
1.2 रीर	101.80	101.66	102.86	104.35	105.29
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	100.00	97.31	97.26	95.42	96.35
2.2 रीर	100.00	99.86	101.04	102.50	103.43

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	90	95	135
1.2 राशि	29461	742	3776	5029
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	0	1	1
2.2 राशि	19748	0	1065	470
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	90	96	136
3.2 राशि	49209	742	4841	5499
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.60	13.90	4.40	6.70
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारित औसत मार्जिन	1.66	1.98	1.36	1.58
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-27.00	0.00-11.00	0.00-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	184	378	926
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	351	328	2941
ए) परिवहन	1505	350	0	200
बी) ऊर्जा	3513	0	15	1449
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	1
डी) संचार	6309	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	0	63
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	0	313	850
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	1	0	378
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	26	437	86
IV. अन्य संस्थाएं	1728	0	0	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	1	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	1727	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	0
VII. एनबीएफसी	13361	31	3578	1436
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	0	2777	285
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	2	31	120
सी) एनबीफसी - अन्य	5096	29	770	1031
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	150	120	110

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**403470**	**379039**	**24432**	**506715**	**501489**	**5226**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**221636**	**230603**	**-8967**	**241638**	**251403**	**-9765**
1.1 पण्य	**104936**	**161637**	**-56701**	**111175**	**176297**	**-65122**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**116700**	**68967**	**47734**	**130463**	**75106**	**55357**
1.2.1 सेवाएं	80569	45449	35121	88466	48740	39725
1.2.1.1 यात्रा	6412	9489	-3077	7352	9171	-1819
1.2.1.2 परिवहन	7408	7693	-285	8507	8609	-102
1.2.1.3 बीमा	761	591	170	903	593	310
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	159	250	-91	161	309	-147
1.2.1.5 विविध	65830	27427	38404	71542	30058	41484
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	38172	4243	33928	41926	4479	37447
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	21831	15203	6627	23000	16625	6375
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1891	1152	739	2215	1267	948
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	831	324	507	519	444	75
1.2.2 अंतरण	27117	4279	22838	29519	3169	26350
1.2.2.1 आधिकारिक	20	255	-235	18	266	-248
1.2.2.2 निजी	27097	4024	23073	29502	2904	26598
1.2.3 आय	9014	19239	-10225	12478	23196	-10718
1.2.3.1 निवेश आय	7187	18372	-11185	10341	22218	-11878
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1827	868	959	2137	978	1159
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**181834**	**148018**	**33816**	**264492**	**250086**	**14406**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**109054**	**88595**	**20459**	**183279**	**176019**	**7259**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19278	14551	4728	23435	17120	6315
2.1.1.1 भारत में	17790	10427	7362	22287	12171	10116
2.1.1.1.1 इक्विटी	11266	9351	1915	16402	11673	4729
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4541	0	4541	4897		4897
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1983	1077	906	988	498	490
2.1.1.2 विदेश में	1489	4123	-2634	1147	4949	-3801
2.1.1.1.1 इक्विटी	1489	1864	-375	1147	2346	-1199
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1500	-1500
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	813	-813	0	1102	-1102
2.1.2 संविभाग निवेश	89775	74045	15731	159844	158899	945
2.1.2.1 भारत में	88743	72654	16089	159240	158343	897
2.1.2.1.1 एफआईआई	88743	72654	16089	159240	158343	897
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	77174	63525	13649	139824	140833	-1009
2.1.2.1.1.2 ऋण	11569	9129	2440	19416	17510	1906
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1032	1391	-358	604	556	48
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**30359**	**28188**	**2171**	**31905**	**25940**	**5965**
2.2.1 बाह्य सहायता	3032	1603	1429	3641	2271	1371
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	49	-40	8	30	-22
2.2.1.2 भारत को	3023	1553	1470	3634	2241	1393
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	15452	9721	5731	12618	10951	1667
2.2.2.1 भारत द्वारा	2212	2071	140	4138	4255	-117
2.2.2.2 भारत को	13241	7650	5591	8481	6696	1785
2.2.3 भारत को अल्पावधि	11875	16864	-4989	15645	12718	2927
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	11875	14352	-2477	13572	12718	854
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2512	-2512	2073	0	2073
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**33279**	**20339**	**12940**	**36380**	**33511**	**2870**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	33107	20339	12769	36259	33511	2749
2.3.1.1 आस्तियां	13315	3382	9934	10705	13570	-2865
2.3.1.2 देयताएं	19792	16957	2835	25554	19941	5614
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	18896	16688	2208	23426	19401	4025
2.3.2 अन्य	172	0	172	121	0	121
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	**0**	**62**	**-62**	**0**	**61**	**-61**
2.5 अन्य पूंजी	**9143**	**10834**	**-1691**	**12928**	**14556**	**-1627**
3 भूल-चक	**0**	**418**	**-418**	**585**	**0**	**585**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**24432**	**-24432**	**0**	**5226**	**-5226**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	24432	-24432		5226	-5226

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3316497**	**3115671**	**200826**	**4227182**	**4183585**	**43597**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1821831**	**1895540**	**-73709**	**2015823**	**2097284**	**-81461**
1.1 पण्य	**862564**	**1328641**	**-466077**	**927458**	**1470724**	**-543266**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**959267**	**566900**	**392367**	**1088365**	**626560**	**461805**
1.2.1 सेवाएं	662275	373584	288691	738010	406609	331401
1.2.1.1 यात्रा	52702	77997	-25295	61335	76511	-15177
1.2.1.2 परिवहन	60895	63237	-2342	70965	71816	-851
1.2.1.3 बीमा	6251	4854	1398	7535	4950	2585
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1305	2051	-746	1346	2575	-1229
1.2.1.5 विविध	541121	225445	315676	596830	250757	346073
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	313769	34880	278889	349760	37363	312397
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	179448	124971	54477	191873	138694	53178
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	15546	9473	6073	18478	10572	7906
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	6827	2663	4165	4331	3702	629
1.2.2 अंतरण	222898	35170	187728	246261	26440	219821
1.2.2.1 आधिकारिक	160	2094	-1934	150	2216	-2066
1.2.2.2 निजी	222738	33076	189662	246112	24225	221887
1.2.3 आय	74093	158146	-84052	104093	193510	-89417
1.2.3.1 निवेश आय	59076	151014	-91938	86265	185352	-99087
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	15018	7132	7886	17829	8158	9670
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1494666**	**1216698**	**277968**	**2206479**	**2086302**	**120178**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**896414**	**728246**	**168169**	**1528971**	**1468411**	**60560**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	158467	119605	38862	195500	142821	52679
2.1.1.1 भारत में	146230	85713	60517	185930	101538	84392
2.1.1.1.1 इक्विटी	92604	76861	15743	136835	97382	39453
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	37323	0	37323	40849	0	40849
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	16303	8853	7450	8246	4156	4090
2.1.1.2 विदेश में	12237	33892	-21654	9570	41283	-31713
2.1.1.2.1 इक्विटी	12237	15322	-3085	9570	19574	-10004
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	11889	-11889	0	12515	-12515
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	6681	-6681	0	9194	-9194
2.1.2 संविभाग निवेश	737947	608641	129306	1333471	1325590	7881
2.1.2.1 भारत में	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
2.1.2.1.1 एफआईआई	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	634364	522169	112195	1166461	1174878	-8416
2.1.2.1.1.2 ऋण	95097	75040	20058	161973	146071	15901
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8486	11432	-2946	5037	4641	396
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**249550**	**231703**	**17847**	**266160**	**216400**	**49760**
2.2.1 बाह्य सहायता	24921	13173	11749	30377	18943	11433
2.2.1.1 भारत द्वारा	72	404	-331	64	247	-184
2.2.1.2 भारत को	24849	12769	12080	30313	18696	11617
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	127016	79909	47107	105264	91357	13907
2.2.2.1 भारत द्वारा	18179	17027	1153	34517	35497	-980
2.2.2.2 भारत को	108837	62882	45955	70747	55860	14887
2.2.3 भारत को अल्पावधि	97612	138621	-41009	130519	106100	24420
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	97612	117969	-20357	113225	106100	7125
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	20652	-20652	17295	0	17295
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**273549**	**167181**	**106367**	**303498**	**279556**	**23942**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	272138	167181	104957	302487	279556	22931
2.3.1.1 आस्तियां	109451	27797	81653	89303	113205	-23902
2.3.1.2 देयताएं	162687	139384	23304	213184	166351	46833
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	155328	137175	18153	195426	161851	33575
2.3.2 अन्य	1410	0	1410	1011	0	1011
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**512**	**-512**	**0**	**508**	**-508**
2.5 अन्य पूंजी	**75153**	**89057**	**-13904**	**107850**	**121427**	**-13577**
3 भूल-चूक	**0**	**3432**	**-3432**	**4880**	**0**	**4880**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**200826**	**-200826**	**0**	**43597**	**-43597**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	200826	-200826	0	43597	-43597

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस $)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**221635**	**230581**	**-8945**	**241638**	**251377**	**-9739**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**185505**	**207085**	**-21580**	**199641**	**225037**	**-25396**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**104936**	**161637**	**-56701**	**111175**	**176297**	**-65122**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	104497	151939	-47442	111136	166784	-55648
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	438	0	438	39	0	39
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	9698	-9698		9512	-9512
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**80569**	**45449**	**35121**	**88466**	**48740**	**39725**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	481	42	439	268	22	246
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	47	431	-385	81	238	-157
1.अ.ख.3 परिवहन	7408	7693	-285	8507	8609	-102
1.अ.ख.4 यात्रा	6412	9489	-3077	7352	9171	-1819
1.अ.ख.5 निर्माण	870	697	174	1478	563	915
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	761	591	170	903	593	310
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1891	1152	739	2215	1267	948
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	381	3647	-3266	341	4448	-4107
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	39091	4859	34231	42541	5215	37326
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	21831	15203	6627	23000	16625	6375
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	968	1279	-312	1175	1249	-74
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	159	250	-91	161	309	-147
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	272	116	156	444	432	12
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**9014**	**19239**	**-10225**	**12478**	**23196**	**-10718**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1827	868	959	2137	978	1159
1.आ.2 निवेश आय	5777	17935	-12158	8448	21594	-13146
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2355	9950	-7595	3173	12343	-9170
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	208	2250	-2042	70	2411	-2341
1.आ.2.3 अन्य निवेश	517	5546	-5029	1110	6620	-5510
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	2697	189	2508	4095	220	3876
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1410	436	973	1892	624	1268
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**27116**	**4256**	**22860**	**29519**	**3144**	**26376**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	27097	4024	23073	29502	2904	26598
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	26325	2680	23645	28644	1989	26655
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	772	1343	-571	857	914	-57
1.इ.2 सामान्य सरकार	19	232	-214	18	240	-222
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**150**	**145**	**5**	**185**	**146**	**40**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	12	51	-39	4	45	-41
2.2 पूँजी अतंरण	138	94	44	182	101	81
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**181685**	**172328**	**9358**	**264307**	**255192**	**9114**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**19278**	**14551**	**4728**	**23435**	**17120**	**6315**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	17790	10427	7362	22287	12171	10116
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	15806	9351	6456	21299	11673	9626
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11266	9351	1915	16402	11673	4729
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4541	0	4541	4897		4897
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1983	1077	906	988	498	490
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1983	1077	906	988	498	490
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1489	4123	-2634	1147	4949	-3801
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1489	3310	-1822	1147	3847	-2699
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1489	1864	-375	1147	2346	-1199
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	1446	-1446		1500	-1500
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	813	-813	0	1102	-1102
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	813	-813		1102	-1102
3.2 संविभाग निवेश	**89775**	**74045**	**15731**	**159844**	**158899**	**945**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	88743	72654	16089	159240	158343	897
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	77174	63525	13649	139824	140833	-1009
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11569	9129	2440	19416	17510	1906
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1032	1391	-358	604	556	48
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5013**	**5736**	**-723**	**6053**	**9666**	**-3613**
3.4 अन्य निवेश	**67619**	**53565**	**14053**	**74976**	**64281**	**10694**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	19068	16688	2380	23547	19401	4146
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	172	0	172	121	0	121
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	18896	16688	2208	23426	19401	4025
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	32695	14974	17720	29093	27331	1762
3.4.3अ भारत को ऋण	30474	12854	17621	24948	23046	1901
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2220	2120	100	4145	4285	-139
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	38	168	-130	47	133	-86
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	11875	16864	-4989	15645	12718	2927
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	3943	4871	-928	6643	4698	1945
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**24432**	**-24432**	**0**	**5226**	**-5226**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	24432	-24432	0	5226	-5226
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**181685**	**172328**	**9358**	**264307**	**255192**	**9114**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	100552	83480	17072	168975	166708	2266
4.2 ऋण लिखत	77190	59545	17645	88689	78560	10129
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	3943	29302	-25359	6643	9924	-3281
5. निवल भूल-चूक	**0**	**418**	**-418**	**585**	**0**	**585**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	1821825	1895356	-73531	2015820	2097068	-81248
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	1524839	1702225	-177386	1665468	1877333	-211865
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	862564	1328641	-466077	927458	1470724	-543266
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	858960	1248927	-389967	927134	1391370	-464235
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3604	0	3604	324	0	324
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	79714	-79714	0	79355	-79355
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	662275	373584	288691	738010	406609	331401
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	3955	345	3610	2234	183	2051
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	382	3546	-3164	676	1983	-1307
1.अ.ख.3 परिवहन	60895	63237	-2342	70965	71816	-851
1.अ.ख.4 यात्रा	52702	77997	-25295	61335	76511	-15177
1.अ.ख.5 निर्माण	7153	5726	1427	12327	4693	7635
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6251	4854	1398	7535	4950	2585
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	15546	9473	6073	18478	10572	7906
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3128	29977	-26849	2843	37103	-34261
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	321321	39942	281380	354891	43507	311384
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	179448	124971	54477	191873	138694	53178
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	7953	10515	-2562	9803	10418	-615
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1305	2051	-746	1346	2575	-1229
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2235	950	1285	3706	3604	102
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	74093	158146	-84052	104093	193510	-89417
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	15018	7132	7886	17829	8158	9670
1.आ.2 निवेश आय	47486	147426	-99940	70478	180146	-109668
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	19356	81790	-62434	26468	102971	-76503
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	1710	18491	-16781	582	20112	-19530
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4252	45590	-41337	9262	55229	-45968
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	22167	1555	20612	34166	1833	32333
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	11590	3588	8002	15787	5206	10581
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	222893	34986	187907	246259	26225	220034
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	222738	33076	189662	246112	24225	221887
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	216392	22033	194358	238960	16597	222364
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6346	11042	-4696	7151	7628	-477
1.इ.2 सामान्य सरकार	155	1910	-1755	147	2000	-1852
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	1232	1188	44	1547	1214	333
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	100	418	-319	32	375	-343
2.2 पूँजी अतंरण	1132	770	362	1515	839	675
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1493440	1416520	76920	2204934	2128900	76035
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	158467	119605	38862	195500	142821	52679
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	146230	85713	60517	185930	101538	84392
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	129927	76861	53067	177683	97382	80301
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	92604	76861	15743	136835	97382	39453
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	37323	0	37323	40849	0	40849
3.1.अ.2 ऋण लिखत	16303	8853	7450	8246	4156	4090
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	16303	8853	7450	8246	4156	4090
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	12237	33892	-21654	9570	41283	-31713
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12237	27211	-14974	9570	32089	-22519
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	12237	15322	-3085	9570	19574	-10004
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	11889	-11889	0	12515	-12515
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	6681	-6681	0	9194	-9194
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	6681	-6681	0	9194	-9194
3.2 संविभाग निवेश	737947	608641	129306	1333471	1325590	7881
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	634364	522169	112195	1166461	1174878	-8416
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	95097	75040	20058	161973	146071	15901
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8486	11432	-2946	5037	4641	396
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	41207	47148	-5941	50493	80637	-30144
3.4 अन्य निवेश	555819	440301	115518	625470	536255	89216
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	156738	137175	19563	196437	161851	34586
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	1410	0	1410	1011	0	1011
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	155328	137175	18153	195426	161851	33575
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	268748	123088	145661	242702	228005	14697
3.4.3अ भारत को ऋण	250497	105658	144839	208121	192261	15861
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	18252	17430	821	34581	35744	-1164
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	308	1380	-1072	396	1109	-714
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	97612	138621	-41009	130519	106100	24420
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	32413	40037	-7624	55416	39189	16227
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	200826	-200826	0	43597	-43597
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	200826	-200826	0	43597	-43597
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1493440	1416520	76920	2204934	2128900	76035
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	826529	686201	140328	1409641	1390737	18904
4.2 ऋण लिखत	634499	489457	145042	739877	655377	84500
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	32413	240863	-208450	55416	82786	-27370
5. निवल भूल-चूक	0	3432	-3432	4880	0	4880

टिप्पणीः प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023		2024			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542777	228227	532278	242271	542777	246072	552178
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	143893	501412	153343	511142	156042	520277
1.2 अन्य पूंजी	88927	31635	84334	30866	88927	31635	90029	31900
2. संविभाग निवेश	12162	277118	14511	258539	12162	277118	12103	277272
2.1 इक्विटी	10644	162061	12567	152928	10644	162061	10367	160898
2.2 ऋण	1517	115057	1944	105611	1517	115057	1736	116374
3. अन्य निवेश	128450	571045	105256	531184	128450	571045	141261	590312
3.1 व्यापार ऋण	33450	123659	29658	119317	33450	123659	32874	126577
3.2 ऋण	13578	221886	13037	206940	13578	221886	16837	225023
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	52803	154787	33117	144069	52803	154787	57032	160628
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	28619	48804	29443	38848	28619	48804	34518	56319
4. आरक्षित निधियाँ	646419		595051		646419		651997	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1029301	1390940	943044	1322001	1029301	1390940	1051433	1419761
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361639		-378956		-361639		-368329	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.31	4.08	3.59	259206893	21422005	23840258	25730864
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.26	1.57	1.69	170464587	13902085	14750412	16664120
1.1.1 आउटराइट	9.51	0.66	0.99	1.04	13463848	889349	1468346	1626397
1.1.2 रेपो	4.94	0.40	0.37	0.41	76718788	5760793	6038102	6573748
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.21	0.23	80281951	7251944	7243965	8463975
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	1.96	2.40	1.74	80984671	7018310	8415273	8046345
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.10	0.11	0.16	7757636	501610	674573	1020399
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	224.62	233.33	267.92	170886670	13464400	17786483	17070975
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	223.48	232.21	266.69	152406168	11899324	16027655	15418778
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.14	1.12	1.23	18480503	1565076	1758828	1652197
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	128356.32	166626.30	185187.17	67542859	5667254	6384754	7358283
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.31	0.30	0.31	261	20	14	17
2.2 एपीबीएस $	25888.17	1745.79	2342.41	4021.91	390743	19666	35550	69157
2.3 आईएमपीएस	60053.35	4928.80	4299.36	4668.23	6495652	538239	565233	629382
2.4 एनएसीएच जमा $	16227.27	1278.99	1657.93	1463.68	1525104	131546	122079	157479
2.5 एनईएफटी	72639.50	6314.53	7908.83	9183.38	39136014	3262015	3597885	4152428
2.6 यूपीआई @	1311294.68	114087.90	150417.47	165849.66	19995086	1715768	2063995	2349821
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.63	1.31	1.64	352	38	14	18
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1499.66	1805.36	1871.73	1687658	139050	180707	189818
3.1 भीम आधार पे @	193.59	15.14	18.81	24.54	6112	525	568	773
3.2 एनएसीएच नामे $	16426.49	1348.29	1651.69	1710.21	1678769	138287	179945	188844
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	136.23	134.86	136.98	2777	238	193	202
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	5104.71	5275.26	5774.01	2423563	230670	216304	248709
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	3200.48	3921.62	4332.14	1831134	178569	176202	201789
4.1.1 पीओएस आधारित $	18614.08	1596.74	1978.05	2196.73	651911	57774	60857	79293
4.1.2 अन्य $	16996.08	1603.73	1943.57	2135.41	1179223	120795	115345	122496
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1904.23	1353.64	1441.87	592429	52101	40102	46920
4.2.1 पीओएस आधारित $	16477.95	1375.28	995.07	1063.87	393589	33731	25777	32182
4.2.2 अन्य $	6381.69	528.95	358.58	378.00	198840	18370	14324	14738
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	6687.84	5476.69	5977.88	283048	25012	17489	20419
5.1 वालेट	63256.69	5329.32	4054.95	4425.20	234353	20649	11889	13074
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1358.52	1421.74	1552.68	48695	4362	5600	7345
5.2.1 पीओएस आधारित $	8429.87	735.65	721.65	718.88	11247	872	858	981
5.2.2 अन्य $	7088.84	622.87	700.09	833.81	37447	3490	4743	6365
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	559.90	484.94	546.98	7212333	584454	543387	624057
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	559.90	484.94	546.98	7212333	584454	543387	624057
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	142208.43	179668.57	199357.77	79149461	6646440	7342641	8441287
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	142433.05	179901.90	199625.69	250036131	20110841	25129124	25512262
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	141873.15	179416.96	199078.71	242823799	19526387	24585737	24888205

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	109334.05	143577.22	156523.15	30687088	2619086	3164355	3568090
1.1 अंतर्बैंक $	83000.56	6877.68	9082.11	9560.14	5676805	474253	601793	667326
1.2 अंतर-बैंक $	1169598.65	102456.37	134495.11	146963.01	25010283	2144833	2562562	2900764
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3736.00	3847.73	4190.45	102117736	8464802	10092959	10129153
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	983.50	1101.62	1149.60	53247042	4400612	5123573	4971326
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2752.51	2746.11	3040.85	48870694	4064190	4969386	5157826
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	66440.72	5721.32	4949.81	5545.14	3259388	277832	245223	285511
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	95.80	8.54	8.02	8.32	4648	413	417	444
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	66001.01	5683.38	4922.18	5515.33	3241538	276289	243930	284081
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	343.90	29.40	19.62	21.49	13202	1130	876	985
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	15.18	0.85	0.27	0.29	148	8	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	15.06	0.84	0.25	0.28	147	8	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.12	0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	986.49	975.12	1227.30	314003	25378	23389	31480
5.1 एईपीएस @	11754.95	986.49	975.12	1227.30	314003	25378	23389	31480

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2023	2024	
		अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10748.82	10968.21	11053.03
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	947.11	1061.03	1068.90
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9801.71	9907.18	9984.13
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	16830.82	15339.88	15503.27
2.1 वालेट @	13381.80	13668.03	11381.79	11439.31
2.2 कार्ड @	3361.82	3162.79	3958.09	4063.95
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.58	2.55	2.56
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.23	2.23	2.20	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.35	0.35	0.35	0.35
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	15.30	14.45	14.43
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	83.48	93.43	95.09
6 भारत क्यूआर @	62.50	59.75	64.16	64.31
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	3017.20	6069.95	6167.67

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधनं के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।

भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।

भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक शृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2023	2024		
			सितं	जूला	अग	सितं
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**232460**	**17908**	**17440**	**12130**	**11569**
	बकाया	**1865029**	**1747246**	**1928913**	**1940611**	**1951745**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**161344**	**13376**	**13575**	**9998**	**9281**
	बकाया	**1298795**	**1216325**	**1351214**	**1361210**	**1370491**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	2879	2445	-205	810
	बकाया	191692	211296	199223	199017	199827
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	1672	2115	2005	1878
	बकाया	157611	99427	167150	169154	171032
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	2073	1907	1710	1222
	बकाया	269007	258381	276451	278161	279383
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2643	2703	2436	1942
	बकाया	175472	162188	185389	187824	189766
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	1849	3494	3052	2436
	बकाया	305776	291826	319069	322122	324558
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	131305	149939	152099	153904
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	10640	13188	13491	13737
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8255	9619	9773	9907
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	141626	146323	146759	147010
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	2284	935	1005	1020
	बकाया	197134	191314	201958	202963	203983
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-24	-25	-6	-28
	बकाया	1754	1553	1623	1617	1589
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	1	1	1
	बकाया	349	340	351	352	353
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**56069**	**4343**	**3742**	**1788**	**2152**
	बकाया	**418021**	**396508**	**429706**	**431065**	**432781**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1176	1395	1180	768
	बकाया	183905	173807	189081	190261	191030
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1853	1492	-174	695
	बकाया	220560	211987	225358	225184	225879
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1314	855	782	689
	बकाया	18277	11454	21761	22543	23232
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-740	-6494	-6923	-7360
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**15047**	**189**	**123**	**344**	**136**
	बकाया	**148213**	**134413**	**147993**	**148336**	**148473**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**10383607**	**10538792**	**10740389**	**10946860**	**11271589**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.96	37.55	37.66	37.52	37.55
2. सहकारी बैंक	1.52	1.49	1.47	1.42	1.35
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.66	0.67	0.66	0.70	0.77
4. बीमाकृत कंपनियां	26.05	26.16	25.98	26.11	25.95
5. म्यूच्युअल फंड	3.02	3.03	2.90	2.87	3.14
6. भविष्य निधियां	4.42	4.57	4.47	4.41	4.25
7. पेंशन निधि	4.32	4.44	4.52	4.74	4.86
8. वित्तीय संस्थाएं	0.54	0.55	0.55	0.57	0.63
9. कॉरपोरेट	1.21	1.33	1.35	1.44	1.60
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.61	1.92	2.34	2.34	2.80
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.06	12.54	12.31	11.92	11.16
12. अन्य	5.64	5.74	5.79	5.97	5.92
12.1 राज्य सरकार	2.04	2.07	2.04	2.13	2.19

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**5161642**	**5338587**	**5646219**	**5727482**	**5909490**
1. वाणिज्यिक बैंक	33.87	33.90	34.14	33.85	34.39
2. सहकारी बैंक	3.60	3.53	3.39	3.38	3.29
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.61	0.63	0.60	0.59	0.60
4. बीमाकृत कंपनियां	26.97	26.64	26.14	25.85	25.56
5. म्यूच्युअल फंड	1.86	2.00	2.09	2.08	1.93
6. भविष्य निधियां	21.70	22.00	22.35	22.94	23.02
7. पेंशन निधि	4.82	4.56	4.76	4.87	4.87
8. वित्तीय संस्थाएं	1.65	1.63	1.59	1.58	1.57
9. कॉरपोरेट	1.87	2.03	2.02	2.03	1.95
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.02	0.03	0.07	0.05	0.04
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.69	0.66	0.63	0.62	0.60
12. अन्य	2.34	2.37	2.20	2.17	2.18
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**925317**	**849151**	**871662**	**858193**	**747242**
1. वाणिज्यिक बैंक	56.35	57.18	58.53	47.79	44.74
2. सहकारी बैंक	1.20	1.28	1.67	1.49	1.58
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.54	1.70	1.66	2.69	2.28
4. बीमाकृत कंपनियां	5.26	5.50	5.06	5.78	5.26
5. म्यूच्युअल फंड	12.74	11.21	11.89	14.50	15.06
6. भविष्य निधियां	1.52	0.08	0.15	0.60	0.26
7. पेंशन निधि	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	4.10	5.34	7.16	6.56	6.36
9. कॉरपोरेट	4.00	4.58	4.50	4.79	4.66
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.10	0.07	0.01	0.20	0.15
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	14.17	13.06	9.36	15.59	19.65
12.1 राज्य सरकार	11.36	9.26	5.88	11.55	14.95

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7098451**	**8376972**	**9045119**
1.1 विकास संबंधी	2882758	3074492	3823423	4189146	5073367	5426440
1.1.1 राजस्व	2224367	2446605	3150221	3255207	3838714	3836447
1.1.2 पूंजी	596774	588233	550358	861777	1146013	1471534
1.1.3 ऋण	61617	39654	122844	72163	88639	118460
1.2 गैर-विकास संबंधी	2078276	2253027	2442941	2810388	3188699	3490946
1.2.1 राजस्व	1965907	2109629	2271637	2602750	2988556	3277722
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	894520	955801	1060602	1226672	1403183	1589435
1.2.2 पूंजी	111029	141457	169155	175519	196688	208268
1.2.3 ऋण	1340	1941	2148	32119	3455	4957
1.3 अन्य	79713	83368	86995	98916	114906	127733
2. कुल प्राप्तियां	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7156342**	**8258187**	**9149787**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3797731	3851563	3688030	4823821	5706246	6337126
2.1.1 कर प्राप्तियां	3278947	3231582	3193390	4160414	4837048	5477428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2030050	2012578	2076013	2626553	2967610	3372525
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1246083	1216203	1114805	1530636	1865298	2100430
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2814	2800	2572	3225	4140	4473
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	518783	619981	494640	663407	869198	859698
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	36273	31137	33448	35250	37974	45199
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	140287	110094	64994	44077	88273	119373
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	44667	59515	16951	27665	25661	34501
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	95621	50578	48044	16412	62611	84872
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2230553**	**2582453**	**2588620**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	387091	571872	890012	627255	687904	…
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	325987	190241	107493	350911	529	…
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	710119	868676	1640143	1567151	1870675	…
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	795845	971378	1696012	1213169	1776747	1902862
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	88961	209232	458801	526693	403838	441189
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	51004	38280	41273	28100	36454	37114
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-18298	10411	4545	42153	3524	24429
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	66289	-14227	25682	42203	82485	58404
3ख.1.6 नकद शेष	17395	-323279	-43802	-57891	118784	-104667
3ख.1.7 अन्य	96014	548753	347643	399980	136748	207172
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*26.7*	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*31.1*	*30.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*26.6*	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*30.6*	*30.3*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*21.2*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*9.6*	*8.6*

… : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बज़ट अनुमान।
स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।
टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।
1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।
3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।
3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।
नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।
3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्तूबर 2024 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5564.01	31	1983.24	23	1515.84	12
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	94.11	2	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	297.46	3	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	190.53	6	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	462.55	8	316.77	3
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	651.42	1	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1336.12	31	1796.00	25	321.00	8
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	82.21	24	123.33	15	316.21	1
17	मेघालय	278.78	24	267.00	9	163.46	9
18	मिज़ोरम	256.76	9	51.35	7	-	-
19	नगालैंड	173.06	5	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	3958.54	31	646.55	13	-	-
23	राजस्थान	2580.47	24	2016.13	10	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4501.71	31	1290.59	19	1630.52	2
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	1304.81	21	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां : 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2024 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11343	1118	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2697	7	0	4200
3	असम	8167	89	0	0
4	बिहार	12232	-	0	18000
5	छत्तीसगढ़	7651	479	0	8887
6	गोवा	1029	449	0	0
7	गुजरात	14985	655	0	2000
8	हरियाणा	2282	1674	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2357	-	0	1530
12	कर्नाटक	19900	736	0	68077
13	केरल	3047	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1250	0	0
15	महाराष्ट्र	70350	1711	0	0
16	मणिपुर	68	137	0	0
17	मेघालय	1248	107	0	0
18	मिज़ोरम	450	62	0	0
19	नगालैंड	1853	45	0	0
20	उड़ीसा	17807	2007	115	10594
21	पुदुचेरी	569	-	0	1850
22	पंजाब	8969	0	0	0
23	राजस्थान	1286	-	0	8700
24	तमिलनाडु	3366	-	0	3505
25	तेलंगाना	7743	1697	0	0
26	त्रिपुरा	1199	26	0	25
27	उत्तरप्रदेश	4921	207	0	0
28	उत्तराखंड	10518	-	0	15000
29	पश्चिम बंगाल	13118	1013	239	0
	कुल	**229173**	**13486**	**354**	**142367**

टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में ली गई कुल राशि	
						अग		सितं		अक्तू			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	3000	2000	4000	-1000	6000	4000	50000	34918
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	-	-	-	-	-	-	-	-146
3	असम	17100	16105	18500	16000	2000	1500	1750	1750	1500	1000	9250	7800
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	6000	6000	6000	3922	8000	3000	20000	12922
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	1500	-550	2000	2000	3000	2300	6500	3000
6	गोवा	1350	500	2550	1560	150	-50	300	300	200	100	850	150
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	2500	2500	-	-1000	1500	-500	6000	-
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	4500	3500	3000	1700	1500	750	21000	15220
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	500	350	700	700	600	200	5200	3550
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	1550	1550	-	-	400	-40	9750	8410
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	-	-	3000	1000	20000	18000	23000	14500
13	केरल	30839	15620	42438	26638	6000	4300	3753	2253	2745	1245	26998	16098
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	10000	10000	5000	3950	5000	4000	20000	14400
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	24000	21600	24000	17000	3000	600	67000	47500
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	200	200	-	-	200	-	800	540
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	-	-	150	-258	197	197	1247	759
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	90	90	90	40	50	50	591	481
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	-	-	-	-	-	-	300	100
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-	-	-	-	-500	-	-1500
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	-	-	-	-200	300	300	550	250
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	3200	3200	2000	1888	3150	3150	30043	25589
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	5000	3750	6000	3500	7000	5230	43500	29668
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	-	-130	-	-	1000	1000	1000	870
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	8000	6000	9000	7875	8000	3150	58000	37775
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	6000	6000	4500	2500	4500	3700	36000	29282
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	-	-	-	-	3000	24	3000	-4209
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	-	-	-	-	500	500	1900	1900
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	5000	3500	7000	5000	3500	2000	28000	16900
	कुल	758392	518829	1007058	717140	89190	75310	82243	52920	84842	53457	470479	316728

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रुप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**3,42,813**	**3,30,490**	**4,85,203**	**5,54,816**	**17,13,322**
जीडीपी का प्रतिशत	***6.6***	***5.9***	***7.7***	***8.5***	***7.3***
I. वित्तीय आस्तियां	**3,63,395**	**5,25,419**	**8,16,484**	**9,07,366**	**26,12,664**
जीडीपी का प्रतिशत	***7.0***	***9.3***	***13.0***	***13.9***	***11.1***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**(81,064)**	**2,04,486**	**4,28,035**	**2,83,634**	**8,35,091**
(ए) बैंक जमाराशि	**(1,06,429)**	**1,97,105**	**4,22,393**	**2,70,025**	**7,83,094**
i. वाणिज्यिक बैंक	(1,07,941)	1,95,442	4,18,267	2,62,326	7,68,094
ii. सहकारी बैंक	1,512	1,663	4,126	7,699	15,000
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**25,365**	**7,380**	**5,642**	**13,610**	**51,997**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**17,555**	**(435)**	**(2,178)**	**5,770**	**20,712**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5,578	(1,371)	73	4,021	8,302
ii. आवास वित्त कंपनियां	11,977	936	(2,252)	1,748	12,410
2. जीवन बीमा निधियाँ	**1,15,539**	**1,28,277**	**1,04,076**	**1,38,998**	**4,86,889**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,24,971**	**1,12,810**	**95,493**	**2,18,719**	**5,51,993**
4. मुद्रा	**1,28,660**	**(68,631)**	**62,793**	**1,46,845**	**2,69,667**
5. निवेश	**24,884**	**82,260**	**69,715**	**50,926**	**2,27,785**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14,573	63,151	37,912	44,964	1,60,600
(बी) इक्विटी	4,502	13,218	27,808	3,084	48,613
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**50,405**	**66,218**	**56,372**	**68,243**	**2,41,238**
II. वित्तीय देयताएँ	**20,583**	**1,94,929**	**3,31,281**	**3,52,550**	**8,99,343**
जीडीपी का प्रतिशत	***0.4***	***3.5***	***5.3***	***5.4***	***3.8***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**20,479**	**1,94,825**	**3,31,178**	**3,52,446**	**8,98,928**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**21,428**	**1,38,720**	**2,67,955**	**2,74,181**	**7,02,284**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26,979	1,40,269	2,65,271	3,37,010	7,69,529
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**(949)**	**56,105**	**63,223**	**78,266**	**1,96,644**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	(8,708)	30,151	32,177	40,003	93,623
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,132	24,404	29,495	37,436	98,467
iii. बीमा कंपनियाँ	627	1,550	1,551	827	4,554
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**34**	**34**	**34**	**135**
3. सामान्य सरकार	**70**	**70**	**70**	**70**	**279**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**2,89,980**	**2,99,395**	**2,96,132**	**4,54,240**	**13,39,748**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.5***	***4.6***	***4.3***	***6.4***	***5.0***
I. वित्तीय आस्तियां	**5,79,958**	**6,34,471**	**7,50,245**	**9,71,526**	**29,36,200**
जीडीपी का प्रतिशत	***8.9***	***9.8***	***10.9***	***13.6***	***10.9***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**1,85,429**	**3,17,361**	**2,80,233**	**3,25,853**	**11,08,876**
(ए) बैंक जमाराशि	**1,63,172**	**2,99,533**	**2,56,400**	**3,07,867**	**10,26,971**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,58,613	3,00,565	2,48,460	2,84,968	9,92,606
ii. सहकारी बैंक	4,559	(1,032)	7,940	22,899	34,365
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**22,257**	**17,829**	**23,833**	**17,986**	**81,905**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6,505**	**2,077**	**8,082**	**2,234**	**18,897**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,231	3,267	3,247	3,946	14,690
ii. आवास वित्त कंपनियां	2,274	(1,191)	4,835	(1,712)	4,207
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73,298**	**1,51,677**	**1,67,522**	**1,56,613**	**5,49,109**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,48,915**	**1,20,367**	**1,38,584**	**2,18,709**	**6,26,575**
4. मुद्रा	**66,439**	**(54,579)**	**76,760**	**1,48,990**	**2,37,610**
5. निवेश	**51,503**	**48,530**	**49,779**	**64,151**	**2,13,962**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35,443	44,484	40,206	58,955	1,79,088
(बी) इक्विटी	13,561	1,378	6,434	1,665	23,038
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54,375**	**51,115**	**37,368**	**57,211**	**2,00,068**
II. वित्तीय देयताएँ	**2,89,978**	**3,35,076**	**4,54,113**	**5,17,285**	**15,96,452**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.5***	***5.2***	***6.6***	***7.3***	***5.9***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**2,89,781**	**3,34,880**	**4,53,917**	**5,17,089**	**15,95,667**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**2,34,235**	**2,63,450**	**3,70,783**	**3,83,845**	**12,52,313**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,30,284	2,61,265	3,68,305	3,31,293	11,91,146
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**55,546**	**71,429**	**83,134**	**1,33,244**	**3,43,354**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30,532	36,650	55,792	94,565	2,17,539
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22,337	33,031	24,903	36,746	1,17,017
iii. बीमा कंपनियाँ	2,678	1,748	2,439	1,933	8,798
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**34**	**34**	**34**	**135**
3. सामान्य सरकार	**163**	**163**	**163**	**163**	**650**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**3,53,093**	**2,89,675**	**2,98,111**	**6,11,366**	**15,52,245**
जीडीपी का प्रतिशत	***5.0***	***4.1***	***3.9***	***7.8***	***5.3***
I. वित्तीय आस्तियां	**6,74,763**	**8,15,842**	**8,08,779**	**11,32,130**	**34,31,514**
जीडीपी का प्रतिशत	***9.6***	***11.5***	***10.7***	***14.5***	***11.6***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**2,68,925**	**4,12,388**	**2,99,372**	**4,10,559**	**13,91,244**
(ए) बैंक जमाराशि	**2,55,249**	**5,06,208**	**2,79,872**	**3,94,573**	**14,35,902**
i. वाणिज्यिक बैंक	2,46,079	5,06,700	2,82,537	3,87,313	14,22,629
ii. सहकारी बैंक	9,170	(492)	(2,665)	7,260	13,273
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**13,676**	**(93,820)**	**19,499**	**15,986**	**(44,658)**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**(485)**	**(1,07,982)**	**5,338**	**1,825**	**(1,01,305)**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6,119	4,782	4,896	1,943	17,740
ii. आवास वित्त कंपनियां	(6,605)	(1,12,764)	442	(118)	(1,19,045)
2. जीवन बीमा निधियाँ	**1,58,358**	**1,41,413**	**1,61,192**	**1,30,036**	**5,90,999**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,63,508**	**1,48,178**	**1,53,255**	**2,53,719**	**7,18,661**
4. मुद्रा	**(48,636)**	**(36,701)**	**56,719**	**1,46,644**	**1,18,026**
5. निवेश	**41,409**	**73,060**	**79,633**	**1,08,732**	**3,02,834**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32,086	55,769	60,135	90,973	2,38,962
(बी) इक्विटी	3,757	7,146	9,941	8,236	29,080
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**91,198**	**77,504**	**58,607**	**82,441**	**3,09,751**
II. वित्तीय देयताएँ	**3,21,670**	**5,26,167**	**5,10,667**	**5,20,764**	**18,79,269**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.6***	***7.4***	***6.7***	***6.7***	***6.4***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**3,21,520**	**5,26,016**	**5,10,516**	**5,20,613**	**18,78,666**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**2,13,606**	**8,68,874**	**4,02,647**	**3,92,330**	**18,77,458**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,08,027	8,75,654	3,89,898	3,82,558	18,56,136
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**1,07,914**	**(3,42,858)**	**1,07,869**	**1,28,283**	**1,208**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81,449	59,684	85,032	1,00,836	3,27,001
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23,784	(4,04,294)	21,233	25,853	(3,33,424)
iii. बीमा कंपनियाँ	2,681	1,753	1,604	1,594	7,631
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**35**	**35**	**35**	**138**
3. सामान्य सरकार	**116**	**116**	**116**	**116**	**465**

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसपंत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसपंत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता है।

2. 2022-23 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान।

3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2022-23 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।

4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।

5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,33,27,377**	**2,39,99,280**	**2,47,08,474**	**2,54,40,650**
जीडीपी का प्रतिशत	**110.4**	**108.9**	**108.2**	**107.8**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,07,90,832**	**1,09,87,937**	**1,14,10,330**	**1,16,80,355**
i. वाणिज्यिक बैंक	99,53,044	1,01,48,486	1,05,66,753	1,08,29,079
ii. सहकारी बैंक	8,37,788	8,39,451	8,43,577	8,51,276
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,06,509**	**2,06,074**	**2,03,896**	**2,09,665**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67,840	66,469	66,542	70,564
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,38,669	1,39,605	1,37,353	1,39,102
(सी) जीवन बीमा निधि	**49,29,725**	**51,42,279**	**52,13,527**	**53,57,350**
(डी) मुद्रा	**27,42,897**	**26,74,266**	**27,37,059**	**28,83,904**
(ई) म्यूचुअल फंड	**18,55,000**	**20,64,364**	**21,26,112**	**21,52,141**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**7,57,398**	**7,62,264**	**7,67,287**	**8,34,148**
(जी) पेंशन निधि	**6,16,517**	**6,67,379**	**6,99,173**	**7,36,592**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**14,28,499**	**14,94,717**	**15,51,089**	**15,86,496**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**77,43,630**	**79,38,456**	**82,69,633**	**86,22,079**
जीडीपी का प्रतिशत	**36.6**	**36.0**	**36.2**	**36.5**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**61,80,377**	**63,19,097**	**65,87,052**	**68,61,233**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	56,47,239	57,87,508	60,52,779	63,89,789
ii. सहकारी बैंक	5,31,728	5,30,164	5,32,833	4,69,989
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**15,63,253**	**16,19,358**	**16,82,581**	**17,60,847**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	7,36,312	7,66,463	7,98,641	8,38,643
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,21,510	7,45,914	7,75,408	8,12,845
iii.बीमा निगम	1,05,431	1,06,981	1,08,532	1,09,359

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,56,21,348**	**2,64,23,992**	**2,71,87,716**	**2,78,44,981**
जीडीपी का प्रतिशत	**102.8**	**102.6**	**103.2**	**103.3**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,18,43,527**	**1,21,43,060**	**1,23,99,459**	**1,27,07,326**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,09,87,692	1,12,88,257	1,15,36,717	1,18,21,685
ii. सहकारी बैंक	8,55,835	8,54,803	8,62,742	8,85,641
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,16,170**	**2,18,247**	**2,26,328**	**2,28,562**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74,794	78,061	81,308	85,254
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,41,376	1,40,185	1,45,020	1,43,308
(सी) जीवन बीमा निधि	**53,25,967**	**55,59,682**	**57,86,593**	**57,95,431**
(डी) मुद्रा	**29,50,343**	**28,95,764**	**29,72,524**	**31,21,514**
(ई) म्यूचुअल फंड	**20,48,097**	**22,60,210**	**23,55,316**	**23,67,793**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**8,51,913**	**8,58,591**	**8,64,731**	**9,39,449**
(जी) पेंशन निधि	**7,44,459**	**7,96,454**	**8,53,412**	**8,98,343**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**16,40,871**	**16,91,985**	**17,29,353**	**17,86,563**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**89,11,861**	**92,46,741**	**97,00,657**	**1,02,17,746**
जीडीपी का प्रतिशत	**35.8**	**35.9**	**36.8**	**37.9**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**70,95,468**	**73,58,918**	**77,29,701**	**81,13,546**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	66,20,073	68,81,338	72,49,643	75,80,936
ii. सहकारी बैंक	4,73,897	4,76,025	4,78,487	5,30,915
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**18,16,393**	**18,87,823**	**19,70,956**	**21,04,201**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	8,69,175	9,05,825	9,61,617	10,56,182
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	8,35,181	8,68,213	8,93,116	9,29,862
iii.बीमा निगम	1,12,037	1,13,785	1,16,223	1,18,157

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,87,56,851**	**2,96,44,299**	**3,07,47,010**	**3,19,86,847**
जीडीपी का प्रतिशत	**104.6**	**105.4**	**106.6**	**108.3**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,29,62,575**	**1,34,68,783**	**1,37,48,656**	**1,41,43,228**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,20,67,764	1,25,74,464	1,28,57,001	1,32,44,314
ii. सहकारी बैंक	8,94,811	8,94,319	8,91,655	8,98,914
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,28,077**	**1,20,095**	**1,25,432**	**1,27,257**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91,373	96,156	1,01,051	1,02,994
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,36,703	23,939	24,381	24,263
(सी) जीवन बीमा निधि	**60,64,437**	**62,55,801**	**65,53,726**	**67,69,272**
(डी) मुद्रा	**30,72,878**	**30,36,177**	**30,92,896**	**32,39,540**
(ई) म्यूचुअल फंड	**26,26,046**	**28,29,859**	**31,56,299**	**33,87,208**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**9,55,061**	**9,60,344**	**9,64,852**	**10,51,376**
(जी) पेंशन निधि	**9,70,016**	**10,17,975**	**10,91,276**	**11,72,651**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**18,77,761**	**19,55,265**	**20,13,873**	**20,96,314**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**1,05,39,266**	**1,10,65,282**	**1,15,75,799**	**1,20,96,412**
जीडीपी का प्रतिशत	**38.3**	**39.3**	**40.2**	**41.0**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**83,27,152**	**91,96,026**	**95,98,673**	**99,91,003**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	77,88,962	86,64,616	90,54,514	94,37,072
ii. सहकारी बैंक	5,36,409	5,29,528	5,42,241	5,51,852
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**22,12,114**	**18,69,256**	**19,77,126**	**21,05,409**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	11,37,631	11,97,315	12,82,347	13,83,183
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	9,53,646	5,49,352	5,70,585	5,96,438
iii.बीमा निगम	1,20,837	1,22,590	1,24,194	1,25,788

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आकंड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।
3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं **(https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsViewaspx?id=17618)**

'वर्तमान सांख्यिकी' का समय श्रृंखला डेटा https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2024	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 44, सं. 1, 2023	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022-23	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-जून 2024	आरबीआई बुलेटिन जुलाई, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2024	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2024 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नंवबर 2024	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।